संयुक्त सैन्याभ्यास 'त्रिशूल'

गुजरात और राजस्थान की पश्चिमी सीमाओं पर तीनों सेना ने जो साझा युद्धाभ्यास त्रिशूल शुरू किया है, वह 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास तो है ही, इसे देश में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्याभ्यास भी बताया जा रहा है. पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा तथा सर क्रीक से लेकर अरब सागर तक के क्षेत्र में भारतीय नौसेना के नेतृत्व में हो रहे इस संयुक्त युद्धाभ्यास में लगभग 30,000 सैनिकों के अलावा नौसेना के 20-25 युद्धपोत तथा वायुसेना के करीब 40 युद्धक विमान शामिल बताये जा रहे हैं. इस अभ्यास का मकसद जमीन, हवा, समुद्र तथा डिजिटल व साइबर डोमेन में देश के सुरक्षा तंत्र के बीच ऑपरेशनल तालमेल की पुष्टि करना है. इस साझा सैन्याभ्यास में सेना ने अपनी नयी हमलावर इकाइयों- भैरव और अश्नि प्लाटून को भी शामिल किया है.

पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा तथा सर क्रीक से लेकर अरब सागर तक के क्षेत्र में तीनों सेना ने जो संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया है, उसका मकसद पड़ोसी देश को यह संदेश देना है कि अगर फिर कोई हिमाकत की गयी, तो उसका नतीजा खतरनाक होगा.

भैरव बटालियन को तेज और सटीक कार्रवाई के लिए गठित किया गया है. जबकि ड्रोन और ड्रोन रोधी ऑपरेशन में माहिर अश्नि प्लाटून को थार के मरुस्थल में उतारा गया है. दरअसल युद्ध के बदलते स्वरूप के कारण सेना परंपरागत युद्ध के साथ-साथ अब युद्ध के तकनीकी आयाम पर भी विशेष ध्यान दे रही है. इस सैन्याभ्यास के दो उद्देश्य हैं- एक तो थलसेना, नौसेना और वायुसेना की साथ काम करने की क्षमता बढ़ाना, और दूसरा- सेना का एक समन्वित नेटवर्क तैयार करना. इसका उद्देश्य अचानक हमले या फिर किसी आपातकालीन स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया देने की क्षमता को परखना और उसे तैयार रखना है. त्रिशूल से मिली सीख से युद्ध के तौर-तरीकों का परिशोधन किया जायेगा. सिर्फ यही नहीं कि पाक नौसेना ने भी इस महीने की शुरुआत में उत्तरी अरब सागर में चार दिवसीय नौसैनिक युद्धाभ्यास किया था, बल्कि भारत के संयुक्त सैन्याभ्यास से बौखलाये-घबराये पाकिस्तान ने नौसैनिक अलर्ट भी जारी किया है. इस संयुक्त सैन्याभ्यास को कच्छ और सर क्रीक क्षेत्र में आयोजित किये जाने की भी वजह है. दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में सर क्रीक पर विवादास्पद बयान दिये थे. जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान सर क्रीक के नजदीकी इलाकों में सैन्य ढांचा विकसित करने में लगा है. इस पृष्ठभूमि में साझा सैन्याभ्यास के जरिये पाकिस्तान को यह संदेश दिया जा रहा है कि अपनी सीमा की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारत न केवल तैयार है, बल्कि पाकिस्तान ने अगर इस बार हिमाकत की, तो उसका नतीजा बेहद खतरनाक होगा.

सकारात्मक है भारत-अमेरिका रक्षा समझौता

राजन कुमार
प्रोफेसर, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान, जेएनयू, नयी दिल्ली
rajan75jnu@gmail.com

भारत-अमेरिकी रक्षा समझौते का दस वर्षों के लिए विस्तार दोनों देशों के संबंधों के लिए सकारात्मक कदम है. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जो चीन के विरुद्ध मजबूत दीवार बन सकता है. इसलिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से वाशिंगटन भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपरिहार्य रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है. भारत भी समझता है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके हित अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं. हालांकि दोनों के बीच विश्वास की कमी बनी हुई है.

भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर उत्साहित था और भावनाएं बहुत सकारात्मक थीं. ये संबंध बढ़ते व्यापार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रक्षा सहयोग और मजबूत प्रवासी भावनाओं पर आधारित थे. दोनों स्वाभाविक साझेदार और लोकतांत्रिक मित्र प्रतीत होते थे. लेकिन अमेरिका के उच्च टैरिफ, भारत-पाक युद्धविराम और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप के अनर्गल बयानों ने दोनों देशों में तनाव पैदा किया. व्हाइट हाउस की पाक सैन्य प्रमुख के साथ निकटता और चीन के प्रति ट्रंप के नरम रवैये ने भी भारतीय नीति-निर्माताओं में गंभीर चिंता पैदा की. विशेषज्ञों ने भारत और अमेरिका के 'स्वाभाविक साझेदार' के रूप में गढ़े गये आख्यान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और भारत के प्रति ट्रंप प्रशासन की नीति में संभावित बदलाव की आशंका जतायी. नयी दिल्ली ने अपनी नीति में भी बदलाव लाने की कोशिश की, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लेने चीन गये, निमंत्रण के बावजूद इस्राइल-गाजा शांति बैठक के लिए मिस्र की यात्रा से परहेज किया और कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए. ये घटनाक्रम दर्शाते हैं कि नयी दिल्ली ट्रंप प्रशासन के साथ अपने व्यवहार में सतर्कता बरत रही है.

बहरहाल, भारत और अमेरिका के बीच दस साल के रक्षा समझौते से दोनों देशों के बीच संबंध फिर से बहाल होने की उम्मीद जगी है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और उनके भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह ने कुआलालंपुर में इस समझौते को अंतिम रूप दिया. अमेरिका द्वारा दस दिनों में चीन और भारत, दोनों के साथ अलग-अलग समझौते करना किसी विडंबना से कम नहीं है. इस विरोधाभासी नीतिगत रुख को कैसे समझा जाये? इसके बावजूद वाशिंगटन और नयी दिल्ली के बीच हुई दस वर्षीय संधि महत्वपूर्ण तो है ही. दोनों देशों के बीच कई रक्षा और सुरक्षा समझौतों का इतिहास रहा है. 'भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए नये ढांचे' को 2015 में दस वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था. चूंकि यह विस्तार 2025 में समाप्त हो रहा था, इसलिए राजनाथ सिंह और पीट हेगसेथ के बीच हुई नवीनतम बैठक में इसे 2035 तक बढ़ा दिया गया है. दोनों देशों ने कई संस्थागत संवाद तंत्र भी विकसित किये हैं. जैसे, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद तंत्र. दोनों देशों ने कई रक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये हैं. जैसे- 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, 2018 में कम्युनिकेशंस कम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, 2019 में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट. भारत अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा सैन्य अभ्यास भी करता है. ये हैं- युद्ध अभ्यास (थलसेना), वज्र प्रहार (विशेष बल), मालाबार (नौसेना), कोप इंडिया (वायुसेना), और टाइगर ट्रायंफ (तीनों सेना). इसके अलावा अमेरिका से भारत की रक्षा खरीद लगभग 20 अरब डॉलर की है. कुछ प्रमुख खरीदों में सी-130जे, सी-17, अपाचे, चिनूक, एमएच60आर हेलीकॉप्टर और पी8I शामिल हैं. ये समझौते दोनों देशों को और करीब ला रहे थे. लेकिन ट्रंप की अमेरिका को फिर से महान बनाने की नीति ने भारत को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है.

ट्रंप तीन अंतर्निहित मान्यताओं के साथ अमेरिकी विदेश नीति को पुनर्परिभाषित करना चाह रहे हैं : अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व को बनाये रखना, यदि इससे लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलती है, तो विरोधियों के साथ भी संबंध बनाने के लिए तैयार रहना, और अमेरिकी प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए मित्र देशों को भी अपने संबंधों को पुनर्गठित करने के लिए मजबूर करना. भारत अकेला मित्र देश नहीं है, जो दबाव में है. यूरोपीय संघ और जापान जैसे सहयोगियों के साथ भी ट्रंप सख्ती से पेश आये हैं. ट्रंप अपने पत्ते थोड़े बेढंगे ढंग से जरूर खेल रहे हैं, पर इसे अस्थायी नजरिया नहीं माना जाना चाहिए. ट्रंप मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका की अपरिहार्यता को जानते हैं और इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं. नयी दिल्ली की कमजोरी सेमीकंडक्टर सहित उच्च स्तरीय तकनीक के लिए अमेरिका पर उसकी निर्भरता है. हमारे नीति-निर्माताओं ने यह गलत अनुमान लगाया कि वैश्वीकरण निर्बाध रहेगा और अमेरिका व चीन महत्वपूर्ण तकनीक और खनिजों की आपूर्ति जारी रखेंगे. फिलहाल अमेरिका और चीन के पास इन दोनों क्षेत्रों में किसी भी देश को दंडित करने की क्षमता है. भारत के पास चीन जैसी क्षमता नहीं है, इसीलिए अमेरिका के प्रति उसका रुख अपेक्षाकृत नरम है.

भारत को अपनी जनसांख्यिकी, भौगोलिक स्थिति और खुली राजनीति के कारण अनूठा लाभ प्राप्त है. मध्यम लेकिन निरंतर विकास के साथ अगले दो दशकों में भारत तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरेगा. अमेरिका यह भी जानता है कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है. पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जो चीन के विरुद्ध मजबूत दीवार बन सकता है. जापान, दक्षिण कोरिया या आसियान का कोई भी अन्य देश भारत की क्षमता नहीं रखता. इसलिए, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, वाशिंगटन भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक अपरिहार्य रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है. भारत भी समझता है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके हित अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं. यदि चीन को नियंत्रित करना है, तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी आवश्यक है. भारत अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन नहीं बनाना चाहता, बल्कि क्वाड जैसे राजनीतिक गठबंधन में काम करना चाहता है. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि भारत के निकटवर्ती पश्चिम में अमेरिका एक सिरदर्द है, जबकि पूर्व में एक आवश्यकता. दुनिया में कहीं भी, भारत के भू-राजनीतिक हित अमेरिका के साथ उतने नहीं मिलते, जितने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मिलते हैं. इसलिए अल्पकालिक टैरिफ संबंधी बाधाओं को भारत-अमेरिका संबंधों के अंतिम निर्णायक कारक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. ट्रंप चले जायेंगे, टैरिफ भी बदल जायेंगे, पर चीन का खतरा कम नहीं होगा. चीन के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई सही रणनीति है. निष्कर्षतः रक्षा समझौते का दस वर्षों के लिए विस्तार दोनों देशों के संबंधों के लिए एक सकारात्मक कदम है. हालांकि दोनों के बीच विश्वास की कमी बनी हुई है. व्यापार वार्ताएं चल रही हैं. पर बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि भारत को ट्रंप प्रशासन से क्या रियायतें मिलती हैं. भू-राजनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान के प्रति ट्रंप का अनुकूल रवैया भारत को और नाराज कर सकता है. दोनों देशों के बीच मुद्दे बने रहेंगे और अतीत की सौहार्दपूर्ण स्थिति वापस नहीं आ सकती.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

गर्मी से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपायों की जरूरत

किरण पांडे
प्रोग्राम डायरेक्टर, सीएसई, नयी दिल्ली
kiran@cseindia.org

अमेरिका स्थित शोध समूह क्लाइमेट सेंट्रल के एक नये अध्ययन से पता चलता है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है, तो इस शताब्दी के अंत तक दुनिया 2.6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है तथा उसे हर वर्ष 57 अतिरिक्त दिन भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. भारत के लिए भी खतरा दूर नहीं है.

अमेरिका स्थित शोध समूह क्लाइमेट सेंट्रल के एक नये अध्ययन ने चेतावनी दी है कि 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के तहत किये गये वादे भी वैश्विक तापमान वृद्धि के खतरनाक स्तर को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. अध्ययन से पता चलता है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है, तो इस शताब्दी के अंत तक दुनिया 2.6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है तथा उसे हर वर्ष 57 अतिरिक्त दिन भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. वर्ष 2015 से अब तक पृथ्वी लगभग 0.3 डिग्री गर्म हो चुकी है, यानी एक दशक पूर्व की तुलना में हर वर्ष 11 अतिरिक्त गर्म दिन जुड़े हैं.

भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश के लिए भी खतरा दूर नहीं है. आज औसत भारतीय को प्रतिवर्ष लगभग 48 दिनों तक अत्यधिक गर्मी झेलनी पड़ रही है. तापमान में 2.6 डिग्री की वृद्धि के साथ यहां अत्यधिक गर्मी के दिनों की संख्या बढ़कर 71 तक होने की आशंका है. मजबूत वैश्विक कार्रवाई के बिना, भारत को प्रतिवर्ष लगभग 101 दिन भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. देश के 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही हर वर्ष 45 से 90 दिनों तक भीषण गर्मी झेल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य, खेती और आजीविका पर संकट मंडरा रहा है. क्लाइमेट सेंट्रल के अध्ययन की मानें, तो इस सदी के अंत तक अधिकांश राज्यों को 20 से 30 अतिरिक्त गर्म दिनों का सामना करना पड़ सकता है, तथा 21 राज्यों में यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक हो सकती है. तापमान बढ़ने से भारत के तटीय और द्वीपीय क्षेत्र सर्वाधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तापमान में 2.6 डिग्री की वृद्धि के साथ अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या आज के 106 से बढ़कर 230 हो सकती है, और यदि दुनिया चार डिग्री तक तक गर्म हो जाती है, तो यह संख्या बढ़कर 327 हो सकती है. गोवा में भी अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या 47 से बढ़कर 117 हो सकती है और तापमान में चार डिग्री की वृद्धि से यह 204 पर पहुंच सकती है. केरल और पुदुचेरी में भी समुद्र के गर्म होने और बढ़ती आर्द्रता से मछली पकड़ने, पर्यटन और जन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की आशंका है.

गंगा के मैदानी क्षेत्रों- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब- में भी भीषण गर्मी के दिनों की संख्या में 70 से 90 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे फसलों की पैदावार और पानी की उपलब्धता में भारी कमी आयेगी और खुले में काम करने वाले लाखों मजदूरों के काम के घंटे सीमित हो जायेंगे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर जैसे पहाड़ी राज्य भी इससे अछूते नहीं रहेंगे. इस शताब्दी के अंत तक इन क्षेत्रों को भी 100 से 170 दिन तक भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है. हमें समझना होगा कि अत्यधिक गर्मी अब केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं रह गयी है, यह जन स्वास्थ्य और आर्थिक आपातकाल में तब्दील हो गयी है. हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि गर्मी और लू से जुड़ी मौतें, जो 2021 में 374 थीं, वे बढ़कर 2023 में 804 पर पहुंच गयीं. हीट वॉच के आंकड़े बताते हैं कि अकेले 2024 में ही अत्यधिक गर्मी से कम से कम 733 लोगों की मौत हुई. दिन में तो चढ़ता पारा लोगों को संकट में डालता ही है, सूर्यास्त के बाद भी इसका कहर शांत नहीं होता. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मार्च से जून 2024 के बीच कम से कम 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रातें भी असामान्य रूप से गर्म दर्ज की गयीं.

बढ़ती गर्मी भारत की आर्थिक उत्पादकता को भी कम कर रही है. लैंसेट पत्रिका के नवीनतम अनुमानों की मानें, तो गर्मी के कारण देश को 2024 में रिकॉर्ड 247 अरब संभावित श्रम घंटे का नुकसान हुआ है. ग्लोबल चेंज बायोलॉजी के एक अध्ययन ने आशंका जतायी है कि 2100 तक हीट स्ट्रेस के कारण भारत जैसे देशों की श्रम उत्पादकता 40 प्रतिशत तक गिर सकती है. वैज्ञानिकों ने चेताया है कि यदि वैश्विक तापमान में दो डिग्री की वृद्धि होती है, तो लू की बारंबारता 30 गुना बढ़ सकती है. ऐसे में न केवल उत्पादकता में और कमी आयेगी, बल्कि आय भी घटेगी तथा आर्थिक संकट भी बढ़ेगा. बढ़ता तापमान स्वास्थ्य और श्रम के साथ-साथ भारत की प्राकृतिक प्रणालियों को भी अस्थिर कर रहा है- विशेष रूप से इसके जल संसाधन को. अत्यधिक गर्मी नदियों, झीलों और जलभृतों को सुखा रही है. भारत की लगभग तीन-चौथाई जनसंख्या उच्च ताप जोखिम वाले क्षेत्रों में रह रही है, इसलिए तत्काल कार्रवाई अब वैकल्पिक नहीं रह गयी है. ताप प्रबंधन के लिए भारत को अब अल्पकालिक राहत से दीर्घकालिक लचीलेपन की ओर बढ़ना होगा. इसका अर्थ है कि भूगोल और व्यवसाय के आधार पर जोखिमों का मानचित्रण करना, तापमान से निपटने की तैयारी को आवास, श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना और सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा. शहरों को बेहतर चेतावनी प्रणालियों, ठंडे आश्रय स्थलों और वृक्षों से घिरे सार्वजनिक स्थानों की जरूरत है. राष्ट्रीय स्तर पर देश को पूर्व चेतावनी प्रणालियों, जलवायु अनुकूल खेती, जल संरक्षण व स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना होगा. **(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)**

देश दुनिया

सार्वजनिक सेवा में सुधार की जेन जेड की मांग पूरी करें सरकारें

युवाओं के नेतृत्व में जेन जेड विरोध प्रदर्शनों की लहर दुनियाभर में फैल रही है. मोरक्को में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक नारा बार-बार दोहराया गया था- हमें अस्पताल चाहिए, स्टेडियम नहीं- जो दर्शाता है कि कैसे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सेवाओं को दरकिनार किया जा रहा है. मेडागास्कर में बिजली और पानी की कटौती के कारण विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे सरकार गिर गयी. उच्च स्तर की असमानता, सार्वजनिक सेवाओं में कमी और पीढ़ीगत हताशा में निहित ये विरोध प्रदर्शन सरकारों और युवा नागरिकों के बीच सामाजिक अनुबंध का टूटना दर्शाते हैं. दुनिया में धन की कमी नहीं है, पर इसका अधिकांश हिस्सा धनी लोगों के हाथों में है. अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा केवल उन्हीं लोगों को मिल रही है जिनके पास पर्याप्त धन है. यह एक पीढ़ी की प्रतिभा को बर्बाद कर रहा है. कई देशों में, धनी परिवारों के बच्चों के विश्वविद्यालय जाने की संभावना गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों की तुलना में कई गुना अधिक होती है. गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए, यह संभावना और भी कम है. इन बातों का गुस्से और आक्रोश में बदल जाना, कोई आश्चर्य की बात नहीं है. मितव्ययिता और सरकारी व्यय में कटौती के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता के सामने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्षीण होती जा रही है. यह दुखद है, क्योंकि इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि मजबूत कल्याणकारी प्रणालियां असमानता को कम करने, सामाजिक हानि को दूर करने और विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं. जेन जेड के विरोध प्रदर्शन ने दिखा दिया है कि अगली पीढ़ी अब इन चिंताओं के समाधान के लिए पारंपरिक दलगत राजनीति की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है. यदि सरकारें सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और मजबूत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा असमानता को दूर करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें और अधिक प्रतिरोध और विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

-अमिताभ बेहर

ALJAZEERA

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

बोधि वृक्ष

भक्ति सौदा नहीं है

जरा सोच कर देखिए कि आप कब और किसलिए अपने भगवान या इष्ट को याद करते हैं? जब आपको कुछ मांगना होता है या जब कोई परेशानी या तकलीफ आन पड़ती है तभी न? तो फिर यह भक्ति है या एक तरह का सौदा? अंग्रेजी में 'डिवोशन' (भक्ति) शब्द 'डिसोल्यूशन' शब्द से बना है जिसका अर्थ है, विसर्जन. जब हम भक्त कहते हैं, तो भक्त का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता. उसका एकमात्र उद्देश्य उस चीज में विसर्जित हो जाना होता है जिसकी वह भक्ति कर रहा है, बस. वह अच्छी तरह से रहने के बारे में नहीं सोच रहा है. वह धनी होने के बारे में भी नहीं सोच रहा है. वह स्वर्ग जाने के बारे में भी नहीं सोच रहा है. मान लीजिए वह भगवान शिव का भक्त है. इसका अर्थ है कि वह बस शिव में ही विलीन हो जाना चाहता है, वह शिव में ही समाप्त हो जाना चाहता है. बस यही है, जो वह जानता है. इस दुनिया में होने वाली प्रार्थनाओं को देखिए. निन्यानबे प्रतिशत प्रार्थनाओं में क्या होता है? मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो. मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो. यह भक्ति नहीं है, यह सौदा है. आप एक मूर्खतापूर्ण सौदा करने की कोशिश में लगे हैं. तो यदि आप वास्तव में भक्त बनना चाहते हैं और भक्ति के जरिये उस परम चेतना तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपका अपना कोई उद्देश्य नहीं होगा. आप नहीं चाहेंगे कि जीवन वैसे चले जैसा आप चाहते हैं.

आप उसके साथ विलीन हो जाना चाहेंगे, बस. यदि आप ऐसे हैं, तो भक्ति आत्म ज्ञान प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका है. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपमें भक्ति का अंश बिल्कुल है ही नहीं. आपके भीतर जितनी भक्ति है उससे हो सकता है कुछ उद्देश्य हल हो जाये, पर यह आपको उस परम अवस्था तक नहीं पहुंचा सकती. आप ऐसी भक्ति से छोटे-मोटे काम कर सकते हैं, बस. आप तब तक किसी के सामने पूरी तरह झुकने को तैयार नहीं होते जब तक आप अनुभव के एक खास स्तर तक नहीं पहुंचते, एक ऐसा स्तर जहां आप स्वाभाविक रूप से एक भक्त के रूप में निखर जाते हैं.

-सद्गुरु जग्गी वासुदेव

कुछ अलग

प्रेम विवाह पर पहरा

सरस्वती रमेश
टिप्पणीकार
saramesh17@gmail.com

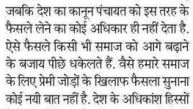

प्रेम पर पहरा कोई नयी बात नहीं है. पर यह भी सच है कि समाज का एक वर्ग प्रेम विवाह को खुले मन से स्वीकार करने लगा है. कानून भी बालिग लोगों को स्वेच्छा से विवाह करने की अनुमति देता है. ऐसे में प्रेम विवाह करने वालों के लिए तालिबानी फरमान की बात कुछ हजम नहीं हो रही. कुछ दिनों पूर्व पंजाब के कुछ गांव की पंचायतों ने प्रेम विवाह पर रोक लगाने का निर्णय लिया. पंचायत के निर्णय के अनुसार, परिवार और समुदाय की सहमति के बिना कोई विवाह नहीं हो सकता. प्रेम विवाह करने वाले जोड़े गांव या आसपास नहीं रह सकते. विवाह करने वाले प्रेमी जोड़े की किसी भी तरह की मदद करने वाले परिवार को भी पंचायत की सुनाई सजा भुगतनी पड़ेगी. सजा न मानने पर उन्हें गांव से बाहर भी किया जा सकता है.

खबर के अनुसार, ये सारे निर्णय पंजाब स्थित कई गांवों में वहां की पंचायतों द्वारा लिये गये हैं. उन्होंने समाज की परंपराओं का हवाला व गांव में शांति कायम रखने को इसका कारण बताया है. हैरत की बात यह है कि गांव वालों ने भी इस निर्णय में अपनी सहमति जतायी है, जबकि देश का कानून पंचायत को इस तरह के फैसले लेने का कोई अधिकार ही नहीं देता है. ऐसे फैसले किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेलते हैं. वैसे हमारे समाज के लिए प्रेमी जोड़ों के खिलाफ फैसला सुनाना कोई नयी बात नहीं है. देश के अधिकांश हिस्सों में अभी भी प्रेम व प्रेम विवाह पर पहले से ही अघोषित प्रतिबंध है. प्रेमी जोड़ों को प्रताड़ित करने के समाचार जब-तब मिलते रहते हैं. सम्मान के नाम पर प्रेमी/प्रेमिकाओं की हत्या तक कर दी जाती है. पर अब तक यह सब परिवार व व्यक्ति की इच्छा से हो रहा था. पंचायतों के फैसले के बाद अब यह वहां सामूहिक रूप से होगा.

प्रेम विवाह एक बालिग स्त्री-पुरुष को अपने जीवनसाथी के चुनाव की स्वतंत्रता देता है. समाज की जड़ों में घुन की तरह लगे जातिवाद को खुरचता है. चूंकि अधिकतर प्रेम विवाह सादे तरीके से होते हैं, इसलिए दहेज प्रथा व ब्याह में होने वाली फिजूलखर्ची को भी यह बचाता है. प्रेम विवाह पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि इसे बढ़ावा देने की जरूरत है. हां, इसके लिए पहले अपने बेटे-बेटियों को इस काबिल बनाने की आवश्यकता है कि वे अपने लिए सही जीवनसाथी का चुनाव कर सकें. उन्हें प्रेम विवाह करने से डराने की बजाय, अपरिपक्व उम्र में विवाह के खतरों के बारे में समझाया जाये. बालिग होने पर उन्हें विवाह का सही अर्थ भी समझाने की आवश्यकता है, जिससे प्रेमी-प्रेमिका से पति-पत्नी बनने पर जोड़े विवाह के बाद की जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निभा सकें.

आपके पत्र

भारतीय महिला टीम को बधाई

हाल ही में नवी मुंबई में हुए महिला विश्व कप फाइनल (भारत- दक्षिण अफ्रीका) में भारतीय टीम ने जो जीत हासिल की है, वह प्रशंसनीय है. यह जीत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गयी है. इस जीत से एक ओर जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी प्रतिभा दिखायी है, वहीं दूसरी ओर उसने देश की लाखों बेटियों को सपने देखने के लिए प्रेरित किया है. इस जीत से न जाने कितने परिवार अपनी बेटियों को खेलों में भेजना शुरू करेंगे. भारतीय महिला टीम को जीत के लिए बहुत-बहुत बधाई.

श्वेता बड़ाईक, रांची

ठेकुआ को मिले जीआइ टैग

छठ महापर्व का महाप्रसाद है ठेकुआ. यह गेहूं के आटे एवं गुड़ से मिलकर बनता है. यह मीठा होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी होता है. ठेकुआ पूर्वांचल, विशेषकर बिहार की एक प्रसिद्ध मिठाई है. देश के किसी दूसरे अंचल से इसे बनाने की बात सामने नहीं आती है. अतः इसे भौगोलिक संकेत, यानी जीआइ टैग मिलना जरूरी है. भौगोलिक संकेत एक ऐसा पहचान चिह्न है, जो किसी उत्पाद को उसके मूल भौगोलिक स्थान से जोड़ता है. महापर्व छठ के महाप्रसाद ठेकुआ को जीआइ टैग मिलना समय की मांग है.

तारामुनी देवी, वैशाली

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें** : 0651-2544006 ■ **मेल करें** : eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

दैनिक
जलते दीप
जयपुर, गुरुवार 6 नवम्बर 2025

भयावह असमानता

उदारीकरण व वैश्वीकरण के दौर के बाद पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता अपने चरम पर जा पहुंची है। एक तरफ लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सड़कों पर उतर रहे हैं तो दूसरी ओर अमीर से और अमीर होते लोगों की विलासिता के किस्से तमाम हैं। जिस बात की पुष्टि स्वतंत्र विशेषज्ञों के जी-20 पैनल द्वारा किए एक अध्ययन के निष्कर्षों में की गई है। इस अध्ययन के अनुसार, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर असमानता भयावह स्तर तक जा पहुंची है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2000 और 2024 के बीच दुनिया भर में बनी नई संपत्तियों का बड़ा हिस्सा दुनिया के सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों के पास है। जबकि निचले स्तर की आधी आबादी के हिस्से में एक प्रतिशत ही आया है। निस्संदेह, भारत भी इस स्थिति में अपवाद नहीं है। देश के सबसे अमीर एक फीसदी लोगों ने केवल दो दशक में अपनी संपत्ति में 62 फीसदी की वृद्धि की है। दुनिया की इस चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अमीर लगातार अमीर होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब गुरबत के दलदल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। इस आर्थिक असमानता का ही नतीजा है कि अमीर व गरीब के बीच संसाधनों का असमान वितरण और बदतर स्थिति में पहुंच गया है। निस्संदेह, पैनल की हालिया रिपोर्ट नीति-निर्माताओं को असमानता के इस बढ़ते अंतर को पाटने के तरीके तलाशने और नये साधन खोजने के लिये प्रेरित करेगी। पिछले ही हफ्ते, केरल सरकार ने दावा किया था कि राज्य ने अत्यधिक गरीब तबके की गरीबी का उन्मूलन कर दिया है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने इन दावों को लेकर संदेह जताया है। वहीं दूसरी ओर राज्य के विपक्ष ने भी इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद राज्य में जन-केंद्रित विकास और सामुदायिक भागीदारी के लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह, इस पहल ने हजारों अत्यंत गरीब परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के बेहतर साधनों तक पहुंचने में मदद की है। इसमें दो राय नहीं कि यदि सरकारें वोट बैंक की राजनीति से इतर ईमानदारी से पहले करें तो गरीबी उन्मूलन की दिशा में सार्थक पहल की जा सकती है। चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की तेजी से बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। यह एक हकीकत है कि कोई भी सुविधा मुफ्त नहीं हो सकती। इस तरह की लोकलुभावनी कोशिशों से राज्यों का वित्तीय घाटा ही प्रभावित होता है। जिसकी कीमत लोगों को विकास योजनाओं से दूर रहकर ही चुकानी पड़ती है। जनता को मुफ्त में सुविधाएं देने के बजाय ऋण व अनुदान से उत्पादकता बढ़ाकर उन्हें स्वावलंबी बनाना होगा। प्रत्येक चिन्हित गरीब परिवार के लिए सूक्ष्म योजनाएं तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना उचित होगा। निस्संदेह, देश के अन्य राज्य भी अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार केरल के मॉडल को अपना सकते हैं। इसमें केंद्र व राज्य सरकारों को अनुकूल आंकड़ों का सहारा लेना भी जरूरी होगा। इस साल की शुरुआत में, विश्व बैंक ने बताया था कि भारत 2011-12 और 2022-23 के बीच 17 करोड़ लोगों को गरीबी की दलदल से बाहर निकालने में सफल रहा है। केंद्र सरकार ने अपने काम के लिये खुद की पीठ भी थपथपाई थी। हालांकि, गरीबी के अनुमानों की रिपोर्टिंग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाये गए थे। निर्विवाद रूप से सभी हितधारकों को यह तथ्य समझना होगा कि केवल संख्याएं ही पूरी तस्वीर को नहीं उकेर सकती हैं। गरीबी कम करने के प्रयासों के दावों के मुताबिक जमीनी स्तर पर गुणात्मक बदलाव नजर भी आना चाहिए। हालांकि, अर्थशास्त्री आमतौर पर संपत्ति कर लगाने के पक्षधर नहीं होते हैं, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अति-धनी लोग सरकारी खजाने में अपना उचित योगदान दें। अब चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबका ध्यान विकास पर केंद्रित किया जाना चाहिए। तभी देश उत्पादकता के क्षेत्र में आगे बढ़कर गरीबी उन्मूलन की दिशा में सार्थक प्रगति कर सकता है। यह पहल ही विकसित भारत के सपने को साकार करने में मददगार साबित हो सकती है।

महिला के हक

केरल हाईकोर्ट का एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है जिसमें जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि केरल विवाह पंजीकरण नियम 2008 के तहत मुस्लिम पुरूष पहली पत्नी के जीवित रहते और विवाह कायम रहते किसी और महिला से शादी के रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि उसके सामने पेश एक मामले में राज्य सरकार को ऐसी दूसरी शादी रजिस्टर करने का निर्देश देने की अपील की गई थी, लेकिन अदालत ऐसा इसलिए नहीं करेगी कि उसकी पहली पत्नी को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत विशेष परिस्थितियों में दूसरी शादी की अनुमति है, और उसे देखते हुए कोई मुस्लिम पत्नी अपने पति की दूसरी शादी के पंजीकरण के दौरान मूकदर्शक बनी नहीं रहती। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ दूसरी शादी की इजाजत देता है, तो पुरूष दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन दूसरी शादी को रजिस्टर कराने के मामले में देश का कानून लागू होगा। उन्होंने अपना यह विचार भी सामने रखा कि 99.99 फीसदी मुस्लिम महिलाएं अपने पति के साथ शादी के बंधन में रहते हुए उसकी दूसरी शादी के खिलाफ होंगी। उनका यह भी कहना है कि पहली पत्नी अगर मौजूद है, और उसका पति अपनी दूसरी शादी को देश के कानून के मुताबिक रजिस्टर कराता है, अदालत पहली पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। जज ने लिखा है कि धर्म बाद में आता है, संवैधानिक अधिकार सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि जब दूसरी शादी के पंजीकरण की बात आती है, तो धार्मिक-रस्मी कानून लागू नहीं होते। यह कानून मुस्लिम महिला के हक की एक स्पष्ट व्याख्या करता है कि अगर उसका पति उसके रहते हुए और शादी कायम रहते हुए कोई दूसरी शादी करता है, तो पहली बीवी की सहमति के बिना दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। यहां पर दो कानून एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े होते हैं, एक मुस्लिम विवाह कानून है जो कि मुस्लिम पुरूष को कुछ नियम और शर्तों के साथ चार शादियां समानांतर करने और रखने की छूट देता है। दूसरा कानून विवाह पंजीयन का है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए अनिवार्य किया है, और किसी भी तरह की शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। केरल हाईकोर्ट के इस अकेले जज के फैसले ने मुस्लिम पुरूष की दूसरी शादी को नहीं रोका गया है, क्योंकि वह उस समुदाय के विवाह कानून के तहत मुमकिन है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन करने से अदालत ने इंकार कर दिया है। इसी वक्त केरल से एकदम दूर, असम में वहां के कट्टर मुस्लिम विरोधी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यह बीड़ा उठाया है कि वे राज्य में किसी भी कीमत पर बहुविवाह रोकेंगे। उन्होंने इसके पहले यह बीड़ा भी उठाया था कि नाबालिगों की शादी कोई नहीं कर सकेंगे, और देश के कानून के मुताबिक उस पर सजा दी जाएगी। उन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए एक सरकारी अभियान चलाया है, और हजारों नाबालिग लड़कियों की शादी रूकवाई है जिनमें से अधिकतर मुस्लिम थीं। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम विवाह कानून के मुताबिक किसी लडक़ी को माहवारी शुरू होने के बाद उसकी शादी की जा सकती है। असम में बाल विवाह देश में सबसे अधिक, करीब 32 फीसदी था, और 2022 से वहां पर इसे रोकने की मुहिम बड़ी कड़ाई से चल रही है। 2023 में एक जिले में एक दिन में 4 हजार से अधिक लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें तकरीबन तमाम लोग मुस्लिम थे। सरमा का कहना है कि बाल विवाह गरीबी, और अशिक्षा की उपज है, और उन्होंने 2022 में असम बाल विवाह निषेध नियम लागू किया, और नाबालिगों की शादी पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की इनसे मुस्लिम नाबालिग लड़कियों (हो सकता है कुछ संख्या में दूसरे धर्मों की भी) की शादियां बहुत कम हुई हैं। अब उन्होंने 2024 में एक बहुपत्नी निषेध विधेयक पेश किया है, और 2024 में एक और कानून धर्मांतरण को लेकर बनाया है जिसमें बहुविवाह को भी जुर्म बनाया गया है, उन्होंने अभी-अभी यह कहा है कि वे किसी भी हालत में बहुविवाह नहीं होने देंगे।

प्रसंगतः उदारता की राह

पंडित मदनमोहन मालवीय का कहना था कि यदि मूक जीवों का कष्ट समझकर हम इंसान उनके हित में कुछ कर सकें तो शायद इससे बढ़कर दूसरा कोई पुण्य नहीं होगा। यह बात उनके आचरण में हमेशा दिखती थी। उनके भीतर प्राणी मात्र के लिए दया थी। इससे जुड़ी एक घटना बड़ी चर्चित है। मालवीय जी किसी जरूरी काम से कहीं पैदल जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक कुत्ता छटपटाता दिखाई दिया। उसके कान के पास एक घाव था और वह पीड़ा के मारे इधर-उधर भाग रहा था। उसकी कराह सुनकर मालवीय जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपना काम निपटाने का विचार छोड़ा और पशु चिकित्सालय दौड़ते हुए गए। वैद्य जी को कुत्ते की तकलीफबताकर दवा मांगी। वैद्य जी ने दवा तो दे दी, मगर बोले, 'मदनमोहन, ऐसे कुत्ते प्रायः पागल हो जाते हैं। छूने पर काट भी लेते हैं। तुम इस खतरे में न पड़ो तो अच्छा है।' किंतु मालवीय जी नहीं माने। वह कष्ट में पड़े किसी प्राणी से मुंह नहीं फेर सकते थे। उन्होंने दवा लेकर एक लंबे बांस में कपड़ा लपेटा और कुत्ते को ढूंढने लगे। कुत्ता एक संकरी गली में बैठा था। मालवीय जी ने पहले कपड़े पर दवा लगाई फिर बांस की सहायता से कुत्ते को दवा लगाना शुरू किया। कुत्ता गुर्राता, दांत निकालता और झपटने की भी कोशिश करता रहा, किंतु मालवीय जी बिना डरे उसे दवा लगाते रहे। जब कुत्ते की पीड़ा कम हुई तो वह सो गया। तब मालवीय जी को शांति मिली और वह अपने कार्य के लिए रवाना हुए।

बिहार : क्या यही है 'सुशासन' के दावों की हक़ीक़त ?

सबसे पहले तो ज़िक्र करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह (आरके सिंह) के बयानों का। आर के सिंह बिहार के आरा से दो बार सांसद रह चुके हैं और मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में वे ऊर्जा मंत्री थे। उनकी गिनती भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में होती है। सर्वप्रथम तो आर के सिंह ने चुनाव अभियान के बीच ही गत 20 अक्टूबर को एक वीडियो संदेश जारी कर मतदाताओं से अपील की थी कि वे अपराधी और भ्रष्ट छवि वाले उम्मीदवारों को वोट हरगिज़ न दें। उन्होंने विशेष रूप से जेडीयू के मोकामा से उम्मीदवार अनंत सिंह व भाजपा के तारापुर से उम्मीदवार व बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लिया था। उस सन्देश में सिंह ने यहां तक कहा था कि ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना चुल्लू भर पानी में डूब मरने से भी बदतर है, क्योंकि ये जनता का खून चूस रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि 'आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को हटाकर ही बिहार का विकास संभव है, और यदि सभी उम्मीदवार ऐसे हों तो मतदाता नोटा का विकल्प चुनें'।

– निर्मल रानी

बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। दावों प्रतिदावों और आरोपों व प्रत्यारोपों का दौर अपने चरम पर है। सत्ता की तरफ़ से चुनाव जीतने के लिये सबसे अधिक ज़ोर लगाया जा रहा है। हरियाणा सहित कई अन्य भाजपा शासित राज्यों से तो बिहारी मतदाताओं को विशेष ट्रेन्स द्वारा मतदान करने हेतु बिहार भेजा जा रहा है। उधर भाजपा स्टार प्रचारक नीतीश सरकार को 'सुशासन' व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के रूप में प्रचारित करते नहीं थक रहे। परन्तु सुशासन व भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के इन्हीं दावों के बीच कुछ ऐसे सनसनीख़ेज़ रहस्योद्घाटन हो रहे हैं व घटनायें घटित हो रही हैं जिन्होंने बिहार में 'सुशासन' व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की क़लई खोल कर रख दी है। हैरानी की बात तो यह है कि इसतरह के खोखले दावों की हवा निकालने में किसी सत्ता विरोधी दल या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है बल्कि स्वयं भाजपा-जे डी यू के नेता ही इस 'क़लई खोल अभियान ' के मुख्य सूत्रधार हैं।

सबसे पहले तो ज़िक्र करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह (आरके सिंह) के बयानों का। आर के सिंह बिहार के आरा से दो बार सांसद रह चुके हैं और मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में वे ऊर्जा मंत्री थे। उनकी गिनती भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में होती है। सर्वप्रथम तो आर के सिंह ने चुनाव अभियान के बीच ही गत 20 अक्टूबर को एक वीडियो संदेश जारी कर मतदाताओं से अपील की थी कि वे अपराधी और भ्रष्ट छवि वाले उम्मीदवारों को वोट हरगिज़ न दें। उन्होंने विशेष रूप से जेडीयू के मोकामा से उम्मीदवार अनंत सिंह व भाजपा के तारापुर से उम्मीदवार व बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लिया था। उस सन्देश में सिंह ने यहां तक कहा था कि ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना चुल्लू भर पानी में डूब मरने से भी बदतर है, क्योंकि ये जनता का ख़ून चूस रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि 'आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को हटाकर ही बिहार का विकास संभव है, और यदि सभी उम्मीदवार ऐसे हों तो मतदाता नोटा का विकल्प चुनें'। सिंह ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले इसी तरह के कुल 8 उम्मीदवारों के नाम लिए। अब आरके सिंह के इस बयान को भाजपा के अंदर सुलग रही बग़ावत की चिंगारी के रूप में देखा जा रहा है।

आर के सिंह के उपरोक्त बयानों पर अभी चर्चा चल ही रही थी कि पिछले दिनों उन्होंने बिजली घोटाला सम्बन्धी एक और बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप मुख्य रूप से बिहार में बिजली विभाग से जुड़े 62,000 करोड़ रुपये के घोटाले से संबंधित हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक पहले यानी गत 4 नवंबर को सामने लाये गये हैं। इन आरोपों के अनुसार बिहार सरकार ने एक थर्मल पावर प्लांट के निर्माण के लिए अदानी ग्रुप से सम्बंधित एक कंपनी को अत्यधिक ऊंची क़ीमत पर अनुबंध दिया। इस अनुबंध के तहत कंपनी को 25 वर्षों के लिए बिजली की क़ीमत 6.075 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई, जो बाज़ार दर से काफ़ी अधिक है। इससे सरकार को पूंजी की वापसी के साथ-साथ अतिरिक्त लाभ होगा, जो कुल 62,000 करोड़ रुपये का नुक़्सान बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को पहुंचाएगा। उन्होंने बिहार सरकार के बिजली विभाग के कई अधिकारियों को इस घोटाले के लिये आरोपित करते हुये सीबीआई से इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। सिंह का आरोप है कि यह घोटाला सीधे तौर पर बिहार के लोगों को प्रभावित करेगा, क्योंकि बिजली के दाम बढ़ेंगे। इससे पहले भी आर के सिंह राज्य की 'सुशासन ' कही जाने वाली नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगा चुके हैं। परन्तु चुनावों के बीच उनके द्वारा लगाये जा रहे उपरोक्त गंभीर आरोपों ने बिहार में कोहराम मचा दिया है। विपक्षी महागठबंधन इन आरोपों को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।

दूसरी बड़ी घटना केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह से संबंधित है। गत 4 नवंबरको पटना ज़िला प्रशासन ने लल्लन सिंह के विरुद्ध एफ़ आई आर दर्ज की है। ललन सिंह ने मोकामा में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह जोकि इस समय दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में बेऊर जेल में बंद हैं के समर्थन में किये जा रहे प्रचार के दौरान एक सभा में कहा कि ÷कुछ नेताओं को वोटिंग के दिन घर में बंद कर दो। घर से उसी को निकलने दो जो हमारे पक्ष में वोट करे। अगर ज़्यादा हाथ-पैर जोड़े तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है।÷ ग़ौर तलब है कि अनंत सिंह की गिरफ़्तारी के बाद ललन सिंह ही उनके चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे थे। विपक्ष ने ललन सिंह के इस बयान को ÷लोकतंत्र पर हमला÷ बताया और कहा कि यह ग़रीब वोटरों को डराने की साज़िश है।

अब इन घटनाओं व बयानों के सन्दर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावों का ज़िक्र भी ज़रूरी है। एक ओर तो आर के सिंह व ललन सिंह जैसे भाजपा-जे डी यू के केंद्रीय स्तर के नेताओं के बयान बिहार में भ्रष्टाचार,कुशासन व जंगल राज की तस्वीर पेश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ़ गृह मंत्री अमित शाह इन्हीं चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को 'भ्रष्टाचार मुक्त' सरकार का प्रमाणपत्र दे रहे हैं। शाह के अनुसार नीतीश कुमार पर ÷ चवन्नी के भ्रष्टाचार' का भी आरोप नहीं लगा है÷। उनके अनुसार केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, जिन पर चार आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वे ही बिहार का विकास कर सकते हैं।÷ वे केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्षों और बिहार में नीतीश के 20 वर्षों के शासन को ÷भ्रष्टाचार मुक्त÷ बताते हैं जबकि विपक्ष पर घोटालों का आरोप लगाने के साथ ही लालू यादव के 20 वर्ष पूर्व के कथित 'जंगल राज ' की भी याद दिलाना नहीं भूलते। ऐसे में आर के सिंह के व लल्लन सिंह जैसे सत्ता से जुड़े केंद्रीय नेताओं के ही बयान क्या यह सवाल नहीं खड़ा करते कि क्या यही है बिहार में 'सुशासन' के दावों की हक़ीक़त ?

शिशु सुरक्षा के लिए उठाने होंगे ठोस कदम

– रमेश सर्राफ धमोरा

हर साल 7 नवम्बर को शिशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, टीकाकरण और माता-पिता की शिक्षा को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर को कम करने पर केंद्रित है। दुनिया भर में लाखों शिशु अभी भी संक्रमण, कुपोषण और चिकित्सा सुविधा की कमी जैसे रोकथाम योग्य कारणों से मर जाते हैं। यह दिवस समाज और सरकारों को यह याद दिलाता है कि वे हर बच्चे के जीवन में एक स्वस्थ शुरुआत के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाएँ।

भारत और कई अन्य देशों में शिशु संरक्षण दिवस मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। जननी सुरक्षा योजना और पोषण अभियान जैसे कार्यक्रम शिशुओं की प्रारंभिक देखभाल में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यह दिवस माता-पिता को स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने के लिए उचित आहार, स्वच्छता और टीकाकरण के नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नवजात शिशुओं की उचित सुरक्षा ना हो पाने के कारण दुनिया में बहुत सारे बच्चे मौत के आगोश में चले जाते है। हालांकि सरकार ने इसे रोकने कि दिशा में सार्थक प्रयास किये है। जिनकी बदौलत देश में शिशु मृत्यु दर में कमी आयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार देश 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत में नवजात बच्चों की मौतों के मामलों में सरकार के लिए बीते 77 साल बड़ी चुनौती भरे रहे हैं। हालांकि इसमें लगातार कमी आ रही है।

देश में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और शिशु जन्म दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 2023 की नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) रिपोर्ट के मुताबिक देश में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम 25 पर आ गई है। 2013 में 40 के मुकाबले इसमें 37.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं शिशु जन्म दर में पिछले 10 साल में 14 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2013 में ये दर 21.4 प्रतिशत थी अभी ये 18.4 प्रतिशत है। आइएमआर एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतक है, जिसे एक वर्ष से कम आयु के पैदा होनेवाले प्रति 1,000 शिशुओं पर होनेवाली मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संख्या जितनी कम होगी स्वास्थ्य सेवा की पहुंच उतनी ही बेहतर मानी जाएगी।

एसआरएस रिपोर्ट के मुताबिक 1971 में शिशु मृत्यु दर के मुकाबले 2023 में 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाल मृत्यु दर प्रति हजार पर 37 दर्ज की गई है। वहीं मणिपुर में ये आंकड़ा तीन का है। 21 राज्यों में केरल ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जहां शिशु मृत्यु दर इकाई में दर्ज की गई है। राज्य में ये आंकड़ा 5 का है और मणिपुर के बाद ये दूसरे नंबर पर है।

रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में ये आईएमआर 44 से घटकर 28 पर आ गई है। वहीं शहरी इलाकों में 27 से घटकर 18 पर आंकी गई है। इस तरह 10 साल में इस दर में 36 प्रतिशत और 33 प्रतिशत की गिरावट क्रमशः दर्ज की गई है। शिशु जन्म दर में भी गिरावट का रुख रिपोर्ट में शिशु जन्म दर में भी गिरावट का रुख दर्ज किया गया है। ये दर जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। इसके तहत सालभर में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित शिशुओं की संख्या बताई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच दशकों में जन्म दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये दर 1971 के 36.9 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 18.4 प्रतिशत पर आ गई है। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिशु जन्म दर करीब-करीब बराबर हो गई है। पिछले 10 वर्ष में जन्म दर 21.4 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 18.4 प्रतिशत पर आ गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दशक में जन्म दर में लगभग 14 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 2013 में 21.4 से घटकर 2023 में 18.4 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 11 प्रतिशत घटकर 22.9 से 20.3 हो गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह 17.3 से घटकर 14.9 हो गई है, जो लगभग 14 प्रतिशत है। बिहार में 2023 में सबसे ज्यादा जन्म दर 25.8 दर्ज की गई, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10.1 के साथ सबसे कम पर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि चंडीगढ़ में सबसे कम मृत्यु दर 4 और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 8.3 दर्ज की गई।

भारत ने पिछले सात दशकों में भले ही चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति करते हुए शिशु मृत्यु दर पर काबू पाया है। लेकिन आज भी शिशुओं की मौत बड़ा सवाल है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर में काफी सुधार देखा गया है। ये साल 2013 में हर 1000 जन्मे बच्चों में से 40 से घटकर अब 25 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। यानी कि मृत्युदर में 37.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

देश में स्वास्थ्य सम्बन्धी चीजों की कमी के कारण यह समस्या और बढ़ जाती है। सरकारों ने इस समस्या से निपटने के लिए बहुत सी योजनायें लागू की है। मगर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा जागरूकता की कमी के कारण शिशुओं की मृत्यु दर में पूर्णतया कमी नहीं आई है। उचित पोषण के भाव में अब भी कई बच्चे दम तोड़ देते है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की कमी एवं प्रशिक्षित नर्सो व दाइयों की कमी के कारण भी विभिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होती है।

2025-26 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अनुमानित व्यय 99,859 करोड़ रुपए है। यह 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 11त्न अधिक है। जो 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के कुल बजट का लगभग 1.97 त्न है। यह राशि कम है इसे बढ़ाना होगा तभी भारत में नवजात शिशुओं की मौत पर रोक लगायी जा सकती है। शिशु सुरक्षा सिर्फ सरकार की ही नहीं वरन सभी की जिम्मेदारी है। सभी को एकजुट होकर इसके लिए आगे आना होगा तब जाकर हम अपने देश के शिशुओं की सुरक्षा के मामले में अन्य देशों की तुलना में ऊपरी पायदान पर आ पाएंगे।

शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शिशु जन्म के एक घंटे के भीतर मां का दूध पिलाना चाहिए। मा के गाढ़े पीले दूध में सर्वाधिक मात्रा में संक्रमण-रोधी तत्त्व मौजूद होता है। जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन ए के साथ 10 प्रतिशत तक प्रोटीन होता है। जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है। 6 माह तक शिशुओं को केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए। जिसमें मां के दूध के अलावा कोई अन्य दूध, खाद्य पदार्थ,पेय पदार्थ और यहां तक पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। इससे शिशु डायरिया, निमोनिया,अस्थमा एवं एलर्जी से बचा रहता है।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत के स्वास्थ्य खर्च को दुनिया के औसत और अन्य विकासशील और विकसित देशों से काफी नीचे छोड़ देता है। भारत का खर्च नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से तो ज्यादा है। मगर यूनाइटेड किंगडम, न्यूज़ीलैंड, फ़िनलैंड, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तुलना में जो अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं उनसे भारत बहुत पीछे है। इसी तरह, जापान, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी कुल जीडीपी का कम से कम 10 प्रतिशत खर्च करते हैं। वहीं अमेरिका अपनी जीडीपी का करीब 16 फीसदी स्वास्थ्य पर खर्च करता है। बजट में स्वास्थ्य आवंटन में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और प्रौद्योगिकी में सुधार पर जोर देना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

निर्वाचन आयोग के हठ

एसआईआर की जरूरत एवं उसके औचित्य पर कोई सवाल नहीं है। मुद्दा वो माहौल है, जिसमें इसे आगे कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के हठ के कारण सवाल और संदेहों से भरा ये माहौल आगे भी जारी रहने वाला है।

निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इसके पहले विपक्ष की आपत्ति और शिकायतों पर गौर करने की जरूरत उसने नहीं समझी। बेशक, बिहार की तुलना में अब अपनाई जा रही प्रक्रिया में कुछ सुधार किए गए हैं। बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए, 12 राज्यों की एसआईआर प्रक्रिया में उन्हें शामिल कर लिया गया है। लेकिन उल्लेखनीय है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है। उधर कर्नाटक में संगठित रूप से मतदाताओं के नाम हटाने के मामले की चल रही एसआईटी जांच से संबंधित प्रक्रिया भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है।

इन सबसे अप्रभावित रहते हुए एसआईआर को आगे बढ़ाने का निर्णय विपक्षी दलों में नए संदेह को जन्म दे चुका है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, सीपीएम आदि की प्रतिक्रियाएं इसकी मिसाल हैं। समस्या निर्वाचन आयोग का जाहिर होने वाला नजरिया है, जिससे नहीं लगता कि वह विपक्ष को चुनाव प्रक्रिया में समान हितधारक मानता हो! विपक्ष के एतराज को जैसे वह ठेंगे पर रखता है। विपक्ष की शिकायतों पर निष्पक्ष रेफरी की भूमिका अपनाने के बजाय अतीत में वह एक पक्ष बनता नजर आया है। उसके इस रुख का गहरा साया भारतीय चुनावों पर पहले ही पड़ चुका है।

इसकी मिसाल बिहार है, जहां विधानसभा चुनाव में भाग लेने के बावजूद विपक्षी नेता नई मतदाता सूची को लेकर संदेह जताते और चुनाव प्रक्रिया के स्वच्छ रहने को लेकर आशंका जताते सुने गए हैं। निर्वाचन आयोग चाहता तो इससे सबक लेते हुए ताजा घोषणा से पहले 12 राज्यों में हित रखने वाले तमाम दलों के साथ संवाद कायम कर सकता था। उससे भरोसे का माहौल बनता, जिससे ये प्रक्रिया बिना विवादास्पद हुए आगे बढ़ती। गौरतलब है कि एसआईआर की जरूरत एवं उसके औचित्य पर कोई सवाल नहीं है। मुद्दा उसे कराने का तरीका और वो माहौल है, जिसमें इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।

पहले चरण में जनता दे संदेश : विकास वहीं, जहां सुशासन सही

आरती कुमारी

भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता की इच्छा ही सर्वोपरि मानी जाती है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके चुनाव कितने निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक आधारों पर संचालित होते हैं। चुनाव केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही की कसौटी भी है। बिहार, जो भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अहम स्थान रखता है, यहां के चुनाव हमेशा से देशभर में चर्चा का विषय रहे हैं।

ईमानदारी, नैतिकता और सुशासन—ये तीनों शब्द न केवल एक आदर्श शासन प्रणाली के स्तंभ हैं, बल्कि बिहार की राजनीति में परिवर्तन के प्रतीक भी बन चुके हैं। बिहार चुनाव के संदर्भ में इन तीनों मूल्यों की भूमिका, चुनौतियों और संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालता है।

बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि

बिहार की राजनीति ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत तक अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। जयप्रकाश नारायण के 'संपूर्ण क्रांति आंदोलन' से लेकर लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय के दौर और नीतीश कुमार के सुशासन के युग तक, बिहार की राजनीति ने हमेशा नई दिशा देने का प्रयास किया है।

हालांकि, इन दशकों में जातिगत समीकरण, धनबल, बाहुबल और भ्रष्टाचार ने राजनीति की पवित्रता को कई बार प्रभावित किया। यही कारण है कि आज भी जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है।क्या चुनाव में ईमानदारी, नैतिकता और सुशासन को प्राथमिकता दी जा रही है?

ईमानदारी का प्रश्न

ईमानदारी किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है। यदि जनप्रतिनिधि और प्रशासन ईमानदार हों, तो विकास स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन बिहार की राजनीति में पूर्व की सरकारों में लंबे समय तक यह मूल्य हाशिए पर रहा। कई चुनावों में उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज रहे, और धनबल के सहारे चुनाव जीतने की परंपरा ने ईमानदारी की जड़ों को कमजोर किया। हाल के वर्षों में हालांकि एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। युवा मतदाताओं में यह जागरूकता बढ़ी है कि ईमानदार उम्मीदवारों को वोट देना ही सच्चा लोकतंत्र है। सोशल मीडिया, जनमंचों और नागरिक संगठनों ने पारदर्शिता की मांग को बल दिया है। दल अब अपने घोषणा पत्रों में अधिक व्यावहारिक और तथ्य आधारित वादे कर रहे हैं। ईमानदारी को चुनावी मुद्दा बनाने में युवाओं और सिविल सोसाइटी की भूमिका अहम रही है।इन प्रयासों के बावजूद यह कहना कठिन है कि ईमानदारी पूरी तरह से बिहार की राजनीति में स्थापित हो चुकी है। लेकिन इसकी मांग अब जनता के एजेंडे का हिस्सा बन चुकी है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है।राजनीतिक नैतिकता का अर्थ है कि सत्ता प्राप्ति के लिए नैतिक सीमाओं का पालन करना, सार्वजनिक जीवन में आचरण की शुचिता बनाए रखना, और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना।बिहार चुनावों में नैतिकता की स्थिति मिश्रित रही है। एक ओर नेताओं ने नैतिकता की बातें कीं, तो दूसरी ओर राजनीतिक गठबंधन और दल-बदल ने उसकी परीक्षा ली है।बिहार में कई बार देखा गया है कि व्यक्तिगत लाभ या सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक नैतिकता से समझौता किया गया। जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर वोट माँगना आज भी नैतिकता के विपरीत माना जाता है, फिर भी यह एक आम चुनावी रणनीति बन चुकी है। चुनावों के समय जनता से किए गए वादों को पूरा न करना नैतिक पतन का द्योतक है।फिर भी, नैतिकता का पुनर्जागरण धीरे-धीरे हो रहा है। कई युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।इसके अलावा, मीडिया और नागरिक संगठनों की निगरानी ने भी राजनीतिक दलों को कुछ हद तक जवाबदेह बनाया है।

सुशासन की अवधारणा

"सुशासन" शब्द बिहार की राजनीति में विशेष रूप से चर्चित रहा है। जब 2005 में नीतीश कुमार ने 'सुशासन बाबू' की छवि के साथ सरकार बनाई, तो यह नारा केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि एक नई शासन दृष्टि बन गया।सुशासन का अर्थ है—पारदर्शी, जवाबदेह, न्यायसंगत और जनहितकारी प्रशासन। बिहार ने इस दिशा में कई सुधार देखे, जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण में सुधार।

सुशासन के प्रमुख स्तम्भ में

कानून व्यवस्था में सुधार,पहले जहाँ अपराध राजनीति से गहराई से जुड़ा था, अब कई सुधारात्मक कदम उठाए गए। ग्रामीण सड़कों, पुलों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण से जनता को राहत मिली।पंचायती चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। 'साइकिल योजना' और 'पोशाक योजना' जैसे प्रयासों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया।महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाने का कार्य सतारूढ़ सरकार ने किया। लेकिन बिहार में यह चेतना अवश्य आई है कि शासन केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम होना चाहिए।चुनाव में तीनों मूल्यों का परस्पर संबंध है।ईमानदारी, नैतिकता और सुशासन — ये तीनों एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं।

ईमानदारी के बिना नैतिकता टिक नहीं सकती, और नैतिकता के बिना सुशासन असंभव है। यदि उम्मीदवार ईमानदार और नैतिक होंगे, तो शासन अपने आप पारदर्शी होगा। इसी प्रकार, यदि शासन ईमानदार और जवाबदेह होगा, तो जनता का विश्वास राजनीति में बढ़ेगा। बिहार के चुनावों में यह त्रिकोण अब धीरे-धीरे मजबूत हो गया । जनता अब केवल वादों पर नहीं, बल्कि उम्मीदवारों के चरित्र और नीतियों पर ध्यान दे रही है। राजनीति में नए चेहरे, युवा ऊर्जा, और सामाजिक जागरूकता इस मजबूत शासन की नींव है। यद्यपि बिहार ने कई सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, फिर भी कुछ प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।धनबल और बाहुबल का हिस्सा न बनने दिया जाए। कई बार अपराध और राजनीति के गठजोड़ ने ईमानदारी को कमजोर किया।युवाओं को बेहतर अवसर मिलने से राजनीति में आदर्शवाद का विकास हुआ है। चुनावी घोषणाएँ अक्सर जमीनी हकीकत से दूर होती हैं। राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवार चयन में ईमानदारी और योग्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए।शिक्षा प्रणाली में नागरिक नैतिकता और राजनीतिक जागरूकता को शामिल किया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग को अपराधियों और धनबलियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मीडिया को निष्पक्ष रहकर जनमत निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि मतदाता सजग, जागरूक और नैतिकता के पक्षधर होंगे, तो राजनीतिक दल स्वतः सुधार करने को बाध्य होंगे।बिहार की जनता में यह जागरूकता तेजी से बढ़ी है। आज युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार, अन्याय और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ग्रामीण स्तर पर भी पंचायत चुनावों में पारदर्शिता की माँग बढ़ी है, जो लोकतंत्र के परिपक्व होने का संकेत है।बिहार के चुनाव केवल राजनीतिक घटनाएँ नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के प्रतीक हैं।ईमानदारी, नैतिकता और सुशासन जैसे मूल्य अब केवल आदर्श नहीं, बल्कि जनआकांक्षा बन चुके हैं।

यह परिवर्तन धीमा जरूर है, पर स्थायी दिशा में अग्रसर है। यदि राजनीतिक दल और जनता दोनों मिलकर इन मूल्यों को व्यवहार में उतारें, तो बिहार न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।

जब राजनीति ईमानदारी से प्रेरित होगी, शासन नैतिकता से संचालित होगा, और जनता सुशासन की प्रहरी बनेगी — तभी बिहार अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगा। पहले चरण के मतदान में आखिरी दिन महिलाओ के लिए बड़ी घोषणा करने वाले लालू के सुपुत्र तेजस्वी यादव पर जनता भरोसा कर पाएगी ?क्योंकि 2005 के पहले लालू के जंगलराज और बिहार में घास चारा घोटाला और केंद्र में मंत्री रहते लालू ने नौकरी के बदले निर्दोष लोगों की जमीन अपने परिवार के नाम करवा दी थी।अब तक के उदाहरण है कि राहुल ने चुनाव के वक्त चुनाव जीतने पर नकद राशि खाते में डालने की घोषणा की थी।लेकिन कांग्रेस को हार ही मिली।उसी तरह बिहार चुनाव में तेजस्वी ने घोषणा तो की है-लेकिन वोटरों के हाथ मे है।जीविका दीदियों को एकमुश्त 30 हजार रुपए देने का वादा लोगो पर असर नही करेगा।अब तक के उदहारण बताते है कि सत्ता में रहते हुए जो रकम केश दी जाती है,उस पर ही महिला वोटरों ने ज्यादा भरोसा किया है।मध्यप्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत महिलाओ के खाते में सरकार ने 1250 रूपए डाल रही थी।कांग्रेस ने 2023 में दो हजार देने की घोषणा की गई।2024 में महाराष्ट्र के चुनाव के पहले लाडली बहिन योजना में हर महीने 1500 दे रही थी।अघाड़ी ने तीन हजार रुपए देने का वादा किया।झारखंड में झामुमो सरकार ने प्रतिमाह एक हजार देने का वादा किया।भाजपा ने 21 सौ देने का वादा किया।लेकिन मतदाताओ को जिस सरकार ने पैसे दिए,उस पर भरोसा किया।तेजस्वी ने 30 हजार की घोषणा, सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त,धान पर 300 और गेहूं पर 400 बोनस आदि घोषणा पर जनता भरोसा कम ही करती है।क्योंकि महागठबंधन की कथनी और करनी में समानता नही दिखाई दे रही है।

रूस ने किया समुद्र की गोद में परमाणु सबमर्सिबल ड्रोन का सफल परीक्षण - 'पोसाइडन'

जितेन्द्र कुमार सिन्हा

दुनिया की सैन्य ताकतें अक्सर आसमान और धरती पर देखी जाती हैं। लेकिन जल-गहराइयों में चल रही दौड़ कहीं ज्यादा खामोश, रहस्यमय और डरावनी है। समुद्र हमेशा से रणनीतिक खेल का सबसे गूढ़ मैदान रहा है, जहां पनडुब्बियों की फुसफुसाहट भी भू-राजनीति का भविष्य बदल सकती है। इसी समुद्री शतरंज में रूस ने एक ऐसा मोहरा चला है, जिसने पूरे वैश्विक रक्षा तंत्र के दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह घोषणा की है कि रूस ने 'पोसाइडन' नामक परमाणु ऊर्जा संचालित मानव-रहित सबमर्सिबल ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है। यह ड्रोन असीमित दूरी तक मार करने की क्षमता रखता है और दावा है कि यह दुनिया की सबसे घातक पारंपरिक या परमाणु मिसाइलों से भी आगे की शक्ति रखता है।

यह महज एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि महासागरों की दुनिया में शक्ति संतुलन बदलने वाली घटना है। एक शांत लहर, पर पीछे भूचाल की संभावना।

'पोसाइडन' नाम ग्रीक देवता से लिया गया है। समुद्रों के देवता, जिनके हाथों में शक्ति, विनाश और रहस्यमय सागर का नियंत्रण था। रूस ने इस नाम को चुनकर दुनिया को संकेत दिया है कि यह हथियार भी वही शक्ति समेटे है।

रूस के कहने के अनुसार, यह ड्रोन एक रणनीतिक पनडुब्बी से छोड़ा गया और यह एक ऐसे रिएक्टर से चलता है जो पारंपरिक पनडुब्बी रिएक्टर से 100 गुना छोटा है। यह किसी भी समुद्री देश के तट को गुप्त रूप से निशाना बना सकता है। असीमित दूरी का दावा इसे लगभग न रोके जाने वाला हथियार बनाता है। यह मानव-रहित है, यानि जोखिम कम और रणनीतिक लाभ अधिक। इसे ट्रैक करना बेहद कठिन होगा, क्योंकि यह समुद्र की गहराइयों में बिना सतह पर आए यात्रा कर सकता है।

दुनिया परमाणु शक्ति की चर्चा करते ही हवा की तरफ देखती है,

क्योंकि कल्पना में मिसाइलें ही उड़ती हैं। लेकिन अब युद्ध का नया अध्याय समुद्र में लिखा जा रहा है। परमाणु मिसाइलों की रेंज सीमित होती है, लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म स्थिर होता है। लेकिन पोसाइडन जैसे सिस्टम समुद्र को अनंत लॉन्च पैड में बदल देता है।

भविष्य की युद्धक रणनीति अब सिर्फ "कौन पहले हमला करेगा" नहीं है, बल्कि यह भी होगी कि कौन विरोधी की पहुंच तक चुपचाप पहुँच सकता है और कब। पोसाइडन जैसी तकनीकें AI आधारित गाइडेंस, समुद्री छिपाव क्षमता, लम्बा समय पानी में रहने की क्षमता, रेडियेशन मुक्त ऑपरेशन तंत्र, इन सभी को जोड़कर एक नई चुनौती तैयार करती हैं।

जब अमेरिका ने 'स्टार वार्स' कार्यक्रम बनाया था, रूस ने संतुलन बदलने के लिए Sarmat जैसी मिसाइलें बनाई। अब भी तस्वीर कुछ वैसी ही है। पोसाइडन पश्चिम के लिए इसलिए खतरनाक है कि यह पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अप्रभावी कर देता है। यह "अदृश्य हमला" करने की क्षमता रखता है। यह समुद्र आधारित निरोधक शक्ति को चरम रूप देता है। अमेरिका की तटीय सुरक्षा अवधारणा को चुनौती देता है।

अमेरिका और नाटो पहले ही इसकी निगरानी और जवाब योजना बना रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह हथियार Mutually Assured Destruction की संकल्पना का जलीय संस्करण है, जो जवाबी हमले की गारंटी देता है।

पोसाइडन सिर्फ ड्रोन नहीं है, पानी के अंदर तैरती हुई रणनीतिक चेतावनी है। आर्थिक प्रतिबंधों के बीच तकनीकी श्रेष्ठता का संदेश है। नाटो के समुद्री प्रभुत्व को चुनौती है। आर्कटिक क्षेत्र में बढ़त है। समुद्री डिटरेंस सिस्टम में बढ़त है।

भारत, समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। हिंद महासागर रणनीतिक आंगन है। पोसाइडन जैसी तकनीकें भारत को भी सोचने पर मजबूर करेंगी। भविष्य की पनडुब्बी तकनीक का अपग्रेड करना होगा। समुद्री AI और स्वायत्त ड्रोन विकास करना होगा। परमाणु निरोधक रणनीति का विस्तार करना होगा। समुद्री निगरानी और सुरक्षा तंत्र मजबूत करना होगा। भारत पहले ही Arihant Nuclear Submarine कार्यक्रम में आगे बढ़ रहा है। ऐसे हथियार संकेत देता है कि भविष्य में अधिक उन्नत समुद्री ड्रोन भारत की रक्षा नीति का हिस्सा बन सकता है।

परमाणु तकनीक का समुद्र में प्रवेश पर्यावरणीय चिंताएँ उठाता है। दुर्घटनाओं की संभावना। समुद्री विकिरण प्रदूषण। समुद्री जीवों पर प्रभाव और वैश्विक समुद्री कानूनों की चुनौतियाँ। समुद्र सिर्फ रणनीतिक क्षेत्र नहीं है, पृथ्वी की सांस भी है। युद्ध की गूंज उसमें भी सुनाई पड़ती है। लगता है कि देश एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुका है, जहां समुद्र में स्वायत्त हथियारों की भीड़ होगी। AI आधारित पनडुब्बियाँ, परमाणु ऊर्जा वाले समुद्री ड्रोन, हाइपरसोनिक टॉरपीडो और अंडरसी निगरानी नेटवर्क। समुद्री युद्ध अब "स्टील एंड शैडो" नहीं, बल्कि "कोड एंड करंट" का खेल होगा।

रूस का पोसाइडन परीक्षण इतिहास में दर्ज हो गया है। यह सिर्फ तकनीकी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि दुनिया को संदेश है समुद्र अब सिर्फ व्यापार और जहाजों का क्षेत्र नहीं है, बल्कि सामरिक शक्ति का नया ध्रुव है।

आज का राशिफल

मेष राशिः आज पारिवारिक जीवन में चल रहे कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें। भविष्य के लिये बनायी योजनाओं पर भी आज कुछ सोच-विचार कर सकते हैं। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आज आपके स्वभाव में संयम और धीरज बना रहेगा, जिसके कारण आप अपनी सभी समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ लेंगे।

वृष राशिः आज आपका मन घर और ऑफिस की दुनिया से बाहर निकल कर प्रकृति का आनंद लेगा। पुरानी बहुमूल्य चीज़ों के मोलभाव पर आज आपको लाभ होगा। अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आज आपका आत्मबल आपके लिये सफलता की कुंजी साबित होगी।

मिथुन राशिः आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपका मन नये काम करने में लग सकता है। बिजनेस में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आज अपने कामकाज को पूरी सावधानी से करें, साथ ही अपने काम में दूसरों की मदद भी लें। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। ।

कर्क राशिः आज का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। आज अपनी सोच को सकारात्मक रखें, नकारात्मक चीज़ों को अपने ऊपर हावी न होने दें। आज आप जॉब स्विच करने का मन बना सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे ऑप्शन देखकर ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए।

सिंह राशिः आज का दिन नॉर्मल रहेगा। आज जिससे भी मिलेंगे वह व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। बिजनेस में परिवार से कुछ सहयोग मिल सकता है। वर्क प्लेस पर अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें, आपके लिये अच्छा होगा। अपने करियर को लेकर मन में दुविधा होगी, लेकिन जल्द ही वह सॉल्व भी हो जायेगी।

कन्या राशिः आज का दिन व्यापारिक दृष्टि से फायदेमंद रहेगा। निवेश से जुड़े कुछ बेहतर मौके मिल सकते हैं। आज नए विचार आपके सामने आते रहेंगे। आज योजना बनाने और फैसला लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आप पूरा ध्यान अपनी जिमेदारियों पर बनाये रखेंगे। हर काम जोश से पूरा करने की कोशिश करेंगे।

तुला राशिः आज आपके मन में नए – नए विचार आएंगे। आज आप कुछ ज्यादा ही जोश में रहेंगे। आपके बनाए प्लान में नया बदलाव हो सकता है। आप किसी क्राफ्ट एग्जीबिशन में मित्रों के साथ जा सकते हैं। आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेंगे।

वृश्चिक राशिः आज प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन अच्छा रहेगा। बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। धन लाभ का योग बन रहे है। समाज कल्याण की तरफ भी आपका रुझान होगा। शत्रु आपको हराने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके सामने अधिक देर तक ठहर नहीं पायेंगे।

धनु राशिः आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। राजनीतिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके काम सफल होंगे। आज पड़ोसियों के बीच आपका मान – सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। साइंस से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है।

मकर राशिः आज कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आपकी सैलरी में बढ़ोत्तरी भी हो सकती है, जिससे आपका आज का दिन अच्छा रहेगा। अपने सीनियर्स के प्रति अच्छा व्यवहार बनाए रखें।

कुंभ राशिः आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देंगे। कार्यक्षेत्र में उम्मीद के अनुसार कामयाबी हासिल होगी। आज आपकी मुलाकात अपने बेस्ट फ्रेंड से हो सकती है। पारिवारिक मामलों में किसी बात को लेकर जीवनसाथी से वार्तालाप हो सकती है। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए सही समय है। सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा है।

मीन राशिः आज का दिन आपके लिए उत्साहपूर्वक रहेगा। आज कार्यों में तरक्की बनी रहेगी। साथ ही आप मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं। आज मित्रों की सहायता से आपको आय के अवसर मिलेंगे, जिनसे आप लाभ कमा कर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। दोस्तों के साथ बाहर मौसम का लुफ्त उठा सकते हैं। आज नए लोगों के साथ संपर्क बनेंगे। सरकारी ऑफिस में काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं। आज आप नया काम शुरु करते समय माता-पिता के पैर छूएं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

बिहार की सियासत की पहली परीक्षा, 121 सीटों पर जनता तय करेगी नीतीश और तेजस्वी की किस्मत

अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

बिहार में राजनीतिक तापमान अपने चरम पर है। 6 नवंबर को राज्य की सियासत की दिशा तय करने वाला पहला चरण होने जा रहा है, जिसमें 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यह सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का पहला पड़ाव नहीं, बल्कि सत्ता की कुर्सी की नींव रखे जाने वाला निर्णायक मोड़ है। 3 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आंकड़ों से लेकर उम्मीदवारों की सूची तक, हर तथ्य इस बात की गवाही दे रहा है कि इस बार की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा कड़ी, रोचक और निर्णायक है।बिहार के पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन और भोजपुर बेल्ट के वे इलाके शामिल हैं जहां राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों और स्थानीय प्रभावशाली चेहरों पर टिकी रही है। इस बार भी स्थिति कुछ अलग नहीं। इन इलाकों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, तेजस्वी यादव की आरजेडी, भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीधे-सीधे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। कुल 1314 उम्मीदवारों में से 122 महिलाएं भी मैदान में हैं, जो बिहार की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती सक्रियता को दर्शाता है।

पहले चरण में मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा है, लेकिन दिलचस्प यह है कि इस बार दोनों गठबंधनों के भीतर भी अंदरूनी जंग जारी है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी 72 सीटों पर, कांग्रेस 24 पर और सीपीआई माले 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं सीपीआई और वीआईपी छह-छह सीटों पर, सीपीएम तीन पर और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी दो सीटों पर मैदान में है। एनडीए में जेडीयू 57, भाजपा 48, एलजेपी (रामविलास) 13, आरएलएम 2 और हम (जीतनराम मांझी की पार्टी) एक सीट पर किस्मत आजमा रही है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जन सुराज पार्टी ने 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं।यह आंकड़े भले चुनावी गणित की एक झलक भर हों, लेकिन असल कहानी उम्मीदवारों की प्रोफाइल और इलाकाई समीकरणों में छिपी है। पहले चरण में करीब 32 प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार, हर तीसरा उम्मीदवार किसी न किसी मुकदमे में आरोपी है। इनमें से 20 प्रतिशत उम्मीदवार गंभीर धाराओं में केस झेल रहे हैं। यही बिहार की सियासत की सच्चाई है, जहां अपराध, प्रभाव और राजनीतिक पूंजी एक-दूसरे के पूरक बन चुके हैं।

पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2020 में इन 121 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर रही थी। महागठबंधन ने 61 सीटें जीती थीं जबकि एनडीए ने 59 सीटें। उस वक्त चिराग पासवान की एलजेपी अकेले मैदान में थी और सिर्फ एक सीट जीत सकी थी। आरजेडी ने उस चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 सीटें जीती थीं, भाजपा को 32, जेडीयू को 23, कांग्रेस को 8, माले को 7, वीआईपी को 4 और सीपीआई व सीपीएम को दो-दो सीटें मिली थीं। यही कारण है कि इस बार आरजेडी पर अपनी बढ़त बनाए रखने का दबाव है, जबकि जेडीयू और भाजपा के सामने खोया जनाधार वापस लाने की चुनौती।नीतीश कुमार के लिए यह पहला चरण किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं। जेडीयू जिन 57 सीटों पर लड़ रही है, उनमें से 36 पर आरजेडी से, 13 पर कांग्रेस से और सात पर सीपीआई माले से सीधा मुकाबला है। इसके अलावा दो सीटों पर वीआईपी से टक्कर है। यही कारण है कि नीतीश की राजनीति की साख इसी फेज पर टिकी मानी जा रही है। 2020 में जेडीयू के जिन 43 विधायकों ने जीत दर्ज की थी, उनमें से 23 पहले चरण की सीटों से आए थे। अगर इस बार वही सीटें डगमगाईं, तो नीतीश की मुख्यमंत्री कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। दो दशक से सत्ता की धुरी बने नीतीश के लिए यह चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है।

दूसरी तरफ, तेजस्वी यादव के लिए यह फेज सत्ता की राह का पहला पड़ाव है। पिछली बार उन्होंने भोजपुर और सारण बेल्ट में आरजेडी का परचम फहराया था और इस बार उनका लक्ष्य उन इलाकों में बढ़त बरकरार रखते हुए नई सीटों पर कब्जा करना है। तेजस्वी खुद राघोपुर से चुनाव मैदान में हैं, जो उनकी पारिवारिक परंपरा की सीट रही है। यहां जीत दर्ज करना तो उनके लिए सहज है, लेकिन चुनौती यह है कि सहयोगी दलों कांग्रेस और लेफ्ट के उम्मीदवारों को भी मजबूत प्रदर्शन दिलाया जाए। पिछली बार सहयोगी दलों के कमजोर प्रदर्शन के कारण ही तेजस्वी बहुमत से पीछे रह गए थे। इस बार उनका फोकस पूरे गठबंधन को एकजुट रखकर जीत की राह बनाना है।पहले चरण में नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। इनमें जेडीयू के 5 और भाजपा के 11 मंत्री शामिल हैं। भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सीवान से, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से, और दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा पटना के बांकीपुर से नितिन नवीन, दरभंगा के जाले से जीवेश मिश्रा, साहेबगंज से पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, अमनौर से आईटी मंत्री कृष्ण मंटू और बिहारशरीफ से पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार जैसे बड़े चेहरे भी मैदान में हैं। जेडीयू के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी सरायरंजन से, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा से, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी बहादुरपुर से और सूचना मंत्री महेश्वर हजारी कल्याणपुर से मैदान में हैं। इनके लिए यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक भविष्य का निर्णायक मोड़ है।

बिहार की राजनीति का चरित्र हमेशा से गठबंधनों और समीकरणों पर टिका रहा है। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। भाजपा अब जेडीयू पर पूरी तरह निर्भर नहीं दिखना चाहती। नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की सुगबुगाहट भी है, और भाजपा इसी लहर को अपने पक्ष में भुनाने में लगी है। वहीं जन सुराज पार्टी जैसे नए संगठन भी जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश में हैं। प्रशांत किशोर की यह पार्टी 119 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर सियासी हलचल बढ़ा रही है। हालांकि, इनका असर कितना होगा, यह नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि वोटों का बिखराव इस बार निर्णायक असर डालेगा।बिहार की जनता हर बार की तरह इस बार भी जातीय समीकरणों और स्थानीय मुद्दों से प्रभावित दिख रही है। बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और कानून-व्यवस्था चुनावी विमर्श के केंद्र में हैं, लेकिन विकास और नेतृत्व की तुलना में भावनात्मक समीकरण ज्यादा असर डालते दिख रहे हैं।

तेजस्वी जहां युवाओं को रोजगार और परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार अपनी सुशासन और विकास की छवि को दोहराने में लगे हैं। 6 नवंबर का मतदान सिर्फ 121 सीटों का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह तय करेगा कि बिहार की राजनीति आगे किस दिशा में बढ़ेगी। अगर पहले चरण में आरजेडी और उसके सहयोगी बढ़त बनाते हैं, तो तेजस्वी का रास्ता आसान होगा। लेकिन अगर नीतीश और भाजपा ने संतुलन बनाए रखा, तो बाकी चरणों में मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा।पहले चरण का चुनाव बिहार के भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए। 20 साल से बिहार की राजनीति जिन दो ध्रुवों पर टिकी रही है, वही अब फिर से आमने-सामने हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार दोनों के पास खोने को भी बहुत कुछ है। नीतीश के लिए सत्ता का निरंतरता दांव पर है और तेजस्वी के लिए भविष्य की राजनीति का स्वप्न। यह चरण तय करेगा कि जनता किसे अगले पांच साल की बागडोर सौंपना चाहती है।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

नारी समानता की नई राह दिखाने वाले फैसले

मद्रास हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट ने विवाह नामक संस्था में महिलाओं के अधिकारों को अगले चरण में ले जाने वाले अहम फैसले दिए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि पत्नियों को आराम, सुरक्षा और सम्मान देना वैवाहिक बंधन का अहम दायित्व है। यह टिप्पणी नारी समानता और सम्मान के हक को नया आयाम देने वाली है। एक तरह से वैवाहिक संबंधों में पुरुषप्रधान की छाया से निकलने की अदालत की नसीहत ने साफ किया है कि पुरुषों के लिए पत्नी को सिर्फ रिश्ता निभाने वाली समझने की मानसिकता से मुक्त होना होगा। अन्य फैसले में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरा विवाह पंजीकृत कराने वाले मुस्लिम पुरुष को भी कानूनी हक होने के बावजूद पहली पत्नी का पक्ष सुनना होगा। महिला की गरिमा को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में यह भी अहम फैसला है।

अदालतों के इन अलग-अलग फैसलों को इस संकेत के रूप में भी समझना होगा कि विवाह जैसी संस्था सिर्फ सामाजिक बंधन ही नहीं, बल्कि समानता और परस्पर सम्मान की साझेदारी है। इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट ने पत्नी का आराम, सुरक्षा और सम्मान पति का वैवाहिक दायित्व मानने की गहरी बात कही है। यह गहरी इसलिए भी है क्योंकि हमारे समाज में आज भी बहुत से घरों में विवाह का अर्थ जिम्मेदारी से ज्यादा अधिकार माना जाता है। अदालत का यह कहना कि विवाह में समानता और सम्मान ही टिकाऊ रिश्ते की बुनियाद हैं, समाज के सोचने के तरीके में बदलाव की उम्मीद जगाता है। दूसरे विवाह के इच्छुक मुस्लिम पति को पहली पत्नी का पक्ष सुनने के निर्देश भी सोच में ऐसे ही बदलाव की राह खोलने वाला है। यह सब जानते हैं कि विशेष कानूनों के नाम पर कई मामलों में महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों को सीमित किया गया है। अब देश की अदालतें यह कह रही हैं कि हर धर्म, हर परंपरा से ऊपर महिला की गरिमा है तो यह साफ है कि महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इन न्यायिक निर्णयों से यह उम्मीद जगी है कि समाज की मानसिकता में बदलाव की लहर और तेज होगी। अब परिवारों और समाज को भी यह समझना होगा कि समानता किसी उपहार की तरह नहीं, बल्कि प्रत्येक स्त्री का मौलिक अधिकार है।

जरूरत इस बात की है कि ऐसे फैसलों को कागजों तक सीमित न रखा जाए। प्रशासन से लेकर पंचायत स्तर तक यह संदेश पहुंचे कि विवाह दो आत्माओं का सम्मानपूर्ण गठबंधन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम महिला अधिकारों के मुद्दे पर तेजी से आगे बढ़ रहे लेकिन इस दिशा में कई स्तर पर और प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही विवाह कानून में समान अधिकार के लिए अधिक स्पष्टता लानी होगी ताकि धर्म या परंपरा के नाम पर किसी भी महिला के साथ अन्याय न हो। इन सबके साथ हमें यह भी समझना जरूरी है कि कानून सिर्फ दिशा दिखा सकता है, रास्ता समाज को ही तय करना होगा।

कर्पूर चन्द्र कुलिश
जन्म शताब्दी वर्ष
भाग -33

भावुकता में मतदाता का प्रभाव कम हो जाता है। एक प्रवाह में आम लोग बह जाते हैं और बाद में हाथ मलते दिखाई देते हैं

मतदाता प्रचण्ड प्रहार करे लोकतंत्र की विकृतियों पर

लोकतांत्रिक शासन की मौलिक आवश्यकता है आम सहमति

भारतीय लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसकी जड़ें पाताल से भी गहरी है। इन जड़ों को गहरी करने में सबसे अहम योगदान रहा है इस देश के मतदाता का जो हर चुनावों के मौकों पर किसी धारा के बहाव में आने के बजाय नीर-क्षीर विवेक में विश्वास करता है। सत्तर व अस्सी के दशक के चुनावों में मतदान के पूर्व और चुनाव नतीजे आने के बाद कुलिश जी ने मतदाता की ताकत का जिक्र अपने आलेखों में किया। बिहार विधानसभा व राज्यों में उपचुनावों के संदर्भ में प्रासंगिक उनके आलेखों के प्रमुख अंशः

देश के सामने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को निखारना। पिछले एक दशक से हमारी शासन व्यवस्था में जो विकृति बढ़ती देखी जा रही है, वह यह है कि शासन अपने दैनिक कार्यकलाप में आम सहमति के बजाय पुलिस और फौज पर निर्भर करता आ रहा है और देश के राजनीतिक जीवन में सभी प्रकार के अपराधियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। परिपाटियां और संस्थाएं छिन्न-भिन्न होती जा रही हैं। असहमति को सहन नहीं किया जा रहा बल्कि असहमति को पशुबल, प्रलोभन या छल-छद्म से दबाया जा रहा है। व्यक्तिपूजा का भाव बढ़ रहा है। लोकतांत्रिक शासन की मौलिक आवश्यकता है आम सहमति, विचार विमर्श, स्वस्थ परिपाटियां और साधनों की स्वच्छता। ये उदात्तता तिरोहित होती जा रही है। मतदाता के सामने आज उपयुक्त अवसर है कि वह इन पहलुओं पर विचार करे। उसका प्रचण्ड प्रहार उन विकृतियों पर होना चाहिए जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में घर कर गई है। नेतृत्व के लिए सुदृढ़- सुचारु व्यवस्था सर्वोपरि है। यदि कोई एक व्यक्ति नेतृत्व के लिए उपयुक्त या उपलब्ध नहीं है, तो संयुक्त नेतृत्व की स्थापना की जा सकती है। मिलीजुली सरकार की स्थापना को न तो सैद्धांतिक आधार पर और न ही व्यावहारिक आधार पर नकारा जाना चाहिए। यह देश तो वैसे ही विविधताओं से भरा हुआ है। यही नहीं बल्कि विविधता इस देश की एक विशेषता है। इस देश में एक ही नेतृत्व परम्परा का पक्ष लेना कदापि उचित नहीं होगा बल्कि परिवर्तन का क्रम चलाना ही होगा।

(24 दिसम्बर 1984 को 'निर्णय की घड़ी' अग्रलेख के अंश)

यह देखा जा रहा, सबसे कम बुराइयां किसमें

एक तरह से यह दौर अच्छा है कि चुनाव में किसी लहर या भावुकता का दौर नहीं है। अत्यधिक भावुकता में सोच विचार या विवेक को अवसर नहीं मिलता। उम्मीदवार, मतदाताओं पर हावी रहता है। राजनीतिक दल मतदाता को उचित सम्मान नहीं देते। बढ़चढ़ कर बातें करते हैं। भावुकता में मतदाता का प्रभाव कम हो जाता है। एक प्रवाह में आम लोग बह जाते हैं और बाद में हाथ मलते दिखाई देते हैं। चुनाव प्रचार में किसी तरह की लहर न हो तो मतदाता को सोच-विचार का अवसर भी मिला है। वह प्रत्येक दल के उम्मीदवारों, कार्यक्रमों और पिछले अनुभवों की तुलनात्मक समीक्षा करता है। इन तुलनाओं में कार्यक्रम और विचारधारा का पक्ष अब प्रायः गौण हो गया है तथा उम्मीदवार और संबंधित दल का आचरण प्रधान विषय बन गया है। राजनेताओं और राजनीतिक दलों में अच्छाइयां खोजना अब जनसाधारण ने बंद कर दिया है। बल्कि यह देखा जा रहा है कि सबसे कम बुराइयां किस में हैं। राजनीति अब अनचाही चीज या मजबूरी बन गई हे। राजनेताओं के आचरण के प्रति भी और राजनीतिक दलों की कार्यशैली के कारण मतदाताओं में इतनी ग्लानि भर गई है कि वे सहज ही किसी को विश्वास देने को तैयार नहीं हैं। इन चुनावों में आम जनता यह भी सोचती है कि यदि किसी को वोट दिया भी तो क्या पता वह उस दल में रहेगा भी या नहीं जिसके निशान पर चुनाव लड़ रहा है।

(31 दिसम्बर 1979 के अंक में 'हर उम्मीदवार कठघरे में' शीर्षक आलेख से)

सुबह-साँझ

राजा बणग्या दानक्या,
सुबह-साँझ को ध्यान।
हार्‌या-थाक्या कर रह्या,
दोन्यूँ वक्त गुजार।।

'सात सैंकड़ा' से

लोकतंत्र में गहरी आस्था

पिछले दो चुनावों की भांति ही इन चुनावों में भी परिणामों के बारे में सारे अनुमान विफल हो गए और आकलन का कोई मापदण्ड काम नहीं आया। अलबत्ता यह निरंतरता देखने में आई कि लोकतंत्र में भारतीय मतदाता की गहरी आस्था है। चुनाव का आह्वान होते ही वह अपना मन बनाकर मतदान केन्द्र तक पहुंच जाता है। इसी तरह सात चुनाव शांतिपूर्वक हो चुके हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश को मतदाता की इस परिपक्वता पर गर्व होगा। उसके फैसले को नतमस्तक हो स्वीकार करना होगा। राजनीतिक दलों को नए सिरे से देश की समस्याओं के समाधान में अपने-अपने तरीके से योगदान करना होगा। जरूरी है राजनीतिक दल स्वस्थ राष्ट्रीय सहमति का दृष्टिकोण अपनाएं।

(8 जनवरी 1980 को '1980 का फैसला' शीर्षक अग्रलेख से)

(जारी... कुलिश जी का सृजन संसार पढ़ें आगामी गुरुवार को भी)

आर्थिक स्थिरता: सामाजिक सुरक्षा फंड के नए युग की शुरुआत की जरूरत

आरबीआइ की सिफारिशों से ईपीएफओ के वित्तीय प्रबंधन में सुधार की उम्मीद

डॉ. पी.एस. वोहरा
आर्थिक मामलों के जानकार
@patrika.com

ईपीएफओ के अंतर्गत वर्ष 1952 से प्रोविडेंट फंड की योजना, वर्ष 1976 से बीमा योजना और वर्ष 1995 से पेंशन योजना को जोड़ा गया, ताकि समाज में सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा में किसी भी पक्ष पर कोई कमी न रहे।

इन दिनों भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को उसके वित्तीय संचालन की नीतियों के संबंध में दिए गए कुछ गहन दिशा-निर्देश व सुझाव चर्चा में हैं। इस बात की सुगबुगाहट भी है कि आने वाले समय में आरबीआइ, ईपीएफओ के सभी वित्तीय संचालन की नीतियों का अपने हिसाब से संचालन करना शुरू भी कर सकता है, जो भारतीय वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार आदि में एक नए युग की शुरुआत होगी। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2025 में खुद भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की विभिन्न वित्तीय नीतियों से संबंधित दिशा-निर्देशों के लिए केंद्रीय बैंक को अनुरोध किया था।

इस संबंध में श्रम व रोजगार मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य ईपीएफओ की मौजूदा वित्तीय प्रबंधन की नीतियों का आकलन करना था ताकि विभिन्न प्रकार के जोखिमों को चिह्नित किया जा सके। इसके अलावा श्रम व रोजगार मंत्रालय, ईपीएफओ की विभिन्न लेखांकन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा भी चाहता था तथा भविष्य निधि, पेंशन व बीमा के लिए अलग-अलग वित्तीय निवेश की रणनीति भी। अब आरबीआइ ने इस संदर्भ में विभिन्न दिशा-निर्देशों को प्रस्तुत किया है। गौरतलब है कि ईपीएफओ वर्तमान में किसी तरह के आर्थिक घाटे में नहीं है परंतु मुख्य समस्या यह आ रही है कि ईपीएफओ को सरकारी प्रतिभूतियों से मिलने वाला रिटर्न लगातार कम होता जा रहा है। जबकि उसे लगातार अपने अंशधारकों व सदस्यों को एक आकर्षक और अधिकतम ब्याज दर देनी है, जो कि देश में सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से उसका मुख्य मकसद भी है।

एक रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 वर्षों में सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश से औसतन रिटर्न 6.8 प्रतिशत ही मिला है जबकि ईपीएफओ के ब्याज की औसतन दर 8.34 प्रतिशत रही है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर दी जबकि सरकारी प्रतिभूतियों से उसे मात्र 6.86 प्रतिशत का ही मुनाफा हुआ। दरों का ये अंतर ही ईपीएफओ पर लगातार वित्तीय दबाव बनाता जा रहा है। वर्ष 2015 में यह करीब 6 लाख करोड़ रुपए था, जो कि वर्ष 2024 के अंत तक 24.75 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

आरबीआइ द्वारा प्रस्तुत किए गए दिशा-निर्देशों में मुख्य बिंदुओं के तौर पर चार बातें सामने आई हैं। पहले बिंदु के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रोविडेंट फंड, पेंशन व बीमा तीनों के संबंध में अलग-अलग वित्तीय निवेश की नीतियां बनानी चाहिए न कि मात्र एक नीति से ही तीनों का वित्तीय संचालन किया जाए। दूसरे बिंदु के अंतर्गत ईपीएफओ को अपने द्वारा किए गए वित्तीय निवेश पर होने वाले घाटे को भी अपने लेखांकन में दर्ज करना चाहिए जो कि अब तक उसके द्वारा नहीं किया जाता है। तीसरे बिंदु के अंतर्गत दूरगामी सोच को ध्यान में रखकर आरबीआइ द्वारा ईपीएफओ की नियामक के तौर पर कार्य विधियां और वित्तीय निवेश से संबंधित नीतियों व उनके क्रियान्वयन को अलग-अलग करने की सोच पर काम करना होगा। चौथे बिंदु के अंतर्गत पीएफ को सरकारी प्रतिभूतियों में वित्तीय निवेश को तुलनात्मक रूप से कम करके पूंजी बाजार में इक्विटी के अंतर्गत निवेश को बढ़ाने की सलाह दी गई है ताकि पिछले लंबे अरसे से सरकारी प्रतिभूतियों से कम मिलने वाली आय का जो दबाव बना हुआ है, इक्विटी में निवेश को उसका विकल्प बनाया जा सके। इन सुझावों को अमल में लाने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया गया है।

यह समझना भी आवश्यक है कि ईपीएफओ के अंतर्गत वर्ष 1952 से प्रोविडेंट फंड की योजना, वर्ष 1976 से बीमा योजना और वर्ष 1995 से पेंशन योजना को जोड़ा गया, ताकि समाज में सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा में किसी भी पक्ष पर कोई कमी न रहे। लेकिन वर्तमान में ईपीएफओ से किसी कर्मचारी की मृत्यु पर बीमा से मिलने वाले प्रतिफल की अधिकतम राशि मात्र 6 लाख रुपए ही है, जो कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के लिए बहुत कम आर्थिक सुरक्षा है। अब सोचना यह होगा कि आज के दौर में जहां भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर अपनी बढ़त बना रहा है तो वहां समाज में सामाजिक सुरक्षा के लिए इन मूल्यों में बढ़ोतरी क्यों ना की जाए। ये सब संभव हैं, अगर भविष्य निधि संगठन अपने अंशधारकों के वित्तीय अंशदान को आकर्षक जगह निवश करे।

हंसी के पीछे छिपे भय को उजागर करता इंस्टॉलेशन

बर्लिन की 'नोए नेशनल गैलरी' में फेबियन क्नेख्ट की अनोखी इंस्टॉलेशन 'लाफिंग इज सस्पिशियस' हंसी के पीछे छिपे भय को उजागर करती है। फेस्टिवल ऑफ फ्यूचर नाउज 2025 प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शित इस इंस्टॉलेशन में 600 वर्ग मीटर का विशाल कैमुफ्लाज नेट इस्तेमाल किया गया है, जिसे यूक्रेन के लोगों ने रोजमर्रा के कपड़ों से बनाया है।

बुक इनसाइट रिश्तों की जटिलता की कहानी 'द लैंड इन विंटर'

द लैंड इन विंटर एंड्रयू मिलर का एक संवेदनशील और गहरा उपन्यास है, जो अपने पाठकों को ठंडे और बर्फीले इलाके में जीवन की कठिनाइयों और रिश्तों की जटिलताओं से परिचित कराता है। शानदार लेखन और गहरी भावनाओं का चित्रण उपन्यास का मुख्य आकर्षण है।

कहानी का केंद्र एक छोटे-से गांव में बसी सर्दी से घिरी हुई भूमि है, जो अपने अंदर स्थायी ठंडक और शांति समेटे हुए है। उपन्यास के पात्र इस ठंडे परिवेश में निजी और सामाजिक जटिलताओं से जूझते हैं। लेखन की शैली में नाजुकता है, जो हर पात्र के आंतरिक संघर्ष को स्पष्ट रूप से उकेरती है। मिलर ने न केवल बाहरी परिवेश को, बल्कि पात्रों के भीतर चल रही मानसिक उथल-पुथल को भी बखूबी दर्शाया है। किताब में जीवन के यथार्थवादी पहलुओं को बड़े ही संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पात्रों के व्यक्तिगत संघर्ष, उनके रिश्तों की जटिलताएं और भावनात्मक उतार-चढ़ाव कहानी के मुख्य तत्त्व हैं। किताब के अंदर कई परतें हैं, जो धीरे-धीरे खुलती हैं। इसके संवाद सरल और प्रभावशाली हैं।

प्रसंगवश

शहरों के विस्तार को ध्यान में रखकर सुविधाएं जुटाने को दें प्राथमिकता

न तो चार शहर 'स्मार्ट' बन पाए, न ही लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया

किसी भी विकास योजना की सफलता निर्भर करती है कि उसका क्रियान्वयन ईमानदारी से हो रहा है अथवा नहीं। लेटलतीफी व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाली योजनाएं आमतौर पर लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाती। राजस्थान के चार शहरों को केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल होने पर उम्मीद बंधी थी कि न केवल इन शहरों की तस्वीर बदलेगी, बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी बदलाव आएगा। लेकिन न तो ये शहर ही स्मार्ट बन पाए और न ही लोगों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ पाया।

स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा ऐसे शहर हैं, जो पिछले सालों में बेतरतीब बसावट का रूप ले चुके हैं। सोचा तो यह था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से इन शहरों में गंदगी से निजात मिलेगी, आवागमन सुलभ होगा, पर्यावरण स्वच्छ होगा और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। इनमें एक भी पक्ष ऐसा नहीं, जिसमें चार हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद कोई बड़ा सुधार नजर आ रहा हो। जबकि वर्ष 2015 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के तहत चारों शहरों में लगभग 95 प्रतिशत काम पूरा होने का दावा किया गया है। हकीकत तो यह है कि चारों ही शहरों में गंदगी बड़ी चुनौती है। ट्रैफिक जाम हर शहर के लिए नासूर बना हुआ है। निर्बाध बिजली आपूर्ति और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं भी कोसों दूर हैं। जयपुर, उदयपुर और अजमेर की पहचान पर्यटन सिटी के रूप में और कोटा की पहचान कोचिंग सिटी के रूप में है। स्थानीय आबादी, पर्यटकों की आवक तथा विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों की आवाजाही इन शहरों में खूब है। कचरा संग्रहण, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, सुपर कनेक्टिविटी, सुरक्षित ट्रैफिक लेन स्मार्ट पार्किंग, बेहतर ट्रैफिक सिस्टम आदि को प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग में बरती गई खामियां लील गईं। जरूरत इस योजना में आई खामियों का पता लगा उन्हें दुरुस्त करने की है। तभी स्मार्ट सिटी अपने नाम के अनुरूप 'स्मार्ट' दिखेगी।

- रुद्रेश शर्मा
rudresh.sharma@in.patrika.com

सड़क सुरक्षा गति प्रबंधन गाइडलाइन नहीं लागू की गई तो रोड सेफ्टी के प्रयास अधूरे रहेंगे

राष्ट्रीय राजमार्ग : स्पीड कॉरिडोर से ज्यादा 'मौत के गलियारे'

प्रदीप मेहता
(लेखक कट्स इंटरनेशनल के महासचिव हैं)
@patrika.com

महाराष्ट्र का मॉडल अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सड़क सुरक्षा प्रवर्तन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

भारत में सड़क सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। वर्ष 2023 में देशभर में 4.61 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 1.72 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि देश के सड़क नेटवर्क का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा- राष्ट्रीय राजमार्ग ही कुल मौतों के 30-35 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारत के राजमार्ग अब 'मौत के गलियारे' बनते जा रहे हैं।

भारत में 2023 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं 29.8% और मौतें 35.2% हुई हैं। राजस्थान में विगत कुछ दिनों में भीषण सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 2 नवंबर को फलोदी (जोधपुर) के भारतमाला हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक टेम्पो ट्रैवलर, जो तीर्थयात्रियों को लेकर लौट रही थी, सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जबकि 2-3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वैसा ही लोमहर्षक हादसा 3 नवंबर को नेशनल हाईवे के निकट लोहा मंडी-सीकर रोड, हरमाड़ा में हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये घटनाएं राज्य में सड़क सुरक्षा की गंभीर स्थिति को दर्शाती हैं और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता पर बल देती हैं। भारत में राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिनके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। सबसे बड़ा कारण अधिक गति है- कुल दुर्घटनाओं में लगभग 66.5% हादसे और 72.3% मौतें इससे जुड़ी पाई गई हैं। इसके अलावा, चालकों की थकान और ध्यान विचलन भी एक गंभीर समस्या है। तीसरा प्रमुख कारण है खराब सड़क अभियांत्रिकी, जिसमें तीखे मोड़, अंधे मोड़ और अपर्याप्त संकेतक शामिल हैं। कमजोर प्रवर्तन भी एक अहम कारण है- ट्रैफिक नियमों के ढीले पालन और सीमित स्पीड कैमरों के कारण नियमों का प्रभावी अनुपालन नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त शराब या नशे की हालत में ड्राइविंग, तथा कोहरे या बारिश जैसी खराब दृश्यता की स्थिति, हादसों को और बढ़ाती है।

ओवरस्पीड की भयावहता
72.3% मौतें होती हैं इस कारण से कुल दुर्घटनाओं में।

सड़क सुरक्षा के लिए केवल अवसंरचना का विकास ही नहीं, बल्कि सख्त प्रवर्तन और जनजागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। भारत सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें अवैध सड़क कट एवं अतिक्रमण हटाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश, साइड रोड डिजाइन, संकेतकों तथा मर्जिंग लेन में सुधार और ब्लैक स्पॉट की पहचान एवं सुधार कार्य में तेजी लाना जैसी कार्यवाही शामिल हैं।

हालांकि इन पहलों के बावजूद, राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। यह दर्शाता है कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में केवल नीतिगत प्रयास पर्याप्त नहीं हैं- इनके प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और जनजागरूकता पर भी समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सड़क सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कुछ राज्यों ने समर्पित हाईवे ट्रैफिक पुलिस बल की स्थापना की है।

महाराष्ट्र इस दिशा में एक अग्रणी उदाहरण है, जहां एक विशेष राजमार्ग पुलिस बल कार्यरत है। इस बल में 2,000 से अधिक कर्मी तैनात हैं, जो राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर निरंतर गश्त और निगरानी करते हैं। महाराष्ट्र का मॉडल अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सड़क सुरक्षा प्रवर्तन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरे राज्यों में यह जिम्मेदारी राज्य पुलिस और यातायात इकाइयां निभा रही हैं। भारत में अब तक एकीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल का गठन नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'स्पीड मैनेजमेंट गाइडलाइंस' शीघ्र लागू नहीं की गई, तो सड़क सुरक्षा पर किए जा रहे सभी प्रयास अधूरे रह जाएंगे।

सड़क सुरक्षा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कुछ कदम तत्काल उठाए जाने आवश्यक हैं। सबसे पहले, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन शीघ्र किया जाना चाहिए, ताकि सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी नीतिगत, तकनीकी और संस्थागत एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। दूसरा, देश के लिए एक राष्ट्रीय गति प्रबंधन दिशा निर्देश तैयार किए जाने चाहिए, जिनके अंतर्गत स्पीड मॉनिटरिंग, कैमरा-आधारित प्रवर्तन और स्वचालित दंड प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके। तीसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य परिवहन विभाग और राज्य सरकारों के बीच नियमित संयुक्त समीक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जिससे सड़क सुरक्षा योजनाओं, ब्लैक स्पॉट सुधार कार्यों और प्रवर्तन गतिविधियों की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित हो सके। इन कदमों से केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वित प्रयासों को बल मिलेगा और सड़क सुरक्षा लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी आएगी।

यदि सड़क अभियांत्रिकी, प्रवर्तन, और जन-जागरूकता में ठोस सुधार नहीं हुए, तो ये 'विकास के राजमार्ग' आगे भी 'मौत के राजमार्ग' बने रहेंगे।

आपकी बात

राजनीतिक दबाव से मुक्ति जरूरी

सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए उन्हें राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना चाहिए। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता मिलने से वे निष्पक्ष व प्रभावी कार्य कर सकेंगे। राजनीति संरक्षण से दूरी बनाकर हर वर्ग के हित में योजनाओं को समय पर लागू किया जा सकता है। ऐसे नियम बनें जो योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में सहायक हों।

- कुमार जितेन्द्र जीत, मोकलसर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?' अन्य प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें। https://shorturl.at/9zGZU

आज का सवाल

शोध और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

प्रेरणा

खूबसूरती हर तरफ है, बस देखने की देर है।
- बॉब रॉस

संपादकीय

चुनाव आयोग को आरोपों का जवाब देना चाहिए

चुनाव की विश्वसनीयता प्रजातंत्र की रीढ़ है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की वेबसाइट दिखाते हुए संस्था पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। ब्राजील की मॉडल का वोटर लिस्ट में नाम, एक ही घर में दर्जनों नहीं, सैकड़ों वोटर्स का पता, एक ही वोटर का दर्जनों जगह धुंधला फोटो या नाम और कई वोटर्स का अनेक राज्यों में नाम- ये आयोग की साइट से लिए गए तथ्यों पर आधारित आरोप हैं। तर्कशास्त्र में अगर सत्य को गलत ठहराने वाला एक भी तथ्य अकाट्य है तो पूरा सत्य चाहे कितना भी पुख्ता क्यों न हो, ध्वस्त हो जाता है। आखिर विदेशी मॉडल देश के वोटर लिस्ट में कैसे आई या वही मतदाता एक ही या पिता के बदले नाम के साथ चार राज्यों, विधानसभा क्षेत्रों या उसी क्षेत्र के कई बूथों पर कैसे सूची में आ जाता है। जहां आयोग स्वच्छ चुनाव के नाम पर एसआईआर लाकर यह दावा कर रहा है कि गैर-नागरिक वोटर्स की पहचान करेगा, वहीं उसके अपने सिस्टम में इतनी बड़ी खराबी क्या प्रजातंत्र के लिए कलंक नहीं बनेगी? विगत हरियाणा चुनाव में केंद्र में सत्ता पर बैठी पार्टी के पक्ष में आए अप्रत्याशित परिणाम को कांग्रेस ने अपने आरोप का आधार माना है। यह सच है कि सभी एग्जिट पोल्स और सर्वे कांग्रेस की जीत का अनुमान लगा रहे थे लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे। देश की जनता इस बार राहुल के प्रमाणनिष्ठ आरोपों पर असहज भाव से चुनाव आयोग की ओर देख रही है। उसे डर है कि अगर इन आरोपों में रंच मात्र भी सच्चाई है तो संविधान-सम्मत शासन कैसे चलेगा।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

समय का मान करिए, समय आपका खूब सम्मान करेगा

आजकल कोई भी काम करने जाओ, दबाव जरूर बनेगा। लेकिन दबाव तनाव में ना बदल जाए, यह जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। क्योंकि हर काम में हमारे साथ और भी व्यक्ति होते हैं, परिस्थिति होती है, जिस पर आपका नियंत्रण नहीं। आजकल जिससे मिलो, वो यह कहता हुआ दिखेगा कि काम करने वाले लोग मिलते ही नहीं। सरकारें पैसा बांट रही हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी बांटना चाहिए। ये बात सरकार को जब समझ में आएगी, तब आएगी। हम पुरुषार्थ कैसे बांट सकते हैं, यह देखना पड़ेगा। जब भी कोई काम करने जाएं, उसकी समय-सीमा- जिसको डेडलाइन कहते हैं- तय करें। श्रीराम की सफलता के पीछे डेडलाइन थी 14 वर्ष की। यह केवल मंथरा या कैकेयी के मुंह से निकला हुआ समय का आंकड़ा नहीं था। यह राम के लिए डेडलाइन थी कि मुझे 14 वर्ष में राजकुमार से लोकनायक तक की यात्रा करनी है। मनुष्य का मस्तिष्क प्रेशर अर्जेंसी में- आवश्यक दबाव में बहुत अच्छे से सक्रिय होता है और परिणाम देता है। जो भी काम करें, समयबद्ध होकर करें। समय का मान करें, समय आपका सम्मान करेगा।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

पाठकों के पत्र

वेलनेस पर अधिक खर्च उपयोगी

भारत सरकार 'आयुष्मान भारत' के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देकर अच्छा कार्य कर रही है। वर्तमान में खराब जीवन शैली, मिलावटी खाद्य सामग्री, जानकारी और प्रशिक्षण के अभाव में लोग बीमार होने को अभिशप्त हैं। वेलनेस कार्यक्रमों पर अधिक बजट का प्रावधान करने से लोगों को बीमार होने से बचाया जा सकेगा। महंगे इलाज में लगने वाला धन अन्य विकास कार्यों में खर्च किया जा सकेगा। -अजय कुमार डांगी, मंदसौर, मध्यप्रदेश

टीवी फैला रहा है नकारात्मकता?

आमतौर पर टीवी पर पारिवारिक झगड़ों वाले धारावाहिक, न्यूज चैनल पर अक्रामक बहसें, सेक्स और हिंसा भरी वेब सीरीज दिखाई जा रही हैं। ऐसे में देखे तो हमारे घरों में टीवी के माध्यम से निगेटिव वाइब्स ही प्रसारित होती हैं। हमारे गुस्सा करने, चिड़चिड़ा रहने, निराश, उदास व असंतुष्ट होने, परेशान रहने, नाते-रिश्तों में दूरियां बढ़ने का कारण कहीं टीवी के माध्यम से प्रसारित नकारात्मकता ही तो नहीं? जरा सोचिए। -विनय मोघे, पुणे, महाराष्ट्र

नीदरलैंड में दक्षिणपंथी पार्टी पिछड़ी

नीदरलैंड के आम चुनाव में मध्यमार्गी डी-66 पार्टी ने बढ़त हासिल की है। जबकि दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी को आशा से बहुत कम समर्थन मिला है। डी-66 नेता रॉब जेटन के लिए देश का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुल गया है। आशा करनी चाहिए ऐसे नतीजे यूरोप के सभी देशों में दिखेंगे और नफरती, अल्पसंख्यक-आप्रवासी विरोधी एवं नस्लवादी नेताओं को इसी तरह से हराया जाता रहेगा। -जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर, झारखंड

सीनेट भंग करना लोकतंत्र पर हमला

केंद्र सरकार द्वारा 59 साल पुराने पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट को भंग करना असंवैधानिक और पंजाब के अधिकारों पर हमला है। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना पंजाब विधानसभा में 1947 में पारित एक्ट से हुई थी। केंद्र सीनेट और सिंडिकेट को अपना रबर स्टैंप बनाना चाहता है। आधिकारिक हलकों में कहा जा रहा है कि यह कोई सुधार नहीं है, बल्कि पंजाब के सबसे ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान का केंद्रीय अधिग्रहण और लोकतंत्र पर सीधा हमला है।
-एसके खोसला, चंडीगढ़

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

फूलों का रस ही नहीं, आंसू व खून तक भी पीती हैं तितलियां

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तितलियां केवल फूलों का रस पीती हैं, लेकिन वे जीवों का पसीना, खून और आंसू भी पीती हैं। तितलियों का यह व्यवहार 'मड-पडलिंग' कहलाता है। खासतौर पर नर तितलियां ऐसा करती हैं, क्योंकि उन्हें प्रजनन के लिए अधिक मात्रा में सोडियम और अमीनो एसिड की जरूरत होती है। चूंकि फूलों के रस में ये मिनरल्स बहुत कम होते हैं, इसलिए तितलियां अतिरिक्त पोषक तत्वों के लिए मड पडलिंग करती हैं। तितलियां गीली मिट्टी पर बैठ कर भी इस जरूरत को पूरा करती हैं।

18000 प्रजातियां तितलियों की पाई जाती हैं दुनियाभर में। अमेरिका में हुए एक शोध में बीते एक दशक में तितलियों की आबादी में 22% गिरावट बताई गई है।

विहंगावलोकन • ये चुनाव लोकतांत्रिक गिरावट को और गहराएंगे या इस पर रोक लगाएंगे?

बहुत कुछ दांव पर है बिहार के चुनावों में

बिहार

आशुतोष वार्ष्णेय
ब्राउन यूनिवर्सिटी, अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर

बिहार का ऐतिहासिक और समकालीन महत्व जगजाहिर है। आमतौर पर चुनावी चर्चाओं में समकालीन मुद्दे ही हावी रहते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति पर लगभग हमेशा चर्चा होती है, लेकिन इस प्रक्रिया में हम अक्सर बिहार के गौरवशाली अतीत के कुछ चमकदार पहलुओं को भूल जाते हैं।

शायद बिहार के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा यह है कि बुद्ध को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों- चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में फैल गया और एक विश्व-धर्म के रूप में स्थापित हुआ। हालांकि भारत में इसका प्रभाव समय के साथ कम होता गया। दो अन्य ऐतिहासिक पहलू भी उल्लेखनीय हैं। डेविड स्टैसेवेज ने अपनी किताब द डिक्लाइन एंड राइज ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है कि प्राचीन भारत के गणराज्य लोकतंत्र के शुरुआती उदाहरण थे, यूनान और मेसोपोटामिया के साथ। ये गणराज्य बिहार के 'संघ' कहलाते थे। यह सच है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है।

दूसरा, आज भले ही बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे कम में से एक है और इस पर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। गरीब राज्य या गरीब गणराज्य विश्व-प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नहीं बनाते। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो ऑक्सफोर्ड से 500 साल पहले और इटली के बोलोन्या विश्वविद्यालय (यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालय) से पहले की है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है।

जहां तक बिहार के आधुनिक इतिहास की बात है, तो ब्रिटिश शासन को देशव्यापी असहयोग आंदोलनों से हिलाने से पहले गांधी ने सबसे पहले बिहार के चंपारण में 1917 में एक छोटे स्तर पर सत्याग्रह का प्रयोग किया था। यह उनके दक्षिण अफ्रीका के आंदोलनों जैसा ही था। इस तरह, बिहार को भारत में गांधीवादी सत्याग्रह का जन्मस्थान कहा जा सकता है। गुजरात के खेड़ा का आंदोलन बाद में हुआ था। इसके अलावा, जयप्रकाश नारायण का जन्म भी बिहार में हुआ था। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने इंदिरा के शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन का नेतृत्व किया। 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ और इंदिरा चुनाव हार गईं, तब वे दिल्ली में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के गठन में अहम भूमिका में थे। आंतरिक मतभेदों के कारण वह सरकार अधिक समय तक नहीं चल सकी, लेकिन उसने भारत के लोकतंत्र को अधिक मजबूत और जीवंत बनाया।

अब हम बिहार की दो और आधुनिक विशेषताओं की ओर आते हैं, जो इन चुनावों से गहराई से जुड़ी हैं। यह कम ही नोट किया जाता है कि हिंदी भाषी उत्तर भारत में बिहार ही एकमात्र राज्य है, जहां भाजपा कभी अपने दम पर सत्ता में नहीं आई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भाजपा का हिंदू राष्ट्रवाद मंडल की जाति राजनीति पर हावी हो गया। लेकिन बिहार में पिछड़ी जातियों की राजनीति इतनी गहराई से जमी हुई है कि हिंदू राष्ट्रवाद अब तक केवल उसके साथ गठबंधन बनाकर ही आगे बढ़ सका है।

इतिहास के अनुसार, पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाने वाली मंडल-शैली की राजनीति सबसे पहले दक्षिण भारत में, खासकर पुरानी मद्रास प्रेसीडेंसी में, 1910 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। लेकिन उत्तर भारत में इस तरह की राजनीति को उभरने में पांच-छह दशक और

मंडल राजनीति के साथ साझेदारी बढ़ाने के प्रयास

कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी आरक्षण नीति लागू की थी, जो एससी और एसटी को दिए आरक्षण से अलग थी। लालू और नीतीश के शासन के दौरान इसने संस्थागत रूप लिया। केंद्र ने भी उन्हें भारत रत्न देकर मंडल राजनीति के साथ साझेदारी बढ़ाने का प्रयास किया।

लग गए। और इसका जन्मस्थान बिहार था। बिहार में मंडल राजनीति के नेता कर्पूरी ठाकुर थे। 1978 में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ओबीसी आरक्षण नीति लागू की थी, जो एससी और एसटी को दिए आरक्षण से अलग थी। इसे सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण मॉडल कहा गया। यह योजना मुख्य रूप से, हालांकि पूरी तरह नहीं, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण देकर आगे बढ़ाने के लिए थी। कर्पूरी ठाकुर को लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों का गुरु माना जाता है। दूसरे शब्दों में, ठाकुर की राजनीति उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद भी जारी रही। बल्कि, लालू और नीतीश के शासन के दौरान- जो साढ़े तीन दशकों से अधिक समय तक फैला है- यह राजनीति संस्थागत रूप ले चुकी है।

जहां भाजपा ने यूपी में मंडल राजनीति की पकड़ तोड़ दी, वहीं वह बिहार में ऐसा नहीं कर पाई है। वास्तव में, जनवरी 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देना मंडल राजनीति के साथ साझेदारी बढ़ाने का प्रयास था। इसका उद्देश्य आंशिक रूप से नीतीश के साथ गठबंधन मजबूत करना था, और आंशिक रूप से यह दिखाना कि भाजपा सिर्फ ऊंची जातियों की पार्टी नहीं है, वह ओबीसी की भी परवाह करती है।

साथ ही, बिहार पहला राज्य है, जहां चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को शुद्ध करने की कोशिश की है। ईसी और केंद्र के इस तर्क से असहमति नहीं जताई जा सकती कि वैध नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार है। लेकिन असल में, एसआईआर एक ऐसे अभियान में बदल गया है जो उन समुदायों के वोटिंग अधिकारों को खत्म करने या बहुत सीमित करने की कोशिश करता है, जो सत्ता में बैठे नेताओं के खिलाफ वोट डाल सकते हैं। यह दुनिया भर में लोकतांत्रिक गिरावट से सीधे तौर पर जुड़ा मामला है। यह गिरावट तब शुरू होती है, जब कार्यपालिका स्वतंत्र संस्थाओं- अदालतों, चुनाव आयोगों, खुफिया एजेंसियों, कर विभागों, केंद्रीय बैंकों, मीडिया और विश्वविद्यालयों- की शक्ति और स्वायत्तता को सीमित करने लगती है। जबकि लोकतंत्र में इनका काम कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे सीमित करना होता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

विश्लेषण • बिहार में जारी सियासी कहानी अद्भुत

जाति और कैश का वितरण सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं

सियासत

शीला भट्ट
वरिष्ठ पत्रकार
sheelabhatt@gmail.com

भारत में आज गरीब के लिए 10 हजार रुपए की उपयोगिता और ताकत देखनी है तो बिहार घूमकर आइए। गांव-मोहल्लों में 'प्रधानमंत्री से मिले 10 हजार रुपयों' की चर्चा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने 18 से 60 साल की सभी गैर आयकरदाता गरीब महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए बांटे हैं। 6 और 11 नवंबर को यदि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए महिलाओं को पोलिंग बूथों पर लाने में सफल हुआ तो यह तेजस्वी और महागठबंधन के लिए मुश्किल पैदा करेगा।

बिहार चुनाव में आज कैश वितरण से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। ऐसा नहीं कि आरजेडी-कांग्रेस का महागठबंधन कमजोर है, लेकिन उसका अतीत उसे सताता है। 2025 के चुनाव में 20 साल पुरानी हकीकतों की चर्चा है और एनडीए 'जंगलराज' के नारे को मजबूत चुनावी हथियार बना रहा है। इसके जवाब में महागठबंधन ने युवाओं के पलायन, ऊंची बेरोजगारी दर और आजीविका के घटते साधन जैसे गंभीर मुद्दे उठाए हैं। दोनों गठबंधनों के घोषणा-पत्रों में रेवड़ियों की भरमार है। ऐसे में कह सकते हैं कि चुनावी मौसम हमेशा सपने दिखाने का खेल है।

बिहार में वोटर वोट देने से पहले अपनी जाति और फायदे-नुकसान का आकलन करते हैं। दलों की जाति आधारित सियासत के आधार पर पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही वे वोट देते हैं। वे कहते भी हैं कि 'बेटी और वोट जाति में ही देने चाहिए।' यों तो जाति के आधार पर पूरे देश में ही राजनीति की जाती है, लेकिन बिहार में यह परिवार की सुरक्षा का मसला भी है।

बिहार का चुनाव दूसरे राज्यों से अलग है। कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु से तुलना करें तो बिहार में दलों और प्रत्याशियों को कम पैसों की जरूरत होती है। बिहारी मतदाता राजनीतिक रूप से चतुर और अपने रुख में दृढ़ होते हैं। वर्तमान में मतदाता मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बंटे हैं। 14.2% यादव और 17.7% मुस्लिमों में से अधिकतर तेजस्वी और महागठबंधन को समर्थन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि 'जंगल राज' महज भाजपा का चुनावी प्रोपेगैंडा है। बीते 2-3 सालों में बिहार में कानून-व्यवस्था लालू के दौर से बेहतर नहीं है। जन सुराज पार्टी प्रत्याशी दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में आरोपी अनंत सिंह जेडीयू और एनडीए के ही उम्मीदवार हैं। एक आरजेडी समर्थक ने मोकामा में एक संवाददाता से कहा कि 'अब बताइए, नीतीश राज में बिहार में क्या बदला?'

इधर, गैर यादव ओबीसी (14%), अति पिछड़ा वर्ग (36%) के मतदाताओं, महिलाओं और ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार जैसी अगड़ी जातियों (15.52%) के वोटरों से बात करें तो आज भी उनके शब्दों में लालू राज का डर नजर आता है। नीतीश ने अपने शुरुआती वर्षों में बिहार को आपराधिक अंधकार से निकाला था। लोग आज भी उसकी कृतज्ञता मानते हैं। कहा जाता है कि नीतीश को आंशिक स्मृति लोप है। लेकिन राजगीर के समीप एक युवा मतदाता कहते हैं कि 'पिता की याददाश्त कमजोर हो तो उन्हें घर से नहीं निकालते।'

बिहार में लंबा शासन करने के बावजूद भाजपा की कमजोरी यह है कि वह नीतीश जैसा भरोसा नहीं कमा

बिहार में वोटर वोट देने से पहले अपनी जाति और फायदे-नुकसान का आकलन करते हैं। जाति आधारित सियासत के आधार पर पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही वे वोट देते हैं। वे कहते भी हैं कि 'बेटी और वोट जाति में ही देने चाहिए।' यह परिवार की सुरक्षा का मसला भी है।

पाई। उसके पास करिश्माई नेता नहीं है। नीतीश के बिना वह अति-पिछड़ा वर्ग और दलितों को भी अपनी छतरी तले नहीं ला सकती। लेकिन तयशुदा तौर पर वह अपने भीतर बदलाव ला रही है। भाजपा उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी बिहार के मुस्लिम और यादव वोटर जानते हैं कि नीतीश के सहारे चल रही भाजपा बिहार को लेकर अब किसी नई योजना का खुलासा करेगी।

सरकार के 75 लाख गरीब महिलाओं को 10-10 हजार देने के दावे पर महागठबंधन इसे वोटरों को रिश्वत देना कहता है, जबकि अमित शाह इसे व्यापार शुरू करने के लिए 'सीड मनी' बताते हैं। कई मायनों में बिहार का चुनाव एक हाइपर लोकल चुनाव जैसा है। टिकट वितरण की तुलना करें तो आरजेडी ने यादवों पर भरोसा जताया है और भाजपा ने बड़ी संख्या में अगड़ी जातियों के प्रत्याशियों को टिकट दिया है। सियासत में जातियों का प्रभाव कम करने के लिए बिहार बहुत कुछ नहीं कर पाया है। (ये लेखिका के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • उनका कोई उत्तराधिकारी तक नहीं है

मजबूत दिखने के बावजूद असुरक्षा से घिरे हैं जिनपिंग

चीन

ब्रह्मा चेलानी
पॉलिसी फॉर सेंटर रिसर्च के प्रोफेसर एमेरिटस

अपने 13 वर्षों के शासन के दौरान शी जिनपिंग ने सत्ता के सभी स्तंभों- पार्टी (सीपीसी), राज्य तंत्र और सेना- पर अपनी पकड़ मजबूत की है। समाज के हर पहलू पर निगरानी का विस्तार भी किया है। फिर भी, हाल ही में नौ शीर्ष-रैंकिंग जनरलों की बर्खास्तगी दर्शाती है कि वे आज भी संशय से मुक्त नहीं हुए हैं और उन्हें अभी भी हर जगह दुश्मन दिखाई देते हैं।

2012 में सत्ता संभालने के बाद शी ने सीपीसी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। यह अभियान शुरू में लोकप्रिय था, क्योंकि चीन की एकदलीय प्रणाली भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से भरी है। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह अधिक पारदर्शी या प्रभावी प्रणाली बनाने के लिए नहीं, बल्कि शी के हाथों में सत्ता को मजबूत करने के लिए था। शी के चीन में उन्नति योग्यता या ईमानदारी पर कम और उनका भरोसा अर्जित करने पर अधिक निर्भर करती है।

लेकिन केवल वफादारों को पदोन्नत करने के एक दशक से भी अधिक समय के बावजूद शी नियमित रूप से अधिकारियों को बर्खास्त करते रहते हैं, जिनमें शीर्ष सैन्य कमांडर भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय के अनुसार, शी के शासनकाल में सरकार के सभी स्तरों पर लगभग पांच लाख अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनकी तो बात ही छोड़िए, जो अचानक गायब हो गए।

हुकूमत का दावा है कि हालिया सफाई अभियान में जिन लीडर्स को हटाया गया है- जिनमें पोलित ब्यूरो के सदस्य, केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष और चीन के सैन्य पदानुक्रम में तीसरे सबसे ऊंचे पद पर आसीन जनरल वेइदोंग भी शामिल हैं- उन्होंने अनुशासनात्मक उल्लंघन और कर्तव्य-हनन संबंधी अपराध किए हैं। लेकिन एक ज्यादा विश्वसनीय व्याख्या यह है कि शी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में बेताब होते जा रहे हैं। वैसे उनकी आशंकाएं बेबुनियाद नहीं हैं। क्योंकि इस तरह का हर नया सफाई अभियान चीन के सत्ता-कुलीनों के बीच अविश्वास को गहरा करता है और पूर्व वफादारों के भी दुश्मन बन जाने का जोखिम पैदा करता है। माओ से लेकर स्टालिन तक, इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि तानाशाही शासन से देर-सबेर लोगों का मन उचट जाता है। अब तक तो शी जिनपिंग सहयोगियों और दुश्मनों में फर्क करने की क्षमता भी खो चुके होंगे। 72 की उम्र में भी वे अपनी स्थिति को लेकर इतने असुरक्षित हैं कि माओ के उलट, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने से भी इन्कार कर दिया है- इस डर से कि एक प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी उनके पतन की प्रक्रिया को तेज कर सकता है।

इनमें से कोई भी बात चीन के लिए शुभ संकेत नहीं है। अंततः नेतृत्व परिवर्तन की नींव रखने से इन्कार करके शी जिनपिंग इस जोखिम को बढ़ा रहे हैं कि उनके शासन का अंत राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत करेगा। इस बीच, वैचारिक अनुरूपता के बजाय व्यक्तिगत निष्ठा पर उनका जोर एक ऐसी व्यवस्था में संस्थागत सामंजस्य को कमजोर कर रहा है, जो कभी सामूहिक नेतृत्व पर आधारित थी। मनमानी बर्खास्तगी और मुकदमों के साथ चीन का शासन अब योग्यता के बजाय

केवल वफादारों को पदोन्नत करने के एक दशक से भी अधिक समय के बावजूद शी नियमित रूप से अधिकारियों को बर्खास्त करते रहते हैं, जिनमें शीर्ष सैन्य कमांडर भी शामिल हैं। उनकी तो बात ही छोड़िए, जो अचानक गायब हो गए।

चाटुकारिता से परिभाषित होता जा रहा है।

चीन की सेना भी शी की असुरक्षा की भारी कीमत चुका रही है। हाल के वर्षों में पीएलए में व्यापक संरचनात्मक सुधार हुए हैं, जिनका उद्देश्य इसे सूचना-आधारित युद्ध जीतने में सक्षम एक आधुनिक लड़ाकू बल में बदलना है। लेकिन इससे सैन्य योजना और नेतृत्व में बाधा उत्पन्न होने का खतरा है। उदाहरण के लिए, 2023 में पीएलए के रॉकेट फोर्स- जो चीन की परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों के भंडार की देखरेख करता है- के लीडर्स को अचानक हटाने से चीन की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता खतरे में पड़ सकती है। अनुभवी कमांडरों की जगह अप्रशिक्षित वफादारों को लाना शी के राजनीतिक अस्तित्व को भले सुनिश्चित करता हो, पर इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को फायदा नहीं होता। क्या शी द्वारा लगाई राजनीतिक सीमाओं के तहत काम करते हुए पीएलए किसी बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ युद्ध जीत सकती है? (© प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

डिफ्रेंट एंगल • हर कोई तो पेशेवर खिलाड़ी नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी खेलने के बहुत फायदे हैं...

जीवन एक खेल है, हार-जीत लगी रहेगी... आप बस दिल से खेलो

कसरत

रश्मि बंसल
लेखिका और स्पीकर
mail@rashmibansal.in

कुछ दिनों से मैं जिम जाने लगी हूं। वैसे जिम मेरी बिल्डिंग में ही है और मैं सालों पहले से जा सकती थी। लेकिन सच कहूं तो मुझे एक्सरसाइज से सख्त नफरत थी। बचपन से मेरा ध्यान दिमाग की एक्सरसाइज पर था- पढ़ना, लिखना, एग्जाम देना। और उसी से मैंने जिंदगी में काफी कुछ प्राप्त किया। स्कूल में एक पीरियड होता था पीटी का। हमारी पीटी टीचर थीं मिस चावला, जो खुद फिटनेस की मिसाल नहीं थीं। मुझे याद है उनकी सीटी और अटेंशन-स्टैंड एट ईज-अटेंशन चिल्लाती हुई आवाज। भाई, मुझे मिलिट्री में थोड़े ही शामिल होना है।

स्पोर्ट्स डे पर किसी टीचर ने मेरा नाम 100 मीटर की रेस में डलवा दिया। उनका लॉजिक था मैं लंबी हूं, इसलिए तेज दौड़ूंगी। उन्हें क्या पता कि मेरा लास्ट नंबर आएगा। शायद मैं चाहती ही नहीं थी कि स्पोर्ट्स के झंझट में पड़ूं। स्पोर्ट्स के नाम पर मैंने टेबल टेनिस और कैरम जरूर खेला। वो इसलिए कि बारिश के मौसम में हमारी बिल्डिंग के बेसमेंट में सब बच्चे मिलकर यही टाइमपास करते थे। टीटी में ठीक-ठाक थी, लेकिन कैरम में मैंने 15 अगस्त पर होने वाले टूर्नामेंट में कुछ पुरस्कार भी जीते।

कैरम में न तो दौड़ना पड़ता है, ना कोई धूल-मिट्टी। हां, दिमाग जरूर लगता है। किस एंगल से मारना है, कितने फोर्स से मारना है, इसमें थोड़ा मेंटल मैथ्स तो लगता है। आज भी मैं अच्छे-अच्छों को कैरम में हरा सकती हूं। खैर, कैरम आज स्पोर्ट्स की गिनती में आता ही नहीं। ओलिंपिक्स छोड़ो, हमारी अपनी नई पीढ़ी इस महान गेम को जानती नहीं। एक तो खाली-बोर दोपहरें उन्हें नसीब नहीं, मां-बाप किसी ना किसी क्लास में डाल देते हैं। और जो वक्त मिलता है, उसमें वो वीडियो गेम या सोशल मीडिया में मगन रहते हैं।

मैंने जिम जाना शुरू किया बेटी की वजह से। वो मेरे पीछे पड़ गई कि मम्मी, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगी, तो आगे जाकर क्या होगा? मैंने सोचा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। अब तकलीफ यह कि दिमाग फिर भी शरीर पर हावी। सुबह दिमाग कहता है थोड़ा और सो लो। दोपहर को कहता है, शाम को अच्छी एक्सरसाइज होगी। शाम को कोई और बहाना। इसी वजह से मुझे ट्रेनर रखना पड़ा। एक बार फीस दे दी तो लगता है, अब तो जाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में पिछले 8 महीनों से मैं जिम में दर्शन दे रही हूं। अपने आलस से जूझ रही हूं और सच कहूं तो कुछ बदलने लगा है। शरीर को थोड़ा कष्ट देने के बाद जो दर्द होता है, वो मीठा लगने लगा है।

सोचती हूं, शुरू से ही शरीर पर ध्यान दिया होता तो अच्छा होता। शायद आज भी बच्चे को दिमाग के सहारे ही जीने की सीख दी जाती है। अब तो स्कूल, ट्यूशन और कॉम्पीटिशन की तैयारी के बीच में वो पूरी तरह पिस गए हैं। नींद में भी वो पढ़ाई के सपने देखते होंगे। शहरों में जहां खेल के मैदान होने चाहिए, वहां ऊंची इमारतें खड़ी हैं। फिर भी, सड़कों पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं- आस-पास के गरीब बच्चे। उन इमारतों में रहने वाले बच्चे बालकनी से उन्हें देखते हैं, शामिल नहीं होते।

हमारी लड़कियों ने हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, बड़े गर्व की बात है। क्या उनसे प्रेरणा लेकर हर स्कूल में लड़कियों की क्रिकेट टीम बनेगी? जो खेलेंगी दिल खोलकर, दौड़ेंगी हल्ला बोलकर? क्या नजारा होगा, ऐसा देश हमारा होगा। हर कोई खिलाड़ी नहीं बनेगा पर खेलने के बहुत फायदे हैं। एक टीम में शामिल होना मतलब आपको हार और जीत- दोनों का एहसास होगा। एक मैच हारने से कुछ नहीं होता है, फिर कोशिश करेंगे। एक एग्जाम फेल होने से कुछ नहीं होता, फिर से एग्जाम देंगे।

जीवन एक खेल है, हार-जीत लगी रहेगी। आप बस दिल से खेलो। (ये लेखिका के निजी विचार हैं)

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । मुंबई । गुरुवार, 6 नवंबर 2025

विजय चाहे जितनी लंबी और कठिन राह से हो, उसके बिना अस्तित्व नहीं है।

– विंस्टन चर्चिल

इस जीत के मायने

जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतना अमेरिका की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ है। जब प्रवासी वहां ज्वलंत मुद्दा बने हुए हैं, तब पहली बार एक मुस्लिम नेता का अमेरिका की वित्तीय राजधानी की कमान संभालना अमेरिकी समाज में बढ़ती विविधता और स्वीकार्यता का संकेत है। उनकी जीत बताती है कि अमेरिकी नई सोच के साथ चलने के लिए तैयार हैं।

नई राजनीति । ममदानी ने लगभग एक साल पहले जब अपने कैंपेन की शुरुआत की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह इतिहास रचने जा रहे हैं। जून में वह डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीते और पार्टी की तरफ से उम्मीदवार चुने गए, तब सबका ध्यान उनकी ओर गया। 34 साल के जिस युवा को उसके कम अनुभव की वजह से पहले चुनावी लड़ाई में कमजोर माना जा रहा था, बाद में वही सबसे अहम फैक्टर साबित हुआ।

ममदानी चुने गए मेयर

जनता से जुड़ाव । उनकी खासियत रही जनता से जुड़ाव। उन्होंने विज्ञापनों पर खर्च करने के बजाय सीधे लोगों से संवाद किया। आम शहरियों की समस्याओं को समझा और वादा किया कि वह न्यूयॉर्क को रहने के लिए ज्यादा बेहतर जगह बनाएंगे। उनकी चुनावी घोषणाओं को देखें तो लगता है कि वह किसी विकासशील देश की बात कर रहे हैं - फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किराये पर लगाम और न्यूनतम वेतन। लेकिन, परिणाम से जाहिर है कि वह नब्ज पकड़ने में सफल रहे। उन्होंने उन समस्याओं को छुआ, जिन्हें दूसरे ज्यादा अनुभवी नेता नजरअंदाज करते रहे।

भरोसा जीता । ममदानी ने केवल वादे ही नहीं किए, यह भी बताया कि वह इन्हें पूरा कैसे करने वाले हैं। उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाकर और न्यूयॉर्क के अमीरों पर 2% अतिरिक्त कर लगाकर योजनाओं के लिए पैसा जुटाने की बात कही। इससे मध्यम वर्ग उनसे जुड़ता चला गया। एक लाख लोगों का वॉलंटियर बनना और 20 लाख से अधिक वोटिंग से पता चलता है कि इस बार जनता बदलाव का मन बना चुकी थी।

अगली चुनौती । ममदानी ने जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। उन्होंने इस परिणाम को बदलाव के लिए समर्थन बताया और कहा कि न्यूयॉर्क ने ट्रंप को हराने का रास्ता दिखा दिया है। इस जीत ने पस्त डेमोक्रेट्स में नई जान भरी होगी, लेकिन चुनौती अब शुरू होती है। चुनावी प्रचार के दौरान ट्रंप और ममदानी में जैसी तल्खी दिखी, वैसा कभी नहीं हुआ था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ममदानी जीते तो वह न्यूयॉर्क के फेडरल फंड्स में कटौती कर देंगे। खैर, ममदानी के सामने अब अपने वादों को पूरा करने की चुनौती है।

गुस्ताखी माफ़

अनुप्रास का आनंद

कनपटी पर कट्टा। अनुप्रास अलंकार तो है ही, पर इसमें जो एक धुन है, लय है, पूरे तन-मन में सिहरन पैदा कर देती है। सुबह-सुबह घर में बीवी की झिड़की सुनकर ऑफिस जाने वाले और ऑफिस में बॉस की मचमच पर जरा भी किचकिच न कर पाने वाले प्राणी में भय, विस्मय, रोमांच, उल्लास यानी कि सारे भाव एकसाथ हिलोर मारने लगते हैं।

अखिलेश प्रताप सिंह

लो ब्लड प्रेशर एकदम से नॉर्मल होने लगता है। कभी-कभी तो इतना हाई हो जाता है कि शाम को टीवी के सामने सोफे में धंसा आदमी समझ ही नहीं पाता कि हाथ में जो प्याला है, वह चाय का है या वीर रस का। इसी पिनक में वह बच्चों को पढ़ने-लिखने की रस्मी सलाह देते हुए डांटने लगता है। हालांकि पढ़ने-लिखने में खुद उसकी कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोस्तों के नोट्स और बाप के पैसे से स्कूल से नौकरी तक का सफर पूरा करने वाला इंसान अनुप्रास के आनंद में प्रवचन देने लगता है। लेकिन हाई बीपी की लहरों पर तैर रहा घुड़सवार भूल जाता है कि मोटा दहेज निचोड़कर उसके बाप ने उसकी नकेल मजबूत हाथों दे दी है। किचेन से स्विंग होकर आती एक फटकार भर से उस बांगड़ू का नशा हिरन हो जाता है। बच्चों के सामने दयनीय हो उठा वह प्राणी उलझन में पड़ जाता है कि चाय के प्याले में गोते लगा ले या सोसायटी के स्विमिंग पूल में। वैसे गोता लगाना कोई खराब बात नहीं है। कबीरदास जी कह गए हैं कि जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूड़न डरा, रहा किनारे बैठ।

बनारस और मगहर के बीच कहीं किसी ठीये से उठे इस दोहे की गूंज बिहार चुनाव में भी पहुंच गई है। एक भाई साहब तो बाकायदा तालाब में हाथ-पांव चलाते दिखे। मगर यह साफ नहीं हो पाया कि वह खुद कूदे या किसी दबाव में ऐसा कर बैठे। जो भी हो, मोती मिले न मिले, गहरे पानी में तो उतरे ही। अब चुनाव बाद ही पता चलेगा कि कट्टा, कनपटी और कबीरदास के इस अनुप्रास में बिहार को कितना आनंद आया।

एकदा

संकलन : रेनू सैनी

विज्ञान को दी नई दिशा

पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में जीव विज्ञान के अध्यापक दिनकर दत्तात्रेय समरथ के घर 8 नवंबर 1917 को जन्मी कमल रणदिवे बचपन से ही मेधावी थीं। पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बनें, लेकिन कमल जीवन के रहस्यों को समझना चाहती थीं। उन्होंने बायोमेडिकल रिसर्च का रास्ता चुना और अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज गे के साथ टिश्यू कल्चर तकनीक पर रिसर्च की। फेलोशिप पूरी कर भारत लौटते ही उन्होंने संकल्प लिया, 'देश को अपनी प्रयोगशाला चाहिए।' इसी भावना से भारत की पहली ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना हुई। यहीं से उनके कैंसर और वायरस पर शोध का सफर शुरू हुआ। उन्होंने स्तन कैंसर के आनुवंशिक कारणों की खोज की और कुष्ठ रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु पर भी गहरा अध्ययन किया। इससे संभावित टीके के विकास का रास्ता खुला। साल 1973 में उन्होंने 11 सहकर्मियों के साथ भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की स्थापना की। उन्होंने गांवों में जाकर महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और विज्ञान से जोड़ा। लोगों को बताया कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं, जीवन में भी जरूरी है। अपने कार्यों से उन्होंने भारतीय विज्ञान को नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गईं।

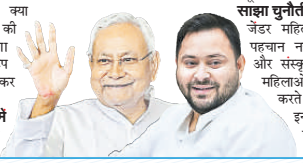

Subrata Dhar

किस अलायंस की लाभार्थी योजना पर भरोसा करेगा यह मतदाता समुदाय

बिहार की महिला वोटर्स क्या चाहती हैं

जिस दिन चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कीं, उसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 लाख महिला वोटरों के बैंक खातों में 2,100 करोड़ रुपये भेजे। यह पीएम मोदी ने पिछले सितंबर में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की थी। इसी के तहत हर महिला को नीतीश ने 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी। विपक्षी दल RJD भी पीछे नहीं रहा। उसने सत्ता में आने पर माई-बहिन मान योजना लागू करने का वादा किया है। इसके तहत कमजोर और पिछड़े समुदायों की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सहायता दी जाएगी।

रूही तिवारी

बिहार चुनाव 2025

अलग वोटर समूह । इन दोनों घोषणाओं का मकसद एक ही है - बिहार की महिला वोटरों को प्रतिबद्धता का यकीन दिलाना। दिलचस्प है कि बिहार जैसे जाति आधारित, पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं ऐसे समुदाय के तौर पर उभरी हैं, जिन्हें अलग मतदाता समूह के रूप में देखा जा रहा है।

नीति-निर्माताओं के लिए अहम । वे दिन गए, जब सियासी भाषणों में महिला वोटरों का जिक्र नाम भर के लिए होता था। आज सभी दलों के घोषणापत्र महिलाओं से जुड़े वादों से भरे रहते हैं। महिलाएं पॉलिसीमेकर्स के लिए सबसे अहम ग्रुप बन गई हैं। चुनाव से पहले महिलाओं को प्रभावित कर अपने पक्ष में करना फैशन नहीं, बल्कि एक जरूरत है।

तीन बड़े सवाल । इस संदर्भ में, तीन प्रमुख सवाल हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। पहला, क्या राजनीतिक वर्ग ने यह समझ लिया है कि महिलाएं वास्तव में क्या चाहती हैं या उसने इन वोटरों को महज लाभार्थी बनाकर रख दिया है जिनकी नजरें हमेशा खैरात पर टिकी होती हैं? दूसरा, क्या महिला वोटर एक समरूप समुदाय है और क्या इन्हें एक ग्रुप के तौर पर एक ही तरह से संबोधित किया जा सकता है? तीसरा, क्या महिलाएं परिवार की सोच-समझ-धारणा से अलग, स्वतंत्र रूप में वोट का फैसला कर रही हैं?

सशक्तीकरण में मददगार । इनके जवाब आसान नहीं हैं। मिसाल के तौर पर, पहले सवाल को लिया जाए तो राजनीतिक दल चाहे जिस सोच के तहत और जिस मकसद से इन कथित कल्याणकारी योजनाओं या महिला वोट कब्जाने वाली नीतियों की घोषणा करें, आखिरकार ये कदम महिलाओं को मजबूत बनाते हैं।

साझा चुनौती है जेंडर । ऐसे ही, जेंडर महिलाओं की इकलौती पहचान नहीं है। जाति, धर्म और संस्कृति से जुड़े सवाल महिलाओं को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन पुरुष इन सवालों से ज्यादा प्रभावित होते रहे हैं। महिलाओं के साथ जेंडर का ऐसा सवाल जुड़ा है जो उन सबके लिए एक साझा चुनौती की तरह आता है। यह उन सबको आपस में जोड़ देता है।

स्टेकहोल्डर की भूमिका । ऐसे ही परिवार के प्रभाव से पूरी तरह अलग होना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल सीधे महिलाओं से संवाद में उतर रहे हैं, उससे महिलाओं को अपनी अहमियत का अहसास हो रहा है, वे राजनीतिक प्रक्रिया में खुद को एक स्टेकहोल्डर की तरह देखने लगी हैं।

लुभाने की होड़

- सत्ता पक्ष और विपक्ष की घोषणाओं के केंद्र में महिलाएं
- महिला मतदाताओं की चुनाव में बढ़ गई है भागीदारी
- नतीजे पर इस वोटर समूह का होगा बड़ा असर

बढ़ी हुई सक्रियता । 2010 का बिहार चुनाव इस मायने में ऐतिहासिक था कि पहली बार महिलाओं का वोट प्रतिशत (54.4%) पुरुषों से (51.1%) कहीं ज्यादा रहा। राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं ने इस वोटिंग गैप को खत्म कर दिया, लेकिन वह 2019 में ही संभव हुआ।

आगे क्या । 2025 का विधानसभा चुनाव महिला मतदाताओं के संदर्भ में इस सवाल को समझने में मदद करेगा कि 'अब आगे क्या?' बिहार में विपक्ष इन मतदाताओं का दिल जीतने के मामले में उतना तत्पर नहीं रहा है। लेकिन एक बड़ा सच यह भी है कि बिहार की महिलाएं अब अपनी राजनीतिक अहमियत को लेकर अनजान नहीं रह गई हैं। इसलिए तय मानिए कि इस बार नीतीश कुमार के लिए भी उनका समर्थन हासिल करना आसान नहीं होगा।

कांटे की बात

अब वाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट के बयान से भारत के लोगों को यह जानकारी मिली है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में व्यापार समझौते को लेकर बार-बार बातचीत कर रहे हैं।

जयराम रमेश,
कांग्रेस नेता

असंभव संवाद

टैरिफ़ नाकाम हुआ, एटम बम तेरे लिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने फिर से परमाणु परीक्षण करने के लिए कहा है, क्योंकि चीन, पाकिस्तान समेत दूसरे कई देश ऐसा कर रहे हैं। क्या हो अगर उनकी मुलाकात हो जाए Julius Robert Oppenheimer से, जिसने दुनिया को यह विनाशकारी ताकत दी?

AI Image

अखबार में ट्रंप का आदेश पढ़ रहे ओपेनहाइमर को पुराने दिन याद आ गए, **'कालेऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः...** मैं काल हूं, लोकों का नाश करने वाला...।' कमरे में घुसते हुए ट्रंप को केवल आखिरी लाइन सुनाई पड़ी - नाश। 'डॉक्टर! नाश नहीं, मैं अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहता हूं।' 'लेकिन यह रास्ता विनाश का है। मुझे पहले टेस्ट के बाद ही समझ आ गया था और तुम अब तक न समझे?' 'दुनिया डर के बिना नहीं चल सकती डॉक्टर। मैंने टैरिफ का डर दिखाया, तो युद्ध रुक गए। अब जहां ट्रेड काम नहीं करेगा, वहां न्यूक्लियर करेगा।' डॉक्टर को भर्तृहरि नीतिशतकम् से लेकर चाणक्य के नीतिशास्त्र तक की याद आ गई। इस बार उन्होंने बात दिल में ही रख ली।

जनता जंक्शन

इरफ़ान

एक शहंशाह ने बनवा के हसीं ताजमहल...

इन दिनों ताजमहल फिर चर्चा में है। दरअसल, फिल्म 'द ताज स्टोरी' के पोस्टर, ट्रेलर और अब फिल्म रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है। फिल्म के एक पोस्टर में अभिनेता परेश रावल ताजमहल की गुंबद हटाते दिखाई दे रहे हैं, जहां से एक प्रतिमा निकलती दिखाई दे रही है। खैर, इस फिल्म में ताजमहल पर क्या कहने की कोशिश हुई है, वह एक अलग मुद्दा है, लेकिन यह भी सच है कि इसी ताजमहल पर मुंबइया फिल्मकार और शायर-गीतकार जमकर प्यार लुटाते रहे हैं। यूं तो ताजमहल पर कई फिल्में बनीं और पसंद भी की गईं, लेकिन 60 के दशक में एम.सादिक की एक फिल्म आई थी 'ताजमहल', जिसके गाने भी खूब चर्चित हुए। इस फिल्म में मुमताज महल के रूप में अभिनेत्री बीना राय और शाहजहां के किरदार में अभिनेता प्रदीप कुमार खूब जंचे थे। यह फिल्म शाहजहां और मुमताज महल के प्यार की अमर दास्तान है।

गुलज़ार हुसैन

कॉमन रूम

दो शायरों की नज़र । शायरों-गीतकारों ने ताजमहल पर जो नज्म लिखे, वह भी खूब चर्चित हुए। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी ने ताजमहल पर बहुत ही खूबसूरत नज्में लिखी थीं, जो आज भी लोग गुनगुनाना पसंद करते हैं। साहिर ने ताजमहल को एक अलग नजरिए से देखते हुए लिखा था-'ये चमन-ज़ार ये जमुना का किनारा ये महल/ ये मुनक़्क़श दर-ओ-दीवार ये मेहराब ये ताक़/ एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर /हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मज़ाक़।' साहिर ने गरीब जनता की नज़र से ताजमहल बनाने वाले एक धनवान शहंशाह की शान-ओ-शौकत को देखा और उस पर तंज किया। उन्होंने सोचा था कि कोई गरीब मजदूर अगर अपनी प्रेमिका की याद में ऐसा महल नहीं बना सकता, तो इससे उसके दिल में प्यार कम तो नहीं हो जाता। वहीं, दूसरी तरफ शकील बदायुनी ने ताजमहल को मोहब्बत की निगाहों से देखते हुए कहा था-'एक शहंशाह ने बनवा के हसीं ताजमहल/ सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है।' शकील का यह गाना जब मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में रूपहले पर्दे पर आया, तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया। शकील ने जहां ताजमहल को मोहब्बत का प्रतीक माना, वहीं साहिर ने 'मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझ से' कहते हुए प्रेमिका से ताजमहल की चकाचौंध से कहीं दूर मिलने की बात की है।

संगमरमर का आकर्षण । मुंबइया फिल्मों की शूटिंग के लिए ताजमहल सबसे पसंदीदा जगहों में से एक रहा है। बहुत सारी फिल्मों के गानों या दृश्यों में ताजमहल जब प्रकट होता है, तो वह पल एक पेंटिंग की तरह खूबसूरत लगने लगता है। विदेश के चर्चित नेता हों या कलाकार, वे जब भी भारत आते हैं, तो एक बच्चे जैसी उत्सुकता के साथ ताजमहल के पास खड़े होकर तस्वीर खिंचवाते हैं। आजकल भले ताजमहल के अस्तित्व पर कुछ कट्टर समूह की ओर ये शंकालु दृष्टि डाली जा रही है, लेकिन क्या वे महाकवि रवींद्रनाथ टैगोर की कविता 'शाहजहां' की इन पंक्तियों को खारिज कर सकते हैं- 'बस बचा रहे/ एक बूंद नयन जल/ समय के चेहरे पर/ यह सफेद, चमकदार-ताजमहल।'

अंग्रेज़ी सिविल सर्विस यूं बनी भारतीय

सरदार वल्लभभाई पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है आजादी के बाद देश को एक सूत्र में बांधना। उन्होंने साढ़े पांच सौ से ज्यादा रियासतों को एक किया। इनमें से हर रियासत की अलग मांग, परिस्थिति और परेशानी थी। सरदार पटेल ने ताकत और कूटनीति के बेहतरीन तालमेल से इस असंभव से दिखने वाले काम को कर दिखाया। लेकिन, यही एक काम नहीं था, जो सरदार पटेल ने इस देश को मजबूत करने के लिए किया- उन्होंने सिविल सर्विस और जनगणना जैसे वे काम कराए, जिनसे देश अपने पैरों पर खड़ा हो सका।

सिविल सर्विस पर फैसला । भारत में सिविल सेवा की शुरुआत ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर में हुई थी। अंग्रेज इस सर्विस को अपने शासन का मजबूत ढांचा कहा करते थे। इसलिए जब भारत आजाद हुआ, तो कई लोग आजाद भारत में सिविल सर्विस को जारी रखने को लेकर संदेह में थे। सरदार पटेल 1947 के पहले बनी अंतरिम सरकार में भी गृह मंत्री थे। उसी समय से उन्होंने सिविल और पुलिस सर्विस पर काम करना शुरू कर दिया था। आजाद भारत में सिविल सर्विसेज का स्वरूप कैसा होगा, इसे लेकर उन्होंने अक्टूबर 1946 में प्रांतीय प्रधानमंत्रियों की एक बैठक बुलाई।

प्रशासनिक व्यवस्था । सरदार पटेल का मानना था कि पूरे भारत को एक साथ जोड़े रखने के लिए योग्यता आधारित अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा बहुत जरूरी है।

टाइम मशीन

उनकी पहल और दृढ़ इच्छा के कारण भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का गठन हुआ। यह ब्रिटिश शासन की ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस का नया भारतीय रूप था। सरदार पटेल ने नई सेवाओं के अधिकारियों से कहा था कि वे जनता की सेवा ईमानदारी और विनम्रता से करें। उन्होंने जिस सर्विस को आकार दिया, वह आज देश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है।

पहली जनगणना । सरदार पटेल ने पहली जनगणना की योजना बनाई और उद्देश्य साफ किया। अपनी मौत से केवल 10 महीने पहले, फरवरी 1950 में उन्होंने दिल्ली में जनगणना अधिकारियों की एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना देश की प्रशासनिक नीतियों को निर्धारित करने में अहम साबित होगी। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा था कि जनगणना सिर्फ आंकड़े गिनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज से जुड़ी अहम और वैज्ञानिक जानकारी जुटाने का माध्यम है। उन्होंने यह भी बताया कि इस जनगणना में खास ध्यान लोगों के रोजगार के साधनों और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा डेटा एकत्र करने पर दिया जाएगा। उनका कहना था कि जनगणना सरकार के लिए ऐसा मौका है, जब वह देश के हर घर तक पहुंच सकती है। कह सकते हैं कि इस तरह से सरदार पटेल ने 1951 में शुरू हुई देश की पहली राष्ट्रीय जनगणना के लिए दिशा तय की थी।

ताकतवर सेना । । सरदार पटेल का मानना था कि देश की मजबूती के लिए सेना मजबूत होनी चाहिए। 17 जनवरी 1948 को उन्होंने मुंबई के चौपाटी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में करीब एक लाख लोग मौजूद थे। इसमें सरदार पटेल ने कहा कि अगर भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में टिके रहना है, तो उसे मजबूत सेना की जरूरत है। लगभग एक घंटे के भाषण में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सशस्त्र शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक व्यावहारिक व्यक्ति होने के नाते जहां तक सैन्य ताकत की बात है, तो वह उनकी सलाह स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था, 'हमारी सेना को इतना ताकतवर होना चाहिए कि कोई शक्ति भारत में दखल देने के बारे में सोचे भी नहीं।'

जीवन की असली ज़रूरत को पहचानिए, तभी मिलेगी शांति

प्रेम रावत जी

जरूरत एक ऐसा शब्द है, जिससे हर कोई परिचित है। बिना जरूरत के जीवन का एक पल भी नहीं चल सकता। इसीलिए कहा गया है- आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पर समय के साथ जरूरतों का स्वरूप बदल गया है। कभी जरूरत भोजन, वस्त्र और आश्रय की थी, आज जरूरत बन गई है नया मोबाइल, नई कार, सोशल मीडिया पर पहचान और लगातार अपडेट रहना। मनुष्य की यह नई दौड़ थमने का नाम नहीं लेती।

हम अपनी जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था में उलझ कर रह गए हैं। यह भूल चुके हैं कि हम किसके लिए जिंदा हैं। हमारे भीतर सांस आती-जाती है, और इस सीमित समय के भीतर हमें अपनी असली जरूरत को पहचानना है। मछली को पानी की जरूरत होती है, पानी को मछली की नहीं। ठीक उसी तरह मनुष्य को शांति की जरूरत है, पर शांति को मनुष्य की नहीं। वह हमारे भीतर है, पर हम उसे बाहर खोजते रहते हैं- किसी नौकरी में, किसी रिश्ते में या लाइक और फॉलोअर की गिनती में।

आज जब दुनिया युद्धों, आर्थिक अस्थिरता और पर्यावरणीय संकटों से जूझ रही है, तब जरूरत की परिभाषा खुद में ही उलझी दिखाई देती है। एक तरफ लोग तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, तो दूसरी ओर मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलेपन के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यह विरोधाभास बताता है कि हमारी असली जरूरत कहीं नजर नहीं आती, जो भीतर की शांति है।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

शांति का मतलब यह नहीं कि युद्ध बंद हो जाए या कोई विवाद खत्म हो जाए। असली शांति वह है जो मन के भीतर ठहर जाए। जब हम अपनी आंतरिक जरूरत को समझ लेते हैं, तब जीवन का हर अनुभव बदल जाता है। जो शांति हम बाहर ढूंढते हैं, वह वास्तव में हमारे भीतर ही जन्म लेती है। अब सवाल यही है, क्या आपने अपने जीवन में उस शांति का अनुभव किया है? अगर नहीं, तो यह समय है रुकने का, सोचने का और खुद से मिलने का, क्योंकि आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है।

प्रस्तुति : आर.डी. अग्रवाल 'प्रेमी'

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

रीडर्स मेल

मुंबई-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर चले

भारतीय रेलवे लगातार प्रगति कर रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। इतना ही नहीं 100 किमी से अधिक की रफ्तार से दौड़ने वाली आधुनिक तकनीक से लैस वंदे भारत ट्रेनें भी यात्रियों को आकर्षित कर रही हैं। इसी के मद्देनजर मुंबई से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जानी चाहिए. जो राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में कम समय लेती हो।

– संजय आर खैर, ईमेल से

readersmail.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः(022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

THE HINDU

चलती सड़क दुर्घटनाओं से बुनियादी ढांचे और लाइसेंसिंग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। 3 नवंबर को हैदराबाद के पास चेवेल्ला में 19 लोगों की जान लेने वाला राजमार्ग हादसा भारत में घातक सड़क दुर्घटनाओं के शर्मनाक रिकॉर्ड को बदलने के लिए बहुत

टी सामान्य था। बजरी से लदे ट्रक के चालक ने जाहिर तौर पर एक गड्ढे से बचने के लिए अपना वाहन मोड़ा और एक बस से टकरा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 163 के उस हिस्से पर कोई डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट और साइनेज नहीं थे। भारत की सड़कें एक बड़ा सार्वजनिक खतरा हैं। भारत की सड़कों पर औसतन 400 से अधिक लोगों की मौत होती है, जिनमें पैदल यात्री, बस सवार और दोपहिया वाहन चालक शामिल हैं, जो एक पूरे अंतरमहाद्वीपीय विमान के गिरने के बराबर है। उड़ान आपदाओं के लिए जांच, बहु-एजेंसी जांच और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें, जिनमें ज्यादातर गरीब लोग शामिल होते हैं, औपचारिक जांच और नियमों में अचानक बदलाव, यदि कोई हो, को जन्म देती हैं। सरकारी दस्तावेजों में मानवीय भूल को सबसे आम कारण बताया गया है, लेकिन गहरे कारणों - वाहन और बुनियादी ढांचे से संबंधित - पर ध्यान नहीं दिया गया है।

भारत में, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सड़क परीक्षण यह जांचता है कि क्या व्यक्ति किसी विशेष विनिर्देश के वाहन को चलाने में सक्षम है, जो कि मोटे तौर पर एक कौशल परीक्षण है, न कि उसके ज्ञान और सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं के निष्पादन का। कोई सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है। अधिकांश दुर्घटनाएँ पीछे से टक्कर के कारण होती हैं - जबकि अन्य देशों में अनुकरणीय ड्राइविंग परीक्षण में पीछे से टक्कर मारने की प्रवृत्ति और मनमाने ढंग से लेन बदलने की संभावना को बाहर रखा जाता है। ड्राइवरों और वाहनों को प्रमाणित करने और निगरानी करने की प्रणाली टूटी हुई और भ्रष्ट है। लगभग सभी भारतीयों के लिए, आरटीओ को नेविगेट करना अप्रिय है। सेवलाइफ फाउंडेशन लाइसेंस सेवा केंद्रों की वकालत करता है - पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर - ताकि वे पारदर्शी, डिजिटल हों, और अच्छे ड्राइवर कौशल और सुरक्षा जागरूकता सुनिश्चित करें। आम तौर पर, राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों का पालन करना ज़रूरी होता है, लेकिन राज्यों ने मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कोई आदेश नहीं दिया है। गड्ढे, खतरनाक मोड़, जल निकासी प्रणालियाँ, पुलों के परकोटे और कंक्रीट की वस्तुएँ तो हैं, लेकिन कोई क्रैश बैरियर या ऊर्जा अवशोषक नहीं हैं।

टक्कर-जोखिम चेतावनी उपकरण अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और इन्हें व्यावसायिक वाहनों में अनिवार्य किया जा सकता है। बेहतर पैदल यात्री बुनियादी ढाँचा ही कई मौतों को रोक सकता है। हैदराबाद में, तत्काल उपचार के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध था और एक सरकारी अस्पताल भी पास ही था। लेकिन अन्य जगहों पर अक्सर ऐसा नहीं होता। बिहार जैसे राज्यों में, अपर्याप्त आघात देखभाल बुनियादी ढाँचे के कारण मृत्यु दर दोगुनी है। भारत में सड़क परिवहन प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन एक तत्काल आवश्यकता है।

असंतोष की सर्दी

अमेरिकी चुनाव परिणाम ट्रम्प प्रशासन की नीतियों पर एक जनमत संग्रह हैं

डी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिका में हुए पहले बड़े चुनाव में डेमोक्रेट्स ने भारी जीत हासिल की है, जो चल रहे संघीय सरकार के बंद से कुछ हद तक हताशा को दर्शाता है, लेकिन साथ ही उनके प्रशासन की नीतियों की अनुमोदन रेटिंग में व्यापक गिरावट का संकेत भी देता है। एक ऐतिहासिक चुनाव में, युगांडा में जन्मे, मुस्लिम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट न्यूयॉर्क राज्य प्रतिनिधि, ज़ोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा पर निर्णायक जीत हासिल की, और दस लाख से अधिक वोट हासिल किए - कुल मतदान का 50.4% - न्यूयॉर्क के मेयर का पद सुरक्षित करने के लिए। इसी तरह, डेमोक्रेट अबीगैल स्पैनबर्गर और मिकी शेरिल ने क्रमशः वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर पद की दौड़ जीती, कैलिफोर्निया में मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक गवर्नर गेविन न्यूसम के उस अभियान को मंजूरी दे दी है जिसमें राज्य के कांग्रेस मानचित्र को इस तरह से पुनर्निर्धारित किया गया है जिससे पार्टी को अमेरिका में पांच अतिरिक्त सीटें हासिल करने में मदद मिलेगी।

2026 के मध्यावधि चुनावों में प्रतिनिधि सभा के लिए। श्री ट्रम्प ने रिपब्लिकन पार्टी की हार के लिए इस तथ्य को ज़िम्मेदार ठहराया है कि वे मतपत्रों में नहीं थे और सरकारी बंद को, जिसके लिए उन्होंने बार-बार डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराया है। हालाँकि, अब तक का सबसे लंबा संघीय सरकारी बंद होना, अमेरिकी लोगों की भलाई के लिए कांग्रेस में एक समझौता करने के लिए सांसदों को एक साथ लाने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाता है।

जबकि इनमें से प्रत्येक परिणाम सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में मतदाता वरीयताओं की एक झलक प्रदान करता है, यह ट्रम्प प्रशासन की नीतियों पर एक व्यापक जनमत संग्रह के रूप में भी कार्य करता है, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था, नौकरियों और जीवन यापन की लागत के संबंध में। श्री ममदानी एक ऐसे मंच पर दौड़े जो आम अमेरिकियों के दिल के करीब के मुद्दों पर केंद्रित था - किफायती आवास, चाइल्डकैअर के लिए व्यापक पेशकश, आप्रवासी समुदायों के लिए अधिक समर्थन और मुफ्त सार्वजनिक परिवहन। श्री ट्रम्प ने अपने अभियान का जवाब श्री ममदानी के मेयर बनने पर संघीय फंडिंग में कटौती करने की कसम खाकर दिया। अपनी जीत के बाद, श्री ममदानी ने संघीय सरकार में श्री ट्रम्प के परिवार की भागीदारी पर निशाना साधा। वास्तव में, श्री ट्रम्प की अनुमोदन रेटिंग अपने दूसरे कार्यकाल के निम्नतम स्तर पर आ गई है सवाल यह है कि क्या वह अब MAGA एजेंडे पर दोगुना ज़ोर देंगे, उदाहरण के लिए, राज्यों के प्रतिरोध के बावजूद आव्रजन छापे और निर्वासन में तेज़ी लाकर, या अमेरिकी आयातकों द्वारा झेली जा रही लागत के बावजूद वैश्विक टैरिफ युद्ध को आगे बढ़ाते हुए। वह जो भी रास्ता चुनें, डेमोक्रेट्स ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दे दी है, और 2026 इस संदर्भ में मतदाताओं के मूड का एक और संकेतक होगा।

ब्राज़ील में COP30 और सच्चाई का क्षण

लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा

ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं

टी आज, ब्राज़ील के अमेज़न पर्वत पर, 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) से पहले बेलेम शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। COP से पहले के दिनों में विश्व के नेता यहाँ एकत्रित हुए ताकि हम सभी जलवायु संकट की माँग के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकें।

अगर हम भाषणों से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई करने में विफल रहे, तो हमारे समाज न केवल COPs में, बल्कि व्यापक रूप से बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विश्वास खो देंगे। इसीलिए मैंने नेताओं को अमेज़न में बुलाया है: इसे सत्य का COP बनाने के लिए; वह क्षण जब हम इस ग्रह के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की गंभीरता प्रदर्शित करते हैं।

मानवता ने एकजुट होकर और विज्ञान के मार्गदर्शन में कार्य करके बड़ी चुनौतियों से पार पाने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की है। हमने ओज़ोन परत की रक्षा की है। कोविड-19 महामारी के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया ने साबित कर दिया है कि साहस और राजनीतिक इच्छाशक्ति होने पर दुनिया निर्णायक रूप से कार्य कर सकती है।

ब्राज़ील की बात करें तो

ब्राज़ील ने 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। हमने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण की रोकथाम पर सम्मेलनों को मंज़ूरी दी और ऐसे सिद्धांतों को अपनाया जो हमारे ग्रह और मानवता के संरक्षण के लिए एक नए प्रतिमान को परिभाषित करते हैं। पिछले 33 वर्षों में, इन सम्मेलनों ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण समझौते और लक्ष्य निर्धारित किए हैं—2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को तीन गुना करने तक।

तीन दशक से भी ज़्यादा समय बाद, दुनिया जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए ब्राज़ील लौट आई है। यह कोई संयोग नहीं है कि COP30 अमेज़न वर्षावन के बीचों-बीच हो रहा है। यह राजनेताओं, राजनयिकों, वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के लिए अमेज़न की वास्तविकता को देखने का एक अवसर है।

हम चाहते हैं कि दुनिया को इसकी वास्तविक स्थिति का पता चले। जंगलों, ग्रह के सबसे बड़े नदी बेसिन और इस क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के लिए। सीओपी केवल अच्छे विचारों या

बेलेम की सेटिंग

अमेज़न में होने वाला शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेगा।

वार्ताकारों के लिए वार्षिक बैठकें। ये वास्तविकता से रूबरू होने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी कार्रवाई के क्षण होने चाहिए।

इस संकट का मिलकर सामना करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता है। और हमें यह स्वीकार करना होगा कि साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियों का सिद्धांत किसी भी जलवायु समझौते का अटूट आधार है।

यही कारण है कि वैश्विक दक्षिण अधिक मांग करता है संसाधनों तक पहुँच — दान से नहीं, बल्कि न्याय से। कार्बन-आधारित अर्थव्यवस्था से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमीर देशों को हुआ है। अब उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना होगा, न सिर्फ़ प्रतिबद्धताओं के ज़रिए, बल्कि अपने कर्ज़ों का भुगतान करके भी।

ब्राज़ील अपनी भूमिका निभा रहा है। सिर्फ़ दो सालों में, हमने अमेज़न में वनों की कटाई को आधा कर दिया है, जिससे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाई संभव है।

वनों के संरक्षण हेतु एक पहल, अन्य उपाय बेलेम में, हम वनों के संरक्षण हेतु एक अभिनव पहल शुरू करेंगे: ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट्स फ़ॉरएवर फैसिलिटी (TFFF)। यह अभिनव है क्योंकि यह एक निवेश कोष के रूप में कार्य करता है, न कि दान तंत्र के रूप में।

टीएफएफएफ उन लोगों को पुरस्कृत करेगा जो अपने जंगलों को बचाए रखेंगे और जो इस फंड में निवेश करेंगे; जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यह एक वास्तविक जीत वाला दृष्टिकोण है। उदाहरण के तौर पर, ब्राज़ील ने टीएफएफएफ में 1 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की है, और हम अन्य देशों से भी इसी तरह की महत्वाकांक्षी घोषणाओं की उम्मीद करते हैं।

हमने एक नया राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेश करने वाला दूसरा देश बनकर भी एक मिसाल कायम की है। ब्राज़ील ने सभी ग्रीनहाउस गैसों और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए अपने उत्सर्जन में 59% से 67% तक की कमी करने की प्रतिबद्धता जताई है।

इस भावना के साथ, हम सभी देशों से समान रूप से महत्वाकांक्षी एनडीसी प्रस्तुत करने और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का आह्वान करते हैं।

ऊर्जा परिवर्तन ब्राज़ील के एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। हमारा ऊर्जा मैट्रिक्स दुनिया के सबसे स्वच्छ ऊर्जा मैट्रिक्स में से एक है, जहाँ 88% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आती है। हम जैव ईंधन में अग्रणी हैं तथा पवन, सौर और हरित हाइड्रोजन ऊर्जा में आगे बढ़ रहे हैं।

तेल उत्पादन से प्राप्त राजस्व को एक न्यायसंगत, व्यवस्थित और समतापूर्ण ऊर्जा परिवर्तन के लिए पुनर्निर्देशित करना आवश्यक होगा। समय के साथ, ब्राज़ील की पेट्रोब्रास सहित दुनिया भर की तेल कंपनियाँ ऊर्जा कंपनियों में बदल जाएँगी, क्योंकि जीवाश्म ईंधन पर आधारित विकास मॉडल लंबे समय तक नहीं चल सकता।

जनता को राजनीति के केंद्र में होना चाहिए जलवायु और ऊर्जा परिवर्तन के बारे में निर्णय। हमें यह समझना होगा कि हमारे समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए न्यायसंगत परिवर्तन और अनुकूलन योजनाओं का लक्ष्य असमानता से निपटना होना चाहिए।

हम यह नहीं भूल सकते कि दो अरब लोगों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। स्वच्छ तकनीकों और खाना पकाने के लिए ईंधन तक पहुँच में कमी आई है, और 67.3 करोड़ लोग अभी भी भूख से जूझ रहे हैं। इसके जवाब में, हम बेलेम में 'भूख, गरीबी और जलवायु पर घोषणा' जारी करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की हमारी प्रतिबद्धता सीधे तौर पर भूख के खिलाफ लड़ाई से जुड़ी होनी चाहिए।

जलवायु परिवर्तन परिषद की आवश्यकता: वैश्विक शासन में सुधार को आगे बढ़ाना भी आवश्यक है। आज, बहुपक्षवाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निष्क्रियता से उत्पन्न हो रहा है। शांति बनाए रखने के लिए गठित, यह परिषद युद्धों को रोकने में विफल रही है। इसलिए, इस संस्था में सुधार के लिए प्रयास करना हमारा कर्तव्य है।

COP30 में, हम महासभा से जुड़ी एक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन परिषद के गठन की वकालत करेंगे। यह एक नई शासन संरचना होगी जिसमें यह सुनिश्चित करने की शक्ति और वैधता होगी कि देश अपने वादों को पूरा करें, और यह बहुपक्षीय व्यवस्था की वर्तमान निष्क्रियता को दूर करने की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा।

हर जलवायु सम्मेलन में, हम ढेरों वादे सुनते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबद्धताएँ बहुत कम देखते हैं। नेक इरादों की घोषणाओं का युग समाप्त हो गया है: कार्ययोजनाओं का समय आ गया है। इसीलिए, आज हम सत्य का COP शुरू कर रहे हैं।

मतदाता सूची को तत्काल साफ करें, लेकिन बिहार की तरह नहीं

प्रवीण चक्रवर्ती

अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं पेशेवरों कांग्रेस और डेटा का विश्लेषण कांग्रेस पार्टी

ए सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 40 करोड़ (400 मिलियन) वाहन पंजीकृत हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। देश भर में किसी भी दो वाहनों का पंजीकरण नंबर बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। इसी तरह, भारत में 20 करोड़ (20 करोड़) लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। किसी भी दो लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। हर नंबर अलग होता है।

एक ही व्यक्ति के पास कई ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं (यद्यपि अवैध), लेकिन प्रत्येक ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अद्वितीय होता है।

यह स्पष्ट और बुनियादी बात है कि हर वाहन का पंजीकरण या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या कोई भी पहचान पत्र अद्वितीय होता है, और दो रिकॉर्डों का एक ही नंबर नहीं हो सकता। फिर भी, भारत के चुनाव आयोग (ECI) की मतदाता सूचियों में इस सरल और बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन होता है। बंगाल के मतदाताओं के पास उत्तर प्रदेश के कुछ मतदाताओं के समान ही मतदाता पहचान पत्र संख्या है; यह पैटर्न कई राज्यों में दोहराया जाता है। लगभग दो दशक पहले, 2008 में, तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने दावा किया था कि ECI ने प्रत्येक मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) दिया है। जाहिर है, उन्हें यह नहीं पता था कि किसी भी पहचान प्रणाली का सबसे बुनियादी नियम यह है कि पहचान पत्र संख्या अद्वितीय हो और कई लोगों के लिए एक जैसी न हो।

चिंता की बात यह है कि यह और भी बदतर हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पंजीकृत मतदाता हैं, तो मैं फॉर्म-8 के ज़रिए आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर अपने नंबर में बदल सकता हूँ, बिना आपको पता चले। फिर, आपके वोटर आईडी कार्ड के लिए अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी का इस्तेमाल करके, मैं आपको मतदाता के रूप में हटाने के लिए आवेदन कर सकता हूँ। यह इतना आसान है। इसी तरह कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6,000 असली मतदाताओं को हटाने की कोशिश की गई थी - जिसका खुलासा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर, 2025 को किया था।

श्री गांधी के खुलासे के पाँच दिन बाद, उनके आरोपों का पुरज़ोर खंडन करने के बाद, चुनाव आयोग ने चुपचाप और गुप्त रूप से इस प्रक्रिया को बदल दिया और अब केवल आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। हालाँकि यह एक स्वागत योग्य और सकारात्मक बदलाव है, लेकिन आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का इतना महत्वपूर्ण कदम बिना किसी प्रेस विज्ञप्ति या चर्चा के उठाया गया।

यह भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली में गंभीर दोषों की स्पष्ट और अंतर्निहित स्वीकारोक्ति है, जिसका उपयोग चुनावी परिणामों में हेरफेर करने और उन्हें प्रभावित करने के लिए किया गया है।

यह भी स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है, जैसा कि श्री. 5 नवंबर, 2025 को गांधी ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत की मतदाता सूचियाँ नकली, फर्जी और छद्म मतदाताओं से भरी पड़ी हैं। विशिष्ट मतदाता पहचान-पत्र संख्याओं का अभाव, और किसी को भी मतदाता सूची बदलने की अनुमति।

यह स्वागत योग्य है कि चुनाव आयोग भारत गंभीर मुद्दों को स्वीकार करता है

भारत की मतदाता सूचियाँ, लेकिन इलाज का तरीका बीमारी से भी बदतर नहीं होना चाहिए

विवरण ऐसी बुनियादी प्रणालीगत त्रुटियाँ हैं जो डेटाबेस की बुनियादी जानकारी रखने वाला एक किशोर इंजीनियर भी नहीं कर सकता। यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग अपनी डेटाबेस प्रबंधन क्षमताओं में बेहद अक्षम है। यह चिंता का विषय है क्योंकि मतदाता सूची भारत का सबसे महत्वपूर्ण डेटाबेस है। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि भारत की मतदाता सूचियों को और अधिक सक्षम लोगों और प्रक्रियाओं द्वारा बेहतर ढंग से शुद्ध और प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

बिहार शैली की एसआईआर खराब है इस संदर्भ में, मतदाता सूचियों को शुद्ध करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विचार स्वागत योग्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की मतदाता सूचियों को साफ़-सुथरा बनाने की ज़रूरत है। लेकिन क्या यह काम उन्हीं अधिकारियों को सौंपा जा सकता है जिन्होंने इसे पहले ही गड़बड़ कर दिया था? मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से पक्षपाती और पक्षपाती है। इसलिए, चुनाव आयोग में मतदाता सूचियों को साफ़-सुथरा बनाने के लिए एक विशेष जांच रिपोर्ट (SIR) आयोजित करने हेतु अपनी प्रक्रियाएँ और नियम बनाने का विश्वास और क्षमता दोनों का अभाव है। एकमात्र विकल्प यह है कि चुनाव आयोग इस सफ़ाई अभियान को एक संयुक्त रचनात्मक अभ्यास के रूप में शुरू करे, जिसमें हर कदम पर सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी हो, न कि केवल आदेश और फ़रमान जारी करे।

पहली बात, बिहार-शैली की एसआईआर दूसरे राज्यों में इस प्रक्रिया को अंजाम देने का तरीका नहीं है। बिहार एसआईआर की मंशा दुर्भावनापूर्ण थी और इसे जल्दबाजी में इस झूठे बहाने से तैयार किया गया था कि असली मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएँ, जैसे कि अवैध प्रवासियों के नाम हटाने का बहाना बनाया गया हो।

दूसरा, आधार एक स्वच्छ मतदाता सूची के लिए मूलभूत और अभिन्न अंग है। आधार के उपयोग को लेकर चुनाव आयोग जानबूझकर भ्रम और भ्रम पैदा कर रहा है, यह दावा करते हुए कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है और इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, जो कि सच है। हर आधार धारक का मतदाता होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हर मतदाता के पास आधार होना ज़रूरी है। मतदाता सूची का आधार से जुड़ा डी-डुप्लीकेशन, डुप्लिकेट, नकली और फर्जी नामों को हटाने और यह सुनिश्चित करने का सबसे आधुनिक और सस्ता तरीका है कि हर मतदाता के पास केवल एक ही मतदाता पहचान पत्र हो जो अद्वितीय और गैर-हस्तांतरणीय हो। आधार और यहाँ तक कि डी-डुप्लीकेशन की आवश्यकता को बार-बार नकारकर, चुनाव आयोग खुद को या तो तकनीकी रूप से अज्ञानी या जानबूझकर द्वेषपूर्ण या दोनों ही दिखा रहा है।

तीसरा, हर घर जाकर और उचित दस्तावेज़ों के साथ मतदाताओं का पंजीकरण करके वास्तविक मतदाताओं का नामांकन किया जाना चाहिए, न कि मतदाताओं से ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने या किसी केंद्र से फॉर्म लेकर स्वयं पंजीकरण कराने के लिए कहा जाना चाहिए। चुनाव आयोग को मतदाताओं के पास जाना चाहिए, न कि मतदाताओं से उनके पास जाने के लिए कहना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बिहार में किया था।

जब तेलंगाना जैसा राज्य दो महीने में हर घर जाकर 3.5 करोड़ लोगों की पूरी जनगणना कर सकता है, तो चुनाव आयोग को भी ऐसा करना चाहिए और कर भी सकता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी वास्तविक मतदाता छूट न जाए। इसका यह भी अर्थ है कि चुनाव आयोग बिहार की तरह इस काम को एक महीने में पूरा नहीं कर सकता। स्वच्छ मतदाता सूचियाँ इतनी महत्वपूर्ण और बुनियादी हैं कि SIR को जल्दबाजी और घटिया तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता।

विपक्ष की बात सुनें राजनीतिक दल एसआईआर प्रक्रिया के अभिन्न अंग और महत्वपूर्ण कड़ी हैं। चुनाव आयोग विपक्षी दलों की शिकायतों और सुझावों के प्रति उदासीन रहने के लिए जाना जाता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला, जहाँ अक्टूबर 2024 में, मतदान से एक महीने पहले, सभी विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को एक संयुक्त पत्र लिखकर बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं के जुड़ने के स्पष्ट प्रमाण दिए। लेकिन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य चुनाव में कैसे 75 लाख नए और रहस्यमय वोट डाले गए। हैरानी की बात यह है कि भाजपा गठबंधन को विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के मुकाबले ठीक 75 लाख अधिक वोट मिले और उसे बहुमत हासिल हुआ। अगर चुनाव आयोग ने विपक्ष की शिकायत को अधिक गंभीरता से लिया होता, तो महाराष्ट्र को एक अलग मुख्यमंत्री मिल सकता था।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठकें ये एक तमाशा है जहाँ चुनाव आयोग पार्टियों की बात सुनने का दिखावा तो करता है, लेकिन फिर अपने नियम और प्रक्रियाएँ जारी कर देता है। एसआईआर प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जहाँ राजनीतिक दलों से हर स्तर पर और हर कदम पर सलाह ली जाए—राज्य की राजधानी में राज्य नेतृत्व से लेकर हर ज़िले और हर बूथ तक।

इन बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए तथा राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए सुझावों, शिकायतों और विचारों को स्पष्ट रूप से दस्तावेजित किया जाना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत मांग विपक्षी दलों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया के बाद फोटोयुक्त मतदाता सूची की अंतिम, समेकित और मशीन-पठनीय डिजिटल प्रति प्रकाशित करे। विपक्षी दलों और जनता का विश्वास फिर से जीतने के लिए चुनाव आयोग के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग एक दिन जाग गया और उसे मतदाता सूचियों को SIR (सटीक जांच) के ज़रिए साफ़ करने की ज़रूरत का एहसास हुआ। कांग्रेस पार्टी द्वारा महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद कर्नाटक के दो निर्वाचन क्षेत्रों और हरियाणा में स्पष्ट विसंगतियों को उजागर करने के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए भारत की मतदाता सूचियों में हेराफेरी की जा रही है। यह स्वागत योग्य है कि चुनाव आयोग देश की मतदाता सूचियों से जुड़ी गंभीर समस्याओं को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारना चाहता है। लेकिन इलाज बीमारी से भी बदतर नहीं होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को यह समझना चाहिए कि बिहार-शैली का SIR एक बुरा विचार है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

द टटर्सटूदएडिटर

एसआईआर दूसरा चरण: इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा की जा रही एसआईआर प्रक्रिया न केवल संविधान के विरुद्ध है, बल्कि एक गुप्त उद्देश्य से भी की जा रही है - बिहार में हुई प्रक्रिया इसका एक उदाहरण है। उच्च न्यायपालिका को मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के किसी भी प्रयास पर मूकदर्शक नहीं रहना चाहिए।

थार्सियस एस. फर्नांडो, चेन्नई

कई राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे संभावित मताधिकार हनन के आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता। यह ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि हमारे चुनावी लोकतंत्र की अखंडता बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से संचालित हो।

Salini Reghuraj,
Mambaram, Kannur, Kerala

भारत के चुनाव आयोग को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इसके प्रति जवाबदेह हो। मतदाताओं. सावधानीपूर्वक योजना और हर मतदाता को विश्वास में लेना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने कार्यों का बचाव कर सके।

चिराग जीवी,
शिवमोग्गा, कर्नाटक

हम बहुत पहले तैयार की गई मतदाता सूची से चिपके नहीं रह सकते। दरअसल, एसआईआर सिर्फ़ चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा और सही दिशा में पहला कदम है। इस विचार का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को यह जानकारी देनी चाहिए। चुनावों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए रचनात्मक विचार।

वी. लक्ष्मणन, तिरुप्पुर,
तमिलनाडु

बोर्डरूम की लड़ाइयाँ
प्राचीन कहावत
चाणक्य को जमशेदजी में आधुनिक अवतार मिला

टाटा का मानना था कि उद्योग का अस्तित्व केवल लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों की प्रगति के लिए होना चाहिए जिनसे वह जुड़ा है। टाटा का दर्शन ट्रस्टीशिप पूंजीवाद पर आधारित था - यह विचार कि उद्यम समाज को समृद्ध करने का ही नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाने का भी एक साधन है।

शेयरधारकों के लिए। टाटा की इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा परोपकारी ट्रस्टों के पास है। मुनाफे से भरे इस दौर में, टाटा के सामने पूंजीवाद को करुणा के साथ संतुलित करने की चुनौती है, जिससे उद्यम और इक्विटी दोनों की सेवा हो सके।

बोर्डरूम में बहस के बावजूद, यह विरासत बैलेंस शीट की प्राथमिकता पर हावी हो सकती है।

R. Narayanan, Navi
Mumbai

सुधार और स्पष्टीकरण

एक रिपोर्ट ('स्पोर्ट' पेज, 3 नवंबर, 2025), "टजेन ने बिरेल को हराकर अपना पहला डब्ल्यूटीए 250 खिताब जीता", में एक बार जेनिस टजेन को ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी बताया गया था। वह इंडोनेशियाई हैं, जैसा कि रिपोर्ट के बाकी हिस्सों में सही ढंग से बताया गया है।

पाठक संपादक की राय से टेलीफोन: +91-44-28576347/28576300; ई-मेल: readereditor@thehindu.co.in पर संपर्क किया जा सकता है।

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

राष्ट्रीय सहारा
पटना। बृहस्पतिवार • 6 नवंबर • 2025
www.rashtriyasahara.com

बुलडोजर पर प्रहार

उप्र के इलाहाबाद में बुलडोजर से घर ढहाने को सुप्रीम कोर्ट ने अमानवीय और अवैध करार देते हुए कहा कि इससे अदालत की आत्मा को झटका लगा है। उप्र सरकार को प्रत्येक परिवार को दस लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ अधिकारियों को उनकी अत्याचारिता के लिए सबक सिखाने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि इस देश में आश्रय का अधिकार, कानून की उचित प्रक्रिया और कानून का शासन जैसी कोई चीज है। आवासीय परिसरों को मनमाने तरीके से ध्वस्त करने पर विकास अधिकारियों को यह याद रखने को कहा कि आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21(जीवन व स्वतंत्रता) का अभिन्न अंग है। सभी छह याचिकाकर्ता इलाहाबाद के लूकरगंज के निवासी हैं जिनके घर मार्च, 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त किए गए थे। उनका कहना है कि स्थानीय अधिकारियों ने गलत धारणाओं के आधार पर घर गिराया कि वे माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की संपत्तियां हैं। शीर्ष अदालत ने अंबेडकरनगर जिले में बुलडोजर कार्रवाई का भी हवाला दिया। झोपड़ियों को ध्वस्त किए जाने पर कहा कि वह बहुत परेशान करने वाला और चौंकाने वाला है। उप्र सरकार के वकील ने दलील दी कि ये मकान अवैध थे इसलिए ध्वस्त किए गए। इनके साथ अन्य संपत्तियां भी ढहाई गईं। हैरत है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तोड़-फोड़ की इस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। राज्य सरकार का दावा था कि बुलडोजर कार्रवाई पेशेवर अपराधियों और माफिया के खिलाफ की गई। इस हकीकत के बावजूद सरकारी तंत्र को उचित नोटिस देने के साथ ही रहवासियों को कागजात दिखाने और मालिकाना साबित करने का वक्त देना चाहिए था। रही बात अवैध कब्जों की तो यह राज्य सरकारों का जिम्मा है कि वे निकाय और स्थानीय विकास अधिकारियों को इतने मुस्तैद बनाएं कि वे कब्जा पक्का करने से पूर्व ही हरकत में आएं। भू-माफिया और सरकारी मिली-भगत के बगैर कोई कब्जा संभव नहीं है। बुलडोजर चलाना समस्या का हल नहीं कहा जा सकता। सरकार को अपनी लापरवाहियों और गैर-जिम्मेदाराना रवैये से सबक लेना चाहिए। इस तरह की कार्रवाइयां बगैर सरकार के इशारे के अधिकारी नहीं कर सकते।

संबंधों में सुधार के संकेत

आजकल कूटनीतिक जगत में भारत-चीन संबंधों में सुधार को लेकर काफी चर्चा है। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुए घटनाक्रम के बाद पिछले वर्ष अक्टूबर में रूस में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। इस बैठक में दोनों शीर्ष नेताओं ने सीमा पर तनाव कम करने और द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर लाने का प्रयास किया था। विवाद के कुछ क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी जरूर हुई लेकिन अन्य मामलों में प्रगति नहीं हुई। इधर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के फैसलों से अमेरिका की घरेलू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नक्शा बदल रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनातनी बढ़ रही है तो दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जुगलबंदी आकार ले रही है। इस बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत और चीन ने कुछ लचीला रुख अपनाया है जिससे आशा बंधती है कि द्विपक्षीय संबंध पटरी पर आ सकते हैं। एक अप्रैल, 1950 को दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध हुआ था। मंगलवार को नई दिल्ली और बीजिंग के कूटनीतिक रिश्तों के 75 वर्ष पूरे होने पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच शुभकामनाओं और पारस्परिक रिश्तों को और बेहतर बनाने के संदेशों का आदान-प्रदान हुआ। राष्ट्रपति जिनपिंग ने भारतीय राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु को प्रेषित अपने संदेश में दोनों देशों के रिश्तों के द्योतक ड्रैगन और हाथी के बीच बेहतर तालमेल बनाने की बात की जबकि राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थाई, स्थिर और सौहार्दपूर्ण संबंध का फायदा नई दिल्ली और बीजिंग के अलावा पूरी दुनिया को मिलेगा।

अनमोल वचन

हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है।
-वाल्मीकि

शुभ संयोग में कार्तिक पूर्णिमा

पवन तिवारी

कार्तिक पूर्णिमा इस साल 5 नवंबर को है कार्तिक मास को सभी महीनों में बेहद शुभ व फलदायी माना गया है कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करने से इस पूरे महीने के गए पूजा-पाठ के बराबर फल मिलता है कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अतिप्रिय है।

5 नवंबर को भद्रावास योग समेत कई शुभ और दुर्लभ योग बन रहे हैं, इन शुभ संयोगों में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा-अर्चना करने से मनुष्य को मनोवांछित फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है।

कार्तिक मास में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसी तिथि पर भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। प्राचीन समय में जब जल प्रलय आया था, तब मत्स्य अवतार के रूप में भगवान ने पूरे संसार की रक्षा की थी। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया था, इस वजह से इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है इस कारण इसे देव दीपावली कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने की परंपरा है, साथ ही हवन, दान, जप, तप आदि धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। विष्णु पुराण के अनुसार, इस दिन भगवान नारायण ने मत्स्यावतार लिया था।

कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान, दीपदान, पूजा, आरती, हवन और दान-पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।

इस साल देव दीपावली पर सिद्धि योग बन रहा है। उस दिन सिद्धि योग प्रातःकाल से लेकर दिन में 11:28 मिनट तक है। देव दीपावली के दिन भद्रावास योग का दुर्लभ और शुभ संयोग भी बन रहा है। यह योग सुबह 8:44 मिनट तक रहेगा। इस दौरान भद्रा स्वर्ग लोक में रहेंगी, जिसे शास्त्रों में अत्यंत मंगलकारी माना गया है। जब भद्रा स्वर्ग या पाताल लोक में रहती हैं, तो पृथ्वी पर सुख-समृद्धि और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस योग में भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन से दुख और बाधाएं दूर होती हैं तथा सौभाग्य और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देव दीपावली के दिन शिववास योग का अत्यंत मंगलकारी संयोग बन रहा है, यह योग शाम 6 बजकर 48 मिनट से प्रारंभ होगा। इस विशेष योग में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिववास योग में की गई पूजा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। इस दिन नदी और तालाब में दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त हो जाते हैं और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्यद्वार पर आम के पत्तों से बनाया हुआ तोरण जरूर बांधे और दीपावली की ही तरह चारों ओर दीपक जलाएं।

तुलसी पूजन

कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम के साथ ही तुलसी जी की पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ और हवन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना का अनंत फल होता है। इस दिन तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं जिससे आपके मनोकामना पूरी हो और दरिद्रता दूर हो सके। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से दस यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपनी क्षमता अनुसार अन्न दान, वस्त्र दान और अन्य जो भी दान कर सकते हों वह जरूर करें इससे घर परिवार में धन-समृद्धि और बरकत बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा पर तिल जल में डालकर स्नान करने से शनि दोष समाप्त होंगे। खासकर शनि की साढ़ेसाती, वही कुंडली में पितृ दोष, चांडाल दोष की स्थिति यदि है तो उसमें भी शीघ्र लाभ होगा।

राशि अनुसार आपको किन चीजों का दान करना चाहिए

मेष-गड़
वृष- गर्म कपड़ों
मिथन-मूंग की दाल
कर्क-चावल
सिंह-गेहूं
कन्या-हरे रंग का चारा
तला भोजन
वृंश्चिक- गुड़ और चना
धन-गर्म खाने की चीजें, जैसे बाजरा,
मकर-कंबल
कुंभ-काली उड़द की दाल
मीन- हल्दी और बेसन की मिठाई

■ **संस्थापक अध्यक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान**

> कार्तिक मास में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था इसी तिथि पर भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था प्राचीन समय में जब जल प्रलय आया था, तब मत्स्य अवतार के रूप में भगवान ने पूरे संसार की रक्षा की थी कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इस तिथि पर शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया था, इस वजह से इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते है कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है इस कारण इसे देव दीपावली कहते हैं इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने की परंपरा है साथ ही हवन, दान, जप, तप आदि धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है विष्णु पुराण के अनुसार, इस दिन भगवान नारायण ने मत्स्यावतार लिया था ।

पूर्वाग्रह

डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

अपने दैनिक जीवन में गौर करें तो पाएंगे कि कई ऐसी समस्याएं हैं, जिनका सामना हम हर रोज कर रहे हैं पर भौतिक दृष्टि से उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पूर्वाग्रह उनमें से एक है। पूर्वाग्रह अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमारा दृष्टिकोण और उससे विकसित हुआ उसका आकार। इसे हम मनगढ़ंत मान्यता या व्यक्तिगत गलतफहमी भी कह सकते हैं। अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान दूसरे अध्याय में सांख्य ज्ञान और आत्मज्ञान की बातें विस्तार से समझाते हैं। किंतु अभी भी अर्जुन का मन पूर्वाग्रह मुक्त नहीं होता। पूछ बैठता है-'आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों झोंक रहे हैं।' वैसे तो सारी बातें स्पष्ट हो चुकी थीं, किंतु पूर्वाग्रह की मगरमच्छ जैसी पकड़ से छूटना इतना आसान नहीं है। आजकल यह नये परिवेश में हमारे सामने है। हम आधे-अधूरे अनुभव से ही लोगों को देखते हैं, और सबको उसी के अनुरूप प्रमाणपत्र देते रहते हैं। लोगों के व्यवहार का 'ब्ल्यूप्रिंट' हमारे दिमाग में तैयार रखते हैं। उसी तरह हम उस व्यक्ति के साथ व्यवहार भी करते हैं। अपने आसपास के लोगों को वैसे नहीं देखते हैं, जैसे वे हैं, लेकिन हमारे मन में जो छवि है, उसके अनुसार उन्हें देखते हैं। और जब तक हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ पूर्व निर्धारित छवि के माध्यम से व्यवहार करते हैं, तब तक छोटी-छोटी बातों में घर्षण होता रहता है। छोटे प्रश्न बड़े हो जाते हैं, और छोटी समस्याओं का स्वरूप बड़ा हो जाता है। इसका असर सेहत पर भी पड़ता है। चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि किसी-की पूर्वनिर्धारित छवि बनाना और उन पर लगातार चर्चा करना, एक ही बात बार-बार सोचना इत्यादि स्वभाव वाले व्यक्ति पर बीमारियां जल्द हावी हो जाती हैं। इसलिए महंत स्वामी महाराज समझाते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में या अपने परिवार के साथ व्यवहार में अपने नजरिए से हम जो धारणाएं बनाते हैं, और दावा करते हैं, 'जो मैं समझता हूं, वही सच है।' वे बातें या हमारी धारणाएं गलत हो सकती हैं। इस पर गंभीरता से सोचें, समुचित मूल्यांकन करें और फिर आगे बढ़ें। इससे आप पाएंगे कि व्यक्ति या वस्तु वैसी नहीं थी जैसा हम सोच रहे थे।

- आर्थिक विकास की तेज गति और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही भीषण गर्मी में बिजली की जबरदस्त जरूरत से वर्ष 2024 में भारत में कोयले की मांग इसके पिछले वर्ष के मुकाबले 5.5 फीसद बढ़ कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है
- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की 'वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2025' रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोयले से बिजली उत्पादन कुल कोयला खपत का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा रखता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयला अब भी दुनिया में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। अलबत्ता, बिजली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है

स्रोत : मीडिया इनपुट्स

400 एकड़ का जंगल विकास के नाम पर उजाड़ देना, प्रोटेस्ट करते हैदराबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को खदेड़ना, नैरेटिव की लड़ाई लड़ते-लड़ते जमीनी लड़ाई हार जाना है। बीजेपी की बुलडोजर संस्कृति का कांग्रेस संस्करण मुबारक।

सुजाता, लेखिका@Sujata1978

रीडर्स मेल

मखाना का कारगर विपणन जरूरी

मखाना आयरन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, जिंक, फाइबर सरीखे कई पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण सामान्य दिनों के साथ-साथ व्रतधारियों के लिए भी महत्त्वपूर्ण खाद्य वस्तु है। अहम बात यह भी है कि मखाना न केवल खाद्य वस्तु के रूप में देखी जाती है, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से मखाना भी बिहार की पहचान है। इसका सर्वाधिक उत्पादन भी बिहार में ही होता है। राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार के सहयोग के कारण मखाना के उत्पादन में और भी अधिक वृद्धि हुई है। इस कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी माग में काफी इजाफा हुआ है। सामान्य लोगों के लिए चिंता वाली बात यह हो जाती है कि उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होने के साथ मखाना की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। अन्य किसी भी ड्राई फ्रूट की अपेक्षा मखाना की कीमतों में बेहताशा वृद्धि हुई है। वर्तमान में स्थानीय मार्केट में यह बारह सौ रुपये किलो बिकती है, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होने के साथ-साथ मूल्य में अधिक वृद्धि न हो ताकि स्थानीय लोग भी क्षेत्रीय उत्पादन का भरपूर सेवन सहजता से कर सकें।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर

नेपाली अवाम की मनोकामना

कहते हैं कि आज की दुनिया में 'लोकतंत्र' वाली शासन पद्धति ही सर्वोत्कृष्ट है। विश्व में आधे से थोड़ा ही अधिक देश लोकतांत्रिक ढांचे के तहत आते हैं। उनमें भी कुछ देश तो महज चुनावी लोकतंत्र कहे जा सकते हैं। भारत का पड़ोसी नेपाल, जिसे दुनिया में एक तरह से भारत के अभिन्न राज्य के रूप में समझा एवं माना जाता है, में चुनावी शासन पद्धति का विरोध शुरू हो चुका है। वहां नवम्बर, 1990 में जन आंदोलन के बाद नया संविधान अपनाया गया और देश संवैधानिक राजतंत्र बन गया। लेकिन लोगों को लग रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई और विकास की मांग राजशाही के जरिए ही पूरी की जा सकती है। इसलिए उसके समर्थन में जनांदोलन जैसा माहौल इन दिनों चल रहा है। ऐसा इसलिए कि नेपाल राजनीतिक अस्थिरता का 'विश्व चैंपियन' बन गया है। छोटे से हिमालयी गणराज्य ने 15 वर्षों में अपना 14वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जो विशुद्ध रूप से लेन-देन वाली सार्वजनिक मामलों की संस्कृति को दर्शाता है।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

अभी भी भ्रम में पड़ी है कांग्रेस

कांग्रेस के लोग जनता को बता रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष को शक्ति दी जाएं। जिला अध्यक्ष की सिफारिश पर टिकट मिलें और उसे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का हिस्सा भी बनाया जाए। लेकिन इसमें एक महत्त्वपूर्ण सवाल है कि इस बदलाव के बाद जिला अध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे? राज्य के बड़े नेता अपने नजदीकियों को ही जिला अध्यक्ष बनाएंगे और राष्ट्रीय नेता अपना प्रदेशाध्यक्ष बैठाएंगे तो इस प्रक्रिया का कैसा फायदा? उससे भी महत्त्वपूर्ण बात, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को शक्ति नहीं मिली वहां जनता को मूर्ख बनाने के लिए ही ऐसी बातें हो सकती हैं।

मनोज श्रीवास्तव, सुलतानपुर
letter.editorsahara@gmail.com

बाल दिवस की प्रासंगिकता को संजोएं

राजेश मणि

आने वाले दिनों में जल्दी ही बाल दिवस मनाया जाने वाला है बाल दिवस की प्रासंगिकता बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने में है। यह दिन समाज को बच्चों के महत्व की याद दिलाता है, उन्हें राष्ट्र का भविष्य मानता है, और बाल श्रम, बाल दुर्व्यापार,बाल विवाह अत्याचार और शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है और उन्हें प्रेम, देखभाल और सुरक्षित माहौल प्रदान करने के सामाजिक दायित्व को भी रेखांकित करता

बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने में देश के सामने आने वाली चुनौतियां:

शिक्षा संबंधी असमानताएं: देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में काफी असमानताएं है, तथा कई बच्चों को अभी भी उचित स्कूली शिक्षा के अवसरों का अभाव है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

बाल श्रम: बाल श्रम एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिसमें कई बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बजाय काम करने के लिए मजबूर है।

बाल स्वास्थ्य: कुपोषण और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर रही है।

बाल अधिकार: बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनका समग्र कल्याण एक सतत चुनौती है, क्योंकि कई बच्चे शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील हैं।

डिजिटल विभाजन: डिजिटल युग में, डिजिटल विभाजन उन बच्चों के लिए आवश्यक ज्ञान और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न कर सकता है जिनके पास इंटरनेट या डिवाइस की सुविधा नहीं है।

बाल दिवस पर हमें अपने बच्चे को ये बातें सिखानी चाहिए:

बाल दिवस न केवल उत्सव का दिन है, बल्कि अपने बच्चे को जीवन के अनमोल सबक सिखाने का भी एक आदर्श अवसर है। इस उत्सव में शामिल हों और अपने नन्हे-मुन्नों के साथ अच्छा समय बिताएं, उन्हें जरूरी मूल्य और कौशल सिखाने पर विचार करें जो उनके भविष्य की मज़बूत नींव रखेंगे। बाल दिवस पर आप अपने बच्चे को कुछ ज़रूरी बातें सिखाये जिससे की हमारी संस्कृति सभ्यता परम्परा जीवंत रहे।

दयालुता और सहानुभूति: हमे अपने बच्चे को दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें लोगों की भावनाओं को समझने और उनका ख्याल रखने, और ज़रूरतमंदों की मदद करने का महत्व सिखाएं।

सम्मान : अपने बच्चे में सिर्फ़ बड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान की भावना पैदा करें। उन्हें विचारों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमि में अंतर का सम्मान करना सिखाएं।

कृतज्ञता : अपने बच्चे को जीवन की छोटी-छोटी चीज़ों की कद्र करने में मदद करें। उन्हें 'धन्यवाद' कहना और मिलने वाले प्यार और समर्थन के लिए आभारी होना सिखाएं।

आत्मविश्वास : अपने बच्चे का आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाएं। उन्हें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करें।

ज़िम्मेदारी : अपने बच्चे को अपने कामों और सामान की ज़िम्मेदारी लेना सिखाएं। इसमें अपने खिलौनों को व्यवस्थित रखना, अपना होमवर्क पूरा करना और अपने पालतू जानवरों की ज़िम्मेदारी लेना शामिल है।

स्वस्थ आदतें: बाल दिवस पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जैसी स्वस्थ आदतों के महत्व पर जोर देने का एक उत्कृष्ट अवसर है।

लचीलापन : अपने बच्चे को सिखाएं कि गलतियां करना और चुनौतियों का सामना करना ठीक है। उन्हें लचीलेपन का महत्व समझाएं और यह भी सिखाएं कि असफलताओं से कैसे उबरें।

रचनात्मकता : अपने बच्चे की रचनात्मकता को पोषित करें। उन्हें चित्रकारी, पेंटिंग और कहानी सुनाने जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपनी कलात्मक और कल्पनाशील क्षमताओं को निखारने के लिए प्रोत्साहित करें।

समस्या-समाधान : अपने बच्चे को समस्या-समाधान कौशल विकसित करने में मदद करें। उन्हें आलोचनात्मक रूप से सोचने और रोज़मर्रा की चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करें।

संचार : प्रभावी संचार एक महत्वपूर्ण कौशल है। अपने बच्चे को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरों की बात सुनना और सम्मानपूर्वक संवाद करना सिखाएं।

पर्यावरण जागरूकता: पर्यावरण और हमारे ग्रह की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। अपने बच्चे को रीसाइक्लिंग, अपशिष्ट कम करने और संसाधनों के संरक्षण के बारे में सिखाएं।

डिजिटल साक्षरता : डिजिटल युग में, अपने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा और तकनीक के ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करें। उन्हें सीखने और रचनात्मकता के लिए इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।

वित्तीय साक्षरता: जैसे-जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, उसे धन प्रबंधन की बुनियादी बातें सिखाएं। उसे बचत, बजट और समझदारी भरे वित्तीय फैसले लेने का महत्व सिखाएं।

सीखने का शौक: अपने बच्चे में सीखने का शौक पैदा करें। उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें और उन्हें अन्वेषण और खोज के अवसर प्रदान करें।

पारिवारिक मूल्य: पारिवारिक बंधनों और रिश्तों के महत्व पर ज़ोर दें। अपने बच्चे को उनकी विरासत, परंपराओं और प्रियजनों के साथ समय बिताने के महत्व के बारे में सिखाएं।

सरकार के साथ साथ स्वयसेवी संस्थाओं को भी बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए

जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन बाल विवाह को लेकर पूरे देश में सरकार और स्वय सेवी संस्थाओं के साथ बाल विवाह मुक्त भारत के लिए अभियान चला रहा है अभी हाल ही में दिन का कैंपेन की शुरूआत की है ये बाल दिवस का असली तोहफा है इस अभियान में बाल विवाह ,बाल श्रम ,बाल दुर्व्यापार से मुक्ति के लिए अलग अलग माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे है । जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन ने 2030 तक बाल विवाह मुक्त का संकल्प ले कर कार्य कर रहा है । बाल दिवस सिर्फ़ उपहार और उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि जीवन के ऐसे अनमोल सबक सिखाने का भी अवसर है जो हमे बच्चे के चरित्र और भविष्य को आकार देंगे। ये बहुमूल्य गुण और कौशल सिखाकर, हम अपने बच्चे को एक ज़िम्मेदार, दयालु और सक्षम व्यक्ति बनने के लिए सशक्त बनाते है।

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 20, अंक 6823 आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी संपादकीय

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

बिहार: मतदान का प्रथम चरण

बिहार में विधानसभा चुनावों के प्रथम चरण का आज मतदान है। इस चरण में कुल 121 सीटों के लिए मतदान होगा जबकि विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। शेष सीटों पर आगामी 11 नवम्बर को मतदान होगा। मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है अत: 121 सीटों पर खड़े एक हजार से अधिक प्रत्याशियों का भाग्य पौन चार करोड़ के लगभग मतदाता ईवीएम मशीनों में कैद कर देंगे। मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं इसका पता आगामी 14 नवम्बर को चलेगा जिस दिन मतगणना होगी। वैसे राज्य में असली मुकाबला सत्ताधारी राजग गठबन्धन व विपक्षी महागठबन्धन में हो रहा है और इन्हीं दो में से किसी एक को मतदाता चुनेंगे। वैसे मैदान में जन सुराज पार्टी व इत्तेहादे मुसलमीन भी हैं मगर इन्हें सिर्फ वोट काटू समझा जा रहा है।

राजग या एनडीए गठबन्धन में भारतीय जनता पार्टी व जनता दल(यू) मुख्य रूप से शामिल हैं। इनके अलावा कुछ छोटी – छोटी जातिगत पार्टियां भी हैं जबकि विपक्षी महागठबन्धन में श्री लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस के अलावा कई वामपंथी पार्टियां व जातिगत पार्टियां शामिल हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मुकाबला बहुत कांटे का है। मगर समझा जा रहा है कि इस बार मतदाता स्पष्ट रूप से किसी एक गठबन्धन के पक्ष में पलड़ा झुकायेंगे जिससे पिछले 2020 के चुनावों जैसा माहौल नहीं बन पायेगा। 2020 के चुनाव इतने अधिक कांटे के थे कि राजग गठबन्धन को पूरे बिहार में महागठबन्धन के मुकाबले केवल 12 हजार वोट ही अधिक मिले थे। इस बार राजनीतिक विशेषज्ञ इसमें बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं। एक सवाल जमीन पर यह भी तैर रहा है कि क्या इन चुनावों के बाद भी वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री नीतीश कुमार मुख्यमन्त्री बने रहेंगे। इस सवाल पर भी पूरे बिहार में संशय का वातावरण बना हुआ है क्योंकि विपक्षी महागठबन्धन ने पहले से ही इस पद के लिए राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता श्री तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा कर दी है जबकि राजग की ओर से इस मुद्दे पर भ्रम का वातावरण बना हुआ है। पिछले 20 साल से बिहार में कुछ समय को छोड़कर राजग का शासन चल रहा है। अत: विपक्षी महागठबन्धन की पूरी कोशिश है कि इस स्थिति में वर्तमान चुनावों में परिवर्तन आये। महागठबन्धन के सभी नेता राज्य में उपजी स्वाभाविक सत्ता विरोधी भावनाओं को अपने पक्ष में भुनाने की जी तोड़ कोशिश भी करते दिखाई दे रहे हैं जबकि राजग सत्ता समर्थक भावनाओं को संघीभूत करना चाहता है। बिहार के सजग मतदाता के लिए इस पहेली का उत्तर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर अभी तक के चुनाव प्रचार का जायजा लेने के बाद यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जमीन पर आम लोगों के मुद्दे ही प्रमुखता से तैर रहे हैं जो कि महंगाई, बेरोजगारी व पलायन के हैं। चुनावों में शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रश्न भी बहुत जोरदार तरीके से उठे हैं जो कि लोकतन्त्र के लिए शुभ संकेत माने जा सकते हैं। जाहिर है कि ये चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर ही हो रहे हैं और बिहार की जनता राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों में भेद करना अच्छी तरीके से जानती है। स्वतन्त्र भारत में समाजवाद की जननी रही बिहार की जमीन ने अपनी मिट्टी में खेलकर बड़े हुए कई राष्ट्रपुरुषों को जन्म दिया है जिनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर आदि शामिल हैं। मगर इसके विपरीत बिहार ऐसा राज्य भी माना जाता है जिसमें जातिगत आधार पर खूनी संघर्ष भी होते रहे हैं और विभिन्न जातियों के कथित नायक अपनी राजनीति भी लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर ही करते रहे हैं। इन कथित जातीय नायकों ने राजनीति का कबायलीकरण करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है जिसके फलस्वरूप लोकतान्त्रिक प्रशासन पद्धति के भी चीथड़े उड़ते हुए बिहार की जनता ने देखे हैं। मगर एक खूबसूरती इस राज्य की यह भी है कि यहां की जनता कभी धर्म के आधार पर गोलबन्द नहीं हुई है। इसकी वजह राज्य में कम्युनिस्टों से लेकर समाजवादी पार्टियों का बर्चस्व रहा है। 1962 तक बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही हुआ करती थी और 1967 में इसकी जगह समाजवादियों ने ले ली थी। हालत तो यहां तक थी कि राष्ट्रीय स्तर के समाजवादी नेता बिहार को सबसे सुरक्षित चुनाव स्थल मानते थे।

> एक सवाल जमीन पर यह भी तैर रहा है कि क्या इन चुनावों के बाद भी वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री नीतीश कुमार मुख्यमन्त्री बने रहेंगे। इस सवाल पर भी पूरे बिहार में संशय का वातावरण बना हुआ है क्योंकि विपक्षी महागठबन्धन ने पहले से ही इस पद के लिए राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता श्री तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा कर दी है जबकि राजग की ओर से इस मुद्दे पर भ्रम का वातावरण बना हुआ है। पिछले 20 साल से बिहार में कुछ समय को छोड़कर राजग का शासन चल रहा है। अत: विपक्षी महागठबन्धन की पूरी कोशिश है कि इस स्थिति में वर्तमान चुनावों में परिवर्तन आये।

स्व. मधु लिमये जैसे बड़े समाजवादी नेता जब संसद में जाने से महरूम रह गये थे तो उन्होंने सत्तर के दशक में बांका से ही उपचुनाव लड़ा था और वह लोकसभा पहुंच गये थे। इसी प्रकार स्व. जार्ज फर्नांडीज भी मुजफ्फरपुर से चुनाव जीता करते थे। जहां तक वर्तमान विधानसभा चुनावों का मामला है तो इन चुनावों के लिए सत्तारूढ़ व विपक्षी गठबन्धन दोनों ही सरल रास्ता अपना रहे हैं और मतदाताओं को फौरी लाभ पहुंचाने वाले वादों की भरमार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भरोसा दिला रहे हैं कि हुकूमत में आने के 22 महीनों के भीतर ही वह बिहार के हर परिवार के किसी एक योग्य या पात्र व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। वहीं भाजपा वादा कर रही है कि वह एक करोड़ नौकरियां व रोजगार के अवसर सुलभ करायेगी और बिहार की महिलाओं को करोड़पति दीदी बनायेगी। ऐसे कई और भी वादे हैं। मगर प्रथम चरण के मतदान से चुनाव आयोग की भी परीक्षा होगी। क्योंकि इसने बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं। मतदान वाले दिन मतदान केन्द्रों पर कैसा वातावरण रहता है उससे चुनाव आयोग के कृत्य का अन्दाजा हो जायेगा। विपक्ष ने चुनाव से पहले मतदाता सूची के संशोधन को भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था। कुल मिला कर बिहार की राजनीति में दोनों ही पक्ष प्रयोग कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि 14 नवम्बर को क्या परिणाम आयेंगे?

विध्वंस की दिशा...

"दुनिया के तमाम मुल्क हथियारों की दौड़ में
आगे बढ़ते जा रहे हैं,
और अहिंसा के मार्ग से खुद को दूर पा रहे हैं,,
सभी युद्धों के बल पर अपनी अपनी
ताकत का लोहा मनवा रहे हैं,
और बढ़ते परमाणु बम विश्व को विध्वंस की दिशा दिखा रहे हैं...।।"

गीता पाढा

मर्यादाएं
चन्द्रमोहन
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

भव्य त्रिमूर्ति, गांधी, नेहरू और पटेल

कृतज्ञ राष्ट्र ने सरदार बल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती एकता दिवस के तौर पर मनाई है। इस महान नेता ने 562 बड़ी-छोटी रियासतों, जिनका विभाजन से पहले के भारत के 40 प्रतिशत हिस्से पर शासन था, को भारत संघ के साथ मिलाया था। कई रियासत तो बहुत छोटी थीं पर समृद्ध हैदराबाद भी थी जो यूरोप के अधिकतर देशों से बढ़ी थी और जिसका तब बजट बेल्जियम के बराबर था, ऐसा करते वक्त उन्होंने साम-दाम-दंड-भेद सबका इस्तेमाल किया था। जॉन जुब्रज़ीकी जिन्होंने रियासतों के भारत में विलय पर किताब लिखी है, ने इसके लिए "पटेल के शक्तिशाली व्यक्तित्व, क्रोध के साथ सौम्यता और मिन्नत के साथ ज़बरदस्ती के मिश्रण" को ज़िम्मेवार ठहराया है। नेहरू और पटेल की सोच में अंतर था। जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी राजा महाराजाओं के प्रति अपनी तीव्र नफ़रत नहीं छिपाई थी, जबकि पटेल के कुछ प्रमुख राजाओं के साथ अच्छे संबंध थे पर जब हैदराबाद और जूनागढ़ के विलय का समय आया तो सरदार का रवैया बेरहम था। जूनागढ़ को तो ताक़त के दिखावे के साथ ही सीधा कर लिया गया पर हैदराबाद में भारतीय सेना भेज दी गई। निज़ाम को विलय करना पड़ा।

यह अफ़सोस की बात है किरदार को उनके योगदान के अनुरूप श्रेय बहुत देर से दिया गया। उन्हें भारत रत्न 1991 में दिया गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू को 1955 में और इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया गया था। पटेल को उनके देहांत को 41 वर्ष के बाद यह सम्मान दिया गया जिस साल राजीव गांधी और मोरारजी देसाई को भी दिया गया। इसका कारण है कि आज़ादी के बाद सत्ता नेहरू-गांधी परिवार के पास रही और उन्होंने छोटापन दिखाते हुए पटेल को पूर्ण सम्मान नहीं दिया, पर यहां भी कुछ विवाद खड़ा हो गया है। उन्हें श्रद्धांजलि देते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे पर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। दूसरी तरफ़ कांग्रेस अध्यक्ष मलिक्कार्जुन खरगे ने कटाक्ष किया कि सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर बैन लगाया था। गांधी जी की हत्या के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे पत्र में पटेल ने संघ की गतिविधियों के बारे चेतावनी दी थी और बताया था कि संघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने हत्या पर ख़ुशियां मनाई थीं। दोनों ही आंशिक तौर पर सही हैं, जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर का भारत में विलय नेहरू के कारण हुआ था पटेल की कश्मीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पटेल की जीवनी के लेखक राजमोहन गांधी बताते हैं, "वल्लभभाई निश्चित नहीं थे कि उन्हें कश्मीर चाहिए...आख़िर वह मुस्लिम बहुसंख्यक रियासत थी और श्रीनगर भारत की सीमा से 300 मील दूर था"। वी.पी. मेनन जो सरदार पटेल की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में सचिव थे के अनुसार जून 1947 में माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह को बताया था कि, "अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाता है तो भारत सरकार उसे अमित्रतापूर्ण कदम नहीं समझेगी"। यह माऊंटबेटन ने पटेल के हवाले से कहा था, जवाहरलाल नेहरू के हवाले से नहीं। नेहरू के लिए कश्मीर उनके पूर्वजों का प्रदेश था जिसे वह किसी हालत में खोना नहीं चाहते थे।

गांधी जी भी कश्मीर भारत में शामिल चाहते थे, पर पटेल का कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि "अगर शासक समझता है कि उनकी रियासत का हित पाकिस्तान में शामिल होने में है तो मैं रास्ते में खड़ा नहीं रहूंगा"।

सरदार पटेल का कश्मीर के बारे उदासीन रवैय सितंबर 1947 तक ही रहा था। उस दिन पाकिस्तान ने जूनागढ़ के विलय को स्वीकार कर लिया। तब पटेल पलट गए, अगर पाकिस्तान एक हिन्दू बहुसंख्यक रियासत जिसका शासक मुसलमान है को लेने की कोशिश कर सकता है तो भारत उस मुस्लिम रियासत को क्यों नहीं शामिल कर सकता जिसका शासक हिन्दू है? उस दिन के बाद जूनागढ़ और कश्मीर दोनों पटेल की प्राथमिकता बन गए। पटेल यूएन में कश्मीर मामलों को भेजने के खिलाफ थे और ज़मीनी कार्रवाई के पक्ष में थे, पर कश्मीर का मामला नेहरू के पास था इसलिए पटेल ने दखल नहीं दिया और वह उसे यूएन में ले गए जहां वह आजतक पड़ा है। एक तिहाई हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के पास है, जिसका ज़िक्र मोदी ने किया है। पर यह भी हक़ीक़त है कि शुरू में अगर नेहरू न अड़ जाते तो शायद पूरा कश्मीर पाकिस्तान में चला जाता।

जहां तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर बैन का सवाल है, 30 जनवरी, 1948 को गांधी जी की हत्या के कुछ सप्ताह के बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई। सरदार पटेल को रिपोर्ट मिली कि कई जगह संघ के कार्यकर्ताओं ने ख़ुशी मनाई थी। ऐसी रिपोर्ट मिलने पर पटेल का कहना था कि "वह ख़तरनाक गतिविधियों मे संलिप्त है" और बैन लगा दिया गया। पर दोनों नेहरू और पटेल के संघ के बारे नज़रिए में अंतर था। नेहरू बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे पर पटेल संघ को "पथभ्रष्ट, पर देश भक्त" समझते थे। नेहरू ने पटेल को बताया था कि उनके विचार में "गांधी की हत्या अकेली घटना नहीं थी। यह बड़े अभियान का हिस्सा थी जिसे आरएसएस ने आयोजित किया था"। पर पटेल का जवाब था कि, "यह सामने आ रहा है... कि आरएसएस इस मे बिल्कुल शामिल नहीं था"। पटेल का मानना था कि "यह हिन्दू महासभा के धर्मांध हिस्से का काम था"। 16 महीने के बाद यह बैन हटा लिया गया। बैन हटाने वाले भी गृहमंत्री सरदार पटेल थे।

'सरदार' का ख़िताब पटेल को आज़ादी से बहुत पहले दिया गया था। गुजरात के बारदोली के किसान सत्याग्रह में पहली बार उन्हें 'किसानों का सरदार' कहा गया था। उसके बाद से ही उन्हें सरदार कहा जाने लगा। महात्मा गांधी जी ने एक पत्र में लिखा था कि "कई लड़ाइयां लड़ने के लिए सरदार को लम्बी आयु मिले"। गांधी जी ने पटेल की बार बार प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि "आप का दिल शेर जैसा है"। एक पत्र में गांधी ने लिखा था, "मुझे इस बात का आभास है कि भगवान की मुझ पर कितनी कृपा है कि मुझे वल्लभभाई जैसे असाधारण व्यक्ति का साथ मिला है"।

दूसरी तरफ़ पटेल सदैव खुद को गांधी जी का सिपाही समझते रहे। राजमोहन गांधी लिखते हैं, "वल्लभभाई के लिए गांधी एक में तीन आदमी थे। उनके लिए गांधी संत, योद्धा और मार्गदर्शक थे जिनके पीछे वह चल सकते थे"। पटेल ने गांधी जी के बारे लिखा था, "उनके साथ रहकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि भारत की मुक्ति उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही हो सकती है"। स्वतंत्रता सेनानी के एम. मुंशी ने भी 1945 में लिखा था कि "सरदार की अपनी कोई इच्छा नहीं है। वह केवल गांधी की नीति की सफलता चाहते हैं। वह अपने लिए कोई श्रेय नहीं चाहते। वह केवल गांधी जी के औज़ार के तौर पर ही पहचान चाहते हैं"। आजकल देश में कुछ आवाज़ें उभर रही है, जो गांधी जी के योगदान को कम बताने की कोशिश कर रही है और कुछ तो उनकी अवमानना कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि आप एक तरफ़ सरदार पटेल की प्रशंसा और दूसरी तरफ़ गांधी जी की अवमानना नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक थे। इसी तरह आप पटेल और नेहरू को एक दूसरे का विरोधी नहीं कह सकते। कश्मीर, चीन, आरएसएस, रियासतों के विलय आदि को लेकर दोनों में मतभेद थे, और कई बार तीखे मतभेद थे पर दोनों ने इन्हें नियंत्रण में रखा था यह जानते हुए कि वह बड़े उद्देश्य, देश की आज़ादी, के लिए कामरेड है। दोनों में कैसी आत्मीयता थी वह गांधी हत्या के समय स्पष्ट हो गया था क्योंकि दोनों ने अपना सब कुछ खो दिया था। इतिहासकार उस क्षण कावर्णन इस प्रकार करते हैं "नेहरू वल्लभभाई से कुछ मिनटों के बाद वहां पहुंचे थे। गांधी के शव के पास बैठकर वह बच्चों की तरह रोने लगे। उसके बाद उन्होंने अपना शोकाकुल सर पटेल की गोद में रख दिया"। उस रात दोनों ने राष्ट्र को सम्बोधित किया। 3 फ़रवरी, 1948 को पटेल को प्रधानमंत्री नेहरू ने भावुक पत्र लिखा, "बापू की हत्या के बाद मैं समझता हूं कि यह मेरा कर्त्तव्य है, और आपका भी, कि हम इस संकट का दोस्त और साथी की तरह सामना करें"। इसका बराबर जवाब सरदार न दिया कि "आपके पत्र की गर्मजोशी और स्नेह मुझे छू गई है...हम दोनों एक संयुक्त उद्देश्य के लिए जीवनभर साथी रहें है..."।

इससे एक दिन पहले पटेल ने कांग्रेस पार्टी को सम्बोधित करते हुए सार्वजनिक तौर पर नेहरू को "माई लीडर" कहा था। ऐसी उदारता की मिसालें राजनीति में कम ही देखने को मिलती हैं, पर वह लोग अलग मिट्टी के बने थे। पटेल चाहते तो वह रंजिश पाल सकते थे कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन सके पर क्योंकि यह गांधी जी का फ़ैसला था इसलिए चुपचाप स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने पटेल के उपर नेहरू को क्यों तरजीह दी? मेरा समझना है कि गांधी जी को मालूम था कि सरदार की सेहत ठीक नहीं। जेल में भी उन्हें आंत्र की समस्या आई थी। गांधी देश की बागडोर जवान और स्वस्थ हाथों में सौंपना चाहते थे। लम्बी बीमारी के बाद आज़ादी के तीन वर्ष के बाद पटेल का देहांत भी हो गया था। गांधी जी का वध हो चुका था। देश की सारी ज़िम्मेवारी जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर आ गई। अगर देश भटका नहीं और भविष्य की सही नींव डाली गई तोबहुत श्रेय नेहरू को जाता है। ग़लतियां हुईं। जो काम करेगा वह गलती करेगा। हमें उनकी ग़लतियां नहीं उनकी देश के प्रति सेवा को याद रखना है। यह देश का सौभाग्य है कि आज़ादी दिलवाने और सम्भालने के समय हमारे पास यह भव्य त्रिमूर्ति थी। ऐसे लोग दोबारा नहीं आए।

सिख सियासत
सुदीप सिंह
newsreporter.2008@gmail.com

पीएम मोदी की सिख गुरुओं में आस्था

देश की आजादी के बाद देखा जाए तो नरेन्द्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी सिख गुरुओं में पूर्ण आस्था है और वह मानते हैं कि सिख गुरुओं के बलिदान के कारण ही देश की अस्तित्वता कायम है अगर 1675ई में गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देकर हिन्दु धर्म की रक्षा न की होती तो आज स्थिति कुछ और ही होनी थी। गुरु तेग बहादुर जी के बाद गुरु गोबिन्द सिंह जी ने मोर्चा संभाला और जुल्म के खिलाफ जंग लड़ते हुए अपने चारों पुत्रों को भी देश और धर्म की खातिर कुर्बान कर दिया। ऐसे महान गुरुओं की शहादत की कोई और मिसाल रहती दुनिया तक नहीं हो सकती।

इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की सत्ता पर काबिज होते ही सबसे पहले सिख धर्म के लोगों की परेशानियों को एक-एक करके दूर करने के निरन्तर प्रयास किए। सिख गुरुओं और साहिबजादों के बलिदान के इतिहास को देश के हर घर तक पहुंचाया। एक ओर वह लोग थे जिन्होंने अपने नाम से बाल दिवस मनाने की शुरूआत की थी और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने गुरु गोबिन्द सिंह जी के उन वीर साहिबाजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रुप में मनाकर देशवासियों को एक संदेश दिया ताकि भारत का हर बच्चा उन्हें अपना रोल माडल बना सके। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक साहिबजादों की शहादत की दास्तां बयान करते हुए बोर्ड लगाए गए। आज तक इतिहास में अत्याचारी मुगल शासकों का इतिहास स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता रहा मगर अब उसके स्थान पर गुरुओं की शहादत का इतिहास बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने गुरु गोबिद सिंह जी के जन्म स्थान तख्त पटना साहिब जाकर माथा टेककर गुरु महाराज का आर्शीवाद प्राप्त किया, यहां तक कि मनमोहन सिंह सिख प्रधानमंत्री होते हुए भी यहां नहीं गए और नरेन्द्र मोदी दूसरी बार नतमस्तक होकर आए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाद से देशभर से शायद ही ऐसा कोई भी राजनेता होगा जो पटना आगमन के बाद तख्त पटना साहिब नतमस्तक न हुआ हो। बुधवार को सुबह गुरु

नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा भी नतमस्तक होकर गुरु जी का आर्शीवाद प्राप्त किया गया।

दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी के स्थान गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जहां उनके धड़ का संस्कार किया गया था वहां भी वह माथा टेक चुके हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर लाल किला परिसर में होने वाले समागमों में आने के लिए वह स्वयं दिल्ली कमेटी से समय की जानकारी मांग रहे हैं।

सिख समुदाय देश के बंटवारे के बाद से निरन्तर अरदास में बिछुड़े गुरधामों के दर्शनों की अरदास करता आया इसी के चलते करतारपुर साहिब कोरीडोर खोला गया जिससे हजारों श्रद्धालुओं ने अभी तक उस पवित्र स्थान के दर्शन किए। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व सरकारी स्तर पर मनाया गया।

पाकिस्तान द्वारा हिन्दुओं का अपमान : पाकिस्तान की सदैव यह कोशिश रहती है कि किसी भी प्रकार से भारत में हिन्दु सिख एकता में दरार डाली जाए जिसके लिए पाकि एजेन्सियों के द्वारा खालिस्तानियों की मदद ली जाती है। पाकिस्तान द्वारा एक ओर खुद को सिखों का हमदर्द साबित करने की कोशिश करता है तो दूसरी ओर खालिस्तानियों को समर्थन देकर उनसे ऐसी गतिविधियां करवाई जाती हैं जिससे संसारभर में सिखों की बदनामी होती है। हाल ही में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने हेतु ननकाणा साहिब के दर्शनों के लिए गए जत्थे में से लगभग 14 हिंदू श्रद्धालु, जिनमें दिल्ली के आठ और अन्य लखनऊ के थे, उन्हें बेईज्जत करके वापस भेजकर दिया गया। हिंदू श्रद्धालुओं के अनुसार, पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें ननकाना साहिब जाने वाली बस में चढ़ने से ठीक पहले रोक लिया। उन्हें यह कहकर वापिस भेज दिया गया, "तुम हिंदू हो, तुम सिख जत्थे के साथ नहीं जा सकते"। इसके बाद उन्हें पैदल ही भारतीय सीमा की ओर लौटना पड़ा। भारतीय अधिकारियों ने इस घटना को "चौंकाने वाली और अभूतपूर्व भेदभावपूर्ण कार्रवाई" बताया है।

यह वह हिन्दु परिवार थे जो कि देश के बंटवारे के बाद से पाकिस्तान में ही रह रहे थे, मगर मुस्लिम कट्टरपंथियों के डर से यह 1999 में भारत आ बसे और 2008 में भारत में इन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल कर ली। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के तहत हर साल भारत से श्रद्धालुओं का जत्था ननकाणा साहिब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व मनाने हेतु जाया करता है जिसमें कई हिन्दु परिवार भी रहते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी के प्रति हिन्दु धर्म के लोगों में भी पूर्ण आस्था है और उनकी भी मंशा रहती है कि वह उस पवित्र धरती के दर्शन करें जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ मगर पाकिस्तान से इस प्रकार हिन्दुओं को जत्थे में से अलग कर उन्हें बेइज्जत कर वापिस भेजकर न सिर्फ उन हिन्दु परिवारों की आस्था का अपमान किया है बल्कि यह समुचे देश का अपमान है और इससे ज्ञात होता है कि पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है और वह भारतीयों में फूट डालने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता।

हरजिन्दर सिंह धामी 5वीं बार अध्यक्ष चुने गए : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव में एक बार फिर से हरजिन्दर सिंह धामी अध्यक्ष चुन लिए गए। उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय ही माना जा रहा था, क्योंकि अभी तक विपक्षी दल इतना मजबूत नहीं हो पाया कि वह शिरोमणि अकाली दल को टक्कर दे सके दूसरी ओर सुखबीर सिंह बादल को भी हरजिन्दर सिंह धामी से ज्यादा तर्जुबेदार, वफादार चेहरा पार्टी में कोई और नहीं मिल पाया जिस पर वह भरोसा रख पाते इसलिए हरजिन्दर सिंह धामी को पांचवीं बार अध्यक्ष बनने का मौका मिल गया। हरजिन्दर सिंह धामी के अध्यक्ष बनने से शिरोमणि कमेटी सदस्यों में भी प्रसन्नता देखी जा रही है। मुम्बई से शिरोमणी कमेटी सदस्य गुरिन्दर सिंह बावा जो कि चीफ खालसा दीवान महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं। उनका मानना है कि हरजिन्दर सिंह धामी जत्थेदार गुरचरण सिंह टोहड़ा के बाद ऐसे एकमात्र प्रधान साबित हुए हैं जिनके कार्यकाल को सदैव याद रखा जाएगा, क्योंकि कौम में जब भी कोई मुश्किल की स्थिति आई तो स. हरजिन्दर सिंह धामी के द्वारा सभी को एकजुट कर मुश्किल दूर की है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

पाकिस्तान में बेरोजगारी की मार: एक तिहाई युवा खाली हाथ

पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल जनगणना हुई और इसी आधार पर पता चल पाया कि यहां बेरोजगारी दर चरम पर है। 7.8 फीसदी युवाओं के पास नौकरी नहीं है यानि 24 करोड़ 15 लाख की आबादी वाले देश के करीब 1 करोड़ 87 लाख युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं।

पाकिस्तान ऑब्जर्वर नाम के अखबार ने देश की इस दुखती नब्ज को टटोला है। ये रिपोर्ट बेबस पाकिस्तानियों और बेपरवाह हुक्मरानों की पोल खोलती है। सिस्टम को लचर बताते हुए कहती है कि ये बेरोजगारी दर उन पाकिस्तानियों की फिक्र नहीं करती जो नीट (एनईईटी) हैं। नीट से मतलब पढ़ाई (एजुकेशन), रोजगार (एम्पलाईमेंट), और प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) से महरूम करना है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि बेरोजगारी का संकट जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा है। 15 से 35 साल की उम्र के एक-तिहाई पाकिस्तानी इस समय बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। प्रकाशित रिपोर्ट की माने तो 'वर्किंग एज पापुलेशन' यानी काम करने की उम्र वाली आबादी की संख्या भी कुछ कम नहीं है। 17.17 करोड़ लोग जो काम करने में सक्षम हैं उनमें से 11 फीसदी के पास कोई नौकरी नहीं है। आर्टिकल में कहा गया है कि 'नीट' ग्रुप में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने पूरी तरह से काम ढूंढना बंद कर दिया है, जो बिना वेतन वाले या असंगठित उपक्रमों से जुड़े हैं, या ऐसे फैमिली बिजनेस में फंसे हैं जिसकी उत्पादन क्षमता कुछ खास नहीं है। लेख में पाकिस्तानी महिलाओं की दयनीय स्थिति का भी विवरण है। रिपोर्ट के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर भी काफी कम है। 'नीट' की समस्या तो है ही, इसके साथ ही देश की आधी आबादी की कम भागीदारी दर ने परिस्थिति को और भी सोचनीय बना दिया है। ये घटती दरें साफ इशारा करती हैं कि लेबर फोर्स का कौशल अर्थव्यवस्था से कदम ताल नहीं कर पा रहा और इसी वजह से स्ट्रक्चरल बेरोजगारी (संरचनात्मक बेरोजगारी जिसमें नियोक्ता और रोजगार की तलाश कर रहे शख्स का कौशल मेल नहीं खा पाता) बढ़ रही है। इसका जिम्मेदार भी पाकिस्तानी शैक्षिक व्यवस्था को बताया गया है जो पुराने ढर्रे पर चल रहा है। छात्रों को मांग के

महिलाओं की स्थिति और खराब

हिसाब से कुशल नहीं बना पा रहा। व्यावसायिक प्रशिक्षण भी सीमित है, तो दूसरी ओर पढ़े-लिखे युवाओं का झुकाव सरकारी नौकरियों की ओर ज्यादा है। सरकारी नौकरी आबादी के लिहाज से बहुत कम हैं और इसमें कम्पटीशन भी तगड़ा है। कुछ को नौकरी मिलती है तो कइयों के हाथ खाली रह जाते हैं और इस तरह पढ़े-लिखे बेरोजगारों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। 2025 में बेरोजगारी दर बढ़कर करीब 8 प्रतिशत हो गई है, जिसमें कुल लेबर फोर्स 8 करोड़ 51 लाख 80 हजार और बेरोजगारों की संख्या 68 लाख 10 हजार है। रिपोर्ट कहती है कि रोजगार दर लगभग 52.2 प्रतिशत है, जो बताता है कि काम करने की उम्र वाली लगभग आधी आबादी या तो बेरोजगार है या अल्प-रोजगार (योग्यता के मुताबिक नौकरी न मिलना) की समस्या झेल रही है।

महंगाई, विदेशी मुद्रा संकट, 2022 और हाल ही में 2025 की बाढ़ के असर ने छोटे बिजनेस और लोकल जॉब मार्केट को तबाह कर दिया है। विश्व बैंक के आपदा-पश्चात आवश्यकता आकलन (पोस्ट-डिजास्टर नीड्स असेस्मेंट) में अरबों डॉलर के नुकसान और लाखों लोगों के दोबारा गरीबी में चले जाने की बात सामने आई। रिपोर्ट सोच समझ कर नीति बनाने की सलाह देती है और आगाह करती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये युवाओं और मुल्क को लंबे समय तक आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्टिकल बेरोजगारी से सिर्फ आर्थिक तौर पर नुकसान की बात नहीं करता बल्कि इससे उभरने वाली बड़ी समस्याओं की ओर भी इशारा करता है। बेरोजगारी की मार और पैसों की कमी के चक्कर में हाशिये पर पड़े युवा जबरन पलायन को मजबूर होते हैं, फिर अपराधी बन जाते हैं या चरमपंथी नेटवर्क का हिस्सा बन देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। निराशा और हताशा के रूप में दिखने वाला मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा और नुकसानदायक होता है। देश के कुछ पिछड़े इलाकों से युवाओं की तस्करी बंधुआ मजदूरी के लिए की जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है या सेक्स ट्रेड में धकेल दिया जाता है।

आईएएनएस

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

प्रवाह
77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

लोकतंत्र के खिलाफ सबसे अच्छा तर्क एक मतदाता के साथ पांच मिनट की बातचीत है। – विंस्टन चर्चिल

न्यूयॉर्क शहर के मेयर की चुनावी जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध के बावजूद डेमोक्रेट्स प्रत्याशी जोहरान ममदानी की जीत को एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। ट्रंप के लिए तो यह झटका है ही, चुनावी नतीजे अन्यथा भी कई सवाल उठाते हैं।

संकेत और सवाल

न्यूयॉर्क शहर के मेयर की चुनावी जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सार्वजनिक तौर पर विरोध जताने के बावजूद डेमोक्रेट्स प्रत्याशी जोहरान ममदानी की जीत महज चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत है। यह ट्रंप के लिए तो झटका खैर है ही, मतदान के नतीजे यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या शहर की विविधता भरी आबादी वाकई अब पारंपरिक राजनीति के सूत्रों से ऊब चुकी है, या फिर यह पहले से ध्रुवीकृत अमेरिका में एक अलग तरह के ध्रुवीकरण का प्रतीक है। ममदानी, जो खुद युगांडा में जन्में भारतीय मूल के मुस्लिम प्रवासी हैं, ने एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा को जिस ढंग से हराया, कम से कम उससे तो यही लगता है। चुनाव बोर्ड के अनुसार, बीस लाख से अधिक न्यूयॉर्कवासियों ने चुनाव में मतदान किया, जिससे यह 1969 के बाद से शहर में मेयर पद के लिए सबसे अधिक मतदान वाला चुनाव बन जाता है। न्यूयॉर्क शहर में करीब 48 फीसदी ईसाई और 11 फीसदी यहूदी हैं। यहां मुस्लिम भी नौ फीसदी हैं, जो अमेरिका में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है। कहा जाता है कि 9/11 के बाद के इस्लामोफोबिया की विरासत से यह शहर अब तक उबर नहीं सका है। यहां आज तक कोई मुस्लिम मेयर रहा भी नहीं। इसके बावजूद अगर ममदानी को जीत मिली है, तो यह केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि उनकी सुविचारित मुहिम की जीत अधिक लगती है। वह खुद को प्रगतिशील कहते हैं, और न्यूयॉर्क की युवा तथा अल्पसंख्यक आबादी ने उनके इस एजेंडे को हाथों हाथ लिया। अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने में उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान और समाजवादी लहजे का भी भरपूर सहारा लिया। न्यूयॉर्क में करीब 70 हजार बेघर लोग हैं। ऐसे में, सस्ती और आसान जिंदगी, मुफ्त सेवाओं और सामाजिक न्याय के वायदों ने लोगों को उनकी ओर झुकाया। उन्होंने अमेरिका के सबसे महंगे शहर में सामाजिक कार्यक्रमों का विस्तार करने का वादा किया, तो धनी और बड़ी कंपनियों पर कर लगाकर अपने प्रस्तावों के लिए पैसे जुटाने की उनकी योजना ने उन्हें शहर के अरबपतियों के बीच बेहद अलोकप्रिय बना दिया। इसमें संदेह नहीं कि ट्रंप प्रशासन उनके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। ऐसे में, सवाल उठता है कि ममदानी अपनी महत्वाकांक्षी मुफ्त योजनाओं के लिए पैसा कहां से लाएंगे। अमेरिका के सबसे बड़े शहर के स्थानीय निकाय का चुनाव कुछ ऐसा हो गया था कि पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी थीं। लिहाजा एक मेयर के तौर पर ममदानी की राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि उनकी कामयाबियां और नाकामयाबियां भी उतनी ही बारीकी से परखी जाएंगी।

यह जीत क्या कहती है

न्यूयॉर्क के चुनाव, जिन पर पूरी दुनिया की नजर थी, में पहले भारतीय-अफ्रीकी और मुस्लिम, जोहरान क्वामे ममदानी की जीत महज प्रतीकात्मकता से कहीं ज्यादा है। शहर की आबादी में रहने वालों का विभाजन ऐसा है कि उनकी यह जीत कुछ अलग कहती प्रतीत होती है।

न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में पहले भारतीय-अफ्रीकी व मुस्लिम, जोहरान क्वामे ममदानी का चुनाव दोहरे संकेतों तथा कई संदेशों के साथ आया है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा उनके 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' अभियान के लिए भी एक गंभीर झटका है। लेकिन इसके साथ ही, वैश्विक पूंजीवाद के 'ग्राउंड जीरो' क्षेत्र में इस स्वघोषित समाजवादी लोकतांत्रिक युवा की जीत, अमेरिका को एक समावेशी राष्ट्र के रूप में राजनीतिक रूप से मजबूत भी करती है। हालांकि, उनकी जीत महज प्रतीकात्मकता से कहीं ज्यादा है, क्योंकि दुनिया अमेरिका के वैश्विक उत्पात पर भी ध्यान दे रही है, जिसमें वह सुदूर देशों के खिलाफ सैन्य धमकियों, व्यापार व टैरिफ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है।

महेंद्र वेद
वरिष्ठ पत्रकार

लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को चुनौती देते इन चुनावों के बाद ध्रुवीकृत अमेरिका और भी अधिक ध्रुवीकृत होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर अपनी विजयी वापसी के पहले दस महीनों में ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने प्रतिद्वंद्वियों से मिली पहली गंभीर चुनौती में नाकाम रहे हैं, जिन्होंने न्यू जर्सी और वर्जीनिया में भी गवर्नर पदों के चुनाव जीते हैं। ट्रंप और उनकी पार्टी ने देश की अर्थव्यवस्था के लंबे समय से बंद रहने को इसका जिम्मेदार बताया है, जिसकी वजह से उनका प्रशासन न तो खर्च कर सकता है और न ही अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी नतीजे जनता के असंतोष को ही दर्शाते हैं।

34 वर्ष की उम्र में न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर बनने जा रहे ममदानी के साथ उनका मुकाबला पीढ़ीगत और वैचारिक, दोनों था। ट्रंप ने उन्हें 'कुछ हद तक कम्युनिस्ट' कहा और न्यूयॉर्क के सभी मतदाताओं को चेतावनी भी दी थी कि अगर ममदानी जीते, तो वह शहर के लिए धन रोक सकते हैं। मतदान के दिन, उन्होंने घोटालों में फंसे न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो का आधिकारिक रूप से समर्थन करके रिपब्लिकन पार्टी के अपने उम्मीदवार की बलि चढ़ा दी। मतदाताओं से स्लिवा पर वोट बर्बाद न करने का आग्रह करते हुए, उन्होंने कुओमो को तरजीह दी, जो एक डेमोक्रेट हैं और पार्टी प्राइमरी में ममदानी से हार चुके हैं। वह शायद ममदानी के वोट काटने के लिए, एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरे थे। ममदानी पर अपशब्दों की बौछार की गई। अरबपति एलन मस्क ने उन्हें 'ममदुमी या जो भी उनका नाम हो' कहकर मजाक उड़ाया। लेकिन, ममदानी, जो एक वर्ष पहले तक एक अनजान राज्य विधानसभा सदस्य थे, ने एक जोशीला अभियान चलाया, जिसमें बॉलीवुड के संवादों का इस्तेमाल, तो शाहरुख खान की शैली में बाहें फैलाकर अपील की गई। उन्होंने न्यूयॉर्क के एक मजदूर वर्ग के बड़े हिस्से व प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए स्पेनिश, अरबी, बंगाली, उर्दू, स्वाहिली व दूसरी भाषाओं का भरपूर इस्तेमाल किया। यहूदी विरोधी रुख के बावजूद हिस्पैनिक, लैटिनो और यहां तक कि गरीब यहूदियों ने भी उन्हें वोट दिया।

उन्होंने न्यूयॉर्क की सड़कों, मॉल और ड्राइव-वे पर घूम-घूमकर सभी वर्गों के लोगों से समर्थन मांगा। उन्होंने चुनाव प्रचार में सबसे आगे रहते हुए सिर्फ एक कार्डबोर्ड प्लेकार्ड, जिस पर लिखा था 'आइए, चुनाव पर चर्चा करें' और हाथ में माइक लेकर, भीड़ को संबोधित करते हुए, उनका उत्साह बढ़ाते हुए, अपनी जीत की मुस्कान बिखेरी। उनके प्रतिद्वंद्वी उनकी विजयी मुस्कान के आगे थके हुए लग रहे थे और सिर्फ अपने अनुभव के नाम पर उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे भूल गए कि ममदानी एक हाउसिंग काउंसलर की तरह गरीबों को किफायती आवास दिलाने में मदद कर रहे थे। दुनिया की आर्थिक राजधानी में, जहां अरबपति रहते हैं, ममदानी ने उन लोगों का एक बड़ा समूह तैयार किया, जो अमीर नहीं हैं। न्यूयॉर्क, जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर होने के साथ ज्ञान और बेहतर जीवन के आकांक्षी लोगों को आकर्षित करता है, का यह चुनाव एक वैश्विक घटना की तरह हो गया था। ममदानी की उपस्थिति ने एशिया और अफ्रीका (उनके भारतीय/युगांडाई वंश), मुस्लिम जगत तथा उन सभी लोगों को आकर्षित किया, जो ट्रंप के दुनिया पर हावी होने के तरीकों से परेशान थे। इस दौरान सोशल मीडिया पर अभूतपूर्व ढंग से विभाजनकारी बहसें चलीं, मानों धर्मयुद्ध का युग लौट आया हो।

ममदानी का समर्थन और विरोध, दोनों ही ध्रुवीकरण कर रहे थे। जो लोग समर्थन कर रहे थे, वे इस्लामोफोबिया का विरोध कर रहे थे और इसे यथास्थिति के खिलाफ विद्रोह बता रहे थे। साथ ही, जो लोग विरोध में थे, वे चाहते थे कि हर मुसलमान पश्चिम छोड़ दे और 'जहां से आया है, वहीं लौट जाए।' रूढ़िवादी अमेरिकियों के लिए, न्यूयॉर्क, लंदन, जो कि एक और विश्व राजधानी है, के नक्शेकदम पर चल रहा था, जहां एक मुसलमान सादिक खान है, जिसे ट्रंप नापसंद करते हैं।

न्यूयॉर्क को अमेरिका के अमीरों का घर कहा जाता है, जहां माना जाता है कि 3,50,000 करोड़पति रहते हैं, के लिए चुनावों के रुझान डरावने थे। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, कम से कम 26 अरबपतियों ने ममदानी को रोकने की कोशिश में 2.2 करोड़ डॉलर से ज्यादा खर्च कर दिए। इनमें दो ऐसे भी थे, जिन्होंने पहले उनका समर्थन किया था, लेकिन बाद में पाला बदल लिया। माइक ब्लूमबर्ग ने कुओमो का समर्थन करने वाले एक समूह को 15 लाख डॉलर का और दान दिया। हालांकि, अपनी सभी कथित राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बावजूद, वह अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वह अमेरिकी मूल के नहीं हैं।

न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे बड़े शहरी समूहों में से एक है और अमेरिका के बाहर जन्मे 32 लाख से अधिक निवासियों का घर है, जो 2016 तक दुनिया के किसी भी शहर की सबसे बड़ी विदेशी मूल की आबादी है। 65 लाख की आबादी के साथ, वे कुल अमेरिकी आबादी का 1.95 फीसदी (2023 के आंकड़े) हैं। अमेरिकी जनगणना के अनुसार, 2000 और 2018 के बीच, भारतीय-अमेरिकी आबादी में लगभग 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2015 में उनकी औसत आय एक लाख डॉलर थी। इस बढ़ती वास्तविकता के साथ, आने वाले वर्षों में अमेरिका के सार्वजनिक जीवन में दक्षिण एशियाई लोगों की भागीदारी बढ़ना तय है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

आर्थर शोपेनहावर

एपिक्टेटस कहते हैं कि इन्सान वस्तुओं से नहीं, बल्कि उनके बारे में अपने विचारों से प्रभावित होते हैं। खुद से मिलने वाली खुशी बाहरी चीजों से मिलने वाले सुखद अनुभव से कहीं अधिक मूल्यवान होती है।

मनुष्य अपने विचारों से प्रभावित होता है

एक बार मैंने एक पुरानी किताब खोली और उसमें लिखा देखा कि यदि आप खूब हंसते हैं, तो आप बेहद खुश हैं, अगर खूब रोते हैं, तो दुखी। यह सुनने में जितना साधारण लगता है, उतना ही जीवन बदल देने वाला संदेश है। इसे मैं कभी नहीं भूल पाया। सच्चाई यही है कि खुशी केवल एक पल में अनुभव की जाने वाली भावना है, जिसे आप जितनी जल्दी और पूरी तरह स्वीकार करेंगे, उतना ही जीवन में उसका वास्तविक लाभ मिलेगा। खुशी हमेशा सही वक्त पर ही आती है, आप चाहे जितना हाथ-पैर मार लें। अक्सर कई लोग तो इसे इस डर से दिखाने से बचते भी हैं कि कहीं यह गंभीर चिंतन या जिम्मेदारियों के निर्वहन में बाधा न डाल दे। जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। प्रसन्नता तात्कालिक और वास्तविक अनुभव देती है-जैसे कोई मनचाही चीज अचानक आपके पास आ जाए। इसलिए, इसे सहजता से स्वीकार करना ही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।

खुशी का मूल आधार आत्मा और स्वास्थ्य, दोनों हैं। हालांकि, इसके लिए आपको यह देखना होगा कि जब आप स्वस्थ और ताकतवर होते हैं, तो बाहरी परिस्थितियों या घटनाओं का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब आप अस्वस्थ, उदास और परेशान होते हैं, तो उनका क्या असर होता है। आप महसूस करेंगे कि चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से मजबूत होने पर कठिन परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी, वहीं अस्वस्थ होने पर वही हालात आपको परेशान कर देंगे।

सुख आत्मिक लगाव से भी जुड़ा है। जब आप आत्मीय रूप से ऐसे रिश्ते बनाते हैं, जिनके प्रति आप संवेदनशील हो सकते हैं, जिनसे बात करके आप हंस सकते हैं, रो सकते हैं, और बेबाकी से खुद को व्यक्त कर सकते हैं, तभी आपकी आत्मा फलती-फूलती है, न कि भौतिक वस्तुओं से। जैसा कि एपिक्टेटस कहते हैं कि इन्सान वस्तुओं से नहीं, बल्कि उनके बारे में अपने विचारों से प्रभावित होता है। आत्मीय खुशी बाहरी चीजों से मिलने वाले सुखद अनुभव से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच और नजरिया ही तय करता है कि आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं।

खुशी का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। स्वास्थ्य के बिना शोहरत, पैसा, तरक्की, शिक्षा जैसे जीवन के अन्य सुख, फीके और अधूरे लगते हैं। यही कारण है कि जब दो लोग मिलते हैं, तो वे सबसे पहले एक-दूसरे का हालचाल पूछते हैं, क्योंकि यही मानव सुख का मूल तत्व है। भौतिक सुखों के लिए अपने स्वास्थ्य से समझौता करना सबसे बड़ी मूर्खता है। स्वास्थ्य ही खुशी, शक्ति और जीवन की असली संपत्ति है। इसलिए, हर दिन कसरत, ध्यान व सही जीवनशैली को प्राथमिकता दें, क्योंकि स्वस्थ शरीर और संतुलित मन ही सपनों को साकार करने की शक्ति देते हैं।

सेहत पर ध्यान दें

सूत्र

जीवन में सफलता, खुशी और उपलब्धियों की सारी संभावनाएं तभी पूरी होती हैं, जब हमारी सेहत ठीक हो। आप किसी भी लक्ष्य के प्रति कितने भी समर्पित क्यों न हों, यदि शरीर और मन स्वस्थ नहीं हैं, तो जीवन में सच्ची संतुष्टि और आनंद प्राप्त करना असंभव है। अच्छा स्वास्थ्य ही मानव खुशी का सबसे बड़ा आधार है।

दूसरा पहलू

जोहरान क्वामे ममदानी का नाम उनकी जड़ों की ओर इशारा नहीं करता। उनके पिता मुस्लिम हैं, तो मां पंजाबी हिंदू।

आखिर नाम में क्या रखा है

■ डॉ. सुधीर सक्सेना

शेक्सपियर भले ही कहते हों कि नाम में क्या धरा है, लेकिन नाम बहुत कुछ कहता है। उनका पूरा नाम है जोहरान क्वामे ममदानी, लेकिन यह उनकी जड़ों की ओर भी संकेत नहीं करता। वह गुजरात के शिया-मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी रगों में मिश्रित रक्त बह रहा है। पिता मुस्लिम हैं, तो मां पंजाबी हिंदू। उनके पिता महमूद ममदानी शिक्षाविद हैं, जो गुजरात से अफ्रीका चले गए थे। उनकी मां मीरा नायर सिने-संसार की जानी-मानी हस्ती हैं और *मिसीसिपी मसाला, द नेमसेक, मानसून वेडिंग* और *सलाम बॉम्बे* जैसी चर्चित फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। पद्मभूषण से सम्मानित 67 वर्षीया मीरा ने 1991 में महमूद ममदानी से दूसरी शादी की। 18 अक्तूबर, 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में जन्में जोहरान इसी युगल की संतान हैं। बाल्यावस्था दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद सात साल की उम्र में वह अमेरिका में आकर न्यूयॉर्क में बस गए। ब्रोंक्स हाईस्कूल ऑफ साइंस से स्नातक करने के बाद उन्होंने बोडोइन कॉलेज से अफ्रीकन स्टडीज में डिग्री हासिल की। राजनीति में पदार्पण के पूर्व वह हाउसिंग काउंसलर रहे और हिप-हॉप संगीतकार के रूप में सक्रिय रहे। वह पहले-पहल वर्ष 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए। गत वर्ष उन्होंने साल 2025 के महापौर के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। जोहरान के पूरे नाम पर गौर करें। जोहरान क्वामे ममदानी। नाम और कुल नाम का मध्यवर्ती क्वामे उनके पिता की देन है। क्वामे एनक्रूमा घाना के राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री थे और उन्हें पैन-अफ्रीकी नेता और अश्वेत मुक्ति के महानायक के तौर पर देखा जाता है। वह अफ्रीका के लेनिन कहलाए और साल 1963 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया। बहरहाल, ममदानी न्यूयार्क के मेयर पद के चुनाव की रेस में उलटफेर करने में सफल रहे हैं। उनकी उम्र ज्यादा नहीं है। महज चौंतीस वर्ष। वह साफगो हैं और ऊर्जा से लबरेज हैं। उन्हें अपने मुसलमान होने पर फख्र है और वह इस्राइल के मुखर आलोचक हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र में एस्टोरिया भी है, जहां मुस्लिमों और अरबों की अच्छी-खासी तादाद है। वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रीतियों-नीतियों के विरोधी हैं। गुजरात के सांप्रदायिक घटनाक्रम पर उनकी तीखी टिप्पणी ने सनसनी फैला दी थी। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना करते हुए यहां तक कहा है कि वह उन्हें मैडिसन स्क्वायर में सभा नहीं करने देंगे। किस्सा-कोताह यह कि जोहरान क्वामे ममदानी ऐसा विवादास्पद चेहरा बनकर उभरे हैं, जिसके आगामी कल को लेकर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं।

पद्मभूषण से सम्मानित 67 वर्षीया मीरा नायर ने 1991 में महमूद ममदानी से दूसरी शादी की। जोहरान इसी युगल की संतान हैं।

ममदानी के नाम का मध्यवर्ती क्वामे उनके पिता की देन है। क्वामे एनक्रूमा घाना के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री थे तथा उन्हें पैन-अफ्रीकी नेता और अश्वेत मुक्ति के महानायक के तौर पर देखा जाता है।

आंकड़े

गाजर उत्पादन

भारत में गाजर उत्पादन की कुल पैदावार में 21.49 फीसदी हिस्सेदारी के साथ पंजाब शीर्ष पर काबिज है। अन्य राज्यों की उत्पादकता इस प्रकार है :

राज्य	प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	17.67
हरियाणा	10.89
पश्चिम बंगाल	8.99
मध्य प्रदेश	7.97
तमिलनाडु	6.34

आंकड़े प्रतिशत में हैं। | स्रोत : NHB

भगवान ब्रह्मा और विष्णु में वर्चस्व की होड़ मच गई। भोलेनाथ ने दोनों देवताओं पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की और युद्ध को रोकने में सफल रहे।

शिव ही पृथ्वी के मूल देवता हैं

आज मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा है। यह दिन मार्गशीर्ष (अग्रहायण) माह की शुरुआत का प्रतीक है। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों के बीच के वर्चस्व का यह युद्ध रोकने के लिए भोलेनाथ प्रकट हुए और अपनी तीसरी आंख से एक अग्नि ज्वाला प्रकट की, जिसका कोई छोर नहीं था। शिवजी ने दोनों देवताओं को चुनौती दी कि वे इस अग्नि का छोर खोजें। विष्णु जी सुअर (वराह) का रूप धारण कर धरती के गर्भ में उतरकर अग्नि का अंत खोजने लगे, पर असफल रहे। ब्रह्माजी हंस बनकर आकाश में उड़ चले, पर अग्नि का आरंभ न पा सके।

अंततः, दोनों ने स्वीकार किया कि इस अनंत अग्नि का कोई छोर नहीं है। इस प्रकार भोलेनाथ ने अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए युद्ध रुकवाया और सिद्ध किया कि वही पृथ्वी के मूल देवता हैं। इसके बाद महादेव तिरुवन्नामलाई में एक पर्वत के रूप में प्रकट हुए। इस स्थान पर भव्य अन्नामलाईश्वर मंदिर की स्थापना हुई।

अंतर्यात्रा
संकलित

दक्षिण भारत में इस दिन कार्तिगाई दीपम या मासिक कार्तिगाई उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन भोलेनाथ के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय (मुरुगन) की आराधना के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन दीप जलाने से अंधकार, अज्ञानता और नकारात्मकता दूर होती है।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 6 नवंबर, 1949

भगवान बुद्ध के शिष्यों के अवशेष सारनाथ पहुंचे

भगवान बुद्ध के शिष्यों के अवशेष सारनाथ को
काशी में तोपों से सम्मान
बनारस, ३ नवम्बर। भगवान बुद्ध के शिष्य सारीपुत्त और महामोग्गलाना के पवित्र अवशेष आज यहां एक सजी हुई मोटर कार में कलकत्ता से आ पहुंचे। लाने वाले थे सिक्किम राज्य के नरेश और उनकी बहिन। पवित्र अवशेष फूलों से सजी एक डोली में रखे थे।

भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्त और मोग्गल्लान के पवित्र अवशेष आज यहां एक सजी हुई मोटर कार में कलकत्ता से आ पहुंचे। लाने वाले थे सिक्किम के राज्य नरेश और उनकी बहन। पवित्र अवशेष फूलों से भरी एक डोली में रखे थे।

संतुलन बनाने की चुनौती

भारत व अमेरिका के बीच हुआ सैन्य समझौता निस्संदेह ऐतिहासिक है, पर अपने रूसी संबंधों को देखते हुए भारत को एक संतुलन बनाना होगा।

केएस तोमर | **अंतरराष्ट्रीय संबंध**

भारत की विकसित होती रणनीतिक दिशा में अक्तूबर के अंत में कुआलालंपुर में हस्ताक्षरित दस वर्षीय फ्रेमवर्क फॉर द यूएस-इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप एक निर्णायक लम्हा है। कुआलालंपुर समझौता रक्षा सहयोग के लिए व्यापक नीतिगत दिशा प्रदान करता है, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त सैन्य अभ्यास, उन्नत प्रणालियों का सह-विकास व सशस्त्र बलों के बीच बेहतर अंतर-संचालन क्षमता शामिल है। यह समझौता पहले के बुनियादी करारों लेमोआ (एलईएमओए) कॉमकासा (सीओएमसीएएसए) और बेका (बीईसीए) पर आधारित है, जो दोनों देशों को समुद्र, हवा व जमीनी मोर्चों पर बेहतर ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं।

भारत के लिए यह फ्रेमवर्क रणनीतिक विविधीकरण की दिशा में एक सुनियोजित रुख का संकेत देता है। हालांकि, भारत की ऐतिहासिक निर्भरता रूस पर अब भी बनी हुई है, लेकिन निगरानी ड्रोन से लेकर हैवी-लिफ्ट हेलिकॉप्टर तक, अमेरिकी प्रणालियों का लगातार समावेश, परिचालन लचीलापन, समुद्री वर्चस्व और तकनीकी एकीकरण की दिशा में सैन्य सिद्धांत के पुनर्गठन का स्पष्ट संकेत देता है। यह परिवर्तन ठोस आंकड़ों से भी जाहिर होता है। भारत ने अमेरिका से 31 एमक्यू-9बी स्काईगार्डियन/सीगार्डियन ड्रोन खरीदने के लिए 3.99 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौतों को अंतिम रूप दिया है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी की समुद्री निगरानी तथा आक्रामक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा, भारतीय नौसेना ने 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुबंध के तहत 24 एमएच-60आर सीहॉक हेलिकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया है, जिनका उद्देश्य पनडुब्बी रोधी युद्ध व बहु-मिशन अभियानों की क्षमता को सशक्त बनाना है। लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य वाले जीई एफ414 जेट इंजनों के सह-उत्पादन पर बातचीत जारी है, जो भारत के अगली पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमानों को शक्ति देंगे। इसी तरह, स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों के संयुक्त निर्माण को लेकर भी वार्ताएं आगे बढ़ रही हैं। ये परियोजनाएं भारत-अमेरिका रक्षा उद्योग सहयोग को कई अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचा सकती हैं।

अमेरिका के लिए यह समझौता कोई परोपकारी कदम नहीं, बल्कि एशिया में अपनी रणनीतिक पकड़ बनाए रखने का एक सोचा-समझा रणनीतिक निवेश है। तकनीकी रूप से सक्षम भारत चीन के प्रभाव का संतुलन साधने वाला देश बनकर उभर रहा है और क्षेत्र के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक स्थिर साझेदार की भूमिका निभा रहा है। यह सब अमेरिका की इंडो-पैसिफिक नीति के उस दृष्टिकोण से मेल खाता है, जिसमें फ्री एंड ओपन समुद्री व्यवस्था स्थापित करने पर जोर दिया गया है।

आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम-प्लस) के दौरान हुआ यह समझौता भारत, अमेरिका और आसियान देशों के बीच एक उभरते त्रिपक्षीय संतुलन की ओर इशारा करता है, जो दक्षिण चीन सागर में दबाव या धमकी वाली समुद्री गतिविधियों का विरोध करने तथा नियम-आधारित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह समझौता अप्रत्यक्ष रूप से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) ढांचे को मजबूत करता है, जिससे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा में भारत की भूमिका एक अहम साझेदार के रूप में और सशक्त होती है।

बीजिंग ने इस समझौते को असहजता के साथ देखा और इसे वाशिंगटन की नियंत्रण रणनीति (कंटेनमेंट स्ट्रेटजी) तथा भारत के चीन-विरोधी धुरी की ओर बढ़ने का हिस्सा माना। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति, जिबूती में उसके मजबूत ठिकाने तथा ग्वादर में उसकी क्षमता, और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उसका आक्रामक रवैया, ये सभी कारण भारत के समुद्री आधुनिकीकरण को चीन के प्रभाव के संतुलन के रूप में और अधिक स्पष्ट बनाते हैं। पाकिस्तान के लिए इस समझौते का प्रभाव मनोवैज्ञानिक व रणनीतिक, दोनों ही स्तरों पर है। एक अहम सवाल यह भी उठता है कि क्या अमेरिका-भारत समझौता नई दिल्ली के लंबे समय से चले आ रहे मॉस्को के साथ रक्षा संबंधों को कमजोर करेगा? इसका जवाब अचानक बदलाव में नहीं, बल्कि एक क्रमिक परिवर्तन में छिपा है। भारत के लगभग 45 फीसदी रक्षा आयात अब भी रूस से होते हैं, हालांकि एक दशक पहले यह हिस्सा करीब 70 प्रतिशत था।

फिर भी, अमेरिका के साथ संबंध प्रगाढ़ होते हुए भी, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए अपने रूसी संबंधों को जीवित रखते हुए भारत संभवतः एक संतुलित संतुलन बनाए रखेगा। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती किसी भी गुट में कनिष्ठ भागीदार बने बिना अपनी साझेदारियों का प्रबंधन करना होगी। उसे वाशिंगटन के साथ रणनीतिक तालमेल को रणनीतिक निर्भरता में बदलने से बचाना होगा। एक स्वायत्त शक्ति के रूप में भारत की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने हितों का तालमेल इस तरह बिठाए कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता से समझौता न करना पड़े।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

वोट पर फिर सवाल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कथित 'वोट चोरी' पर सबका ध्यान खींचने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीते हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारी चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कुछ प्रमाण पेश किए हैं। इन सभी साक्ष्यों की जमीनी पड़ताल अवश्य होनी चाहिए। अव्वल तो बिहार में पहले दौर के मतदान से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी की इस प्रस्तुति का राजनीतिक पहलू छिपा नहीं है, किंतु राजनीति से परे जाकर भी लोगों को आश्वस्त करना जरूरी है। जो आरोप हैं, उनका अकाट्य उत्तर चुनाव आयोग को देना चाहिए। अगर मतदाता सूची में सुधार की जरूरत है, तो यह काम जल्दी होना चाहिए। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पुनरीक्षण का काम शुरू किया है, पर दुर्भाग्य की बात है कि विपक्षी दलों द्वारा शासित कुछ राज्य ऐसे किसी पुनरीक्षण के खिलाफ हैं। कथित वोट चोरी के आरोप में दम है, तो सभी विपक्षी दलों को पुनरीक्षण के पक्ष में एकजुट हो जाना चाहिए।

ध्यान रहे, मतदाता सूची के साथ कथित छेड़छाड़ पर राहुल गांधी की यह तीसरी प्रेसवार्ता थी। इससे पहले की प्रेस वार्ता में उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने के आरोप लगाए थे। साथ ही, वोट चोरी संबंधी हाइड्रोजन बम होने का दावा किया था। अब एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर दिखाकर कांग्रेस नेता ने 22 वोट डाले जाने के आरोप लगाए हैं। एक अन्य मामले में एक ही तस्वीर का इस्तेमाल 223 वोटों के लिए किया गया बताया है। उनका यह आरोप बहुत गंभीर है कि हरियाणा में कांग्रेस वोट चोरी की वजह से ही हारी है। क्या हरियाणा में हर आठ में से एक वोट वाकई फर्जी है? इसका यथोचित निराकरण चुनाव आयोग को करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने घोषणा के साथ चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर चिंता जाहिर की है। इन सवालों के ठोस जवाब आने ही चाहिए। वैसे, चुनाव आयोग ने पहली नजर में आरोपों को खारिज कर दिया है। यहां दो बातें हैं, जो आयोग की ओर से सामने आई हैं। पहली यह कि हरियाणा में मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई। दूसरी यह कि अगर कांग्रेस के पोलिंग एजेंटों को फर्जी मतदान का संदेह था, तो उन्होंने बूथ पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? मतदाता सूची जब बनती है, तब उसमें पार्टी के एजेंटों का भी योगदान होता है। अगर कोई पार्टी यह ठान ले कि उसके क्षेत्र में एक भी फर्जी मतदाता नहीं होगा, तो वह फर्जी मतदान को रोक सकती है। क्या कुछ बड़ी खामियों से भरी भारतीय राजनीति में यह मुमकिन है?

कथित 'वोट चोरी' के आरोप में दम है, तो सभी विपक्षी दलों को पुनरीक्षण के पक्ष में एकजुट हो जाना चाहिए। पुनरीक्षण में चुनाव आयोग का पूरा साथ देना चाहिए।

जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो उसने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि राहुल गांधी गंभीर नहीं हैं, उनका एक भी एटम बम फटता नहीं है। भाजपा ने ध्यान दिलाया कि राहुल गांधी पहले एक वोटर मिंता देवी की तस्वीर दिखा चुके हैं, जबकि स्वयं मिंता देवी ने किसी फर्जीवाड़े से साफ इनकार किया था। सत्ता पक्ष यह मानता है कि चुनाव हारने के बाद इस तरह के आरोप लगाना कांग्रेस की आदत बन गई है। हालांकि, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि देश में कांग्रेस मतदाता सूची के प्रति असंख्य लोगों के मन में संदेह पैदा करने में सफल दिख रही है, तो अब उपाय यही है कि सभी पार्टियां मतदाता सूची में संशोधन या पुनरीक्षण के लिए समर्पित हो जाएं। सजग पुनरीक्षण ही मतदाता संबंधी शिकायतों का पटाक्षेप कर सकता है। चुनाव और चुनाव आयोग को ऐसे अप्रिय प्रश्नों से परे लाना समय की मांग है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले

06 नवम्बर, 1950

शांति के प्रयास

विश्व शांति की रक्षा किस प्रकार की जाये, यही-आज की सबसे मुख्य समस्या है। विश्व में शांति कायम रहने की अवस्था में ही मानव जाति की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति संभव हो सकती है। विश्व ने इसी शताब्दि में दो महायुद्धों की विनाश लीला को देखा है। उसके बाद यह आशा की जा सकती थी कि कम से कम इस शताब्दि का बाकी हिस्सा शांतिपूर्वक बीत जायेगा। किन्तु दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के कुछ ही वर्षों बाद जिस प्रकार युद्ध की चिनगारियां उड़ने लगीं और वातावरण क्षुब्ध हो रहा है, उसने मानव जाति की आशाओं पर ठंडा पानी डाल दिया है। कोई नहीं कह सकता कि प्रथम महायुद्ध के बाद जितने समय तक शांति कायम रही, उतने समय तक दूसरे महायुद्ध के बाद भी कायम रह पायेगी अथवा नहीं।

उत्तरी कोरिया की लड़ाई को समाप्तप्रायः समझ लिया गया था, किन्तु इधर उसमें नया खून प्रविष्ट हो गया है। उत्तरी कोरियनों ने जोरदार आक्रमण करके संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं को, जो करीब-करीब मंचूरिया की सीमा तक जा पहुंची थीं, इससे पचास मील पीछे हटने को बाध्य कर दिया है। संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं को सैनिकों और युद्ध-सामग्री के रूप में काफी हानि उठानी पड़ी है। यह कहा जा रहा है कि उत्तरी कोरियनों को चीनी साम्यवादियों से मदद मिल रही है और स्वयं चीनी साम्यवादी सैनिक उत्तरी कोरियनों के पक्ष में लड़ रहे हैं। यदि उत्तरी कोरिया की लड़ाई में चीनी हस्तक्षेप का समाचार सही है, तो उसके फैलने की संभावना बढ़ जाती है। कोरिया के युद्ध को न फैलने देने के उद्देश्य से ही भारत ने संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं के 38वीं अक्षांश के दक्षिण में रुक जाने की हिमायत की थी। किन्तु भारत के सुझाव को नहीं माना गया और संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं को इस रेखा को पार करके उत्तरी कोरिया में दाखिल होने की अनुमति दे दी गई। उत्तरी कोरिया में संयुक्त राष्ट्रीय सेनायें बराबर आगे बढ़ती गईं और चीन ने हस्तक्षेप करने की अपनी धमकी को कार्यान्वित नहीं किया, इस पर भारत की आलोचना भी की गई। कहा गया कि उसका निर्णय गलत सूचनाओं पर आधारित था और दुर्बलता का परिचायक था। यदि संयुक्त राष्ट्रीय सेनाएं 38 अक्षांश के इस पार रुक गई होती, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरिया को संयुक्त करने का सुनहरा मौका अपने हाथ से खो दिया होता।

अमेरिका में मेयर ममदानी के मायने

यहां स्कैन करें

अश्विनी महापात्रा | प्रोफेसर, जेएनयू

जोहरान ममदानी की जीत लोकतांत्रिक समाजवाद की नई वाम विचारधारा की स्वीकार्यता के संकेत देती है। मगर यह तीसरी दुनिया के देशों के समाजवाद से बिल्कुल अलग है।

अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क के मेयर पद पर जोहरान ममदानी की जीत ऐतिहासिक है। इस पद पर पहुंचने वाले वह सबसे युवा राजनेता हैं और अफ्रीका में जन्मे पहले मेयर व मुस्लिम भी। ममदानी मशहूर भारतीय फिल्मकार मीरा नायर के बेटे हैं। उन्होंने उस न्यूयॉर्क में जीत हासिल की है, जहां तमाम कॉरपोरेट और बिजनेस घराने हैं। यहां तक कि वह मैनहट्टन भी यहीं है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र माना जाता है। तमाम पूंजीवादी गतिविधियां यहीं से संचालित होती हैं, जबकि ममदानी अपनी समाजवादी सोच का खुला इजाहार करते रहे हैं। तो, क्या इसे एक पूंजीवादी देश में समाजवाद की जीत माना जाएगा?

इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें अतीत में लौटना होगा। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी में ममदानी गुट डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एसोसिएशन (डीएसए) के नाम से जाना जाता है। 80 लाख की आबादी वाले न्यूयॉर्क शहर में अब इसके करीब एक लाख सदस्य हो चुके हैं। बेशक, यह धड़ा राज्य-प्रायोजित कल्याणकारी उपायों का हिमायती है, लेकिन वैचारिक रूप से नेहरू द्वारा भारत में या स्वीडन के कल्याणकारी राज्य द्वारा अपनाए गए लोकतांत्रिक समाजवाद में इसका भरोसा नहीं है। यह उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण का वह भारतीय मॉडल भी नहीं अपनाना चाहता, जो 1991 तक चलता रहा, जब तक कि उदारीकरण की प्रक्रिया नहीं शुरू हो गई।

इन सबके बजाय ममदानी गुट उस व्यवस्था में विश्वास रखता है, जिसमें अर्थव्यवस्था पर बेशक राज्य का नियंत्रण न हो, लेकिन उसके नियमन की जिम्मेदारी वह जरूर निभाए। वह ऐसे सुधारों पर बल देता है, जिसमें पूंजी कुलीनतंत्र या संपन्न तबकों के हाथों मे न सिमटा हो, बल्कि सभी को फलने-फूलने का मौका मिले। उसका ध्यान मुख्यतः कामकाजी तबकों की समस्याओं और सामाजिक-आर्थिक विषमताओं पर है। इसीलिए, उनकी जीत लोकतांत्रिक समाजवाद की नई वामपंथी विचारधारा की स्वीकार्यता का संकेत देती है, जिसमें आर्थिक चिंताओं के साथ-साथ सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक परिवर्तन और नागरिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। एक अर्थ में, यह स्वतंत्रता और समानता के अनुकूल खुद को देखती है। इसमें समाजवाद की महक आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह वह समाजवाद नहीं, जो तीसरी दुनिया के देशों में देखी जाती रही है।

हालांकि, ममदानी की छवि करिश्माई है। वह नए वामपंथ के प्रतीक के तौर पर उभरते दिखते हैं। वह सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं और नए वोटरों को चुनाव-प्रक्रिया से जोड़ने के साथ-साथ उनको समर्थन भी देते रहे हैं। उन्होंने कामकाजी नौजवानों की परेशानियों को समझते हुए चुनाव में कई वायदे किए हैं। मसलन, सार्वजनिक स्वामित्व वाली किराना दुकानें खोलने की बात, ताकि लोगों को सस्ती कीमतों पर सामान मिल सके। उन्होंने बस यात्रा को मुफ्त बनाने का वायदा किया। इतना ही नहीं, बच्चों की देखभाल को मुफ्त करने और आवास योजना के तहत मकान किराये को तय करने का एलान भी उन्होंने किया है। ये सारे एजेंडे उनकी समाजवादी व साम्यवादी सोच की तरफ इशारा करती है, जिसने खासकर कामकाजी लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया है।

ममदानी की यह छवि इसलिए भी बनी, क्योंकि वह वक्त-बेवक्त अपनी वामपंथी सोच का इजहार करते रहे हैं। 'ग्लोबलाइज द इंतिफादा' का वह समर्थन कर चुके हैं। वह फलस्तीनी नागरिकों के मानवाधिकारों के हिमायती हैं और इजरायली नीतियों का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि वह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार कर लेंगे! हां, यह अलग बात है कि ऐसा करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि किसी देश की विदेश नीति किसी शहर का मेयर नहीं तय कर सकता।

बहरहाल, ममदानी की जीत क्या अमेरिका के अन्य शहरों में समाजवाद की राह प्रशस्त करेगी? अव्वल तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही डीएसए की नीतियों को लेकर आमराय नहीं है। फिर, नजर इस बात भी रहेगी कि ममदानी अपने वायदों को कितना पूरा कर पाते हैं। देखा जाए, तो यही वह पड़ाव है, जो अमेरिका में इस कथित समाजवाद की दिशा तय करेगा। दरअसल, अपने चुनाव अभियान में ममदानी ने जितने भी वायदे किए हैं, उनको हम भारत में राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली 'फ्रीबीज' का एक रूप मान सकते हैं। ये जनता को लुभाती हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए पूंजी की दरकार होगी, जिसके लिए या तो ट्रंप प्रशासन से पैसे लेने होंगे या फिर निजी क्षेत्र से। ट्रंप प्रशासन का आलम यह है कि चुनाव के दौरान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति तमाम तरह की धमकियां दे चुके हैं। उन्होंने तो ममदानी के जीतने की सूरत पर न्यूयॉर्क का 'फेडरल फंड' रोकने तक की बात कही है।

रही बात निजी क्षेत्र की, तो उसकी दशा छिपी नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था फिलहाल कमजोर है और यह हम अमेरिका की टैरिफ नीति से भी समझ सकते हैं। दरअसल, अमेरिका से जब फैक्टरियां चीन की ओर गईं, तो अमेरिका महज उपभोक्ता बाजार बनकर रह गया। इसका नुकसान यहां के रोजगार पर पड़ा और बेरोजगारी दर बढ़ने लगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी समस्या से पार पाने के लिए टैरिफ का दांव खेला है, ताकि फैक्टरियां वापस अमेरिकी जमीन पर लौट सकें और यहां के लोगों को काम मिल सके। इसीलिए, लोक-लुभावन नीतियों की तरफ लोग स्वतः आकर्षित हो जाते हैं। ममदानी को इसी का फायदा मिला है। जाहिर है, अब उन्हें अपने वायदों को हकीकत में बदलना होगा, और यह आसान काम नहीं होगा। एक ऐसे देश में, जहां संघीय सरकार टैक्स व राजस्व हासिल करती है, वहां एक नगर प्रशासन आमदनी के अन्य स्रोत तलाश पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। वैसे मुमकिन यह भी है कि आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क में ऐसे उपाय अमल में लाए जाएं, जिनसे निजी क्षेत्र नगर प्रशासन के साथ खड़ा हो सकता है।

बेशक, ममदानी का भारत से जुड़ाव है और जीत के बाद अपने संबोधन में उन्होंने पंडित नेहरू का भी जिक्र किया, लेकिन उनकी व्यावहारिक नीतियां लोकतांत्रिक समाजवाद से शायद ही प्रभावित होंगी। इस लिहाज से देखें, तो उनका कार्यकाल लोक-कल्याणकारी राज्य को नया रूप दे सकता है। उनकी जीत सैद्धांतिक तौर पर तो पूंजीवादी समाज में नई समाजवादी सोच का बीजारोपण है, पर व्यवहार में उसे कई चुनौतियों से पार पाकर अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक शिक्षा में एआई का इस्तेमाल

यहां स्कैन करें

अनुराग बेहर | सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन

सोचने की क्षमता वह विलक्षण गुण है, जो हमें अन्य प्राणियों से अलग कर इंसान बनाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआई उस सोचने की क्षमता को ही खत्म कर रहा है। एआई नौकरियां खत्म कर रहा है। इससे झूठ-सच, नकली-असली को अलग करना मुश्किल हो रहा है। यह अपराधियों को उकसाकर हिंसा भड़का सकता है या इससे भी बदतर स्थिति पैदा कर सकता है। इसकी बदौलत कई घटनाएं घट भी चुकी हैं। आशंका है कि ये सभी मिलकर अराजकता का ऐसा मंजर उपस्थित कर देंगे, जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। कुल मिलाकर, सबसे खतरनाक बात यही निकलकर आती है कि एआई हमारी इंसानियत को खोखला कर रहा है।

कई मामलों में एआई से फायदे भी हैं। लेकिन मैं 'चीजों को समग्रता में देखने' वाली दलीलों को मानने को तैयार नहीं हूं। एआई की बाढ़ को रोकना होगा और परमाणु क्षमता की तरह इस जिन्न को बोतल में बंद करना होगा। अगर आप इस पर पक्का यकीन करना चाहते हैं, तो किसी शैक्षणिक संस्थान में कुछ समय बिताएं। जितना अधिक कुलीन संस्थान होगा, जितनी अधिक एआई से जुड़ी चीजों तक वहां पहुंच होगी, उतनी ही तेजी से आपका नजरिया बदल जाएगा।

शिक्षण संस्थानों का मूल उद्देश्य सोचने की क्षमता विकसित करना है। मगर एआई के कारण वहां इसके विपरीत होने लगा है। यह धोखा है।

नजीर के तौर पर, काफी गहन शोध द्वारा अलग-अलग तरह के मादक पदार्थों के फायदेमंद असर को खोजा जाता है, इसे साबित किया जाता है और समझा जाता है। इतने सारे परीक्षणों के बावजूद, इन पदार्थों का इस्तेमाल सिर्फ विशेषज्ञ की देख-रेख में ही किया जाता है। बात साफ है कि जो चीजें इंसानियत को बदल देती हैं, उसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को इससे दूर रखना होता है, सिवाय उपचार की जरूरत के। यहां तक कि वयस्कों को भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होता है। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ हमें और हमारी इंसानियत को बदल देते हैं।

कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं, जिन्हें अक्सर सिर्फ 'ड्रग्स' कहा जाता है। उनका इस्तेमाल न केवल सख्त मना है, बल्कि इसे आपराधिक श्रेणी में रखा जाता है। ये पदार्थ और ड्रग्स ऐसे टूल्स हैं, जो हमें बदलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एआई। बस फर्क इतना है कि ये पदार्थ व ड्रग्स हमारे पाचन-तंत्र, श्वसन-तंत्र या रक्त वाहिनियों के जरिये तंत्रिका पथ के संपर्क में आते हैं, जबकि एआई देखने-सुनने व सामाजिक तंत्र के जरिये वहां तक जाता है। बल्कि, एआई कहीं अधिक गहराई से बदलता है। गौर कीजिए, सोशल मीडिया और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी कैसे ध्यान को नियंत्रित कर रही है, मानसिक स्वास्थ्य के संकट पैदा कर रही है, समाज को बांट रही है और भी बहुत कुछ कर रही है। एआई ऐसा ही टूल है, जो इंसानों को बदल रहा है। कई लोग इसकी विध्वंसक ताकत से हैरान हैं। एक बात तो साफ है कि आप जितना ज्यादा एआई का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही खुद के बारे में कम सोचेंगे। इसका नतीजा होता है कि सोचने की क्षमता कम हो जाती है।

आप देखें, इन दिनों शैक्षणिक संस्थानों में क्या कुछ हो रहा है? शिक्षण संस्थानों का मूल उद्देश्य इंसान के सोचने की क्षमता को विकसित करना है। लेकिन वहां इसका उल्टा हो रहा है। शिक्षक और छात्र सोचने की जिम्मेदारी एआई को सौंप रहे हैं। एआई शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण योजना, पाठ्य-पुस्तकें, असाइनमेंट और परीक्षा के प्रश्न-पत्र तक सेट कर रहा है और छात्र जवाब के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तो एक धोखा है। शिक्षा खत्म करना एआई से इंसानियत को पहला खतरा है। इसलिए अब कई संस्थान और शिक्षक एआई के खिलाफ दृढ़ हो गए हैं।

निस्संदेह, मौजूदा डिजिटल दुनिया में एआई को रोकना नामुमकिन है। इसलिए वे शिक्षण के पुराने तरीकों पर वापस जा रहे हैं, यानी कक्षा में आमने-सामने बैठकर पढ़ाई। इंसानी गतिविधियों में एआई से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशों की जरूरत है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि हम युवाओं को ड्रग्स दे रहे हैं। वह ड्रग कोकीन से ज्यादा खतरनाक है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

बहरे की हमदर्दी

एक आदमी अपनी सुनने की क्षमता खोता जा रहा था, मगर वह अपनी इस कमजोरी को मानने को तैयार न था और ऐसा दिखावा करता, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक दिन, उसके दोस्त ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग बहुत बीमार हैं और उनकी मिजाजपुर्सी के लिए उसे जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आता। बहरे हो रहे आदमी ने किसी तरह समझ लिया कि उसका दोस्त उसे क्या बता रहा है। उसने उसी दिन बीमार बुजुर्ग से मिलने का वादा किया। वादा तो उसने कर दिया, मगर पसोपेश में पड़ गया कि वह बात कैसे करेगा? वह तो इतने कमजोर हो गए होंगे कि शायद फुसफुसाकर बोल पाएं? मगर कोई चारा न था।

उसने तय किया कि वह उनके होंठों की जुंबिश पढ़कर समझेगा कि वह क्या कह रहे हैं और उसी हिसाब से जवाब देगा। फिर भी, बचाव के तौर पर उसने अपने मन में खुद के सवाल और पड़ोसी के संभावित जवाब पहले से सोच लिए। उसने तय किया कि जब वह पूछेगा, 'आप कैसा महसूस कर रहे हैं?' तो बीमार पड़ोसी शायद कहें, 'खुदा का शुक्र है, मैं अब ठीक हूं।' फिर उसकी प्रतिक्रिया होगी, शुक्र-ए-खुदा! आगे वह पूछेगा, 'आज आपने क्या खाया?' तो पड़ोसी शायद जवाब दें, 'मैंने सूप पिया, साथ में एक गिलास शरबत भी।' इस पर वह कहेगा, वाह! बढ़िया भोजन। इसके अलावा, वह उनसे पूछेगा, 'आप किस डॉक्टर से मिले?' तब बुजुर्ग शायद स्थानीय डॉक्टरों में से किसी एक का नाम बताएंगे। इस पर वह उन्हें कन्फर्म करेगा, 'वह इस काम में सबसे अच्छा है।' इस योजना से उसे हिम्मत मिली। वह तुरंत बीमार पड़ोसी के यहां पहुंचकर उनके बिस्तर के पास बैठ गया और बड़े प्यार से उनसे पूछा, 'आप कैसा महसूस कर रहे हैं?' बीमार आदमी ने कराहते हुए बोला 'मैं मर रहा हूं।' बहरे हो रहे आदमी ने खुशी से कहा, खुदा का करम है! उसने अपना अगला सवाल पूछा, 'कल रात आपने क्या खाया था?'

'जहर!' बूढ़े आदमी ने पहले जवाब से नाराज होकर कहा। बहरे आदमी ने बिना कुछ समझे जवाब दिया, 'बोन एपेटिट!' इस टिप्पणी से बीमार परेशान हो गया, उसने मेहमान को गाली देने से खुद को रोकने के लिए अपने होंठ काट लिए। मगर बहरे आदमी ने पूछताछ जारी रखी, 'आपका इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है?' बीमार ने चिढ़कर कहा, 'अजराएल, मौत का फरिश्ता!'

कोई आपकी कमजोरियों की ओर ध्यान खींचता है, तो उनको नकारने के बजाय उनसे निपटने की रणनीति बनाइए। वरना गैर-इरादतन भी आप अपने प्रिय जनों को टेस पहुंचाते रहेंगे।

बहरे ने कहा, 'खुदा उसे सलामत रखें। वह जिसके पास जाता है, उसकी सारी तकलीफें हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं।' अपने बीमार पड़ोसी को पीड़ा पहुंचाने से अनजान बहरे आदमी ने विदा लेते समय बीमार का हाथ कसकर हिलाया, यह मानते हुए कि उसने पड़ोसी होने का अपना फर्ज निभाया है और बीमार को राहत दी है।

रूमी

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

बराक ओबामा | पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका

पिछले नौ महीनों में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि चुनाव बहुत मायने रखते हैं। अमेरिका के बारे में खास बात यह है कि यहां बतौर नागरिक हमारे पास वोट के जरिये इस देश को बदलने की ताकत है!

हमारी जरूरतें पूरी करने लगी हरित ऊर्जा

दिल्ली सहित उत्तर भारत के तमाम शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल 15 लाख से अधिक लोगों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। ऐसे में, सवाल उठता है कि क्या विकास की कीमत प्रदूषण होनी चाहिए? क्या आधुनिक भारत प्रदूषण की छाया में ही आगे बढ़ेगा? इन्हीं सवालों का उत्तर खोजते हुए भारत ने एक नई राह अपनाई है, हरित ऊर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सीओपी-26' के दौरान जब वर्ष 2070 तक 'नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन' का लक्ष्य रखा, तो उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि भारत विकास करेगा, पर प्रकृति के साथ।

इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत लाखों परिवारों ने अपने घरों की छतों पर सौर पैनल लगवाए हैं। नतीजा यह है कि अब वे हर महीने 200-300 यूनिट मुफ्त बिजली पा रहे हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी भी कर रहे हैं। अब तो गांवों में स्कूल, पंचायत भवन और छोटे उद्योग भी सौर बिजली से चल रहे हैं।

हरित ऊर्जा का दूसरा मजबूत स्तंभ है, पवन ऊर्जा। तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य अब देश की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा हवा से पैदा कर रहे हैं। 2025 में शुरू हुई ऑफशोर विंड एनर्जी योजना के तहत समुद्र तटों पर विशाल टरबाइन लगाए गए हैं, जिनसे 30 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का उदाहरण है, बल्कि इससे तटीय इलाकों में रोजगार और पर्यटन के अवसर भी बढ़े हैं। वहीं भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन के जरिये भी विश्व को चौंका दिया है। 2030 तक भारत 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु में बड़े संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है। इसी तरह, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में प्रदूषण घटाने और आयातीत तेल पर निर्भरता कम करने की इच्छाशक्ति दिख रही है।

हरित ऊर्जा सिर्फ पर्यावरण की रक्षा का जरिया नहीं, यह हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास का आधार बन चुकी है। 2025 की अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार, भारत हर वर्ष 20 लाख नए रोजगार हरित ऊर्जा क्षेत्र में पैदा कर रहा है। यह संख्या अगले पांच वर्षों में दोगुनी होने की संभावना है। जाहिर है, जब पूरी दुनिया गंभीर ऊर्जा संकट व जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है, तब भारत में यह वरदान ही है। यह हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने लगी है।

नीलू तिवारी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

हरित ऊर्जा

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बनी रहेगी

भारत आज भी जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि लगभग 80 प्रतिशत बिजली उत्पादन और कुल ऊर्जा खपत का एक बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन से ही पूरा होता है। इसी कारण, तेल आयात पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक है। बेशक, यह सच है कि गैर-जीवाश्म ईंधन पर जोर दिया जा रहा है और सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से बिजली उत्पादन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन हरित ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भरता अब भी दूर की कौड़ी है। प्रदूषण जैसे खतरे बेशक हों, लेकिन जीवाश्म ईंधन का पोषण अब भी हमारी मजबूरी है।

वास्तव में, कई ऐसी चुनौतियां हैं, जिस कारण अभी हरित ऊर्जा का सपना साकार नहीं हो सकता। सबसे पहली है, बुनियादी ढांचों का अभाव। कोयले से आगे बढ़कर हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपना सकें, इसके लिए झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों में हमें बुनियादी ढांचों की बेहतरी पर काम करना होगा, जिसमें खासा वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य हमने तय किया है, उसे पूरा करने के लिए हर साल तकरीबन दो हजार अरब रुपये की जरूरत होगी। जाहिर है, बजट का एक बड़ा हिस्सा यदि हम इसी पर खर्च करेंगे, तो बाकी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकेंगे? बेशक, इसके लिए निवेशक ढूंढ़े जा सकते हैं और ढूंढ़े जा भी रहे हैं, लेकिन यह कोई छोटी पूंजी नहीं है और इस दिशा में निवेशकों का रुख भी बहुत उत्साहजनक नहीं दिख रहा। इसी तरह, सौर व पवन ऊर्जा की अस्थायी प्रकृति ग्रिड की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, जिसके लिए मजबूत ऊर्जा भंडारण और बेहतर बुनियादी ढांचों की दरकार है। हालांकि, आपूर्ति शृंखला की बात करें, तो भारत सौर सेल सबसे अधिक चीन से खरीदता है, साथ ही पवन टरबाइन आपूर्ति में भी उसी का प्रभुत्व है। इसका नुकसान भी हमें होता है और हमारी गति स्वाभाविक रूप से धीमी पड़ जाती है।

इन्हीं सब चुनौतियों को देखकर यह कहा जाता है कि हरित ऊर्जा की दिशा में भारत को काफी काम करना होगा। उसे कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ना होगा। उसे न सिर्फ बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाना होगा, बल्कि आपूर्ति शृंखला को भी विविध बनाना होगा। इतना ही नहीं, निवेशकों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जब ये तमाम काम हो जाएंगे, तब जीवाश्म ईंधन की विदाई की भविष्यवाणी की जा सकेगी। उससे पहले हमें अपनी ऊर्जा जरूरत को जीवाश्म ईंधन से पूरा करने के लिए ही दमखम दिखाना होगा।

भव्या कुमारी, टिप्पणीकार

आज के निर्णय ही कल के परिणाम को निर्धारित करते हैं

राहत देने वाला फैसला

यह स्वागतयोग्य है कि ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय इंसाल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है, जिससे दीवालिया कंपनियों और उनके प्रवर्तकों की जब्त की गई संपत्तियों से फ्लैट खरीदारों और बैंकों को राहत दी जा सके। ईडी की ओर से इस संदर्भ में जो मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जा रही है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उसके दायरे में बिल्डरों की जब्त संपत्तियां ही आएंगी। अच्छा हो कि इस प्रक्रिया के दायरे में वे दीवालिया कंपनियां और उनके प्रवर्तक भी आएं, जो बैंकों या बाजार से पैसा लेकर किसी भी तरह की धोखाधड़ी के आरोपित हैं। ऐसे आरोपितों की बड़ी संख्या है। इनमें वे घोटालेबाज भी शामिल हैं, जो अपने कारोबार को विस्तार देने के नाम पर बैंकों से बड़ा लोन लेकर उसे हड़प गए। आम लोगों और बैंकों से पैसा लेकर उसे हजम कर जाने वालों की संपत्तियों को जब्त कर लेना इसलिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतने मात्र से पीड़ित पक्षों को कोई लाभ नहीं मिलता। दीवालिया कंपनियों और कारोबारियों की जब्त संपत्ति को लेकर जो वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाती है, वह आमतौर पर लंबी खिंचती है। इस दौरान पीड़ित पक्ष परेशान होते रहते हैं, क्योंकि अभी नियम यह है कि मामले का निपटारा होने तक जब्त संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। इसका बुरा असर बैंकों, निवेशकों और आम लोगों पर पड़ता है। इसका कोई मतलब नहीं कि घोटालेबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो शुरू हो जाए, लेकिन उनकी हजारों करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति अनुप्रयुक्त पड़ी रहे। न्याय का तकाजा यह कहता है कि घपले-घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के साथ ही पीड़ितों को यथाशीघ्र राहत देने की भी कोई व्यवस्था हो। बैंक तो तब भी घोटाले में डूबी रकम वापस पाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन आम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बड़ी संख्या में ऐसे बिल्डर हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को उनके घर का सपना दिखाकर उनके साथ ठगी की। इनमें से अनेक बिल्डरों ने फ्लैट खरीदारों के साथ बैंकों को भी ठगा। अच्छा होगा कि केंद्र सरकार अपनी विभिन्न एजेंसियों के बीच ऐसा समन्वय कायम करे, जिससे बिल्डरों के साथ-साथ अन्य दीवालिया कंपनियों के मामलों में फंसे अरबों रुपये की वसूली का रास्ता खुले। इसी के साथ ऐसे भी उपाय करने होंगे, जिससे जानबूझकर दीवालिया होने के तौर-तरीकों पर लगाम लगे। कई मामलों में यह देखने में आया है कि घोटालेबाज दीवालिया होने और इस कारण अपनी संपत्ति की जब्ती के बाद भी पहले की तरह ठाठ से रहते हैं। एक समस्या यह भी है कि ऐसे लोगों के मामलों का निपटारा होने में बहुत अधिक समय लगता है।

जरूर करें मतदान

बिहार के 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में आज वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव में 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आपका एक मत न सिर्फ प्रत्याशियों, बल्कि राज्य का भविष्य भी तय करेगा। इसलिए मतदान जरूर करें। यह न सिर्फ आपका अधिकार, बल्कि नैतिक दायित्व भी है। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए राज्यभर में चुनाव आयोग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। मतदान क्यों जरूरी है, यह भी बताया जा रहा। मतदान में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कोई किसी पर दबाव न डाल सके, इसलिए बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सशस्त्र बलों की तैनाती रहेगी। शत-प्रतिशत बूथों पर वेबकास्टिंग होगी। इसकी मदद से चुनाव आयोग बूथों की आनलाइन निगरानी रखेगा, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। बिना किसी भय या दबाव के मतदान करें। 10 अक्टूबर को शुरू हुए नामांकन के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों का जमकर प्रचार किया। वादे किए। इनमें कई प्रत्याशी ऐसे हैं, जिनपर गंभीर मामले दर्ज हैं। मतदान से पूर्व एक बार विचार अवश्य करें कि क्या आप जिसे वोट देने जा रहे हैं, वह आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। विकास को प्राथमिकता के साथ 'पहले मतदान फिर जलपान' का संकल्प ही आने वाले पांच वर्षों तक राज्य की दशा और दिशा तय करेगा।

> मतदान न सिर्फ आपका अधिकार, बल्कि नैतिक दायित्व भी है। आपका एक मत पांच साल तक राज्य की दशा-दिशा तय करेगा।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या बाहुबली छवि वाले उम्मीदवारों के लिए राजनीतिक दलों के साथ जनता भी जिम्मेदार है?

आज का सवाल

क्या न्यूयार्क मेयर चुनाव में ममदानी की जीत ट्रंप को राजनीतिक रूप से कमजोर करेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

बाहुबलियों की बेलगाम राजनीति

राहुल वर्मा

समय के साथ बाहुबली खुद ही राजनीति में उतरने लगे और अब तो वे अपने करीबियों और परिवार के लोगों को भी राजनीति में स्थापित करने लगे हैं

जातिगत समीकरण और राजनीति में अपराधीकरण भारतीय राजनीति की दो कड़वी सच्चाई हैं, जो बिहार के मामले में और मुखरता से सामने आती हैं। बीते दिनों मोकामा में यह फिर से सामने आया, जब जदयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। अनंत सिंह को जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। दुलारचंद यादव के बारे में भी यही जानकारी सामने आई कि उनकी भी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। अनंत सिंह का मुकाबला राजद प्रत्याशी वीणा देवी से है, जो सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। सूरजभान सिंह का अतीत और वर्तमान भी किसी से छिपा नहीं रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि मोकामा राजधानी पटना से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यह राज्य की एक सीट का हाल है। बाकी का आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। आज बिहार में जिन 121 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, उसमें करीब 1,300 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स यानी एडीआर के अनुसार इनमें से 30 प्रतिशत उम्मीदवार गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं।

बिहार की राजनीति में दागियों की पैठ कितनी गहरी है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पिछली विधानसभा में चुने गए 50 प्रतिशत विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज थे। यानी हर दूसरे विधायक का दामन दागदार रहा। इनमें भी 16 विधायक ऐसे थे, जिन पर हत्या से जुड़े मामले दर्ज थे, जबकि 30 विधायकों पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज थे। इसमें आठ विधायकों पर तो यौन शोषण जैसे अपराध का आरोप था। इस चुनाव में भी सभी राजनीतिक दलों ने दागियों और उनके परिवार के लोगों को टिकट देने में खूब दरियादिली दिखाई है। शहाबुद्दीन से लेकर मुन्ना शुक्ला और सुनील पांडे और राजन तिवारी के नाते-रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतरकर विधानसभा पहुंचने की व्यूह रचना बनाने में जुटे हैं। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को समस्या तो सभी बताते हैं, लेकिन कोई इसके समाधान के लिए आगे नहीं आता। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि आखिर राजनीतिक दलों को दागी इतने क्यों पसंद हैं और अगर दल अपने टिकट पर दागियों को उतारते हैं तो फिर जनता उनकी नैया पार कैसे लगा देती है? इस सवाल के जवाब के लिए कोई बहुत मेहनत-मशक्कत करने की जरूरत नहीं। इसमें सबसे बड़ा पहलू तो राज्य की नाकामी के रूप में सामने आता है।

अवधेश राजपूत

जब राज्य कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर पाता तो कुछ लोग अपने बाहुबल के दम पर ही लोगों को 'सुरक्षा और न्याय' दिलाने के ठेकेदार बन जाते हैं। आम लोगों के दुख-दर्द और आड़े वक्त में की गई मदद भी इन्हें जनता के बीच स्थापित करने में मददगार बनती है। ऐसे तमाम एहसानों की कीमत अलग-अलग मौकों पर चुकाई भी जाती है और चुनाव भी उनमें से एक अवसर होता है। चूंकि ऐसे बाहुबलियों का प्रशासनिक अमले में अपना एक दबदबा होता है, इसलिए किसी विनम्र नेता के मुकाबले इनकी बात पर सुनवाई होने के आसार अधिक बढ़ जाते हैं। यह पहलू भी जनता के प्रति इनमें भरोसा बढ़ाता है। भारतीय समाज और कहें कि बिहार में जातिगत बंधन भी बहुत गहरे हैं तो हर जाति से कोई न कोई बाहुबली आगे निकलकर अपने समुदाय का मसीहा बनने की कोशिश करता है और दूसरी जाति के बाहुबली के मुकाबले अपने लोगों को यह भरोसा दिलाने की पूरी जुगत करता है कि वही उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा। यानी बाहुबल में कहीं न कहीं जातीय अस्मिता का भी एक बोध तो दिखता ही है। इस पूरी कवायद में राज्य की अक्षमता ही बाहुबलियों की क्षमताएं बढ़ाने का आधार बनती हैं। राजनीतिक दलों का भी बाहुबलियों के प्रति बढ़ते दुलार की कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह तो उनकी जिताऊ क्षमता है कि वे अपने तबके के समर्थन या डरा-धमका कर लोगों को प्रभावित कर नतीजों को अपने पक्ष में करने में आगे रहते हैं। एक वजह यह भी है कि चुनाव अब बहुत खर्चीले होते हैं और बाहुबलियों के पास धन-संसाधनों का कोई अभाव नहीं होता। इसलिए राजनीतिक दलों को इनसे अच्छा-खासा चुनावी चंदा भी मिलता है, जिससे न केवल उनके चुनाव क्षेत्र, बल्कि आसपास के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी संसाधनों की पहुंच बढ़ती है।

राजनीति और अपराधीकरण के रिश्तों का तानाबाना भी समय के साथ बदला है। बाहुबली एक समय नेताओं को अपना समर्थन देते रहे और बदले में नेता उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। समय के साथ बाहुबली खुद ही राजनीति में उतरने लगे। अब तो वे अपने साथ-अपने खास करीबियों और परिवार के लोगों को भी राजनीति में स्थापित करने लगे हैं। अपराध और वंशवाद का यह नया खतरनाक चलन लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। यदि समय के साथ इस चलन पर विराम नहीं लगा तो भविष्य में इसके परिणाम विध्वंसक होंगे, जिसके रुझान पहले से दिखने भी लगे हैं और समय-समय पर दिखते भी रहते हैं। बाहुबलियों के रवैये से यही लगता है कि राजनीति उनके लिए जनता की समस्याओं के समाधान का माध्यम नहीं, बल्कि अपने वर्चस्व को स्थापित करने का एक अखाड़ा है। यह भी जगजाहिर है कि अपनी अवैध गतिविधियों के लिए भी वे राजनीति को एक ढाल बनाने का काम करते हैं।

राजनीति में अनियंत्रित हो रहे अपराधीकरण पर लगाम लगाने की जितनी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है, उतनी ही जनता की भी है। दोनों ही पक्षों को यह समझना होगा कि बाहुबलियों के साथ जुड़ने और उन्हें अपने साथ जोड़ने के तात्कालिक लाभ के बजाय कितना दूरगामी नुकसान होता है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम नई सरकार के गठन के साथ राजनीति में अपराधियों की बढ़ती पैठ को लेकर भी जनता का आदेश सुनाने का काम करेंगे, जिसका असर अन्य चुनावों पर भी पड़ता दिखेगा।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो और राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

पंथनिरपेक्षता का दिखावटी चेहरा

क्षमा शर्मा

वेंस का बयान दर्शाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए वे कैथोलिक अमेरिका को खुश करना चाहते हैं

पिछले दिनों अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पत्नी उषा वेंस के बारे में दिया गया एक बयान बहुत चर्चा में रहा। उनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं। विवाह भले ही उन्होंने वेंस से किया हो, वह मानती हिंदू धर्म को ही हैं। वेंस ने कहा कि उन्हें लगता है कि उषा एक न एक दिन ईसाई धर्म अपना लेंगी। वह उनके साथ चर्च भी जाती हैं और ईसाइयत में रुचि भी रखती हैं। वेंस ने यह भी बताया कि उनके बच्चों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया है। वे उन्हीं तौर-तरीकों से पाले जा रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ साल पहले शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान की ओर से दिया गया यह वक्तव्य याद आ गया कि वह हिंदू हैं, लेकिन उनका बेटा आर्यन इस्लाम को मानता है। इंटरफेथ शादियों में ऐसा हो सकता है कि पिता एक धर्म को मानता हो और मां किसी और धर्म को, लेकिन बच्चों के साथ मुसीबत यह होती है कि उन्हें चुनाव का कोई अधिकार नहीं दिया जाता। जन्मते ही उन पर माता-पिता का धर्म लाद दिया जाता है। प्रायः उनके नाम भी वैसे ही रखे जाते हैं। कई बार नाम फर्क भी हो सकते हैं, जैसे शाहरुख के बेटे का नाम आर्यन या जेडी वेंस के बेटे का नाम विवेक है।

हमें गलतफहमी है कि पश्चिम में लोग सही मायने में पंथनिरपेक्ष होते हैं। वे अपना मजहब किसी पर लादते नहीं हैं। एक ही घर में अलग-अलग पंथों को मानने वाले लोग रह सकते हैं और राज्य का कोई मजहब नहीं होता। वास्तविकता में ऐसा है नहीं। यदि ऐसा होता तो अमेरिकी राष्ट्रपतियों को बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ क्यों लेनी पड़ती? क्यों इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को कहना पड़ता कि वे ईसाई हैं। जेडी वेंस के बयान को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वे शायद ट्रंप के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए कैथोलिक बहुल अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। जब वेंस उपराष्ट्रपति बने थे तो भारतीय लोग बड़े खुश हुए थे कि चलो उनकी पत्नी का भारत से कुछ रिश्ता है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वे भारत भी आए और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी गए। न जाने क्यों जब भी किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को कोई

यरुशलम के एक चर्च में जेडी वेंस और उषा वेंस ● फाइल

बड़ा पद मिलता है या उसे कोई सफलता हासिल होती है तो हम उसे अपने ही चश्मे से देखने लगते हैं। सोचते हैं कि अपनी जड़ों के कारण यह व्यक्ति भारत के लिए भी कुछ अच्छा करेगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए भारत में बड़ी प्रार्थना की गई थी। वे बाइडेन प्रशासन में उपराष्ट्रपति थीं। हम भूल गए कि वे अतीत में किस तरह भारत विरोधी बयान दे चुकी हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जो विदेशी नागरिक है, वह अपने ही देश को प्राथमिकता देगा, भले ही उसकी जड़ें भारत में रही हों।

मजहबी कारणों से इस धरती पर जितने लड़ाई-झगड़े और खून-खराबा हुआ है, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। इस लड़ाई-झगड़े के पीछे मूल सोच यह रहता है कि हमारा मजहब दूसरे से श्रेष्ठ है। इसलिए जब तक यह पूरी दुनिया ही हमारे मजहब के झंडे तले नहीं आ जाती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मतांतरण पर अरबों-खरबों खर्च इसीलिए किए जाते हैं। जो लोग विविधता को सेलिब्रेट करते हैं, वही यह भी चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ हमारी पसंद का ही धर्म रहना चाहिए। उन्हें लगता है कि ऐसा होने पर ही दुनिया जीने के काबिल रहेगी।

एक लड़की का दशकों पहले अमेरिका में रहने वाले एक लड़के से विवाह हुआ। लड़की हिंदू थी, लड़का ईसाई। लड़के ने कहा कि उसकी कोई और शर्त नहीं है, सिवाय इसके कि लड़की ईसाई बन जाए। लड़की ने ऐसा ही किया। साथ में पढ़ने वाली एक महिला ने एक मुस्लिम से विवाह किया। उसने धर्म नहीं बदला, लेकिन उसके दोनों बच्चे पति के धर्म को ही मानने वाले बने। एक मुसलमान लड़की स्विट्जरलैंड में उच्च पद पर काम करती थी। वह दक्षिण अफ्रीका से आई थी। उसका इंग्लैंड के एक लड़के से प्रेम हो गया। जब दोनों को लगा कि विवाह कर लेना चाहिए तो लड़की ने कहा कि उनके बच्चे मुसलमान ही होंगे। क्या ऐसे विवाह सच में प्रेम विवाह हैं? आम तौर पर लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में देखना चाहते हैं, जैसे वे खुद हैं। साफ है कि बातें भले ही पंथनिरपेक्षता और सारे धर्मों का सम्मान करने को लेकर की जाएं, चाहत अपने धर्म के प्रसार की ही होती है। दुनिया में कोई और समूह इतने बड़े नहीं हैं, जितने धार्मिक समूह। इनके हिस्से बनकर हम ताकतवर महसूस करते हैं, क्योंकि कोई भी अकेला रहकर जी नहीं सकता। इसीलिए सब किसी न किसी धर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो लोग खुद को नास्तिक कहते हैं वे भी कई बार बेहद कट्टर साबित होते हैं। उदाहरण के तौर पर हिटलर और जिन्ना का नाम लिया जाता है।

जेडी वेंस हों या ट्रंप, वे किसी न किसी रूप में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते हुए अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। वेंस की ओर से अपनी पत्नी के धर्म बदलने की चाह के पीछे यही मान्यता दिखती है कि जो धर्म पति का हो, वही पत्नी का होना चाहिए। उषा वेंस क्या करती हैं, यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन संभव है कि वे पति की राष्ट्रपति बनने की इच्छा पूरी करने के लिए न चाहते हुए भी ऐसा करें। आखिर यह तथ्य है कि अतीत में अमेरिका में दूसरे धर्मों के कई नेता राष्ट्रपति के तब उम्मीदवार बने, जब उन्होंने ईसाइयत को अपना लिया।

(लेखिका साहित्यकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

दुख से सीख

सुख और दुख जीवन के दो अनिवार्य हिस्से हैं। प्रत्येक व्यक्ति इनकी अनुभूति करता है। यह भी सच है कि व्यक्ति केवल सुख के आनंद को भोगने की लालसा रखता है। उसे दुख शब्द सुनने से भी भय लगने लगता है। सुख की अनुगूंज से उसके कान केवल उल्लास का मधुर संगीत सुनने के अभ्यस्त हो जाते हैं। सुख को ही वह जीवन का ध्येय बना लेता है, परंतु सुख के पीछे-पीछे दुख की बदली भी अपनी गति से जीवन में प्रवेश करती है। दुख, पीड़ा, संकट आदि सब हमारे जीवन में यथासमय प्रवेश करते ही हैं। इन्हें स्वीकार करने का साहस हम सभी को होना ही चाहिए। अन्यथा दुख अथवा कष्ट के अनायास आगमन पर हम टूटकर बिखर जाएंगे। जीवन की गति थम जाएगी। हमें सदैव स्वयं को मजबूत रखना चाहिए। जीवन अप्रत्याशित है। कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। दुख के झंझावातों से लड़ने एवं उससे बाहर निकलने की सामर्थ्य हमें स्वयं अर्जित एवं विकसित करनी होगी।

देखा जाए तो दुख हमें आंतरिक रूप से अत्यंत मजबूत करता है। दुख जीवन में एक परीक्षा बनकर प्रवेश करता है। जिस परीक्षा को हम अपने विवेक और सामर्थ्य से उत्तीर्ण करते हैं। जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता, वह जीवन की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है। दुख और शोक के बादलों के बीच घिर जाने से उसकी जीवटता का क्षय होने लगता है। वह शोक के सागर में डूबने लगता है। दुख को सहजता से स्वीकारना ही बुद्धिमत्ता है। तभी हम प्रगति के पथ पर गतिमान हो सकेंगे। भगवान श्रीराम के जीवन को देखें तो उन्हें भी अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। उन्होंने विवेकपूर्ण तरीके से दुख एवं पीड़ा को सहकर मर्यादा के नवीन मापदंड स्थापित किए। हमें दुख से घबराकर जीवन के संघर्ष से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, अपितु संघर्ष को जीवन का हिस्सा बनाकर स्वयं में निखार लाने का प्रयास करना चाहिए।

ललित शौर्य

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

सेना को लेकर न हो राजनीति

'विभाजनकारी बयान' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय का संदर्भ बिहार चुनाव प्रचार में राहुल गांधी का वह बयान है, जिसमें वे सेना में कुछ जातियों के वर्चस्व पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ऐसा कहना राष्ट्रीय पार्टी के नेता के तौर पर अप्रत्याशित बयान है। इससे पूर्व उन्हें बताना चाहिए था कि बिहार विधानसभा चुनाव टिकट वितरण में उनकी पार्टी ने किस सीमा तक समावेशी भागीदारी सुनिश्चित की है? वे यह भी बताएं बिहार के अलावा जहां भाजपा से उनकी पार्टी का सीधा मुकाबला रहता है, वहां कांग्रेस पर किस वर्ग या समूह का प्रभुत्व रहता है? तभी सही मायने में वे सामाजिक न्याय के पक्षधर कहलाएंगे। ऐसी बयानबाजी से तो केवल सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने वाली राजनीति को ही बल मिलेगा। सेना जैसी संस्था को तो राजनीति से परे ही रखना चाहिए।

mananmk8155@gmail.com

मतभेद बन गई दुश्मनी

राजीव सचान द्वारा लिखित अग्रलेख 'लापता हुई आम सहमति की राजनीति' पढ़ा। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बहुलता, विविधता और विचारों की व्यापकता रही है। इसी विविधता को संतुलित रखने का माध्यम रही आम सहमति की राजनीति, जिसने दशकों तक नीति-निर्माण, सामाजिक मुद्दों और राष्ट्रीय हितों पर राजनीतिक दलों को एक साझा धरातल पर खड़ा रखा। आज यह सहमति तेजी से क्षीण होती दिख रही है। बीते वर्षों में राजनीतिक विमर्श में मतभेद स्वाभाविक प्रक्रिया से आगे बढ़कर विरोध और दुश्मनी का रूप ले चुका है। संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप ने ले ली है। लोकसभा और राज्यसभा में महत्वपूर्ण विधेयकों पर बिना व्यापक चर्चा के निर्णय होने लगे हैं। राजनीतिक दल सदन में भी एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी समझने लगे हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है। समय-समय पर मतदाता सूची में पुनरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव आयोग द्वारा नौ राज्यों एवं तीन केंद्र शासित राज्यों में मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसका पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है। आयुष्मान योजना को पूर्व की दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया था। यह राजनीति में गिरती नैतिकता का परिचायक है। आज राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता की प्राप्ति है, इसीलिए आम सहमति की राजनीति समाप्त होती जा रही है। क्षेत्रीय और जातीय पहचान की राजनीति ने साझा राष्ट्रीय दृष्टि को कमजोर किया है। संवाद की संस्कृति समाप्त होती जा रही है। सरकारों को चाहिए कि व्यापक विमर्श की परंपरा को पुनर्जीवित करें, महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में विपक्ष को सहभागी बनाएं। विपक्ष को भी विरोध की राजनीति से ऊपर उठकर रचनात्मक सहयोग देना चाहिए। विरोध सिर्फ यह ध्यान में रखकर न हो कि सत्ता पक्ष है तो उसका विरोध करना है। यदि सत्ता पक्ष गलत फैसले ले रहा है, तो उसका विरोध जरूर हो।

हिमांशु शेखर, गयाजी।

कीमत या लालच के परे है वोट

हमारा एक-एक वोट लोकतंत्र की नींव है और इसका मूल्य किसी भी कीमत या लालच से कहीं अधिक है। यह किसी भी रुपये-पैसे से आंका नहीं जा सकता, क्योंकि यह देश और समाज के भविष्य का निर्धारण करता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर मतदाता का यह परम कर्तव्य है कि वह बिना किसी भय, लोभ या लालच के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान करते समय जाति और धर्म जैसी संकीर्ण पहचानों से ऊपर उठकर उम्मीदवार के चरित्र और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। भ्रष्ट और अपराधी चरित्र वाले व्यक्तियों को वोट देना समाज और राज्य, दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसे लोगों के सत्ता में आने से केवल उनका व्यक्तिगत हित सधता है। यदि कोई चरित्रवान और योग्य प्रत्याशी आपकी व्यक्तिगत विचारधारा से पूरी तरह मेल नहीं खाता, तो भी उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। चरित्रवान नेतृत्व ही निष्पक्ष और विकासोन्मुख शासन दे सकता है। चुनाव में धन-बल का प्रयोग करने वाले लोग अक्सर राजनीति को जनसेवा की बजाय व्यापार के रूप में देखते हैं। सच्ची राजनीति का अर्थ है जनसेवा, न कि मेवा खाना। ऐसे धन-बल का प्रयोग करने वाले प्रत्याशियों से समाज और राज्य का वास्तविक कल्याण संभव नहीं है। चुनाव के दौरान जीतने-हारने की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

प्रसिद्ध यादव, पटना

पोस्ट

ट्रंप के लिए बुरी खबरों का दौर शुरू हो गया। ममदानी ने न्यूयार्क में मेयर का चुनाव जीत लिया। वर्जीनिया और न्यूजर्सी गवर्नर चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी को हरा दिया। नवंबर 2026 में मध्यावधि संसदीय चुनाव से पहले ही ट्रंप की लोकप्रियता ढलान पर दिखने लगी है।

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

बिहार को शहाबुद्दीन जैसे कल और अनंत सिंह जैसे आज को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। हर बाहुबली, हर अपराधी को हराना होगा। जाति की आड़ में गैंग्स्टर बने शातिर बदमाशों को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। तभी सभी दलों को ये संदेश जाएगा कि साफ छवि वालों को टिकट दिए जाएं। क्या यह संभव है?

ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

बचपन में हम ऐसे राजा की कथा सुनते थे, जो दुष्टों का दमन कर उनकी संपत्ति निर्धनों में बांट दिया करता था। योगी सरकार ने माफिया अतीक के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर मकान बनवा कर उन्हें गरीबों में बांटकर उस कथा को साकार भी कर दिया।

मालिनी अवस्थी@maliniawasthi

जनपथ

मतदाता घर से निकल जाय करें मतदान,
जनप्रतिनिधि चुनिए सही जिससे हो कल्याण।
जिससे हो कल्याण दूर ही रहे मुसीबत,
वरना 'जंगल राज' करेगा बहुत बुरी गत।
करके बुरा चुनाव पीटना पड़ता माथा,
सोच-समझकर वोट जरा डालें मतदाता!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 202

****

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, गुरूवार 6 नवम्बर 2025
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

वोट चोरी के सबूतों का हाइड्रोजन बम

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बाद 1 सितम्बर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया था कि वे अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तब भाजपा ने उनका आदतन या रणनीति के तहत मजाक उड़ाया था कि राहुल कांग्रेस को चुनाव नहीं जिता सकते तो वोट चोरी का बहाना बनाते हैं। भाजपा ने हाइड्रोजन बम को सीधे अहिंसा से भी जोड़ा था, मानो गांधीजी के विचारों पर भाजपा से बेहतर कोई और नहीं चलता। भाजपा राहुल गांधी को हतोत्साहित करने की पूरी कोशिश करती रही और सितम्बर के बाद अक्टूबर भी बीत गया तो पार्टी काफी हद तक निश्चिंत हो गई थी कि अब राहुल का हाइड्रोजन बम नहीं फूटने वाला। लेकिन भाजपा को शायद यह अनुमान नहीं था कि बिहार विधानसभा चुनावों में पहले दौर के मतदान से ठीक एक दिन पहले फिर नए सबूतों के साथ देश को बताएंगे कि कैसे चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर लाखों वोटों की हेरा-फेरी की है।

5 नवंबर बुधवार की सुबह खबर आई कि 12 बजे राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करने वाले हैं, इसी के साथ तस्वीरें आईं जिनमें सामान ढोने वाली ट्रॉली में कागजात के ऊंचे-ऊंचे बंडल लाए जा रहे थे। तभी समझ आ गया था कि राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम की चेतावनी सितम्बर में दी थी, अब उसका धमाका होने वाला है। और वाकई ऐसा धमाका हुआ है कि चुनाव आयोग और भाजपा पूरी तरह हिल चुके हैं। राहुल की प्रेस कांफ्रेंस के फौरन बाद ही मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजीजू ने प्रेस कांफ्रेंस की और कहा कि बिहार में कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हरियाणा का जिक्र कर ध्यान भटकाया जा रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बुधवार को राहुल की प्रेस कांफ्रेंस के फौरन बाद चुनाव के विभिन्न चरणों की पारदर्शिता और क्रियान्वयन के बारे में लंबी-चौड़ी सफाई सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इससे पता चलता है कि अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करने की तैयारी पहले ही राज्य चुनाव आयोग ने कर ली थी। हालांकि राहुल गांधी ने बड़े आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगे हैं। उनकी तरफ से इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया है।

ज्ञात हो कि हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा था कि हमारी जीत तय है और सारी व्यवस्था हो गई है। इस व्यवस्था शब्द को पकड़ कर राहुल गांधी ने बताया कि भाजपा की चुनावी रणनीति में इसका असली मतलब क्या है। किस तरह चुनाव आयोग को जरिया बनाकर भाजपा धांधली करवा रही है। लेकिन किरण रिजीजू का कहना है कि व्यवस्था का मतलब हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारी है, जो चुनाव जिताने में मेहनत करते हैं। हालांकि इस वार-पलटवार से उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, जो राहुल गांधी ने उठाए हैं। जैसे मतदाता सूची में राहुल गांधी ने एक ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा दिखाया, जिसका नाम 22 जगहों पर मतदाता के तौर पर दर्ज था। एक प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि मकान नंबर शून्य उन्हें दिया जाता है, जो दुर्भाग्यशाली लोग बेघर होते हैं। जो लैंपपोस्ट के नीचे या फुटपाथ पर रहते हैं। लेकिन हरियाणा की मतदाता सूची में मकान नंबर शून्य वाले कई मतदाताओं के पास बड़े घर का मालिकाना हक राहुल गांधी ने दिखा दिया। राहुल गांधी ने बताया कि कुछ भाजपा नेता और उनके रिश्तेदार जो उत्तरप्रदेश में वोट डालते हैं, उनका नाम भी हरियाणा की वोटर लिस्ट में था। कई वोटर आईडी में फोटो एकदम धुंधली है और उस धुंधले चेहरे को कई बूथों पर वोटर के तौर पर राहुल गांधी ने दिखा दिया। ऐसी गलतियां दो-चार होती तब भी इन पर संदेह नहीं होता। हालांकि कम्प्यूटर और एआई की मदद से जब वोटर लिस्ट बनाई जा रही हो, तब ऐसी गलतियां शून्य होना चाहिए। लेकिन हरियाणा में दस-बीस नहीं कम से कम 25 लाख मतदाताओं की चोरी की गई है। राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस में कुछ लोगों की आपबीती भी सुनाई गई, जिनके नाम लोकसभा चुनावों के वक्त दर्ज थे और जिन्होंने वोट भी दिए थे। लेकिन विधानसभा में उनके नाम काट दिए गए।

संविधान के तहत वयस्क मताधिकार का जो अनूठा उपहार भारतीय नागरिकों को मिला है, वह बेशकीमती है। लेकिन दुख की बात है कि भाजपा के शासन में इस अनमोल तोहफे को चालाकी से छीना जा रहा है। इसलिए बुधवार को राहुल गांधी को सीधा आह्वान करना पड़ा कि जेन ज़ी यानी नयी पीढ़ी के लोग अहिंसक तरीके से इस चोरी को रोकने और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आएं। खुद राहुल गांधी ने भी नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी बताई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट और मीडिया के पाले में भी राहुल ने गेंद डाल दी है कि ये खुद से इस वोट चोरी को रोकने के लिए आगे आते हैं या नहीं। गौरतलब है कि इस समय एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। बिहार चुनाव शुरु होने से पहले ही इसे रोकने की याचिकाएं दर्ज करा दी गई थीं, इन पर कई बार अदालत बैठ चुकी है, लेकिन पहले चरण की वोटिंग से पहले भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है। उधर देश भर में अब एसआईआर की कवायद शुरु हो गई है। जबकि तमिलनाडु, प.बंगाल और महाराष्ट्र में इसका विरोध हो रहा है।

ज्ञानेश कुमार मतदाता सूची शुद्धिकरण की बात करते हैं। लेकिन अब उन्हें बताना चाहिए कि 2 करोड़ मतदाताओं वाले हरियाणा में 25 लाख फर्जी मतदाताओं के सबूत राहुल गांधी दे चुके हैं और ये संख्या बढ़ सकती है, ऐसे में उनका क्या जवाब है। क्या हर बार की तरह राहुल गांधी के इस दावे पर भी फेक का ठप्पा चुनाव आयोग लगा देगा।

याद रहे कि अगस्त में राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर के सबूत दिए थे। जिसमें एक ही मकान पर कई लोगों का पता दर्ज होने, फर्जी पते या नाम या उम्र या लिंग के साथ मतदाता के तौर पर दर्ज होने, एक ही व्यक्ति के पास एक से अधिक जगहों के मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) होने के सबूत आए थे और फिर सितम्बर में अलंद सीट पर ऐसे ही सबूत पेश किए थे। लेकिन हर बार राहुल के दावों को खारिज किया गया। क्या इस रवैये के साथ लोकतंत्र बचा रहेगा, यह बड़ा सवाल है।

जोहरान ममदानी ने नेहरू को याद किया

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

34 बरस के जोहरान ममदानी न्यूयार्क शहर के 111वें मेयर बन गए हैं। जीत के बाद अपने भाषण में ममदानी ने दो मशहूर हस्तियों को याद किया- पं.जवाहरलाल नेहरू और नेल्सन मंडेला। पं. नेहरू ने 14 -15 अगस्त 1947 की आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में ऐतिहासिक भाषण दिया था, उस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी (नियति से मुठभेड़) भाषण की कुछ पंक्तियां जोहरान ममदानी ने उद्धृत की, उन्होंने कहा कि:

'मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों के बारे में सोचता हूं। एक ऐसा क्षण आता है, जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है, और जब एक राष्ट्र की आत्मा, जो लंबे समय से दबाई गई थी, अभिव्यक्ति पाती है।'

अमेरिका, भारत और पूरी दुनिया में मोदी समर्थकों को ममदानी की ये बातें कानों में बुरी तरह चुभी होंगीं। नेहरूजी के जिंदा रहते और उनकी मौत के 61 साल बाद भी अगर कोई उन्हें इस शिद्दत से याद करता है, तो न जाने संघी मानसिकता के लोगों को यह बात कैसे बर्दाश्त होती होगी। क्योंकि भाजपा ने पहले से नेहरूजी के बारे में तरह-तरह की झूठी बातें फैलाकर उन्हें एक अय्याश व्यक्ति की तरह स्थापित करने की कोशिश की, मानो उन्होंने खानदानी दौलत के बूते ऐशो आराम के सिवाए कुछ नहीं किया। लेकिन इतने झूठ प्रचार के बावजूद दुनिया के उदार और लोकतांत्रिक सोच वाले नेता उनके मुरीद हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस देश में जाते हैं, वहां नेहरू-गांधी के विचारों से उनका साक्षात्कार हो ही जाता है, एक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यह भी है। बहरहाल, नेहरूजी के अलावा जोहरान ममदानी ने नेल्सन मंडेला को भी याद किया, जिन्होंने गांधीवादी आदर्शों पर चलते हुए रंगभेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और सफल हुए। ममदानी ने कहा कि: 'आज रात हमने इतिहास लिखा है। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था- 'जब तक यह पूरा नहीं हो जाता, यह हमेशा असंभव लगता है'। मेरे दोस्तों, हमने इसे कर दिखाया है।'

नेहरू और मंडेला को याद करते हुए जोहरान ममदानी अब न्यूयार्क की कमान संभालेंगे और वो सारे वादे पूरे करेंगे जो यहां के कामगार, मेहनतकश समुदाय के जीवन को बेहतर बनाएंगे।

जोहरान ममदानी न्यूयार्क के पहले मुस्लिम और पहले दक्षिण एशियाई मूल के पहले मेयर बने हैं। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि ममदानी वर्ल्ड ट्रेड ट्विन टावर पर 11 सितंबर 2001 को हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद मुस्लिम होते हुए भी न्यूयार्क शहर के मेयर बने हैं। अलकायदा ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसका खामियाजा बरसों तक अल्पसंख्यक समुदाय को शक की निगाहों का सामना करते हुए भुगतना पड़ा। पाठकों को माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट ए टेरेरिस्ट(मेरा नाम खान है और मैं आतंकवादी नहीं हूं) संवाद याद होगा, जो शाहरुख खान अभिनीत माई नेम इज़ खान फिल्म का है। इस फिल्म या इसी तरह 11 सितंबर के बाद बनी कई फिल्मों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ हुए भेदभाव को दिखाया गया। हकीकत यह भी है कि राष्ट्रपति कलाम से लेकर शाहरुख खान जैसे प्रतिष्ठित अभिनेता को अमेरिका के विमानतलों पर अपमानजनक तरीकों से सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। लेकिन यह अमेरिकी समाज की उदार सोच, व्यापक नजरिया और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था का कमाल है, जिसने अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए गए कट्टरपंथी अभियान के आगे सिर नहीं झुकाया।

दुनिया भर में इस समय दक्षिणपंथी, पूंजीवादी और धार्मिक कट्टरता वाली सोच राजनीति पर हावी हो चुकी है। इसलिए जोहरान ममदानी की जीत एक बड़ी राजनैतिक घटना के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि वे अमेरिका के महज एक शहर के मेयर ही चुने गए हैं और इसका वैश्विक राजनीति पर कोई प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ने वाला है।

जब वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकी हमला हुआ, उस समय जोहरान ममदानी केवल 9 बरस के थे, और मैनहटन में ही रह रहे थे। लेकिन उनकी धार्मिक पहचान पर इस घटना को लेकर हमले हुए। साउथ कैरलाइना से रिपब्लिकन पार्टी की प्रतिनिधि नैंसी मैक ने 25 जून को एक पोस्ट में ईद पर ज़ोहरान ममदानी के कुर्ते पायजामे वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, '9/11 के बाद हमने कहा था- हम कभी नहीं भूलेंगे। मुझे लगता है कि हम भूल गए। यह बहुत ही दुखद है।' नैंसी मैक ने कुर्ते पायजामे को आतंकवाद से जोड़ दिया। कट्टरपंथ और संकीर्ण मानसिकता से चलने वाले लोग इसी तरह भावनाओं को भुनाने का काम करते हैं। याद कीजिए 2019 झारखंड चुनावों में नरेन्द्र मोदी ने कपड़ों से अल्पसंख्यकों की पहचान की बात कही थी। जोहरान ममदानी पर मुसलमान होने के नाम पर कई हमले हुए, उनके परिवार को धमकियां मिलीं। लेकिन वे इनसे विचलित नहीं हुए। बल्कि उन्होंने कहा कि: 'मैं किसी ऐसे देश का समर्थन नहीं कर सकता जहां नागरिकता धर्म या किसी और आधार पर बांटी जाती हो। हर देश में समानता होनी चाहिए, यही मेरा विश्वास है।' यह बात उन्होंने इजरायल को यहूदी देश के तौर पर मान्यता देने के विरोध में कही थी। हालांकि इससे पता चलता है कि ममदानी का नागरिक समानता और मानवाधिकारों पर कितना यकीन है।

अमेरिका की नागरिकता और बचपन से वहीं जीवन गुजारने के बावजूद उनकी भारतीय मूल का होने की पहचान समय-समय पर सामने आती रही। उनके प्रचार कार्यक्रम काफी रोचक होते थे, जिसमें वे अक्सर हिंदी फिल्मों पर आधारित करते थे। यहां तक कि मेयर चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जब जनता को संबोधित किया तो उसमें पीछे धूम मचा ले का टाइटल ट्रैक बज रहा था। हिंदी फिल्मों का ऐसा असर जोहरान ममदानी पर स्वाभाविक है। वे सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक जैसी उम्दा फिल्म बनाने वाली मीरा नायर के बेटे हैं। उनके पिता महमूद ममदानी राजनीति शास्त्र के ज्ञाता और शिक्षक हैं। महमूद ममदानी के परिवार का गुजरात से नाता है। लिहाजा जोहरान ममदानी अपनी गुजराती पहचान का जिक्र भी करते हैं।

2002 के गुजरात दंगों में जिस तरह मुसलमानों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ और उसमें आज तक इंसाफ का इंतजार है, उस बारे में भी जोहरान ममदानी खुलकर बोलते रहे हैं। नरेन्द्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जोहरान एक ही पलड़े पर तौलते हैं। इस वजह से रिपब्लिकन पार्टी के नेता तो जोहरान ममदानी से चिढ़ते ही हैं, अमेरिका में रहने वाले कट्टरपंथी हिंदुओं का एक धड़ा भी उनके खिलाफ ही था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी का फायदा उठाते हुए मेयर चुनाव से ठीक पहले न्यूयार्क शहर को एक तरह से धमकी देते हुए कहा था कि 'यदि वामपंथी उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के महापौर पद पर चुनाव जीतते हैं, तो संभव है कि मैं अपने प्यारे पहले घर के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि के अलावा संघीय निधि से कोई और मदद नहीं करूंगा, क्योंकि एक वामपंथी के रूप में, इस महान शहर की सफलता या यहां तक कि अस्तित्व में बने रहने की कोई संभावना नहीं है! किसी वामपंथी के सत्ता में आने से हालात और बदतर हो सकते हैं, और मैं राष्ट्रपति होने के नाते, खराब स्थिति में पैसा नहीं भेजना चाहता। देश चलाना मेरा दायित्व है, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर ममदानी जीत गए तो न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह हो जाएगा।' ट्रंप ने ममदानी को निवार्सित करने की धमकी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद जनता ने ममदानी के लिए ही वोट किया।

ट्रंप ने जिस तरह उनके वामपंथी विचारों की भर्त्सना की है, वह स्वाभाविक है। क्योंकि राजनीति भी ट्रंप के लिए व्यापार का ही एक जरिया है। एलन मस्क ने भी जोहरान ममदानी का विरोध किया था। मस्क भी बड़े व्यापारी ही हैं।

दुनिया भर में इस समय दक्षिणपंथी, पूंजीवादी और धार्मिक कट्टरता वाली सोच राजनीति पर हावी हो चुकी है। इसलिए जोहरान ममदानी की जीत एक बड़ी राजनैतिक घटना के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि वे अमेरिका के महज एक शहर के मेयर ही चुने गए हैं और इसका वैश्विक राजनीति पर कोई प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ने वाला है। मगर इसके दूरगामी असर की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

जोहरान ममदानी की जीत को डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब ममदानी की असली परीक्षा शुरु होगी। क्योंकि अमेरिका की सत्ता इस समय ट्रंप जैसे इंसान के हाथ में है, जिसके लिए सबसे पहले व्यापारिक लाभ है, बाकी सारी चीजें दोयम हैं। ट्रंप अपनी इस हार को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे और हर तरह से ममदानी को झुकाने की कोशिश करेंगे। कट्टरपंथी और पूंजीवाद के जरिए शोषण के हिमायती लोग इसमें उनका साथ देंगे, ऐसे में जोहरान ममदानी को अपने राजनैतिक कौशल से इन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मगर फिलहाल कट्टरपंथ पर उदारवाद की जीत के जश्न का मौका है। बाकी नेहरू और मंडेला को याद कर जोहरान ममदानी ने जाहिर कर दिया है कि वह किस तरह अपने विरोधियों का मुकाबला करेंगे।

अमेरिका को दुनिया को परमाणु संकट की ओर धकेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती

■ डॉ. अरुण मित्रा

29 अक्टूबर को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि 'अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के कारण, मैंने युद्ध विभाग (पेंटागन) को समान आधार पर हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी।' यह बयान न केवल परेशान करने वाला है, बल्कि बेहद खतरनाक भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया आखिरी परमाणु विस्फोट 1992 में हुआ था। उत्तर कोरिया के अलावा, 1990 के दशकांत से किसी भी देश ने परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं किया है।

ऐसे समय में जब दुनिया के बड़े हिस्से पहले से ही प्रत्यक्ष या छद्म युद्धों में उलझे हुए हैं—और जब कई क्षेत्र विनाशकारी गृहयुद्धों का सामना कर रहे हैं, जिससे सामूहिक हत्याएं, भुखमरी और मानवीय पीड़ा हो रही है—ऐसा आदेश दुनिया को अंधकार के एक नए युग में धकेलने का खतरा पैदा करता है। इससे पहले से ही ख़तरनाक वैश्विक हथियारों की होड़ और तेज़ हो जाएगी। जिन देशों के पास पहले से ही परमाणु हथियार हैं, वे अपने शस्त्रागार का और भी तेज़ी से विस्तार और आधुनिकीकरण करेंगे। इसके अलावा, परमाणु हथियार विकसित करने की तकनीकी क्षमता वाले देश भी इस दौड़ में शामिल होने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

ईरान, जो लंबे समय से परमाणु हथियारों के विकास को लेकर अमेरिकी आरोपों का निशाना रहा है, ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने राष्ट्रपति ट्रम्प के फ़ैसले को 'प्रतिगामी' और 'गैर-ज़िम्मेदाराना' बताया और अमेरिकी नेता को 'परमाणु-सशस्त्र धौंसिया' कहा। ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि तेहरान अपनी परमाणु सुविधाओं का पुनर्निर्माण करेगा।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस निर्देश को वापस नहीं लेता है, तो रूस भी इसी तरह जवाब देगा। सभी परमाणु शक्तियां बेहतर वितरण प्रणालियों का विकास और परीक्षण कर रही हैं, जिनमें सबसे हाल ही में रूस ने अपने पानी के नीचे चलने वाले 'पोसिडॉन' परमाणु ड्रोन और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले 'बुरेवेस्टनिक' परमाणु-सशस्त्र क्रूज़ मिसाइल का परीक्षण किया है। चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका से परमाणु परीक्षण पर लगी रोक न तोड़ने की अपील की है।

ईरान, जो लंबे समय से परमाणु हथियारों के विकास को लेकर अमेरिकी आरोपों का निशाना रहा है, ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने राष्ट्रपति ट्रम्प के फ़ैसले को 'प्रतिगामी' और 'गैर-ज़िम्मेदाराना' बताया और अमेरिकी नेता को 'परमाणु-सशस्त्र धौंसिया' कहा। ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि तेहरान अपनी परमाणु सुविधाओं का पुनर्निर्माण करेगा। जून में, अमेरिका ने ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले किए, जिनके बारे में वाशिंगटन का कहना है कि वे परमाणु हथियार विकसित करने के एक कार्यक्रम का हिस्सा थे। इराक पर अमेरिका के नेतृत्व वाले हमले को इस झूठे दावे के आधार पर उचित ठहराया गया था कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। हालांकि सद्दाम हुसैन के शासन को तुरंत उखाड़ फेंका गया, लेकिन इस आक्रमण ने क्षेत्र को लंबे समय तक अस्थिरता, हिंसा और अराजकता में डुबो दिया। 22 जून, 2025 को भी ऐसा ही एक पैटर्न देखा गया, जब अमेरिकी वायु सेना और नौसेना ने ईरान-इज़राइल संघर्ष के हिस्से के रूप में 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' के तहत ईरान में तीन परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया। ईरान ने आरोपों का खंडन किया और हमले की कड़े शब्दों में निंदा की।

आधुनिक परमाणु हथियार हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि प्रमुख शक्तियों के बीच किसी भी बड़े पैमाने पर परमाणु आदान-प्रदान आधुनिक सभ्यता की नींव को नष्ट कर देगा- जो हजारों वर्षों की मानव प्रगति पर आधारित है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमित परमाणु आदान-प्रदान भी दो अरब से अधिक लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। प्रमाण स्पष्ट हैं : परमाणु हथियार मानवता के अस्तित्व के लिए ख़तरा हैं और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।

परमाणु हथियारों से उत्पन्न गंभीर ख़तरों को समझते हुए, परमाणु-सशस्त्र राष्ट्रों पर निरस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का वैश्विक दबाव लंबे समय से रहा है। हालांकि कुछ संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन प्रमुख शक्तियों ने उन्हें आंशिक रूप से और अक्सर अनिच्छा से ही लागू किया है।

यहां कुछ प्रमुख शस्त्र न्यूनीकरण और नियंत्रण संधियों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधियां (स्टार्ट- 1, 2, और न्यू स्टार्ट), जिनका उद्देश्य अमेरिका और रूस के बीच द्विपक्षीय समझौतों के तहत सामरिक परमाणु हथियारों को कम करना था; मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति (आईएनएफ) संधि (1987); 500 से 5,500 किमी की मारक क्षमता वाली अमेरिकी और सोवियत भूमि-आधारित बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों पर प्रतिबंध; एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल (एबीएम) संधि (1972) जिसके तहत आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई प्रणालियों की तैनाती को सीमित किया गया; सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता (एसएएलटी 1 और 2), जिसके तहत अंतरमहाद्वीपीय और पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या सीमित कर दी गई; परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (एनपीटी), जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है; व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी), जो किसी भी उद्देश्य के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है; और आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी), जो वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और पानी के भीतर परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है।

परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (टीपीएनडब्ल्यू) परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है, यह नवीनतम बहुपक्षीय संधि है जिसे जुलाई 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया था। इस संधि पर 95 देशों ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं और 74 ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि टीपीएनडब्ल्यू को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी समर्थन के साथ पारित किया गया था, लेकिन परमाणु-सशस्त्र देशों ने न तो विचार-विमर्श में भाग लिया और न ही अपने शस्त्रागार को समाप्त करने का कोई इरादा दिखाया।

कुछ संतोषजनक खबर यह है कि कई क्षेत्रों ने स्वयं को परमाणु-हथियार-मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। उनमें शामिल हैं लैटिन अमेरिका (ट्लाटेलोल्को संधि), दक्षिण प्रशांत (रारोटोंगा संधि), अफ्रीका (पेलिंडाबा संधि), दक्षिण पूर्व एशिया (बैंकॉक संधि), तथा मध्य एशिया (सेमिपालाटिंस्क संधि)।

मंगोलिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने खुद को एकल-राज्य परमाणु-हथियार-मुक्त क्षेत्र घोषित किया है, यह दर्जा उसने 1992 में स्थापित किया था और जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसका कानून अपने क्षेत्र से परमाणु हथियारों या उनके घटकों के विकास, परीक्षण, कब्जे या परिवहन पर प्रतिबंध लगाता है।

दुर्भाग्य से, कुछ प्रमुख संधियां ध्वस्त हो गई हैं। 2019 में अमेरिका के परमाणु हथियार संधि से हटने के बाद आईएनएफ संधि प्रभावी रूप से समाप्त हो गई, जिसके बाद 2025 में रूस का आधिकारिक रूप से इससे बाहर निकलना तय हुआ। इस ऐतिहासिक समझौते के टूटने से आपसी विश्वास कम हुआ है, सुरक्षा जोखिम बढ़े हैं, और हथियारों की होड़ फिर से शुरू होने का खतरा बढ़ गया है।

न्यू स्टार्ट संधि, जो अमेरिका और रूस की परमाणु शक्तियों को सीमित करने वाला अंतिम समझौता है, 4 फ़रवरी, 2026 को समाप्त होने वाला है। यदि कोई नया समझौता इसकी जगह नहीं लेता है, तो दोनों देशों को अपने परमाणु शस्त्रागार पर किसी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबंध हीन भविष्य का सामना करना पड़ेगा।

परमाणु-विहीन राष्ट्रों और दुनिया भर के शांतिप्रिय लोगों के लिए परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाने का समय आ गया है। मानवता का अस्तित्व सामूहिक साहस, बुद्धिमत्ता और सामूहिक विनाश के हथियारों पर आधारित झूठी सुरक्षा के परित्याग पर निर्भर करता है। कुछ परमाणु हथियार संपन्न देशों, विशेष रूप से अमेरिका, को दुनिया को अस्तित्व के खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

शांति भय से सुरक्षित नहीं रह सकती- इसे न्याय, सहयोग और सभी राष्ट्रों के सम्मान पर आधारित होना चाहिए।

आपके पत्र

यूक्रेन युद्ध से वैश्विक संकट की आहट तबाही सन्निकट

रूस-यूक्रेन युद्ध अब केवल दो देशों का संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह सम्पूर्ण विश्व के लिए संभावित विनाश का संकेत बन चुका है। यह युद्ध आधुनिक सभ्यता के सामने एक ऐसी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है जिसमें मानवीय संवेदनाएं, वैश्विक शांति और राजनीतिक संतुलन सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। रूस की बौखलाहट, अमेरिका और नाटो देशों के हस्तक्षेप के साथ मिलकर इस युद्ध को तीसरे विश्वयुद्ध की दहलीज़ पर ला खड़ा कर चुकी है। रूस ने अमेरिका को खुले शब्दों में चेताया है कि यदि पश्चिमी देश इसी तरह यूक्रेन की आर्थिक और सामरिक मदद करते रहे तो उसे परमाणु या जैविक हथियारों के प्रयोग पर विवश होना पड़ सकता है। यह चेतावनी केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि आने वाले संकट का संकेत है, क्योंकि कीव पर हाल में किए गए रूस के बमवर्षक हमलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुतिन अब अपनी हार छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेरिकी अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरस ने दावोस में अपने वार्षिक संबोधन में कहा था कि रूस और चीन का सीमा-विहीन गठबंधन वैश्विक शांति के लिए अत्यंत खतरनाक है। यदि पुतिन, शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच यह रणनीतिक गठबंधन गहराता गया तो विश्वयुद्ध की संभावना को टाला नहीं जा सकेगा। सोरस के अनुसार यह संघर्ष अगर अनियंत्रित हुआ तो हमारी सभ्यता इसे झेल नहीं पाएगी और यह युद्ध समस्त मानवीय मूल्यों को मलबे में बदल देगा। पुतिन और शी जिनपिंग ने अपने हालिया संयुक्त बयान में स्पष्ट कर दिया था कि उनके संबंधों और सहयोग की कोई सीमा नहीं है। यह बयान एक नई ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का संकेत है जिसमें चीन और रूस एक साथ पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने की तैयारी में हैं। पुतिन ने शी जिनपिंग को यूक्रेन पर विशेष सैन्य अभियान की जानकारी भी पहले ही दे दी थी, जिससे स्पष्ट है कि यह सब एक सुनियोजित रणनीति के अंतर्गत हुआ था। इसी बीच रूस के एक राजदूत ने इस्तीफा देकर पुतिन की कार्रवाई का विरोध किया, वहीं युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों ने भी देश के भीतर असंतोष प्रकट किया है। यूक्रेन पर आक्रमण के समय पुतिन को यह भ्रम था कि यूक्रेन में रहने वाले रूसी भाषा-भाषी नागरिक उनका समर्थन करेंगे, परंतु हुआ इसके ठीक विपरीत—उन्होंने यूक्रेन पर हमले की निंदा करते हुए रूस से नाता तोड़ लिया। यह पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका था जिसने उनके आत्मविश्वास को हिला दिया। अब उन्हें यह एहसास होने लगा है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक भूल की है और इसी कारण वे संघर्षविराम की संभावनाएं तलाशने में जुटे हैं, किंतु वर्तमान परिदृश्य में विश्व समुदाय का विश्वास रूस से उठ चुका है। अब स्थिति यह बनती जा रही है कि या तो पुतिन अपनी राजनीतिक विफलता स्वीकार कर पद छोड़ दें या फिर चीन के सहयोग से इस संघर्ष को और गहराकर विश्व युद्ध की दिशा में ले जाएं।

-संजीव ठाकुर

ललित सुरजन की कलम से

विश्व राजनीति के दो संकेत

'एंजेला मर्केल इस समय यूरोप की सबसे कद्दावर नेता हैं, वे सबसे अधिक अनुभवी भी हैं और उन्होंने एक विश्व नेता के रूप में अपनी छवि निर्मित की है। एक ओर जहां विश्व के अनेक देश राजनीतिक कारणों से विस्थापित हुए जनसमूहों को शंका की दृष्टि से देखते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनके प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहते और उन्हें अपने देश में शरण लेने से रोकते हैं, वहीं एंजेला मर्केल सीरिया और अन्य अरब देशों से आए शरणार्थियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का परिचय दे रही हैं। इस समय जर्मनी में बड़ी संख्या में विस्थापितों को शरण मिली हुई है। सुश्री मर्केल पर चुनाव के समय दबाव था कि वे शरणार्थियों के प्रति कठोर रुख अपनाएं अन्यथा उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने चुनावी जीत अथवा राजनीतिक लाभ के लिए सिद्धांतों से समझौता करने से इंकार कर दिया। इस कारण उनसे बहुत से मतदाता नाराज हुए और उनको मिले वोटों में इसी वजह से कमी आई। जबकि भावनाओं को भड़काने वाले अतिवादी दल के वोटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई।'

(देशबन्धु में 12 अक्टूबर 2017 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2017/10/blog-post_11.html

पावन प्रसंग

दुखों को हरने का साधन है योग साधना

जीवन की जितनी भी कठिनाई है जो कुछ भी उसमें हमें आकंठित है, उसका समाधान है योग साधना। योग साधना वह बीज तत्व है, जो एक बार यदि हमारा हृदय ही परिवर्तित हो जाता है। इस योग साधना द्वारा ही जीवन समग्र रूप से परिष्कार के पथ पर बढ़ चलता है। मनुष्य की आत्मा चाहती है कि वह बंधनों में न रहे, उसे पीड़ा-विछोह का सामना न करना पड़े तथा वह हर प्रकार से उन्नत होती जाए। इसी कामना को पूरा करने प्रत्येक जागरुक हृदय कदम बढ़ाता है तथा ईश्वर में सदा एकरस हो अपने उज्जवल स्त्रोत से मिलने को तत्पर हो जाता है। जब तक हम इस संसार में ही रमण करेंगे हमारी आत्मा पूर्ण परिष्कृत नहीं हो पाएगी। उसे यदि अपने भाग्योदय की दिशा में बढ़ना है तो सर्वप्रथम अपने में उस शक्ति को धारण करना होगा, जो कि यथार्थ में हमारा पथ प्रदर्शन करने में समर्थ हो। उसे ही योग की आधारशिला कहते हैं। जिसके पास यह है वह इस संसार के माया-मोह के मध्य कभी विचलित नहीं हो सकता है, उसकी आत्मा कहेगी कि मैं जिस कार्य के लिए बनी हूं, वह तभी संभव है जब मेरा एकाधिकार अपनी वृत्तियों पर हो।

सभी प्रकार के कष्ट, बाधाओं से परे मुझे अपने उज्जवल स्त्रोत से मिलना है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार इस संसार के बंधन को स्वीकार नहीं कर सकती। इस प्रकार जिस मनुष्य के भीतर आत्मा के पुकार की ऐसी तड़प जाग उठी कि उसे तो मात्र ईश्वर की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना है, वह कभी भी भ्रमजाल में नहीं रह सकता है।

योग साधना का भी उद्भव केंद्र यही है कि हमने उसे पहचान लिया जो कि सभी क्षुधाओं का अंत है, जिसके बाद पाने को कुछ नहीं रह जाता तथा इस संसार के कल्याण में ही अपनी दृष्टि जा लगती है। ऐसी कृपा उसी के साथ होगी जो हर प्रकार के दुख-द्वंद्व से परे ईश्वर के साहचर्य में रहना जानता हो। जब तक ईश्वर हमारे साथ हैं, तब तक किसी प्रकार की पीड़ा आसक्ति का हमारे जीवन में स्थान नहीं हो सकता है। ईश्वर वह शक्ति है, जो सदैव हमें जगाए रखे, जिसकी कृपा से मनुष्य अपने दैवी उत्तराधिकार की प्राप्ति किया करता है। हम उस ईश्वर से एकरूप बनें,यही योग साधना है तथा इसके द्वारा जीवन में दुखों का अंत संभव है। जिसने अपने भीतर झांकना सीख लिया, उसके कदम योग साधना के पदचिन्हों पर बढ़ चलते हैं। योग ही वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य हर प्रकार की कठिनाई से पार पाने में समर्थ होता है। उसकी आत्मा सदा प्रकाशित रह कर उसे अपने दैवी स्वरूप की प्राप्ति कराती है। उसकी जीवन विषयों से इतर आत्मा की प्रेरणा से चलने लगता है तथा ऐसा मनुष्य सच में धन्य है, जिसने अपने भीतर छिपी संभावना को उजागर कर लिया हो, योग यही अवसर है हमें प्रदान करता है तथा इसके द्वारा मनुष्य की आत्मा कल्याण को प्राप्त करती है।

-अखंड ज्योति

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

कल्पमेधा

आचरण-रहित विचार कितने ही अच्छे क्यों न हों, उन्हें खोटे मोती की तरह समझना चाहिए।

- महात्मा गांधी

हादसों की पटरियां

देश में आम लोगों के लिए रेल सेवाएं यातायात का प्रमुख साधन हैं। रोजाना लाखों लोग रेलगाड़ियों में सफर करते हैं। सरकार यह दावा करते हुए नहीं थकती कि रेलयात्रा को सुलभ एवं सुरक्षित बनाना उसकी प्राथमिकता में है। फिर क्या वजह है कि रेल हादसों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? कभी दो रेलगाड़ियों के टकराने से दुर्घटना हो जाती है, तो कभी कोई ट्रेन पटरी से उतर जाती है। वहीं, पैदल यात्रियों का ट्रेन की चपेट में आना, तो अब रोजमर्रा की घटनाएं हो गई हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को एक यात्री ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इसके अगले दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रेलगाड़ी से उतर कर पटरी पार कर रहीं महिलाएं दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गईं। इन दोनों हादसों में कई लोगों की जान चली गई। इससे रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर अब तक हुई रेल दुर्घटनाओं से सबक लेकर व्यवस्था में व्याप्त खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की जाती है?

गौर करने की बात है कि एक तरफ देश में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है और दूसरी तरफ रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो की हाल की एक रपट के मुताबिक, देश में वर्ष 2023 में रेलगाड़ियों के टकराने, पटरी से उतरने और पैदल यात्रियों के चपेट में आने से संबंधित चौबीस हजार से अधिक हादसे हुए हैं, जिनमें इक्कीस हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में रेल हादसों में 6.7 फीसद की वृद्धि हुई है। हालांकि, सरकार की ओर से रेल सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल सहित कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन इन्हें व्यावहारिक रूप में ढालने और धरातल पर लागू करने में विभिन्न स्तरों पर बरती जा रही लापरवाही भी रेल हादसों का एक बड़ा कारण है।

बिलासपुर में रेल हादसे की प्रारंभिक जांच रपट में यह सामने आया है कि चालक दल यात्री ट्रेन को लाल बत्ती पर नियंत्रित नहीं कर पाया, जिससे वह आगे जाकर एक मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। यह जांच रपट पांच विशेषज्ञों ने तैयार की है, लेकिन इस पर केवल तीन ने ही हस्ताक्षर किए हैं और इसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुए हादसे को लेकर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कुछ यात्री एक ट्रेन से पटरी वाले हिस्से की ओर उतर गए और वे उसी वक्त सामने से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। यह दावा भी किया जा रहा है कि वहां ऊपरिगामी मार्ग बना हुआ है, लेकिन हादसे में जान गंवाने वाली महिला यात्रियों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। सवाल है कि ट्रेन से उतरने वाले यात्री इसी मार्ग का इस्तेमाल करें, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? देशभर में रेलवे फाटकों पर भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था न होने की वजह से पटरी पार करते समय आए दिन लोगों की जान चली जाती है। सरकार और रेलवे प्रशासन को सुरक्षा से जुड़ी इन व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान देना होगा तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी, तभी हादसों पर अंकुश लग पाएगा।

समानता के बजाय

दुनिया भर में आर्थिक असमानता का लगातार बढ़ते जाना अब कई मायनों में चिंता का विषय बन गया है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ने के साथ जब किसी देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ती है, तो इस पर प्रसन्नता जाहिर करने वाले प्रायः यह भूल जाते हैं कि इसके समांतर करोड़ों लोग हाशिए पर जा चुके हैं और भुखमरी, कुपोषण तथा बेरोजगारी उन्हें घेर रही है। स्वतंत्र विशेषज्ञों की जी-20 समिति की ताजा रपट में भी वैश्विक असमानता पर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2020 में वैश्विक गरीबी में कमी लगभग रुक गई है, लेकिन दुनिया के कई देशों में आर्थिक असमानता बढ़ी है। भारत के संदर्भ में कहा गया है कि यहां सबसे अमीर एक फीसद लोगों की संपत्ति पिछले करीब दो दशकों में बासठ फीसद बढ़ी है। इस चमकती तस्वीर के पीछे एक सच यह भी है कि करोड़ों भारतीय नागरिक बेहद गरीबी में गुजर-बसर कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। रपट में कहा गया है कि करीब सवा दो अरब लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

विश्व भर में आर्थिक असमानता के गंभीर जोखिम कई स्तरों पर दिखने लगे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज की अगुआई में किए गए इस अध्ययन रपट में तो यहां तक चेतावनी दी गई है कि वैश्विक स्तर पर यह असमानता 'संकट' के स्तर पर जा पहुंची है। इससे न केवल लोकतंत्र, बल्कि आर्थिक स्थिरता को भी खतरा है। चीन में भी समान अवधि में शीर्ष एक फीसद लोगों की संपत्ति चौवन फीसद बढ़ी है। इससे पता चलता है कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में आर्थिक असमानता की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे भरना अब आसान नहीं है। हालांकि राजनीतिक स्तर पर इच्छाशक्ति दिखाई जाए, तो इस असमानता को बदला जा सकता है। मगर यह निराशाजनक है कि दुनिया के किसी भी देश की ओर से इस आर्थिक असमानता को पाटने की पहल होती नजर नहीं आ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, जिनसे निपटना बेहद मुश्किल होगा।

अंतरिक्ष में उम्मीदों की नई उड़ान

वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। भारत ने हाल में अपने ताकतवर राकेट एलवीएम3-एम5 से देश का अब तक का सबसे वजनी उपग्रह जीसैट-7आर प्रक्षेपित किया है। यह सफलता दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में भारत की बढ़ती साख की मिसाल है।

अभिषेक कुमार सिंह

भारत अब एक नई उड़ान पर है। यह उड़ान अंतरिक्ष के जरिए देश की सुरक्षा और जनता के सतत विकास के लक्ष्यों को साधने वाली है। इन सपनों को साकार करने में अहम भूमिका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के ताकतवर राकेटों और उपग्रहों की है, जो सफलता के नए कीर्तिमान रचते हुए अपनी क्षमता और योग्यता साबित कर रहे हैं। इसमें सबसे ताजा उपलब्धि बीते दो नवंबर की है, जब इसरो ने अपने सबसे ताकतवर राकेट (एलवीएम3-एम5) से देश का अब तक का सबसे वजनी उपग्रह जीसैट-7आर प्रक्षेपित किया। सामरिक और भारतीय नौसेना की संचालन जरूरतों को साधने के लिए विकसित यह उपग्रह आत्मनिर्भरता के साथ-साथ दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में भारत की बढ़ती साख की मिसाल है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़त की बात आती है, तो मामला वजनदार उपग्रहों और ताकतवर राकेटों पर आकर टिक जाता है। भविष्य की अंतरिक्षीय होड़ वजनदार उपग्रहों को ले जाने, अंतरिक्ष स्टेशनों के निर्माण तथा चंद्रमा और मंगल पर मिशन भेजने की क्षमता को लेकर है। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा दिनोंदिन तेज हो रही है। तथ्यों में देखें, तो अमेरिका में सरकारी एजंसी- नासा और निजी एजंसी- स्पेसएक्स, रूस की रासकासमास, चीन की सीएनएसए और यूरोप की ईएसए एजंसियों से भारत का इसरो प्रतिस्पर्धा में हैं। अमेरिका की स्पेसएक्स दुनिया का अब तक का सबसे ताकतवर राकेट फाल्कन हैवी और स्टारशिप विकसित कर रही है, जो सौ टन से ज्यादा पेलोड (वजन) ले जाने में सक्षम होगा। चीन भी अपने भारी राकेट लांग मार्च5बी और भविष्य के लिए लांग मार्च-9 जैसे सुपर-राकेटों का निर्माण कार्य जारी रखे हुए है। इस किस्म के ताकतवर राकेटों में रूस के प्रोटोन और विकसित किए जा रहे राकेट एंगारा का नाम भी शामिल है।

ऐसे में साढ़े चार टन वजन वाले संचार उपग्रह जीसैट-7आर (सीएमएस-03) के सफल प्रक्षेपण ने भारत और इसरो को वह आत्मबल दिया है, जो देश को सामरिक, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक मिशनों में अग्रणी पंक्ति में शामिल कराने के लिए जरूरी है। उल्लेखनीय है कि जीसैट-7आर अब तक का भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। कई अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकी घटकों वाला यह उपग्रह विशेष रूप से भारतीय नौसेना की संचालन और सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम होना इस बात का संकेत है कि अंतरिक्ष शक्ति के मामले में भारत अब वह दक्षता हासिल कर चुका है, जिसके लिए कभी रूस या अमेरिका की अंतरिक्ष एजंसियों से बाहर कोई विकल्प मौजूद नहीं था।

जहां तक जीसैट-7आर की क्षमताओं की बात है, तो इसे भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे आधुनिक संचार मंच कहा जा सकता है। इससे नौसेना की अंतरिक्ष-आधारित संचार प्रणाली और समुद्री क्षेत्र की निगरानी क्षमता में कई गुना इजाफा होगा। यह उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापक और बेहतर दूरसंचार सेवा प्रदान करेगा। इसमें ध्वनि, डेटा और वीडियो लिंक को तेजी से ग्रहण एवं संप्रेषित करने वाले ऐसे आधुनिक उपकरण

लगाए गए हैं, जो भारतीय नौसेना के जहाजों, विमानों, पनडुब्बियों और समुद्री संचालन केंद्रों के बीच सुरक्षित, निर्बाध तथा वास्तविक समय में संचार की जरूरतों को पूरा करेंगे। जाहिर है कि यह समुद्र में नौसेना की रणनीतिक क्षमताओं में बढ़ोतरी करने में महत्त्वपूर्ण सहायक साबित होगा।

> इसरो ने अपनी स्थापना के साढ़े पांच दशकों के अंतराल में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ताकतवर प्रक्षेपक राकेटों के निर्माण और बहुद्देश्यीय उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने से लेकर चंद्रमा और मंगल ग्रह की खोज संबंधी अभियानों ने पहले से ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की धमक कायम कर रखी है। बीते चार-पांच वर्षों में इसरो ने कई नए मोर्चों पर एक साथ कदम बढ़ाए हैं। वर्ष 2023 में इसरो को कई सफलताएं एक साथ मिलीं, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक उतारना।

करीब साढ़े चार टन वजनी उपग्रह को कामयाबी के साथ अंतरिक्ष की कक्षा में भेजने की घटना को भारत के लिए एक अहम पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। एलवीएम3-एम5 राकेट को उसकी भार उठाने की क्षमता के कारण 'बाहुबली' भी कहा जाता है। राकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस किस्म के जीएसएलवी प्रक्षेपण वाहन की कामयाबी का स्तर यदि हम नापना चाहें तो इसकी एक कसौटी अमेरिका के शुरुआती चंद्र मिशन होंगे। करीब 56 साल पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी नासा ने अपने जिस यान अपोलो-11 से नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा था, उसका वजन 4,932 किलोग्राम था। यानी यदि किसी देश का राकेट पांच टन तक का वजन अंतरिक्ष में ले जाने की हैसियत रखता है, तभी उसे चंद्रमा पर इंसान भेजने के सपने के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से एलवीएम3-एम5 ने नया करिश्मा दिखाया है, उसका अर्थ यह निकलता है कि इस राकेट से जल्द ही पांच टन तक के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है। इससे चंद्रमा पर इंसान भेजने की भारत की दावेदारी पुख्ता होती है। चंद्रयान-4 के प्रक्षेपण में इसी राकेट के इस्तेमाल की योजना है।

बहरहाल, इस प्रक्षेपण के जरिए इसरो ने साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष अभियान अब सिर्फ हमारी जिज्ञासाओं का मामला भर नहीं रह गया है, बल्कि भारत ने एक के बाद एक जो सफलताएं अर्जित की हैं, उनके जरिए खोजों एवं अनुसंधानों से कई संसाधनों के दोहन के रास्ते खुलते हैं। इसके जरिए कारोबारी हित साधे जा सकते हैं और रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। अंतरिक्ष में उपलब्धियों की बात करें, तो अमेरिका और रूस के बाद चीन इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेज चुका है और इससे आगे चलकर चंद्रमा के खनिजों के दोहन की बात भी उसके जेहन में है। साथ ही वह अपने राकेटों से विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण बाजार में भी सेंध लगाना चाहता है।

अपनी स्थापना के साढ़े पांच दशकों के अंतराल में इसरो ने एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ताकतवर प्रक्षेपक राकेटों के निर्माण और बहुद्देश्यीय उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने से लेकर चंद्रमा और मंगल ग्रह की खोज संबंधी अभियानों ने पहले से ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की धमक कायम कर रखी है। बीते चार-पांच वर्षों में इसरो ने कई नए मोर्चों पर एक साथ कदम आगे बढ़ाए हैं। वर्ष 2023 में इसरो को कई सफलताएं एक साथ मिलीं, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक उतारना। तब यह कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। यह कामयाबी इसलिए भी अहम मानी जा सकती है, क्योंकि न तो अमेरिका जैसी महाशक्ति ऐसा कर पाई है और न ही उसका चिर-प्रतिद्वंद्वी रूस वर्ष 2023 में ही आनन-फानन में किए गए ऐसे ही प्रयास में सफलता हासिल कर पाया था।

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अरसे से दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजंसियों की नजर थी, लेकिन वैज्ञानिक और तकनीकी धरातल पर यह काम इतना कठिन है कि इसे अंजाम तक पहुंचाना रूस-अमेरिका या चीन के लिए भी एक चुनौती बन गया था। इसे भी ध्यान में रखना होगा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में किसी बढ़त का कोई मतलब तभी है, जब उससे कारोबार और अंतरिक्ष अनुसंधान के अलावा कुछ ठोस जमीनी लक्ष्य भी हासिल हों और उनसे देश की जनता की बेहतरी एवं विकास का कोई रास्ता खुले। उम्मीद है कि इसरो की क्षमताओं के बल पर देश जो कुछ हासिल करेगा, उससे ठोस आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा और उसका फायदा जनता को मिलेगा।

मुश्किल वक्त

प्रभात कुमार

जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। हम अपने उद्देश्यों में सफल होने के लिए ईमानदार प्रयास कर रहे होते हैं। एकदम नहीं, कुछ समय बाद विश्वास उगता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी कोशिशों का परिणाम एक दिन अच्छा ही निकलेगा। उठते-बैठते हमारे विचारों और भावनाओं में, 'धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय' जैसी पुरानी धारणाएं भी उगती रहती हैं। ऐसे व्यावहारिक विचार हमें आने वाले समय के प्रति आशावान बनाते हैं। हमें धैर्य थमाते हैं। भागदौड़ भरे जीवन में जबरदस्ती तेज चलने की गति को धीमा करते हैं, जिससे हमारे मानस और शरीर को आराम मिलता है। जिंदगी खुशगवार रहने की कोशिश करती है। विवाह के बाद अधिकांश दंपति संतान चाहते हैं। परिवार में शिशु जन्म की प्रतीक्षा हो रही हो, तो खुशी मनाने की प्रतीक्षा और तैयारी में कई व्यक्ति शामिल रहते हैं। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण किरदार तो भावी मां का ही रहता है, जो विवाह के साथ ही, और फिर प्रसव के अप्रत्याशित समय तथा उसके बाद भी डाक्टर की सलाह पर अमल करती है। नौकरी करने वाली महिला का प्रयास रहता है कि जब तक हो सके, काम करते हुए सक्रिय रहे। उसे प्रसूति समय की ओर होती तैयारियों के दौरान पारिवारिक सलाह, संतुलित खानपान, दवाइयों और निश्चित अंतराल पर हो रहे चिकित्सीय परामर्श और जांच की प्रक्रिया से गुजरना होता है। चिकित्सक की महंगी फीस, दवाइयों की कीमत अदा करनी होती है।

सामान्य चल रही स्थिति में महत्त्वपूर्ण अंतराल तब आता है, जब शिशु जन्म होने में कुछ दिन ही बाकी रह जाते हैं। उम्मीद रहती है कि सब ठीक चल रहा है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वक्त किस घड़ी अपना मिजाज बदल लेगा, कह नहीं सकते। चिकित्सक ने गर्भावस्था को आदर्श मानते हुआ कहा कि सब ठीक है। प्रसव से ठीक पहले शिशु अपनी अवस्था बदल लेता है और मां, पिता और चिकित्सकों की टीम को चुनौतीपूर्ण स्थिति में ला खड़ा करता है। ऐसी स्थिति में मां सबसे ज्यादा जोखिम झेलती है और उतना ही संकट दुनिया में आने वाला बच्चा सहता है। हालांकि अगर पिता स्त्रियों के प्रति संवेदनशील मिजाज रखता है, तो उसकी हिम्मत भी कम जोखिम भरी नहीं होती।

जहां माता-पिता साथ हों, वहां वास्तविक व्यावहारिक संबल मिल जाता है, लेकिन जहां कोई प्रियजन साथ नहीं हो पाता, तो परेशानियां सवाल खड़े करती है कि जो होना है, होकर रहेगा। कठिन समय के लिए आपकी तैयारी कितनी रही? हम यह भूल जाते हैं कि अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए क्या जरूरी तैयारी करनी चाहिए थी। यह हम तब समझते हैं जब आपात समय आ चुका होता है और हमारे पास स्थिति से किसी भी तरह निपटने के सिवा और कोई विकल्प नहीं रह जाता।

कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ ही लम्हों में स्थिति का रूप-रंग बदल जाता है। जिंदगी कांटों के बीच उलझ जाती है। व्यक्ति सामान्य जिंदगी जीते हुए सकारात्मक सोचता है। उसे लगता है, सब ठीक रहेगा, लेकिन हम अक्सर यहीं गलती करते हैं। सहज चलते समय के दौरान व्यक्ति कठिन समय के लिए तैयारी करना भूल जाता है और जब अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो वक्त ऐसी भाषा में इम्तिहान लेता है, जो हमने पढ़ी नहीं होती। असमंजसों की भीड़ जमा हो जाती है। वक्त तो कभी भी नई करवट ले सकता है।

आने वाला जीवन सुचारु रहे, इसलिए मासिक आय में मिली राशि में से सबसे पहले बचत के रूप में कुछ फीसद रखने की बहुमूल्य सलाह गौर करने लायक है। यह बचत आकस्मिक, अनियोजित खर्चों के लिए की जाती है। बीमा की महत्ता हमेशा बनी रही है। कठिन समय में बीमा राशि बहुत बड़ा सहारा बनती है। व्यक्ति जान खोता है, लेकिन बीमा उपलब्ध होने के कारण बचे हुए व्यक्तियों की जिंदगी को सहारा मिल जाता है। वाहन का बीमा पहले ही करवाया जाता है, ताकि दुर्घटना में हुआ नुकसान झेला जा सके। जीवन की पल-पल बदलती, संघर्षमय, असुरक्षित परिस्थितियों में सशक्त आर्थिक पक्ष की बहुत जरूरत है। आपात स्थिति में घर के बुजुर्ग बहुत सहयोगी रहते हैं, लेकिन अनेक एकल परिवारों के साथ पारिवारिक सामंजस्य स्थापित न होने के कारण, निजी बीमारी या दूसरी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण साथ नहीं रह नहीं पाते। विदेश में रहने वाले परिवारों के अभिभावकों का कई बार कुछ कारणों से वीजा नहीं लग पाता, इसलिए वे जा नहीं पाते। आस-पड़ोस के लोगों को उनकी प्राथमिकताएं पकड़े रहती हैं। रिश्तेदार, मित्रों के आश्वासन, आपसी संबंधों में कथित सहयोग को व्यावहारिक नहीं बना पाते।

अब वक्त और माहौल ऐसा हो चला है कि आत्मविश्वास, संपर्क और सुविधाओं के साए में जिंदगी आराम से बिताना अच्छा है, लेकिन उस कठिन वक्त के लिए भी तैयारी सुनिश्चित करना जरूरी है जो पता नहीं कब, किस लम्हा आकर सामान्य स्थिति को असामान्य बना सकता है। मुश्किल समय का ध्यान रखा जाए, तो ज्यादा परेशान होने की नौबत नहीं आएगी।

दुनिया मेरे आगे

> अब वक्त और माहौल ऐसा हो चला है कि आत्मविश्वास, संपर्क और सुविधाओं के साए में जिंदगी आराम से बिताना अच्छा है, लेकिन उस कठिन वक्त के लिए भी तैयारी सुनिश्चित करना जरूरी है, जो पता नहीं कब, किस लम्हा आकर सामान्य स्थिति को असामान्य बना सकता है।

सत्ता की खातिर

देश में जब भी कहीं विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक दल मतदाताओं और खासकर महिलाओं के खाते में हर माह एक निश्चित राशि देने का दावा करते हैं। आज देश में कई दल यही तरीका अपना कर सत्ता में आ जाते हैं। यह एक तरह से सत्ता के लिए सौदा है। मतदाताओं के खाते में पैसे डाल कर सरकार बनाना परंपरा बन जाएगी, तो फिर जनता विकास की अपेक्षा कैसे करेगी। बेशक हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है, लेकिन पैसे देकर कोई भी सरकार जनता को इतना सक्षम नहीं कर सकती कि वह आत्मनिर्भर हो जाए। लोगों को सोचना होगा कि उन्हें क्या चाहिए? हर माह कुछ हजार रुपए या फिर आत्मनिर्भर जीवन? देश के सभी जिम्मेदार राजनीतिक दलों को भी मंथन करना होगा कि पैसे बांटने की योजनाओं के कारण विकास कार्यों का कोई मोल जनता के आगे नहीं रहता है। याद रखना होगा कि जनता को चंद पैसे नहीं, जीवन उपयोगी सेवाओं की जरूरत है।

- अरविंद रावल, झाबुआ, मप्र

बेटियों का हौसला

हमारे देश के लिए दो नवंबर, 2025 बहुत महत्त्वपूर्ण दिन बन गया, क्योंकि इस दिन भारत की बेटियों ने क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को परास्त कर पहली बार महिला विश्व कप अपने देश के नाम कर लिया और सारी दुनिया को बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। इस जीत ने हमारे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस शानदार जीत के लिए टीम की सभी खिलाड़ियों के माता-पिता और वे लोग भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की। यह जीत उन लोगों के लिए आईना है, जो बेटियों को कमजोर समझते हैं। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। दूसरी तरफ संकीर्ण मानसिकता वाले लोग भी हैं, जो बेटियों को कमजोर मानकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं, यह बहुत ही निंदनीय है।

- राजेश कुमार चौहान, जलंधर

गुरु-शिष्य संबंध

भारतीय समाज उस प्राचीन सांस्कृतिक और सम्मानित परंपरा का वाहक रहा है, जहां गुरु-शिष्य परंपरा को बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त था। जहां गुरु अपने शिष्य को न केवल ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि उसे जीवन के सही मूल्यों और संस्कारों की भी शिक्षा देता है। लेकिन आज के तथाकथित आधुनिक दौर में हमारी यह अमूल्य परंपरा लगातार क्षीण होती जा रही है। शैक्षणिक संस्थानों में अब एक ऐसी संस्कृति विकसित होती जा रही है, जहां शिक्षक अपने ही छात्रों से डरा-सहमा सा दिखता है। देश भर में अक्सर घटने वाली अनेक घटनाएं हमारे सामने हैं। अभी ताजा उदाहरण दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कालेज का है, जहां एक प्राध्यापक को सरेआम थप्पड़ मार दिया गया। शर्मसार कर देने वाली ऐसी कई घटनाएं हैं। आज शिक्षण संस्थाएं गुरु-शिष्य संबंधों को लेकर संकट के दौर से जूझ रही हैं।

- मुकेश कुमार, द्वारका, दिल्ली

साइबर फर्जीवाड़ा

सर्वोच्च न्यायालय ने साइबर धोखाधड़ी के तहत 'डिजिटल अरेस्ट' की गंभीरता को रेखांकित करते हुए केंद्र सरकार को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। अब तक करीब 3000 करोड़ रुपए की राशि 'डिजिटल अरेस्ट' की आड़ में अपराधियों तक पहुंची है। ये अपराधी बुजुर्गों को ज्यादा निशाना बनाते हैं। जालसाज फोन या वीडियो काल पर पुलिस अधिकारी बन कर लोगों को 'गिरफ्तारी' का डर दिखाते हैं और पैसे वसूलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गंभीरता पर पिछले दिनों स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने इस समस्या को बड़ी चुनौती बताते हुए केंद्र सरकार को कार्रवाई का निर्देश दिया और सख्त कानूनी उपाय करने को कहा। इसमें दोराय नहीं कि यह समस्या गंभीर है और इससे कड़ाई से निपटना अब जरूरी है।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

चिंतन

अपने ही देश अमेरिका में फंस गए राष्ट्रपति ट्रंप

बात-बात पर दुनियाभर के देशों को टैरिफ की धौंस दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का हाल बेहाल है। राष्ट्रपति की सनक के चलते सबसे शक्तिशाली देश में 36 दिनों से सरकारी शटडाउन है। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था। शटडाउन की वजह से 4.2 करोड़ अमेरिकियों की फूड स्टैंप सहायता रुक गई है। अमेरिकी कृषि विभाग के पास इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ 5 अरब डॉलर का रिजर्व फंड है, जबकि नवंबर में फूड स्टैंप जारी रखने के लिए 9.2 अरब डॉलर की जरूरत है। शटडाउन से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। अब तक करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो देश की विकास दर में चौथी तिमाही में एक से दो फीसदी की गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 6.7 लाख सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं, जबकि 7.3 लाख कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। इस तरह लगभग 14 लाख लोग कर्ज लेकर घर चला रहे हैं। ट्रम्प हेल्थ केयर प्रोग्राम की सब्सिडी बढ़ाने को तैयार नहीं हैं, इस वजह से अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो पा रहा है। इस बिल पर अब तक 14 बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हर बार बहुमत के लिए जरूरी 60 वोट नहीं मिल पाए। अमेरिका का फिस्कल ईयर यानी खर्च का साल एक अक्टूबर से शुरू होता है। यह एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है, जिसमें वह अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने की योजना बनाती है। इस दौरान सरकार तय करती है कि कहां पैसा लगाना है, जैसे सेना, स्वास्थ्य या शिक्षा में। अगर इस तारीख तक नया बजट पास नहीं होता, तो सरकारी कामकाज बंद हो जाता है। इसे शटडाउन कहते हैं। अमेरिका के दोनों प्रमुख दल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठनी हुई है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि स्वास्थ्य बीमा की सब्सिडी बढ़ाई जाए। रिपब्लिकन का डर है कि अगर सब्सिडी बढ़ाई गई तो सरकार को खर्च करने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिससे बाकी सरकारी काम प्रभावित होंगे। दोनों दलों के इसी मतभेद के चलते अमेरिका का हाल बेहाल हो रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल सरकारी कर्मचारियों का है। उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा। वे लगातार कर्ज के दलदल में फंस रहे हैं। कर्मचारियों को वेतन न मिलने से बाजार में भी मंदी के हालात हैं। खरीददारी ठप होकर रह गई है। इसके चलते उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि शटडाउन के कारण सरकारी खर्च में देरी हो रही है और इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है। यह असर कुछ हद तक खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। ट्रंप की सनक के चलते पहले तो दुनियाभर के देश परेशान थे, अब उनके अपने देश अमेरिका में ही बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगर हालात यही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ट्रंप की सनक अमेरिका को ले बैठेगी।

प्रबंधन
योगेंद्र माथुर

भगदड़ से बचने के उपाय आवश्यक

वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में देवप्रबोधनी एकादशी के अवसर पर दर्शन के दौरान मची भगदड़ में 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह पहला अवसर नहीं है जब किसी धर्मस्थल पर भगदड़ मची हो और श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ी हो। ऐसी दुर्घटनाओं का देश में लम्बा इतिहास रहा है। अतः ऐसी स्थिति में 'रियल टाइम मॉनिटरिंग' की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे भीड़ की वास्तविक संख्या या स्थिति का आकलन कर तत्काल निर्णय लेने में बहुत मदद मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण लोगों का स्व अनुशासन, सावधानी व सजगता से भगदड़ जैसी दुर्घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा में 'मिनी तिरुपति' कहे जाने वाले वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को देवप्रबोधनी एकादशी के अवसर पर दर्शन के दौरान मची भगदड़ में 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए। जैसा कि अब तक होता आया है कि सभी बड़े नेताओं व राजनीतिक दलों ने दुर्घटना पर शोक जताते हुए संवेदना व्यक्त की है और घटना की जांच करने की बात कही गई है। स्थानीय पुलिस व प्रशासन मंदिर प्रबंधन की गलती बताकर दुर्घटना की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने मंदिर के प्रबंधन द्वारा दर्शन व्यवस्था की पूर्व सूचना न देने से सुरक्षा व्यवस्था न हो पाने की बात कही है। मुख्य रूप से दर्शनार्थियों की अनुमान से अधिक भीड़ होने, मंदिर का प्रवेश व निर्गम द्वार एक ही होने व संकरा होने से भीड़ बढ़ने और व्यवस्था के लिए लगे बैरिकेडिंग के गिरने से भगदड़ होना बताया जा रहा है।

यह पहला अवसर नहीं है जब किसी धर्मस्थल पर भगदड़ मची हो और श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ी हो। ऐसी दुर्घटनाओं का देश में लम्बा इतिहास रहा है। हाल के वर्षों में ऐसी बीसियों दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें सैकड़ों श्रद्धालुओं को असमय काल कवलित होना पड़ा है। इसी वर्ष उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित धर्मस्थलों व विभिन्न आयोजनों में ऐसी लगभग एक दर्जन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अकेले आंध्रप्रदेश में ही धर्मस्थलों पर भगदड़ की इस वर्ष यह तीसरी दुर्घटना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन दुर्घटनाओं से हमने कोई सबक लिया हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता।

भारत एक धर्मप्रधान देश है और सात वार, नौ त्यौहार की कहावत यहां प्रचलित है। आए दिन किसी भी धर्म के पर्व व तीज-त्योहारों पर यहां धर्मस्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इसी के साथ कई छोटे-बड़े धार्मिक आयोजन यथा मेले, कथा, सत्संग व प्रवचन भी यहां प्रायः कहीं न कहीं होते रहते हैं जिनमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। धार्मिक आयोजनों से इतर कई सामाजिक, सांस्कृतिक व संगीत के आयोजनों के साथ राजनीतिक सभा व रैलियां भी इस लोकतांत्रिक देश का अनिवार्य हिस्सा रही हैं जिनमें खासी भीड़ जुटती है। इन अवसरों पर भीड़ नियंत्रण व प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन व सरकारों के लिए बड़ी चुनौती होती है। आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाए तो ठीक वरना किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर लीपापोती के प्रयास करने में स्थानीय प्रशासन की संपूर्ण मशीनरी पूरे प्राण प्रण से जुट जाती हैं। बड़े नेता व राजनीतिक दल दुर्घटना को दुखद बता कर शोक संवेदना व्यक्त कर देते हैं और सरकारें जांच कमेटी या आयोग का गठन कर अथवा मुआवजे का मरहम लगाकर अपने कर्तव्य या जिम्मेदारी की इतिश्री मान लेती हैं। बाद में समय के साथ ताजा जख्म भरते जाते हैं, रुदन व क्रंदन बंद हो जाता है और दुर्घटना को लगभग भूला दिया जाता है, जब तक कि कोई नई दुर्घटना न हो जाए। लेकिन इन दुर्घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया जाता। प्रायः देखा यह जाता है भीड़ की सुरक्षा-व्यवस्था न होने अथवा अपर्याप्त या कुप्रबंध होने से भगदड़ जैसी दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार धर्मस्थलों या आयोजनों से जुड़े प्रबंधन और प्रशासन की घोर लापरवाही या अनदेखी

भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। अधिकांशतः बड़े आयोजनों या राजनीतिक रैलियों के दौरान यह देखने में आता है कि आयोजकों का पूरा ध्यान अपनी शक्ति, सामर्थ्य अथवा लोकप्रियता के प्रदर्शन पर रहता है और व्यवस्था व जनसुरक्षा को हाशिए पर धकेल दिया जाता है और किसी प्रकार की दुर्घटना से बचने के कोई प्रबंध नहीं किए जाते। अतः ऐसे अवसरों पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए नियम व कानून के तहत आयोजकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। किसी भी आयोजन की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब आयोजक सुरक्षा-व्यवस्था की संतोषजनक कार्ययोजना प्रस्तुत करें। आयोजकों के प्रबंधन कौशल का भी आकलन किया जाना चाहिए। वैसे भारत में भीड़ नियंत्रण व प्रबंधन को लेकर कोई ठोस नीति या कार्य योजना का नितांत अभाव सदैव बना रहा है। यही कारण है कि अत्यधिक भीड़ जब-तब भगदड़ या अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं का कारण बनती है। प्रायः अनुमान से अधिक भीड़ होना दुर्घटना का कारण बताया जाता है लेकिन वर्तमान डिजिटल तकनीकी के दौर में संभावित भीड़ का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं रह गया है। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन की सहायता से बढ़ती भीड़ पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। कुंभ मेले जैसे महाआयोजन में शामिल होने और पवित्र नदी में स्नान करने या डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का पूर्वानुमान व सतत निगरानी कर सुरक्षा व्यवस्थाएं जुटाने का महायज्ञ (अनुपातिक रूप में कुछेक दुर्घटनाओं के अपवाद को छोड़कर) सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सकता है तो इससे छोटे आयोजनों में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? हर भीड़ अव्यवस्था या भगदड़ जैसी दुर्घटनाओं में बदल सकती है, यह मानकर ही किसी भी भीड़ वाले आयोजन के अवसर पर सुरक्षा-व्यवस्था तय की जाना चाहिए। किसी भी धर्मस्थल या आयोजन स्थल पर अत्यधिक भीड़ बढ़ने की संभावना पर प्रोजेक्टर या एलसीडी आदि के माध्यम से उसके सीधे प्रसारण के कई स्थानों पर प्रबंध कर भीड़ को एक ही जगह एकत्र होने से रोका जा सकता है। स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की भी सहायता ली जा सकती है। यदि कोई धर्म स्थल पहाड़ी या अधिक ऊंचाई पर, चारों तरफ अन्य निर्माण से घिरा हुआ, संकरा या अधिक अंधेरे में हो तो वहां भीड़ बढ़ने वाले अवसरों पर समुचित प्रकाश के साथ पर्याप्त हवा के प्रबंध पर भी अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है ताकि भीड़ बढ़ने पर वहां श्रद्धालुओं को गर्मी, घुटन या घबराहट महसूस न हो। फिसलन भरी जगह या संकरे मार्ग भी दुर्घटना की वजह बनते हैं। अतः इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए।

प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि धर्म स्थलों या आयोजन स्थलों पर विद्युत व्यवस्था के तार बेतरतीब तरीके से लगे होते हैं या लटके होते हैं। अत्यधिक भीड़ के अवसरों पर धर्मस्थलों अथवा कथा, प्रवचनों के आयोजन स्थलों पर प्रवेश व निर्गम द्वार की व्यवस्थाएं अलग-अलग की जानी चाहिए। इन स्थानों पर आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम व चिकित्सकों सहित एंबुलेंस की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में कोई दुर्घटना होने पर बड़ी जनहानि से बचा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी स्थल या आयोजन में जुटने वाली भीड़ की संख्या का पूर्वानुमान या आकलन सदैव सही साबित हो। भीड़ अनुमान से अधिक या अत्यधिक भी हो सकती है। अतः ऐसी स्थिति में 'रियल टाइम मॉनिटरिंग' की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे भीड़ की वास्तविक संख्या या स्थिति का आकलन कर तत्काल निर्णय लेने में बहुत मदद मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण लोगों का स्व अनुशासन, सावधानी व सजगता से भगदड़ जैसी दुर्घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

सेहत

डॉ. रेनू यादव

डीएनए की रक्षाः जीवन और स्वास्थ्य की आधारशिला

हम अक्सर मानते हैं कि हमारे जीवन के सबसे बड़े खतरे बाहर हैं, जैसे सड़क दुर्घटनाएं, संक्रमण या गंभीर बीमारियां। लेकिन लगातार और सबसे गहरा हमला हमारे शरीर के भीतर मौजूद हमारी कोशिकाओं में डीएनए पर होता है। यह हमला अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। डीएनए हमारे शरीर की सबसे बुनियादी और आवश्यक संरचना है, जिसे जीवन की "निर्देश पुस्तिका" कहा जा सकता है। इसमें हमारे शरीर की बनावट, रंग-रूप, व्यवहार, मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी सुरक्षित रहती है। हर कोशिका के केंद्र में मौजूद डीएनए ही यह तय करता है कि कौन-सी कोशिका क्या काम करेगी और शरीर का कौन-सा हिस्सा कैसे विकसित होगा। यदि डीएनए को नुकसान पहुंचता है, तो शरीर की कोशिकाएं गलत ढंग से काम करने लगती हैं, जिससे कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, हृदय रोग और समय से पहले बुढ़ापा जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अधिकांश डीएनए क्षति की मरम्मत शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली स्वयं कर लेती है, किन्तु जब ऐसे आक्रमण निरंतर होते रहते हैं, तो यह तंत्र भी अपनी कार्यक्षमता खोने लगता है। डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारक डीएनए पर सबसे बड़ा हमला सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। ये किरणें त्वचा की कोशिकाओं में प्रवेश कर उनके आनुवंशिक पदार्थ यानि डीएनए को क्षति पहुंचाती हैं। यदि लंबे समय तक इनसे बचाव न किया जाए, तो यह क्षति त्वचा कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों का कारण बन सकती है। इसके अलावा, चिकित्सीय जांचों में प्रयुक्त एक्स-रे और सीटी स्कैन जैसी विकिरणें भी डीएनए को प्रभावित कर सकती हैं। यद्यपि इनका उपयोग चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है, परंतु बार-बार इनका संपर्क डीएनए क्षति के जोखिम को बढ़ा सकता है। प्रदूषित वायु भी डीएनए की एक गंभीर शत्रु है। यही कारण है कि बढ़ते प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां आज विश्वभर में तेजी से बढ़ रही हैं। खानपान का प्रभाव भी कम नहीं है। अत्यधिक तेलयुक्त और प्रसंस्कृत, पैकेटबंद या मिलावटी भोजन शरीर में ऐसे प्रतिक्रियाशील रसायन उत्पन्न करता है जो कोशिकाओं को क्षति पहुंचाकर डीएनए की सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं। लंबे समय तक ऐसा आहार अपनाने से कैंसर जैसी दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कुछ वायरस भी सीधे डीएनए पर आक्रमण करते हैं।

उदाहरण के लिए, एचपीवी, वायरस गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का प्रमुख कारण है, जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, तनाव और नींद की कमी भी डीएनए के लिए हानिकारक मानी जाती है। तनाव के दौरान बनने वाले हार्मोन कोशिकाओं की मरम्मत क्षमता को घटा देते हैं, वहीं नींद की कमी से शरीर की प्राकृतिक "रिपेयर प्रणाली" सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती। धूम्रपान और शराब सेवन ऐसे कारक हैं जो डीएनए को सीधे क्षति पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डीएनए की क्षति हृदय रोगों को भी बढ़ावा देती है। दिमागी बीमारियां, जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन भी इसी से जुड़ी पाई गई हैं। समय से पहले बुढ़ापा, झुर्रियों का आना, बालों का झड़ना और शरीर का कमजोर होना भी डीएनए क्षति के संकेत हो सकते हैं। इसके साथ ही, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने पर बार-बार संक्रमण होने लगता है। हालांकि यह अदृश्य हमला पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सरल और सजग उपायों से इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डीएनए की सुरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है, संतुलित आहार और स्वच्छ वातावरण। ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और दालें शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करती हैं, जो डीएनए की मरम्मत प्रक्रिया को सक्रिय रखती हैं। इसी प्रकार, आंवला, हल्दी, ग्रीन टी, अखरोट, बादाम और बेरीज का नियमित सेवन भी कोशिकाओं की सुरक्षा देने में सहायक है। स्वस्थ जीवनशैली डीएनए की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। विश्वभर में वैज्ञानिक डीएनए की सुरक्षा और उसकी मरम्मत के लिए निरंतर नए उपायों पर कार्य कर रहे हैं। किंतु जब तक ये खोजें आम जीवन का हिस्सा नहीं बनतीं, तब तक हमें स्वयं अपनी जीवनशैली, आदतों और परिवेश में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन की पूरी रूपरेखा हमारे डीएनए में ही दर्ज है। यदि यह सुरक्षित और संतुलित है, तो हमारा वर्तमान ही नहीं, बल्कि भविष्य भी सुदृढ़ और स्वस्थ रहेगा। इसलिए अब समय है कि हम इन अदृश्य हमलों के प्रति जागरूक हों और अपने डीएनए की सुरक्षा को जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं क्योंकि सुरक्षित डीएनए ही एक सुरक्षित जीवन की नींव है।

(लेखिका पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में सीनियर डेमोंस्ट्रेटर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जीवन मूल्यों का पाठ है योग

संकलित
दर्शन

भारत ने जो विश्व को बहुमूल्य उपहार दिए हैं, योग उनमें से एक है। योग हमारी अंतर्जात क्षमताओं को जाग्रत करने और पूर्णता की उच्चतम स्थिति की प्राप्ति में सहायक है। लोहे का एक टुकड़ा चुंबक कैसे बन जाता है? जब लौह कण एक दिशा-विशेष में एकत्र हो जाते हैं, तब यह होता है। उसी प्रकार, यदि हम अपने मन को एक ही बिंदु पर-एक ही दिशा में एकत्र करें तो हम असीम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने एकाग्रता के साथ तप किया और इतनी शक्ति अर्जित की। जैसे सूर्य की किरणों को आवर्धक लेंस द्वारा एक बिंदु पर एकत्रित करें, तो रुई जल सकती है। यही बात हमारी आंतरिक शक्तियों पर भी लागू होती है। हम निष्ठापूर्ण एकाग्रता-शक्ति अर्थात योग द्वारा इनका आह्वान कर सकते हैं। योग हो या कोई अन्य साधना, सम्यक ज्ञान और मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। साथ ही, बाहरी व भीतरी अनुशासन भी बरतना चाहिए। बुरे कर्मों से बच कर, हम स्वस्थ विचार और दृष्टिकोण बनाएं और धर्मोचित कर्म करें। मूल्यों पर आधारित जीवन जिएंगे, तभी हमें योगाभ्यास का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त होगा। योग हमारी बुद्धि, भावनात्मक मन एवं शरीर के लिए उपयोगी है। यह बिना दुखी हुए, हमें जीवन की समस्याओं से संतुलित रूप से निपटना सिखाती है। आइए, हम सब अपने प्राचीन ऋषि-मुनियों द्वारा सिखाई गई इस अमूल्य विद्या को प्रोत्साहन देने एवं इसे लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करें।

जिन लोगों में मतभेद उन्हें सफलता मिलती हैं कम

संकलित
प्रेरणा

महाभारत में पांडव कौरवों से जुएं में सब कुछ हार गए थे। इस हार के बाद ये तय हुआ था कि पांडव जब 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास करके लौटेंगे तब कौरव पांडवों को इनका राज्य वापस लौटा देंगे। पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा कर लिया तो वे अपना राज्य वापस मांगने कौरवों के पास पहुंचे, लेकिन दुर्योधन ने पांडवों को राज्य देने से मना कर दिया। बहुत कोशिशों के बाद भी दुर्योधन पांडवों को एक गांव तक देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद पांडवों के सामने सिर्फ युद्ध करने का एक मात्र उपाय बचा था। पांडवों ने युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी। कौरव सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा थे। विरोधी पक्ष में सभी पांडवों के रिश्तेदार ही थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। पांडवों ने विचार किया कि हम तो सिर्फ पांच भाई हैं। हमारे पास सेना भी नहीं है, तो हम कौरवों की विशाल सेना का सामना कैसे करेंगे। श्रीकृष्ण ने पांडवों को समझाया कि कौरव पक्ष में भले ही बड़े-बड़े योद्धा हैं, लेकिन सभी के बीच मतभेद हैं। भीष्म कर्ण को पसंद नहीं करते, द्रोण दुर्योधन को पसंद नहीं करते। दुर्योधन भीष्म और द्रोण को अपमानित करते रहता है। जबकि आप पांचों भाई एक साथ हैं, आपके बीच एकता है। जहां एकता होती है, जीत भी वहीं होती है। श्रीकृष्ण ने संदेश दिया है कि जहां मतभेद होते हैं, वहां सफलता नहीं होती है। कौरव पक्ष में बड़े-बड़े योद्धा थे, विशाल सेना थी, लेकिन मतभेदों के चलते सभी एक मत होकर पांडवों से युद्ध नहीं लड़ सके और अंत में पांडवों की जीत हुई।

अंतर्मन

आज की पाती

युवाओं के सपनों की तस्करी

भारत के अनेक इलाकों में, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, एक गंदा और खतरनाक चलन तेजी से फैल रहा है- डंकी रूट के जरिए विदेश पहुंचने का सपना। यह शब्द डंकी अंग्रेजी के शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है बिना अनुमति या अवैध रास्ते से जाना। सुनने में यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, पर हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह है। इस रूट ने न केवल युवाओं के भविष्य को निगल लिया है, बल्कि समाज और प्रशासन के सामने एक गंभीर मानवीय और आर्थिक संकट भी खड़ा कर दिया है। भारत के ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में विदेश जाना अब सिर्फ एक आकांक्षा नहीं, बल्कि सफलता का प्रतीक बन गया है। ऐसे में यह जाल तेजी से फैल रहा है। - पवन कुशवाहा, बिलासपुर

ट्रेंड

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखकर प्रसन्नता हो रही है। हमारी सरकार अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चल रही बातचीत व्यापार, निवेश और नवाचार संबंधों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे साझा संकल्प से हम उत्साहित हैं।
-पीयूष गोयल, केंद्रीय उद्योग मंत्री

चुल्लू भर ही काफी

जो देश का अपमान करते हैं, विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, उन्हें तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफी है।
- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

राहुल का नाटक

न ईवीएम, न वोट चोरी और न संविधान। कड़वा सच यह है कि विरासत का दाव अब राहुल गांधी के लिए कभी ठीक न होने वाला एक घाव बन चुका है। इसलिए वह अपने को खबरों में बनाए रखने के लिए नाना प्रकार के नाटक करते रहते हैं। लेकिन अब उनका कोई दांव नहीं चलेगा।
- केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, उप्र

करंट अफेयर

अंतरिक्ष में चीन का चालक दल फंसा, वापसी टाली गई

चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर तैनात दल की बुधवार को निर्धारित वापसी को टाल दिया गया है। ऐसा संदेह है कि अंतरिक्ष यान पर सूक्ष्म अंतरिक्ष मलबे का प्रभाव पड़ा है। यह घोषणा 'चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी' (सीएमएसए) ने की। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वापसी में देरी का निर्णय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। चीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन के दल को हर छह महीने में बदलता है। शनिवार को शेनझोउ-20 अंतरिक्ष यान ने शेनझोउ-21 दल के साथ कक्षा में कार्यभार हस्तांतरण पूरा किया था और उसका बुधवार को पृथ्वी पर लौटने का कार्यक्रम था। शेनझोउ-20 में वर्तमान अंतरिक्ष दल सवार है। मंगलवार को अंतरिक्ष स्टेशन पर तैनात तीन सदस्यीय दल ने कार्यभार हस्तांतरण समारोह आयोजित किया और औपचारिक रूप से स्टेशन की चाबियां नए दल को सौंप दीं। आधिकारिक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शेनझोउ-20 दल में शामिल चेन डोंग, चेन झोंगरुई और वांग जिए ने अपने सभी निर्धारित कार्य पूरे कर लिए हैं और उन्हें बुधवार को उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के डोंगफेंग लैंडिंग स्थल पर लौटना था। हालांकि, अब उनकी वापसी स्थगित कर दी गई है।

ऑफ बीट

कुत्ते पढ़ सकते हैं आपका दिमाग और चेहरा

जब आप रोते हैं तो आपका कुत्ता अपना सिर झुका लेता है, जब आप तनाव में होते हैं तो इधर-उधर टहलता है, और आपके सबसे बुरे पलों में किसी न किसी तरह आपके पास होता है। यह महज संयोग तो नहीं हो सकता। हजारों सालों के सह-विकास ने कुत्तों को हमारी आवाज, चेहरों और यहां तक कि मस्तिष्क के रसायन विज्ञान को समझने के खास तरीके दिए हैं। हमारी बातचीत को समझने वाले मस्तिष्क के क्षेत्रों से लेकर हमारी नजरें मिलाने पर बढ़ने वाले 'लव हार्मोन' या ऑक्सीटोसिन तक, आपके कुत्ते का दिमाग आपकी भावनाओं को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस असाधारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रमाण मस्तिष्क में ही शुरू होता है। कुत्तों के मस्तिष्क में आवाज के प्रति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जो इंसानों के समान होते हैं। एक 'ब्रेन इमेजिंग' अध्ययन में, अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि कुत्तों के 'टेम्पोरल कॉर्टेक्स' में आवाज को समझने वाले क्षेत्र होते हैं, जो ध्वनियों के जवाब में सक्रिय हो जाते हैं। कुत्ते न केवल किसी भी ध्वनि पर, बल्कि आपकी आवाज के भावनात्मक स्वर पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। कुत्तों के मस्तिष्क के अध्ययन से पता चलता है कि भावनात्मक ध्वनियां, मसलन हंसी, रोना, गुस्से से चीखना उनके श्रवण और भावनाओं को समझने से संबंधित मस्तिष्क के एक हिस्से को सक्रिय करती हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 223

महिलाओं को नकदी हस्तांतरण

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने राज्य सरकारों की वित्तीय हालत को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है। सच तो यह है कि राज्य सरकारें कुल सरकारी व्यय के दो-तिहाई हिस्से के लिए जिम्मेदार होती हैं लेकिन उनकी वित्तीय सेहत पर सार्वजनिक बहस में पर्याप्त चर्चा नहीं होती। ऐसे में इस प्रकार की रिपोर्ट राज्य सरकारों की वित्तीय हालत से संबंधित आम समझ को बेहतर बनाने में मदद करती हैं।

उम्मीद के मुताबिक ही रिपोर्ट राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर कुछ कमियों को रेखांकित करती है जिन पर यहां चर्चा करना उपयोगी होगा। उदाहरण के लिए यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2023-24 में राज्यों ने अपनी राजस्व प्राप्तियों का 60 फीसदी से अधिक वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान जैसे मदों पर खर्च किया। समग्र स्तर पर राज्यों ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.4 फीसदी राजस्व घाटा भी दर्ज किया, जिसका अर्थ है कि वे बार-बार होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए उधार ले रहे हैं। प्रतिबद्ध व्यय का उच्च स्तर विकासात्मक कार्यों को करने की राज्य सरकारों की क्षमता को सीमित करता है।

राज्यों के पूंजीगत व्यय को केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना से मदद मिल रही है। इस योजना के तहत राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। वर्ष 2020-21 से 2025-26 (11 अगस्त 2025 तक) तक राज्यों को इस योजना के तहत 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया गया। विश्लेषण बताता है कि अपने स्रोतों से राज्यों का पूंजीगत व्यय सपाट बना रहा और बढ़ोतरी को केंद्र सरकार से सहायता मिली।

यह एक आदर्श स्थिति नहीं है, क्योंकि यदि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता को बंद कर दिया गया (जिसे जारी रखना उसकी बाध्यता नहीं है) तो इससे राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय में तेज गिरावट आ सकती है, जिसका कुल आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में उजागर किया गया एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है राज्यों के बीच बढ़ती असमानता। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, वे अधिक राजस्व जुटा पाते हैं और इस कारण उनके पास विकास पर खर्च करने की क्षमता भी अधिक होती है। यह प्रवृत्ति समृद्ध और गरीब राज्यों के बीच की खाई को और चौड़ा करती रहेगी, जिसके आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं। इस बढ़ती असमानता को दूर करना नीति-निर्माताओं के लिए एक गंभीर चुनौती होगा।

एक अन्य पहलू जिस पर उचित नीतिगत ध्यान दिया गया है वह है महिलाओं को बिना शर्त नकदी हस्तांतरण। पीआरएस द्वारा जुटाए गए आंकड़े बताते हैं कि ऐसी सहायता देने वाले राज्यों की तादाद वर्ष2022-23 के 2 से बढ़कर 2025-26 में 12 हो गई। वर्ष 2025-26 में राज्यों ने कुल मिलाकर 1.68 लाख करोड़ रुपये की राशि या जीएसडीपी का करीब 0.5 फीसदी इस मद में यानी महिलाओं को देने में खर्च किया। ऐसी सहायता देने वाले करीब आधे राज्यों को इस वर्ष राजस्व घाटा होने की उम्मीद है। वास्तव में वे ऋण लेकर पैसे बांट रहे हैं। ऐसी योजनाओं की राजनीतिक सफलता को देखते हुए यह मानना उचित होगा कि आने वाले समय में और भी राज्य इसे अपनाएंगे। प्रतिस्पर्धी राजनीति के कारण समय के साथ आवंटित होने वाली राशि भी बढ़ती जाएगी।

बिना शर्त हस्तांतरण अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग अर्थ भले समेटे हो लेकिन राजनीतिक दलों के लिए लाभ स्पष्ट है। कहा जाता है कि इससे सामाजिक आर्थिक हालात में सुधार हो रहा है। परंतु यह बात बहस तलब है कि क्या बजट की बाधाओं से जूझ रहे देश में सामाजिक आर्थिक हालात सुधारने का यही श्रेष्ठ तरीका है। स्पष्ट समझ की मदद से बजटीय संसाधनों का आवंटन सुधारा जा सकता है। मार्च 2025 तक राज्यों पर कुल मिलाकर जीएसडीपी का 27.5 फीसदी कर्ज था। एफआरबीएम समीक्षा समिति ने 2017 में अनुशंसा की थी कि राज्यों का कर्ज 20 फीसदी तक रहना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकारें सरकारी उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण की भी गारंटी देती हैं जो 2023-24 में जीएसडीपी का 4.2 फीसदी था। यह राज्यों की वित्तीय हालत के लिए एक जोखिम है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे कुछ राज्य कुल आंकड़ों से कहीं अधिक गंभीर वित्तीय संकट में हैं और इन्हें अलग नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

अजय मोहंती

विदेशी निवेशकों के मन में भारत की छवि

भारत के प्रति निवेशकों का उत्साह ठंडा पड़ा है लेकिन उनमें अभिरुचि की कमी एक विपरीत सकारात्मक संकेत हो सकती है। बता रहे हैं आकाश प्रकाश

पिछले दिनों मुझे वैश्विक निवेशकों के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला। इनमें से कुछ तो पूंजी के सबसे चतुर दीर्घकालिक आवंटकों में शुमार हैं और उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। वे इस उद्योग को नेतृत्व भी प्रदान करते रहे हैं। इतने वर्षों से लगातार यह सब करते हुए मुझे भी यह समझ आने लगा है कि कैसे समय के साथ प्राथमिकताएं और थीम बदल सकती हैं।

मेरे लिए इनमें से प्रमुख हासिल क्या रहा? इस यात्रा के दौरान मुझे भारत को लेकर जितनी उदासीनता देखने को मिली उतनी पहले कभी नहीं दिखी थी। ये हालात 20 वर्ष पहले की याद दिला रहे थे। मेरी मुलाकात सबसे हुई लेकिन इसके पीछे उनकी विनम्रता और पुराने रिश्ते ही बड़ी वजह थे। एक भी बैठक ऐसी नहीं हुई जहां लोगों ने भारत के बाजारों में निवेश का इरादा जताया हो। वे भारत के बारे में जानकारी पाकर खुश थे और यह तर्क समझ सकते थे कि भारत सापेक्ष प्रदर्शन के मामले में अब क्यों अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंच चुका है, यानी यहां से यह ऊपर ही जाएगा। परंतु किसी भी प्रकार की कार्रवाई को लेकर उनका कोई झुकाव नहीं था। यह काफी गंभीर बात है।

भारत को लेकर वही पुरानी चिंताएं हैं। मूल्यांकन बहुत अधिक है। आर्थिक और आय के क्षेत्र में कोई गति नहीं है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हमारी कोई तरक्की नहीं है, न ही हम इसके लाभार्थी हैं और हम लोकलुभावनवाद में उलझे हुए हैं। कई वर्षों में पहली बार मुझे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 7 फीसदी के स्तर पर टिकाऊ बने रहने को लेकर सवालों का सामना करना पड़ा। पहले इसे स्वाभाविक माना जाता था। पहली बार मुझे ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा कि क्यों भारत निम्न मध्य आय वाले देश के रूप में अटका नहीं रह सकता?

एआई के आगमन और रोजगार पर उसके असर के साथ भारत की आबादी अब उतनी बड़ी शक्ति नहीं नजर आती। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भारत एआई के क्षेत्र में सक्रिय क्यों नहीं है? मुझे बताया गया कि चीन शोध एवं विकास पर भारत की तुलना में 25 गुना अधिक व्यय करता है। वहां शोध और विकास व्यय जीडीपी के 3.5 फीसदी के बराबर है जबकि भारत में यह व्यय 0.7 फीसदी है। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था का आकार भी भारत से पांच गुना है। जहां तक उभरते उद्योगों की बात है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत प्रमुख भागीदार हो या जिसकी तकनीक पर नियंत्रण रखता हो। वाहन और औषधि क्षेत्र के उद्योगों में भी भारत पीछे छूट रहा है। क्या शेयर पर रिटर्न और मार्जिन पर भारत का जोर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है। क्या बाजार पूंजीकरण को लेकर जुनून लंबी अवधि के नवाचार को क्षति पहुंचा रहा है? क्या हमारा बाजार अल्पकालिक सोच में ज्यादा उलझा हुआ है?

सबसे प्रमुख संदेश यही था कि दुनिया एक और चीन को सहन नहीं कर सकती है। चीन वैश्विक विनिर्माण के क्षेत्र में दबदबे से पीछे नहीं हट रहा है। वह अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। भारत जैसे आकार के देश के लिए यह गुंजाइश नहीं है कि वह विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में ऐसा कुछ करे जैसा कि चीन ने तीन दशकों में किया है। शेष विश्व इसे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि इस समय वैश्वीकरण का भारी राजनीतिक प्रतिरोध हो रहा है। आईटी सेवाओं के क्षेत्र में क्या एआई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को नुकसान पहुंचाएगा? अगर हमें दफ्तरों में काम करने वाले कम लोगों की जरूरत होगी तो इन भूमिकाओं को विदेश स्थानांतरित करने की क्या संभावना है? जो नौकरियां बची रहेंगी उन्हें देश में ही रखना जरूरी है ताकि सामाजिक शांति बनी रहे।

ये सारी बातें वृद्धि में स्थिरता और उसके अनुमान से जुड़ी हुई हैं। जब हर कोई इस बात से सहमत होता कि भारत में दशकों तक तेज वृद्धि हासिल करने की क्षमता है तो वे ऊंचे मूल्यांकन और वृद्धि की कीमत चुकाने को तैयार होते। लेकिन अगर वृद्धि ही संदेह के दायरे में आ जाए तो मौजूदा मूल्यांकन टिकाऊ नहीं रह जाता है। विदेशी निवेशकों पर लगने वाले पूंजीगत लाभ कर को लेकर भी वास्तविक चिंताएं थीं। उन्हें किसी अन्य विदेशी बाजार में ऐसा कर नहीं चुकाना होता है और इस बात ने बीते कुछ वर्षों में रिटर्न पर असर डाला है। यही वजह है कि भारत का आकर्षण कम हुआ है।

शुल्क दरों और भू-राजनीति को लेकर ज्यादातर लोग चिंतित नहीं थे। हर किसी को यही लगता है कि अमेरिका के लिए चीन ही इकलौता वास्तविक रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी है। चीन को काबू में रखने के लिहाज से भारत महत्त्वपूर्ण है और इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते लंबे समय तक ठंडे न रहें। हालांकि इस घटनाक्रम ने भारत की आर्थिक प्रभावशीलता की कमी को उजागर कर दिया। भारत भले ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन क्या वह किसी आपूर्ति श्रृंखला में वास्तव में अपरिहार्य भूमिका निभाता है?

अधिकांश निवेश आवंटक अभी भी नकदी के मोर्चे पर कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हालात 12 महीने पहले की तुलना में बेहतर हैं, लेकिन अमेरिका का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम बाजार अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है। संभावित सूचीबद्धता की पाइपलाइन बहुत बड़ी है, और सभी यूनिकॉर्न कंपनियों का मुद्रीकरण संभव नहीं है। किसी भी नए निवेश की अपेक्षित तरलता पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, और नकदी की कमी का जोखिम उठाने के लिए भुगतान प्राप्त करना एक सामान्य विषय बन गया है। भारत डिस्ट्रिब्यूशन टू पेड-इन कैपिटल यानी डीपीआई (यानी निवेशकों द्वारा लगाई गई पूंजी की तुलना में उनको लौटाई गई नकदी) के दृष्टिकोण से अभी भी एक कमजोर कड़ी बना हुआ है। भारत में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इस मोर्चे पर काफी निराशाजनक रहे हैं, जबकि यहां आईपीओ बाजार दुनिया के सबसे मजबूत बाजारों में से एक है। इसके अलावा, नए फंड्स के आकार को लेकर भी काफी बहस हुई।

हर किसी के दिमाग में एआई ही प्रमुख है। कुछ लोग इतने भाग्यशाली हैं कि उनके पास इस विषय में बहुत अधिक निवेश है, और वे बबल (कीमतों में भारी अस्थायी उछाल) को लेकर चिंतित हैं कि कब बाहर निकलना चाहिए? दूसरे लोग, जिनका इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं है, सोच रहे हैं कि क्या अब निवेश करना उचित होगा। एआई दुनिया को कैसे बदलेगा? बबल के दौर में निवेश कैसे किया जाए? क्या 1999/2000 का डॉट-कॉम बबल एक अच्छा मार्गदर्शक साबित हो सकता है?

उभरते बाजारों में लंबे समय के बाद नए सिरे से रुचि देखी गई। कई निवेशक डॉलर में अपना जोखिम कम करने को लेकर उत्सुक थे। उभरते बाजारों के शेयर परिसंपत्ति वर्ग ने 15 वर्षों के कमजोर प्रदर्शन के बाद आखिरकार इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन किया। यह एक नए रुझान की शुरुआत हो सकती है। अगर धन अमेरिका से उभरते बाजारों में आता है तो इस क्षेत्र में बहुत आवक होगी।

मैंने भारत में रुचि की कमी को एक विरोधाभासी सकारात्मक संकेत के रूप में देखा। इसके साथ ही विदेशी स्वामित्व का रिकॉर्ड निम्न स्तर, सभी फंडों द्वारा संरचनात्मक रूप से भारत में कम निवेश और गत पांच साल में विदेशी निवेश प्रवाह का शून्य स्तर भी इस संकेत को मजबूत करते हैं। भारत ने गत एक वर्ष में उभरते बाजारों और एशिया की तुलना में 30 फीसदी कमजोर प्रदर्शन किया है। यह पिछले 30 साल में एक रिकॉर्ड है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 27 में आय की गति बढ़ेगी खासतौर पर वित्तीय क्षेत्र के नेतृत्व में ऐसा होगा और नॉमिनल जीडीपी करीब 400 आधार अंक तक बढ़ेगा। वैश्विक निवेश प्रवाह किसी न किसी चरण में फिर से शुरू होगा। चाहे वह उभरते बाजारों की वापसी के साथ हो या एआई कारोबार के फीके पड़ने पर। मूल्यांकन सस्ते तो नहीं हैं, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 फीसदी कम हैं। इस यात्रा के दौरान जो संशय मैंने महसूस किया, उसके बावजूद मुझे लगता है कि भारत के लिए अगले वित्तीय वर्ष की स्थिति सकारात्मक दिख रही है। बशर्ते घरेलू निवेश प्रवाह स्थिर रहें और हम आईपीओ बाजार को क्षति न पहुंचाएं।

(लेखक अमांसा कैपिटल से संबद्ध हैं)

नए राजकोषीय लक्ष्य की तरफ बढ़े कदम

अर्थतंत्र

राजेश कुमार

वस्तु एवं सेवा कर दरों में कमी और उन्हें युक्तिसंगत बनाने का आर्थिक वृद्धि और कर संग्रह पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका वित्त मंत्रालय को सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा। खासतौर पर इसलिए क्योंकि वित्त मंत्रालय ने आगामी आम बजट की तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी।

हालांकि, वित्तीय बाजार और अन्य अंशधारक केवल इसी पहलू पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। अगले वित्त वर्ष से सरकार अलग राजकोषीय आधार अपनाने जा रही है। चूंकि इसके लिए वित्तीय बाजार की अपेक्षाओं को समायोजित करने की जरूरत है इसलिए आने वाले महीनों में कुछ व्यापक मुद्दों पर चर्चा करना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की थी कि 2026-27 से केंद्र सरकार का लक्ष्य वार्षिक राजकोषीय घाटा इस तरह रखने पर होगा कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की तुलना में सरकार के ऋण में गिरावट आए। गौरतलब है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में वर्ष 2018 में संशोधन कर इसमें ऋण और घाटे दोनों के लक्ष्य शामिल किए गए। इसके तहत राजकोषीय घाटे को वर्ष2020–21 तक जीडीपी के 3 फीसदी तक लाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि केंद्र सरकार के ऋण को 2024–25 तक जीडीपी के 40 फीसदी तक सीमित करने का लक्ष्य था। हालांकि, यह लक्ष्य कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह बाधित हुआ, जिससे राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फिर भी, इसके बाद सरकार ने इस दिशा में प्रशंसनीय सुधार किया है।

वर्ष2021-22 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार का इरादा 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम करके जीडीपी के 4.5 फीसदी से नीचे लाने का है। सरकार इस वर्ष इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। यह आसान नहीं था क्योंकि राजकोषीय घाटा 2020-21 में बढ़कर जीडीपी के 9.2 फीसदी तक जा पहुंचा था। इस दौरान आर्थिक परिदृश्य भी अनिश्चित था। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि सुदृढ़ीकरण पूंजीगत व्यय के बढ़े हुए स्तर के साथ हासिल हुआ है। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 2019-20 के जीडीपी के 1.67 फीसदी से बढ़कर 2025-26 में जीडीपी के 3.14 फीसदी तक पहुंच गया। ऐसे में सरकार ने अपने वित्त का कारगार तरीके से प्रबंधन किया है।

बहरहाल, अगले वित्त वर्ष से होने वाले बदलाव को लेकर और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। राजकोषीय आधार के प्रभावी होने के लिए उसे सरल तरीके से संप्रेषित करने वाला यानी ल क्षित जगहों तक असरकारी होना चाहिए। यद्यपि ऋण को राजकोषीय कानून में शामिल किया गया था लेकिन वार्षिक संचालन लक्ष्य राजकोषीय घाटा था जिसे एक निश्चित स्तर तक व्यवस्थित रूप से कम किया जाना था। वित्तीय बाजार और अन्य हितधारकों ने इस बात को अच्छी तरह समझा।

हालांकि ऋण को कम बनाए रखने का संप्रेषण उतना आसान नहीं है और इसका असर सरकारी बॉन्ड की कीमतों पर पड़ सकता है। फरवरी में बजट के साथ प्रस्तुत राजकोषीय नीति वक्तव्य में उल्लेख किया गया कि राजकोषीय घाटा इस तरह रखा जाएगा कि कुल ऋण घटते मार्ग पर रहे और मार्च 2031 तक जीडीपी के 50 फीसदी (1 फीसदी ऊपर या नीचे) के स्तर तक पहुंच सके। दस्तावेज में विभिन्न स्तरों की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि और राजकोषीय समेकन की विभिन्न डिग्रियों के साथ संभावित परिदृश्यों को भी प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि नॉमिनल वृद्धि 11 फीसदी हो और राजकोषीय मजबूती हल्की हो, तो केंद्र सरकार का ऋण वर्तमान वर्ष के अनुमानित 56.1 फीसदी से घटकर मार्च 2031 तक जीडीपी का 50.1 फीसदी हो सकता है। हालांकि, यदि नामिनल वृद्धि 10 फीसदी हो और समेकन कम ही रहे, तो ऋण घटकर जीडीपी का 52 फीसदी ही रहेगा। स्पष्ट है कि यदि नॉमिनल वृद्धि और कम हो, तो स्थिति और जटिल हो जाएगी। वर्तमान वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था की नॉमिनल वृद्धि केवल 8.8 फीसदी रही, और पूरे वर्ष की वृद्धि भी इसी स्तर के आसपास रहने की संभावना है। यदि ऐसी वृद्धि कुछ वर्षों तक जारी रहती है, तो 50 फीसदी ऋण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काफी सख्त राजकोषीय अनुशासन अपनाना पड़ सकता है।

इसका अर्थ यह है कि कई पहलू होंगे, जो संप्रेषण को कठिन बना सकते हैं। इसके अलावा, कई अन्य मुद्दों पर स्पष्टता और बहस की आवश्यकता है। पहले केंद्र सरकार के ऋण को घटाकर जीडीपी के 40 फीसदी तक लाने का लक्ष्य था, जबकि अब इसे मार्च 2031 तक लगभग 50 फीसदी तक रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या अधिक ऋण स्तर सरकार की किसी संभावित आर्थिक झटके पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता को सीमित कर देगा? या फिर मौजूदा राह पर चलते हुए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 फीसदी या उससे कम तक करना, नीति निर्माण के लिए अधिक गुंजाइश उपलब्ध कराने में मददगार नहीं होगा?

इसके अलावा, वित्तीय बाजार सामान्य सरकारी ऋण को देखते हैं। ऐसे में इस संदर्भ में यह सवाल उठता है कि क्या राज्यों से भी इसी तरह की रूपरेखा अपनाने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें मध्यम अवधि में ऋण स्तर को लक्षित किया जाए? ऐसा करने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामान्य सरकारी ऋण घटता रहे।

आखिर में मध्यम अवधि में राजकोषीय घाटा किस स्तर पर स्थिर होने की उम्मीद है, इस पर स्पष्टता जरूरी है। यह विशेष रूप से अर्थव्यवस्था की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में विशुद्ध घरेलू वित्तीय बचत में गिरावट आई है। यदि अधिकांश बचत का उपयोग सामान्य सरकारी घाटे की भरपाई करने में होता है, तो इससे पूंजी की लागत प्रभावित हो सकती है और विदेशी बचत पर निर्भरता बढ़ सकती है। विशेषकर तब जब निजी निवेश में दीर्घकालिक रूप से उभार होता है, जो उच्च दर से वृद्धि के लिए आवश्यक शर्त है। इस प्रकार, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नीति-निर्माताओं का ध्यान आवश्यक है। सरकार ने पिछले कई वर्षों में राजकोषीय मोर्चे पर सराहनीय कार्य किया है, और भविष्य की दिशा को लेकर कोई भी अस्पष्टता इन कठिनाई से अर्जित उपलब्धियों को जोखिम में डाल सकती है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

आपका पक्ष

वैश्विक शक्ति बनने के लिए चाहिए मोलतोल की ताकत

संपादकीय 'भारत-अमेरिका समझौता जरूरी' यह स्पष्ट करता है कि अमेरिका और चीन दोनों आयातक और निर्यातक के रूप में किसी भी दवाब को झेलने में सक्षम हैं। परंतु इससे इतर दोनों देशों के पास सबसे विकसित तकनीक है और मुख्यतः यही दोनों देशों की वास्तविक शक्ति है। इससे भी अधिक दोनों देशों के आधुनिकतम हथियार, मिसाइलें, परमाणु हथियार, वायु सेना और नौसेना की शक्ति है जिसके बल पर वे कभी भी, किसी भी क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। अमेरिका और चीन के समझौते में वैश्विक व्यापार की ताकत के अलावा मुख्य कारक उनकी सैन्य शक्ति है। जब भारत निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तो वैश्विक स्तर पर परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना, सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित होना और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के पास सबसे विकसित सैटेलाइट और संचार तंत्र है। अमेरिका और चीन दोनों अभी डेटा सेंटर स्थापित करने में यूरोप की बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ठंडी जलवायु में विशालकाय डेटा सेंटर स्थापित करना बहुत लाभदायक है। भारत के पास ठंडी जलवायु के क्षेत्र भी हैं और प्रचुर टैलेंट है। आधुनिकतम आयुध निर्माणी के क्षेत्र में भारत अपना वर्चस्व स्थापित करने में सक्षम है। इसके अलावा अमेरिका, चीन और यूरोप विश्व भर के विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं जबकि भारत के पास उनसे बड़ा शिक्षा का इन्फ्रास्ट्रक्चर है। केवल तकनीक, दवा और प्रबंधन में विश्व स्तर की फैकल्टी सृजित करने की जरूरत है। अमेरिका और यूरोप में भारतीय प्रोफेसर ही पढ़ा रहे हैं। आज अमेरिका में भारतीय ऊंचे पदों पर आसीन हैं। हमारी ताकत हमने ही उनको दे रखी है और उनको विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। अमेरिका, चीन, यूरोप एवं अन्य बड़े देशों के साथ व्यापारिक, रक्षा और सामरिक समझौतों के लिए भारत को अपनी बारगेनिंग पावर स्थापित करनी होगी।

विनोद जौहरी, दिल्ली

अमेरिका और चीन के समझौते में वैश्विक व्यापार की ताकत के अलावा मुख्य कारक उनकी सैन्य शक्ति है

चुनावी सौगात या वोट के लिए रिश्वत?

बिहार विधान सभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार 6 नवंबर को होगा। मंगलवार 4 नवंबर की शाम पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया था। चुनाव प्रचार की आखिरी घड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव जीतने पर महिलाओं को 30 हजार रुपये हर माह देने की घोषणा की। इससे काफी पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की घोषणा की थी तथा उनके खाते में यह राशि पहुंच भी गई है। चुनावी वादों में इस प्रकार की घोषणा मतदाताओं को वोट के बदले रिश्वत देने जैसा है। चुनाव आयोग को ऐसी घोषणाओं के लिए एक मानक तय करने की जरूरत है। अगर कोई दल चुनाव जीतता है तो उसे वादे पूरे करने के लिए राज्य का खजाना खाली करना पड़ेगा जिससे विकास में खर्च होने वाला पैसा इसमें खर्च हो जाएगा।

शंभू नाथ, पटना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से अपने निवास पर मुलाकात की और विश्व कप में लगातार तीन हार के कठिन दौर से गुजरने के बाद 'दृढ़ता और शानदार वापसी' के लिए खिलाड़ियों की तारीफ भी की ।

पायनियर
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 6 नवंबर 2025

बिहार चुनाव
वादों की बाढ़

बिहार एक और चुनाव के दौर से गुजर रहा है, यह पांच साल की प्रघटना है जो जमीन पर कुछ भी नहीं बदलती है लेकिन इसे पूरी तरह से झटका देती है। जैसे ही बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, हाल के दिनों में सबसे कड़े मुकाबले वाले विधानसभा चुनावों में से एक के लिए मंच तैयार हो गया है। यह चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि न केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के लिए, बल्कि राजद-कांग्रेस गठबंधन के नेतृत्व वाले भारतीय ब्लॉक के लिए भी दांव ऊंचे हैं, क्योंकि उनकी ताकत और एकजुटता का परीक्षण किया जाएगा। ऐसे राज्य में जहां राजनीतिक समीकरण जातिगत गणित पर आधारित हैं और गठबंधन बदलना अपवाद से अधिक एक नियम है, दोनों पक्ष बिल्कुल विपरीत आख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं।

मुद्दे नये नहीं हैं, लेकिन वादे नये हैं। अनुमानतः, कथा वास्तविक समस्याओं और समाधानों से बहुत दूर है। बिहार के मतदाताओं से चाँद का वादा किया जा रहा है, सीता मंदिर से लेकर बाढ़ नियंत्रण तक, शहरों के पुनरुद्धार से लेकर रक्षा गलियारे तक, सूर्य के नीचे लगभग सब कुछ, लेकिन उस आदमी की तत्काल चिंताओं से वंचित हैं जो ईवीएम पर बटन दबाएगा।

भाजपा के नेतृत्व में राजग अपने अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासित बिहार दृष्टिकोण और नीतीश कुमार के शासन रिकॉर्ड के इर्द-गिर्द पेश कर रहा है, भले ही यह कितना भी कमजोर क्यों न हो गया हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवहर और सीतामढी में रैलियों को संबोधित करते हुए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का अनावरण किया: औद्योगिक रोजगार पैदा करने के लिए एक रक्षा गलियारा, बंद चीनी मिलों का पुनरुद्धार, हर जिले में कारखाने और हवाई अड्डों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बदलना। यह कब और कैसे होता है यह बिल्कुल अलग बात है।

शायद सबसे भावनात्मक वादा बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का शाह का आश्वासन है, यह एक आवर्ती त्रासदी है जिसने दशकों से राज्य की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। एनडीए ने मिथिलांचल में 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए कोशी नदी का उपयोग करने और बाढ़ नियंत्रण के लिए एक आयोग बनाने का संकल्प लिया है।

पुनौरा धाम में 850 करोड़ रुपये के सीता मंदिर के साथ-साथ, सीतामढी से अयोध्या तक वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की योजना, सांस्कृतिक प्रतीकवाद के साथ विकास का मिश्रण है - पहचान की राजनीति के साथ बुनियादी ढांचे को जोड़ने की एक परिचित भाजपा रणनीति। दूसरी ओर, भारतीय गुट बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और सामाजिक न्याय के क्षरण के इर्द-गिर्द एक लड़ाई लड़ रहा है, जो बड़े विकास के लिए एनडीए की पिच के समान ही काल्पनिक है। तेजस्वी यादव खुद को बिहार के युवाओं की आवाज के रूप में पेश करते रहते हैं, बार-बार पलायन और बेरोजगारी के दोहरे संकट का जिक्र करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि इससे कैसे पार पाया जाएगा।

कांग्रेस, हालांकि एक गौण भूमिका निभा रही है, लेकिन राहुल गांधी की बुलेट रैलियों से उत्साहित है, एक कल्याण-केंद्रित मुद्दे के माध्यम से अपनी चुनावी प्रासंगिकता को फिर से स्थापित करना चाहती है जिसमें किसान समर्थन और महिला सशक्तिकरण शामिल है। लेकिन बिहार में यह कभी भी सीधी लड़ाई नहीं है, छोटे, क्षेत्रीय और सीमांत खिलाड़ियों, जैसे पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, एआईएमआईएम और कई जाति-आधारित संगठनों की बढ़ती उपस्थिति परिदृश्य को जटिल बनाती है और मतदाताओं को भ्रमित करती है।

हालांकि वे कई सीटें नहीं जीत सकते हैं, वोट-स्प्लिटर के रूप में उनकी भूमिका निर्णायक रूप से करीबी मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में परिणामों को बदल सकती है और मार्जिन को स्विंग कर सकती है और गठबंधन अंकगणित को प्रभावित कर सकती है। इसका परिणाम 14 नवंबर को ईवीएम की गिनती के बाद उपलब्ध होगा।

जनादेश, नेतृत्व और विरासत की लड़ाई

एनडीए के पास पूरे बिहार में एक ठोस नेटवर्क है, जिसमें भाजपा और जनता दल यूनाइटेड दोनों के कार्यकर्ता शामिल हैं, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समूहों से भी समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित हालिया विकास परियोजनाओं ने एनडीए के अभियान को मजबूत करने में मदद की है।

कल्याणी शंकर
लेखिका, वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार हैं।

आगामी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बेहद प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है, जिसमें शामिल सभी दलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। जबकि जनमत सर्वेक्षण सत्तारूढ़ एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के पक्ष में हैं, वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी भावनाओं को अस्पष्ट करते हैं। बीजेपी नेता अभी से ही जीत का दावा कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स को ऐलान किया कि बीजेपी-एनडीए बिहार में व्यापक जीत दर्ज करेगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि सर्वेक्षण में पार्टियां और उनके नेता शामिल होते हैं। वे नेतृत्व, जाति की गतिशीलता और मतदाता धारणा पर भी निर्भर करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेतृत्व वाला और कांग्रेस तथा छोटे दलों के साथ गठबंधन वाला इंडिया ब्लॉक दो दशकों के एनडीए शासन को समाप्त करना चाहता है। मजबूत नेतृत्व और संगठन के साथ, मतदाताओं का मूड आगे एक अस्थिर दौड़ का सुझाव देता है।

स्थानीय विधायकों के बीच असंतोष, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार सृजन की कमी के साथ मिलकर, सत्तारूढ़ गठबंधन के समर्थन को कमजोर करता है। हालांकि एनडीए को उच्च जातियों और वृद्ध मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है, लेकिन युवाओं और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समूहों को शामिल करने में इसकी असमर्थता पार्टी के लिए चुनौतियाँ पेश करती है।

चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रचार नेताओं से काफी प्रभावित होते हैं। कुमार को मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं से मजबूत समर्थन प्राप्त है, जो मुफ्त बिजली, स्वच्छ पानी और एक करोड़ (10 मिलियन) नौकरियां पैदा करने की योजना जैसी उनकी पहल की सराहना करते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 25 लाख महिलाओं की सहायता करने वाले महिला कल्याण कार्यक्रम के लिए प्रत्येक को 10,000 रुपये आवंटित किए हैं।

सी-वोटर सर्वे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता में उतार-चढ़ाव देखा गया; उत्तरदाताओं ने उन्हें अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री चुना। एक आश्चर्यजनक दावेदार जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर थे, जो 16 प्रतिशत वोट के साथ एक पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में उभरे।

एनडीए के पास पूरे बिहार में एक ठोस नेटवर्क है, जिसमें भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) और जेडी (यू) (जनता दल यूनाइटेड) दोनों के कार्यकर्ता शामिल हैं, साथ ही आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) समूहों से भी समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित हालिया विकास परियोजनाओं ने एनडीए के अभियान को मजबूत करने में मदद की है।

भाजपा ने जद (यू) का समर्थन किया और भाजपा के शीर्ष नेता एनडीए के लिए प्रचार कर रहे थे, और वित्तपोषण कोई मुद्दा नहीं है। हालाँकि, एनडीए स्थानीय स्तर पर संघर्ष करता है, जहाँ उसके पास अपने विरोधियों के समान विश्वसनीयता और जमीनी समर्थन का अभाव है। राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को एक वफादार मुस्लिम-यादव मतदाता आधार होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो मतदाताओं का लगभग 30 प्रतिशत है। नवीनतम सी-वोटर सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि वह बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए शीर्ष पसंद बने हुए हैं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं और उन्होंने मतदाताओं से कई लोकलुभावन उपायों का वादा किया है। इनमें पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे बढ़े हुए सामाजिक कल्याण लाभ, साथ ही सरकारी रोजगार अभियान और छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन के माध्यम से रोजगार सृजन की पहल शामिल हैं।

इस समय नीतीश कुमार के लिए एक हार उनके राजनीतिक करियर का अंत हो सकती है। राहुल और प्रियंका गांधी को भी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और अन्य छोटे दलों के लिए नतीजे महत्वपूर्ण हैं। चुनाव परिणाम कुछ नेताओं को मदद करेंगे और दूसरों के लिए चुनौतियां पैदा करेंगे। यह एक अद्भुत अनुभव होगा।

तेजस्वी राजद का नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनके पिता, लालू प्रसाद यादव और परिवार के अन्य सदस्य अभी भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। पारिवारिक विवाद अक्सर तेजस्वी को पार्टी की रणनीति के बजाय आंतरिक विवादों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ लोगों को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें नौकरी के बदले जमीन घोटाले की ईडी जांच भी शामिल है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले प्रचार नहीं किया था लेकिन अब कांग्रेस के वफादारों से समर्थन जुटाने के लिए रैलियां और रोड शो करने की योजना है। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी राज्य में सक्रिय रूप से प्रचार कर रही हैं। हालाँकि, पार्टी मजबूत स्थानीय नेताओं की कमी के कारण संघर्ष कर रही है। कांग्रेस के लगातार खराब प्रदर्शन को गठबंधन में एक कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस किसी भी चुनाव में 30 से अधिक सीटें जीतने में कामयाब नहीं हुई है। इस बार, कांग्रेस ने 61 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिनमें से 56 सीटों पर भाजपा और जद (यू) के खिलाफ सीधा मुकाबला है - ये सीटें काफी हद तक एनडीए के नियंत्रण में हैं।

भाजपा मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करती है, जिसमें लगभग 30 प्रतिशत आबादी शामिल है। ऐतिहासिक और सामाजिक कारकों के परिणामस्वरूप, इसका उच्च जाति का प्रभुत्व, पिछड़े और हाशिये पर रहने वाले समुदायों तक इसकी अपील को सीमित करता है, जो कि महत्वपूर्ण ओबीसी और दलित आबादी वाले बिहार जैसे राज्य में एक चुनौती हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेता बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

एनडीए नीतीश कुमार के कल्याण अनुभव पर प्रकाश डालता है, जबकि इंडिया ब्लॉक युवा नेतृत्व और मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर देता है। युवा वोट और समग्र मतदान बिहार के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा। नवीनतम वोटवाइब सर्वेक्षण में एमजीबी 34.7 प्रतिशत और एनडीए 34.4 प्रतिशत के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है। जन सुराज को 12.3 फीसदी का समर्थन है, जबकि 8.4 फीसदी को त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान है। यह चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई नेताओं के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अगर मोदी और अमित शाह जीतते हैं, तो अगले साल के चुनाव में उनके पास बेहतर मौका होगा।

इस समय नीतीश कुमार के लिए एक हार उनके राजनीतिक करियर का अंत हो सकती है। राहुल और प्रियंका गांधी को भी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और अन्य छोटे दलों के लिए नतीजे महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर, चुनाव परिणाम कुछ नेताओं को मदद करेंगे और दूसरों के लिए चुनौतियां पैदा करेंगे। यह एक अद्भुत अनुभव होगा।

विदेश नीति निर्धारण में संसद की भूमिका

संविधान द्वारा प्रदत्त विदेश नीति में कार्यपालिका किस प्रकार निर्णायक भूमिका निभाती है, इसके बारे में बोधपूर्वक लिखते हुए लेखक ने संसद की 'न्यूनतम' भूमिका पर जोर दिया है। यह लेटमोटिफ पुस्तक में एक आवर्ती विषय है।

संथानम प्रभाकर
लेखक, स्तम्भकार हैं।

इस शोधपूर्ण पुस्तक में, अनुभवी पत्रकार केवी प्रसाद भारतीय संसद की पहल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह केवल लेखक के व्यापक प्रदर्शन और लंबी पत्रकारिता यात्रा पर चिंतन नहीं है; वह बड़ी मेहनत से यह बताते हैं कि कैसे शीर्ष विधायी निकाय ने 1947 से देश की विदेश नीति के निर्माण और सुदृढ़ीकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।

यह संसद की भूमिका का पता लगाते हुए विदेश नीति के विशाल क्षेत्र में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वास्तव में, यह पुस्तक इस बात का विस्तृत विवरण देती है कि किस तरह एक के बाद एक सरकारों और प्रधानमंत्रियों ने संसद के भीतर चुनौतीपूर्ण समय का सामना किया।

परिचय सदस्यों के लिए उपलब्ध उपकरणों और विदेश नीति को आकार देने में शामिल संसदीय प्रक्रियाओं और विस्तृत समिति की स्थापना को संक्षेप में चित्रित करता है। यह इस बात की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है कि पाठक पुस्तक से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

संविधान द्वारा प्रदत्त विदेश नीति में कार्यपालिका किस प्रकार निर्णायक भूमिका निभाती है, इसके बारे में बोधपूर्वक लिखते हुए लेखक ने संसद की 'न्यूनतम' भूमिका पर जोर दिया है। यह लेटमोटिफ पुस्तक में एक आवर्ती विषय है।

यह वाद-विवाद के विकास को दशार्ता है और कैसे कार्यपालिका द्वारा सांसदों को विश्वास में लिया जाता था, जो 1921 में विदेश नीति की उत्पत्ति का पता लगाता है। जवाहरलाल नेहरू ने 1964 में अपनी मृत्यु तक विदेश नीति को आगे बढ़ाने और संसद में आम सहमति बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

यह पुस्तक तीन विशिष्ट बहसों से संबंधित है - श्रीलंका में आईपीकेएफ, विश्व व्यापार संगठन, और भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता। यह रेखांकित करता है कि कैसे 1991 और 2003 के दौरान, संसद ने खाड़ी युद्ध के दौरान अपने सर्वसम्मत

प्रस्तावों के माध्यम से खुद को मुखर किया, संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया और भारत की गुटनिरपेक्ष स्थिति और इराक के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने से इनकार को व्यक्त किया। घरेलू राजनीति, विरोध और वामपंथी दलों के परिप्रेक्ष्य की पृष्ठभूमि में, पुस्तक पाठक के लिए संसदीय बहसों को डिकोड करती है और बताती है कि उस समय की सरकारें कैसे सफल हुईं।

पुस्तक इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे, विभिन्न अवसरों पर, भारतीय संसद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सरकार ने राज्यों के विरोध को कैसे संभाला, और कैसे राज्य अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए केंद्र पर हावी रहे। परमाणु बहस में गहराई से उतरते हुए, यह पुस्तक 1948 से परमाणु नीति के विकास, 1974 से 'परमाणु रंगभेद', 1998 में 'पोखरण-द्वितीय' और यूपीए सरकार के तहत इसकी परिणति कैसे हुई, पर नजर रखती है।

नागरिक परमाणु सहयोग पर अध्याय में, प्रसाद संसद की भूमिका और उन बहसों की याद दिलाते हैं जिन्होंने उस समय की सरकार को हिलाकर रख दिया था। उनका सटीक अनुमान है कि भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोगग्ग देश की परमाणु ऊर्जा की खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण बना हुआ है। संसद में बहस पर टिप्पणी करते हुए, पुस्तक में पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन को उद्धृत किया गया है: यह सरकार के लिए आसान सफर नहीं था [क्योंकि संसद में चर्चा] ने [वार्ता] को जटिल बना दिया था।

लेखक ने गठबंधन युग के दौरान संसद में लड़ी गई सबसे जटिल सरकार-विपक्ष लड़ाइयों में से कुछ को प्रभावी ढंग से विचारों और विचारों की मुक्त-प्रवाह प्रस्तुति के साथ तोड़ दिया है, और सरकारों ने कठिन समय में विदेश नीति को कैसे संचालित किया। प्रसाद की पुस्तक एक आधिकारिक विवरण और संसद में जो कुछ हुआ उसका एक विस्तृत दृश्य प्रदान करती है।

वह इस विषय पर एक नया दृष्टिकोण लाते हैं, नीतिगत मापदंडों को स्पष्ट रूप से समझाते हैं और बताते हैं कि सरकार ने विपक्ष के दबावों और दबावों का कैसे सामना किया। प्रत्येक अध्याय की सामग्री समृद्ध और सावधानीपूर्वक तैयार की गई है, जो स्पष्ट तरीके से लिखी गई है। लेखक इस विषय को पूरी ईमानदारी के साथ पेश करता है और संसद में सरकार और विपक्ष दोनों द्वारा की गई बहस और रणनीति के संदर्भों से भरपूर है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विद्वानों को शामिल करने और शिक्षित करने के लिए एक व्यापक और मूल्यवान मार्गदर्शिका, यह विदेश नीति पर संसद के प्रभाव का एक उत्कृष्ट अन्वेषण है।

इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख यह है कि कैसे, अपनी सीमित भूमिका के बावजूद, भारतीय संसद विदेश नीति के निर्माण में हर कल्पनीय तरीके और परिप्रेक्ष्य में खुद को मजबूत करती है। कुल मिलाकर, किताब उत्कृष्ट है।

आप की बात

बसों के बाद वंदे भारत लॉक

करोड़पति में प्रतियोगी से पूछे गए सवाल पर उससे मिले जवाब के लिए अमिताभ बच्चन कहते हैं लॉक किया जाए, लेकिन आजकल तो बिना सवाल/जवाब के ही यात्री बस हो या फिर वन्दे भारत ट्रैन अचानक उसके दरवाजे लॉक होने लगे हैं. बेचारे ट्रैन यात्री या तो घबरा जाते हैं या फिर बसों में लगी आग की भेंट बस यात्री चढ़ जाते हैं। गया से हावड़ा पहुंची वन्दे भारत ट्रैन के यात्री अनाउंसमेंट होते ही जब लाइन लगाकर स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार हुए तो ट्रैन के दरवाजे लॉक हो गए। काफी समय तक नहीं खुले तो वे घबरा गए. घबराहट तब और ज्यादा बढ़ गई जब एसी कोच की लाइट भी बंद हो गई तब बच्चे भी रोने लग गए. काफी समय बाद आखिर ऑटो लॉक को मैन्युल टेक्नीशियनों ने खोला तब सभी यात्री ट्रैन से उतर पाए. इसी तरह पिछले कुछ समय में एसी कोच बसों में भी मार्मिक घटनाएं हुई हैं जिनमें आग लगने पर बसों के दरवाजों के ऑटो लॉक नहीं खुल पाए और अनेक यात्रियों की विभिन्न घटनाओं में जिंदा जल जाने से अत्यंत ही दुखद मृत्यु हो गई. बहुत से बेचारे घायल भी हो गए। बसें भी जलकर खाक हो गई। सभी मामलों में जांच होगी। दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा भी मिल सकती है। बस मालिकों को तो बीमा मिल गया होगा और मृतकों/घायलों को सरकारी मुआवजा। पर घटनाएं तो दुखद ही हो रही हैं।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

इबादत नहीं काले कारनामे

अक्सर जब बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने या इबादत करने की जगहों पर जैसे स्कूल-मदरसे आदि जगहों पर जब वहां के शिक्षक या मोलाना कोई काले धंधे करते पाए जाते हैं तो हमे बेहद दुखी होता है। कारण स्कूल या मदरसे हमारे बच्चों के शिक्षा प्राप्ति के केंद्र रहते हैं एवं जब यहां पर इस तरह के काले कारनामों का करोबार जिक्र सुनाई पड़ता है तब इस कारण हमारे देश की शिक्षा पद्धति भी बदनाम होती है एवं इसके कारण फिर न केवल देश बल्कि विश्व भर में हमारी बदनामी तथा जग हंसाई भी होती है। एमपी के खण्डवा जिले के एक ग्रामीण मदरसे से बीस लाख के नकली नोट बरामद होना एवं उसके एक मोलाना का इसमें लिप्त होना तो यही दशार्ता है कि यहां काफी समय से ये नकली नोट का गौरखधंधा चल रहा था । यह भी कहा जा रहा है कि मोलाना के इस काम में उसे एक निलंबित डाक्टर भी मदद कर रहा था।आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा देने वाला मोलाना एवं लोगों को जीवन देने वाला डाक्टर आज देश की जनता को न केवल ठगने बल्कि गुमराह करने का भी काम कर रहा हैं। एक तरफ हमारा देश फर्श से अर्श तक जाने की बात कर रहा है यानी हमारे देश की इस इक्कीसवीं सदी में काफी अधिक तरक्की हो रही है वहीं दूसरी ओर तरफ इस तरह के ये काले कारनामे ,ये नासूर देश को बदनामी के गर्त में भी ले जाते हैं। अतः आज बहुत जरूरी है कि हमें ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

– **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

अमेरिका में जनादेश

इसी मंगलवार को हुए अमेरिका में दो राज्यों का गवर्नर एवं न्यूयोर्क महानगर का मेयर का चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी को पराजित नहीं किया है बल्कि उस उग्र राष्ट्रवाद जैसे खतरनाक विचारधारा को अमेरिकी मतदाताओं ने कुचल दिया है। मंगलवार को पूरे देश में हुए हाई-प्रोफाइल चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत हुई, जिसमें न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव और न्यू जर्सी और वर्जीनिया में गवर्नर के चुनाव शामिल हैं। कैलिफोर्निया में, वोटरों ने अपने राज्य का कांग्रेस का नक्शा फिर से बनाने का फैसला किया, जिससे डेमोक्रेट्स को हाउस की पाँच सीटें मिल सकती हैं। इन चुनावों से यह समझने में मदद मिलती है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में पहले नौ महीनों के बारे में अमेरिकी कैसा महसूस करते हैं। रिपब्लिकन की हार के बाद, ट्रंप ने चुनाव के नतीजों के लिए अपने बैलेट पर न होने और लंबे समय तक सरकारी शटडाउन को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की। क्या पहली जनवरी को जब जोहरान ममदानी मेयर का पदभार ग्रहण करेंगे तो क्या ट्रम्प न्यूयोर्क शहर को मिलने वाला संघीय वित्त सहायता को रोक देंगे ? ट्रम्प अपने करतूतों से न सिर्फ दुनिया भर के देशों को दुखी किया है बल्कि खुद अमेरिकी जनता को हर तरह से परेशान किया है। अब टेर्रिफ वो 5 फीसदी लगाएं या 500 फीसद, उसको अंततः कौन भुगतेगा? जाहिर है अमेरिकी उपभोगता को ही सारा बोझ सहना पड़ रहा है।

– **जंग बहादुर सिंह**, जमशेदपुर

नया बखेड़ा बांग्लादेश का

पाकिस्तान से मधुर संबंधों के बनते बांग्लादेश में भी विस्तारवादी पनपने लगी है। हाल ही में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को अपनी विवादास्पद किताब ह्यआर्ट ऑफ ट्रायम्फह्न भेंट की है जिससे एक नया कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस पुस्तक के कवर पर बने नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों विशेष रूप से असम और आसपास के इलाकों को बांग्लादेश का हिस्सा दशार्या गया है। यह नक्शा कथित तौर पर ग्रेटर बांग्लादेश की उस विवादास्पद अवधारणा का प्रतीक है जिसे कुछ कट्टरपंथी संगठन वर्षों से बढ़ावा देते रहे हैं। यूनुस का यह कदम भारत की संप्रभुता पर प्रत्यक्ष चुनौती है और इसे उनकी राजनीतिक मंशा से जोड़कर देखा जा रहा है। यह प्रकरण ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों में हाल में नजदीकी बढ़ी है जिससे क्षेत्रीय संतुलन पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। भारत सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है किंतु कूटनीतिक हलकों में इसे गहरी चिंता का विषय माना जा रहा है।

– **अमृतलाल मारू**, रवि, इंदौर

पाठकगण अपने विचार responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

दैनिक जागरण
आज के निर्णय ही कल के परिणाम को निर्धारित करते हैं

राहत देने वाला फैसला

यह स्वागतयोग्य है कि ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय इंसाल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है, जिससे दीवालिया कंपनियों और उनके प्रवर्तकों की जब्त की गई संपत्तियों से फ्लैट खरीदारों और बैंकों को राहत दी जा सके। ईडी की ओर से इस संदर्भ में जो मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जा रही है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उसके दायरे में बिल्डरों की जब्त संपत्तियां ही आएंगी। अच्छा हो कि इस प्रक्रिया के दायरे में वे दीवालिया कंपनियां और उनके प्रवर्तक भी आएं, जो बैंकों या बाजार से पैसा लेकर किसी भी तरह की धोखाधड़ी के आरोपित हैं। ऐसे आरोपितों की बड़ी संख्या है। इनमें वे घोटालेबाज भी शामिल हैं, जो अपने कारोबार को विस्तार देने के नाम पर बैंकों से बड़ा लोन लेकर उसे हड़प गए। आम लोगों और बैंकों से पैसा लेकर उसे हजम कर जाने वालों की संपत्तियों को जब्त कर लेना इसलिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतने मात्र से पीड़ित पक्षों को कोई लाभ नहीं मिलता। दीवालिया कंपनियों और कारोबारियों की जब्त संपत्ति को लेकर जो वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाती है, वह आमतौर पर लंबी खिंचती है। इस दौरान पीड़ित पक्ष परेशान होते रहते हैं, क्योंकि अभी नियम यह है कि मामले का निपटारा होने तक जब्त संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। इसका बुरा असर बैंकों, निवेशकों और आम लोगों पर पड़ता है। इसका कोई मतलब नहीं कि घोटालेबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो शुरू हो जाए, लेकिन उनकी हजारों करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति अनुप्रयुक्त पड़ी रहे।

न्याय का तकाजा यह कहता है कि घपले-घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के साथ ही पीड़ितों को यथाशीघ्र राहत देने की भी कोई व्यवस्था हो। बैंक तो तब भी घोटाले में डूबी रकम वापस पाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन आम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बड़ी संख्या में ऐसे बिल्डर हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को उनके घर का सपना दिखाकर उनके साथ ठगी की। इनमें से अनेक बिल्डरों ने फ्लैट खरीदारों के साथ बैंकों को भी ठगा। अच्छा होगा कि केंद्र सरकार अपनी विभिन्न एजेंसियों के बीच ऐसा समन्वय कायम करे, जिससे बिल्डरों के साथ-साथ अन्य दीवालिया कंपनियों के मामलों में फंसे अरबों रुपये की वसूली का रास्ता खुले। इसी के साथ ऐसे भी उपाय करने होंगे, जिससे जानबूझकर दीवालिया होने के तौर-तरीकों पर लगाम लगे। कई मामलों में यह देखने में आया है कि घोटालेबाज दीवालिया होने और इस कारण अपनी संपत्ति की जब्ती के बाद भी पहले की तरह ठाठ से रहते हैं। एक समस्या यह भी है कि ऐसे लोगों के मामलों का निपटारा होने में बहुत अधिक समय लगता है।

कड़ी कार्रवाई जरूरी

बिहार के अररिया में परमान नदी पर बने पुल का पिलर धंस गया। करीब चार करोड़ की लागत से बने इस पुल का महज छह साल में धंस जाना गंभीर सवालों को जन्म दे रहा। ग्रामीण कार्य विभाग ने इस पुल का निर्माण करवाया था। सवाल यह कि क्या पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, इंजीनियरिंग का दोष था या मानकों का पालन नहीं किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के बाद विभाग की ओर से कहा गया है कि पुल का पिलर धंसने की जांच शुरू कर दी गई है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन, बड़ा सवाल है कि क्या दोषी पहचाने जाएंगे, सही तरीके से जांच होगी। सवाल इसलिए कि जिस विभाग ने पुल का निर्माण करवाया, उसी विभाग के अधिकारी अब इसकी जांच कर रहे हैं। क्या विभागीय अधिकारी अपने ही कनिष्ठों के कुकृत्य से पर्दा हटाने में पारदर्शिता बरतेंगे। शायद बरत भी लें, लेकिन लोगों के मन में सवाल तब भी रहेंगे कि क्या ईमानदारी से जांच हुई है। बेहतर होगा कि जांच के लिए एक विशेष दल का गठन हो और विभागीय अफसर इससे बाहर रहें। दोषी चिह्नित किए जाएं और उनपर कड़ी कार्रवाई हो। जांच के दायरे में सिर्फ निर्माण कराने वाले ही नहीं आएं, जांच उनकी भी होनी चाहिए जिन्हें इसकी मानिटरिंग करनी थी। जाहिर है अगर निगरानी सही से होती तो गड़बड़ी करने वालों को खौफ होता और शायद यह घटना नहीं होती। चूंकि बिहार में निरंतर पुलों के गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं, ऐसे में फिर से सभी पुलों का आडिट करवाया जाना चाहिए, ताकि समय रहते उनकी सही स्थिति के बारे में पता चल सके।

बिहार के अररिया में पुल धंसने की जांच पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि दोषियों की पहचान हो सके

बाहुबलियों की बेलगाम राजनीति

राहुल वर्मा

समय के साथ बाहुबली खुद ही राजनीति में उतरने लगे और अब तो वे अपने करीबियों और परिवार के लोगों को भी राजनीति में स्थापित करने लगे हैं

जातिगत समीकरण और राजनीति में अपराधीकरण भारतीय राजनीति की दो कड़वी सच्चाई हैं, जो बिहार के मामले में और मुखरता से सामने आती हैं। बीते दिनों मोकामा में यह फिर से सामने आया, जब जदयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। अनंत सिंह को जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। दुलारचंद यादव के बारे में भी यही जानकारी सामने आई कि उनकी भी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। अनंत सिंह का मुकाबला राजद प्रत्याशी वीणा देवी से है, जो सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। सूरजभान सिंह का अतीत और वर्तमान भी किसी से छिपा नहीं रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि मोकामा राजधानी पटना से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यह राज्य की एक सीट का हाल है। आज बिहार में जिन 121 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, उसमें करीब 1,300 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स के अनुसार इनमें से 30 प्रतिशत उम्मीदवार गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं।

बिहार की राजनीति में दागियों की पैठ कितनी गहरी है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पिछली विधानसभा में चुने गए 50 प्रतिशत विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज थे। यानी हर दूसरे विधायक का दामन दागदार रहा। इनमें भी 16 विधायक ऐसे थे, जिन पर हत्या से जुड़े मामले दर्ज थे, जबकि 30 विधायकों पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज थे। इसमें आठ विधायकों पर तो यौन शोषण जैसे अपराध का आरोप था। इस चुनाव में भी सभी राजनीतिक दलों ने दागियों और उनके परिवार के लोगों को टिकट देने में खूब दरियादिली दिखाई है। शहाबुद्दीन से लेकर मुन्ना शुक्ला और सुनील पांडे और राजन तिवारी के नाते-रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतरकर विधानसभा पहुंचने की व्यूह रचना बनाने में जुटे हैं। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को समस्या तो सभी बताते हैं, लेकिन कोई इसके समाधान के लिए आगे नहीं आता। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि आखिर राजनीतिक दलों को दागी इतने क्यों पसंद हैं और अगर दल अपने टिकट पर दागियों को उतारते हैं तो फिर जनता उनकी नैया पार कैसे लगा देती है? इस सवाल के जवाब के लिए कोई बहुत मेहनत-मशक्कत करने की जरूरत नहीं। इसमें सबसे बड़ा पहलू तो राज्य की नाकामी के रूप में सामने आता है।

अवधेश राजपूत

जब राज्य कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर पाता तो कुछ लोग अपने बाहुबल के दम पर ही लोगों को 'सुरक्षा और न्याय' दिलाने के ठेकेदार बन जाते हैं। आम लोगों के दुख-दर्द और आड़े वक्त में की गई मदद भी इन्हें जनता के बीच स्थापित करने में मददगार बनती है। ऐसे तमाम एहसानों की कीमत अलग-अलग मौकों पर चुकाई भी जाती है और चुनाव भी उनमें से एक अवसर होता है। चूंकि ऐसे बाहुबलियों का प्रशासनिक अमले में अपना एक दबदबा होता है, इसलिए किसी विनम्र नेता के मुकाबले इनकी बात पर सुनवाई होने के आसार अधिक बढ़ जाते हैं। यह पहलू भी जनता के प्रति इनमें भरोसा बढ़ाता है। भारतीय समाज और कहें कि बिहार में जातिगत बंधन भी बहुत गहरे हैं तो हर जाति से कोई न कोई बाहुबली आगे निकलकर अपने समुदाय का मसीहा बनने की कोशिश करता है और दूसरी जाति के बाहुबली के मुकाबले अपने लोगों को यह भरोसा दिलाने की पूरी जुगत करता है कि वही उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा। यानी बाहुबल में कहीं न कहीं जातीय अस्मिता का भी एक बोध तो दिखता ही है। इस पूरी कवायद में राज्य की अक्षमता ही बाहुबलियों की क्षमताएं बढ़ाने का आधार बनती हैं। दलों का भी बाहुबलियों के प्रति बढ़ते दुलार की कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह तो उनकी जिताऊ क्षमता है कि वे अपने तबके के समर्थन या डरा-धमका कर नतीजों को अपने पक्ष में करने में आगे रहते हैं। एक वजह यह भी है कि चुनाव अब बहुत खर्चीले होते हैं और बाहुबलियों के पास धन-संसाधनों का कोई अभाव नहीं होता। इसलिए राजनीतिक दलों को इनसे अच्छा-खासा चुनावी चंदा भी मिलता है, जिससे न केवल उनके चुनाव क्षेत्र, बल्कि आसपास के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी संसाधनों की पहुंच बढ़ती है।

राजनीति और अपराधीकरण के रिश्तों का तानाबाना भी समय के साथ बदला है। बाहुबली एक समय नेताओं को अपना समर्थन देते रहे और बदले में नेता उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। समय के साथ बाहुबली खुद ही राजनीति में उतरने लगे। अब तो वे अपने साथ-अपने खास करीबियों और परिवार के लोगों को भी राजनीति में स्थापित करने लगे हैं। अपराध और वंशवाद का यह नया खतरनाक चलन लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। यदि समय के साथ इस चलन पर विराम नहीं लगा तो भविष्य में इसके परिणाम विध्वंसक होंगे, जिसके रुझान पहले से दिखने भी लगे हैं और समय-समय पर दिखते भी रहते हैं। बाहुबलियों के रवैये से यही लगता है कि राजनीति उनके लिए जनता की समस्याओं के समाधान का माध्यम नहीं, बल्कि अपने वर्चस्व को स्थापित करने का एक अखाड़ा है। यह भी जगजाहिर है कि अपनी अवैध गतिविधियों के लिए भी वे राजनीति को एक ढाल बनाने का काम करते हैं।

राजनीति में अनियंत्रित हो रहे अपराधीकरण पर लगाम लगाने की जितनी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है, उतनी ही जनता की भी है। दोनों ही पक्षों को यह समझना होगा कि बाहुबलियों के साथ जुड़ने और उन्हें अपने साथ जोड़ने के तात्कालिक लाभ के बजाय कितना दूरगामी नुकसान होता है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम नई सरकार के गठन के साथ राजनीति में अपराधियों की बढ़ती पैठ को लेकर भी जनता का आदेश सुनाने का काम करेंगे, जिसका असर अन्य चुनावों पर भी पड़ता दिखेगा।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो और राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

पंथनिरपेक्षता का दिखावटी चेहरा

क्षमा शर्मा

वेंस का बयान दर्शाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए वे कैथोलिक अमेरिका को खुश करना चाहते हैं

पिछले दिनों अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पत्नी उषा वेंस के बारे में दिया गया एक बयान बहुत चर्चा में रहा। उनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं। विवाह भले ही उन्होंने वेंस से किया हो, वह मानती हिंदू धर्म को ही हैं। वेंस ने कहा कि उन्हें लगता है कि उषा एक न एक दिन ईसाई धर्म अपना लेंगी। वह उनके साथ चर्च भी जाती हैं और ईसाइयत में रुचि भी रखती हैं। वेंस ने यह भी बताया कि उनके बच्चों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया है। वे उन्हीं तौर-तरीकों से पाले जा रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ साल पहले शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान की ओर से दिया गया यह वक्तव्य याद आ गया कि वह हिंदू हैं, लेकिन उनका बेटा आर्यन इस्लाम को मानता है। इंटरफेथ शादियों में ऐसा हो सकता है कि पिता एक धर्म को मानता हो और मां किसी और धर्म को, लेकिन बच्चों के साथ मुसीबत यह होती है कि उन्हें चुनाव का कोई अधिकार नहीं दिया जाता। जन्मते ही उन पर माता-पिता का धर्म लाद दिया जाता है। प्रायः उनके नाम भी वैसे ही रखे जाते हैं। कई बार नाम फर्क भी हो सकते हैं, जैसे शाहरुख के बेटे का नाम आर्यन या जेडी वेंस के बेटे का नाम विवेक है।

हमें गलतफहमी है कि पश्चिम में लोग सही मायने में पंथनिरपेक्ष होते हैं। वे अपना मजहब किसी पर लादते नहीं हैं। एक ही घर में अलग-अलग पंथों को मानने वाले लोग रह सकते हैं और राज्य का कोई मजहब नहीं होता। वास्तविकता में ऐसा है नहीं। यदि ऐसा होता तो अमेरिकी राष्ट्रपतियों को बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ क्यों लेनी पड़ती? क्यों इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को कहना पड़ता कि वे ईसाई हैं। जेडी वेंस के बयान को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वे शायद ट्रंप के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए कैथोलिक बहुल अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। जब वेंस उपराष्ट्रपति बने थे तो भारतीय लोग बड़े खुश हुए थे कि चलो उनकी पत्नी का भारत से कुछ रिश्ता है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वे भारत भी आए और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी गए। न जाने क्यों जब भी किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को कोई बड़ा पद मिलता है या उसे कोई सफलता हासिल होती है तो हम उसे अपने ही चश्मे से देखने लगते हैं। सोचते हैं कि अपनी जड़ों के कारण यह व्यक्ति भारत के लिए भी कुछ अच्छा करेगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए भारत में बड़ी प्रार्थना की गई थी। वे बाइडेन प्रशासन में उपराष्ट्रपति थीं। हम भूल गए कि वे अतीत में किस तरह भारत विरोधी बयान दे चुकी हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जो विदेशी नागरिक है, वह अपने ही देश को प्राथमिकता देगा, भले ही उसकी जड़ें भारत में रही हों।

यरुशलम के एक चर्च में जेडी वेंस और उषा वेंस। फाइल

मजहबी कारणों से इस धरती पर जितने लड़ाई-झगड़े और खून-खराबा हुआ है, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। इस लड़ाई-झगड़े के पीछे मूल सोच यह रहता है कि हमारा मजहब दूसरे से श्रेष्ठ है। इसलिए जब तक यह पूरी दुनिया ही हमारे मजहब के झंडे तले नहीं आ जाती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मतांतरण पर अरबों-खरबों खर्च इसीलिए किए जाते हैं। जो लोग विविधता को सेलिब्रेट करते हैं, वही यह भी चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ हमारी पसंद का ही धर्म रहना चाहिए। उन्हें लगता है कि ऐसा होने पर ही दुनिया जीने के काबिल रहेगी।

एक लड़की का दशकों पहले अमेरिका में रहने वाले एक लड़के से विवाह हुआ। लड़की हिंदू थी, लड़का ईसाई। लड़के ने कहा कि उसकी कोई और शर्त नहीं है, सिवाय इसके कि लड़की ईसाई बन जाए। लड़की ने ऐसा ही किया। साथ में पढ़ने वाली एक महिला ने एक मुस्लिम से विवाह किया। उसने धर्म नहीं बदला, लेकिन उसके दोनों बच्चे पति के धर्म को ही मानने वाले बने। एक मुसलमान लड़की स्विट्जरलैंड में उच्च पद पर काम करती थी। वह दक्षिण अफ्रीका से आई थी। उसका इंग्लैंड के एक लड़के से प्रेम हो गया। जब दोनों को लगा कि विवाह कर लेना चाहिए तो लड़की ने कहा कि उनके बच्चे मुसलमान ही होंगे। क्या ऐसे विवाह सच में प्रेम विवाह हैं? आम तौर पर लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में देखना चाहते हैं, जैसे वे खुद हैं। साफ है कि बातें भले ही पंथनिरपेक्षता और सारे धर्मों का सम्मान करने को लेकर की जाएं, चाहत अपने धर्म के प्रसार की ही होती है। दुनिया में कोई और समूह इतने बड़े नहीं हैं, जितने धार्मिक समूह। इनके हिस्से बनकर हम ताकतवर महसूस करते हैं, क्योंकि कोई भी अकेला रहकर जी नहीं सकता। इसीलिए सब किसी न किसी धर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो लोग खुद को नास्तिक कहते हैं वे भी कई बार बेहद कट्टर साबित होते हैं। उदाहरण के तौर पर हिटलर और जिन्ना का नाम लिया जाता है।

जेडी वेंस हों या ट्रंप, वे किसी न किसी रूप में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते हुए अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। वेंस की ओर से अपनी पत्नी के धर्म बदलने की चाह के पीछे यही मान्यता दिखती है कि जो धर्म पति का हो, वही पत्नी का होना चाहिए। उषा वेंस क्या करती हैं, यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन संभव है कि वे पति की राष्ट्रपति बनने की इच्छा पूरी करने के लिए न चाहते हुए भी ऐसा करें। आखिर यह तथ्य है कि अतीत में अमेरिका में दूसरे धर्मों के कई नेता राष्ट्रपति के तब उम्मीदवार बने, जब उन्होंने ईसाइयत को अपना लिया।

(लेखिका साहित्यकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

दुख से सीख

सुख और दुख जीवन के दो अनिवार्य हिस्से हैं। प्रत्येक व्यक्ति इनकी अनुभूति करता है। यह भी सच है कि व्यक्ति केवल सुख के आनंद को भोगने की लालसा रखता है। उसे दुख शब्द सुनने से भी भय लगने लगता है। सुख की अनुगूंज से उसके कान केवल उल्लास का मधुर संगीत सुनने के अभ्यस्त हो जाते हैं। सुख को ही वह जीवन का ध्येय बना लेता है, परंतु सुख के पीछे-पीछे दुख की बदली भी अपनी गति से जीवन में प्रवेश करती है। दुख, पीड़ा, संकट आदि सब हमारे जीवन में यथासमय प्रवेश करते ही हैं। इन्हें स्वीकार करने का साहस हम सभी को होना ही चाहिए। अन्यथा दुख अथवा कष्ट के अनायास आगमन पर हम टूटकर बिखर जाएंगे। जीवन की गति थम जाएगी। हमें सदैव स्वयं को मजबूत रखना चाहिए। जीवन अप्रत्याशित है। कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। दुख के झंझावातों से से बाहर निकलने की सामर्थ्य हमें स्वयं अर्जित एवं विकसित करनी होगी। देखा जाए तो दुख हमें आंतरिक रूप से अत्यंत मजबूत करता है। दुख जीवन में एक परीक्षा बनकर प्रवेश करता है। जिस परीक्षा को हम अपने विवेक और सामर्थ्य से उत्तीर्ण करते हैं। जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता, वह जीवन की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है। दुख और शोक के बादलों के बीच घिर जाने से उसकी जीवटता का क्षय होने लगता है। वह शोक के सागर में डूबने लगता है। दुख को सहजता से स्वीकारना ही बुद्धिमत्ता है। तभी हम प्रगति के पथ पर गतिमान हो सकेंगे। भगवान श्रीराम के जीवन को देखें तो उन्हें भी अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। उन्होंने विवेकपूर्ण तरीके से दुख एवं पीड़ा को सहकर मर्यादा के नवीन मापदंड स्थापित किए। हमें दुख से घबराकर जीवन के संघर्ष से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, अपितु संघर्ष को जीवन का हिस्सा बनाकर स्वयं में निखार लाने का प्रयास करना चाहिए।

ललित शौर्य

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

उजड़ते वन और क्रोधित वनचर

ऋतुपर्ण दवे

जंगली जानवरों के मानव बस्तियों तक पहुंचने का कारण यह भी है कि जानवरों की रिहाइश पर कब्जा हो रहा है

जंगली पशुओं का मानव बस्तियों में घुस आना सामान्य सा हो गया है। प्रायः तेंदुओं, हाथियों, भालुओं और दूसरे हिंसक जानवरों द्वारा मानव बस्तियों में फैलाई जा रही दहशत की खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें नई नहीं हैं। पालतू जानवरों यहां तक कि इंसानों को निवाला बनाने की तस्वीरों ने हर किसी को परेशान कर रखा है। वन विभाग भी इससे निपटने में लगभग नाकाम ही दिखता है।

संसद में एक सवाल के जवाब में एक अगस्त, 2022 को तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया था कि भारत में लगभग 7,40,973 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण है। इसमें सबसे ज्यादा अकेले असम में 13 प्रतिशत है। इन आंकड़ों में उद्योगों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों और निजी संस्थाओं का कब्जा शामिल नहीं है। वन्य जीवों के ठिकानों पर इंसानी अतिक्रमण भी बेजा है। जंगलों के विनाश से जंगली उपज बेतहाशा घटी। भूखे बंदर, सांभर, हिरण, जंगली कुत्ते, सियार, नील गाय आबादी, खेतों और फार्म हाउसों में आ धमकने लगे। जंगल, पहाड़, नदी-नालों का स्वरूप इंसानी रिहाइश और विकास-औद्योगिकीकरण के चलते छिन्न-भिन्न हुआ जो कभी वन्यजीवों का आशियाना था। स्वार्थ से भरे विकास के बीच यह भूलना भारी पड़ा कि हमने वनचरों का ठौर रौंद बड़ा असंतुलन पैदा किया। मानव आबादी बढ़ने लगी, वन्यजीव घटने लगे।

वास्तव में जंगली पशु खाने की तलाश में भटकते वहीं आ जाते हैं जो कभी उनके ठिकाने थे। बस्तियों और सड़कों को बने कितना समय हुआ? दूसरी सच्चाई यह भी कि विशेषकर हाथी अपनी याददाश्त पीढ़ी दर पीढ़ी एक-दूसरे को हस्तांतरित करते हैं। हमें लगता है कि जंगली हाथी आबादी में कैसे? उन्हें लगता है हमारे ठिकानों पर इंसान कैसे?

जब इस बाबत थोड़ी समझ विकसित हुई तो विश्व में बड़ी चिंता शुरू हो गई। 1992 में ब्राजील में जैव विविधता की महत्ता पर सम्मेलन हुआ। भारत और दूसरे 154 देश शामिल हुए। वन्यजीवों को बचाने हेतु वनस्पति से लेकर उनकी दूसरी खुराक की किस्मों और चारा-पानी सहित जल, जंगल और जमीन पर चिंता की गई। तय हुआ कि हर देश वन्य जीवों की रिहाइश चिन्हित कर उनकी सुरक्षा करे। भारत ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। वन्य पशुओं हेतु आरक्षित क्षेत्रों का प्रविधान कर, प्राकृतिक स्वरूप में विकसित करना तय हुआ।

सच्चाई सामने है। वन, पहाड़ उजड़ते गए, नदियों का सीना छलनी कर विकास की कुलांचे भरते रहे। प्राकृतिक ढांचों के भूगोल बदलने की विकासवादी प्रतिस्पर्धा के आनंद में वन्यजीवों के साथ हुआ बड़ा धोखा भूल गए। वही वनचर अपने मूल ठिकानों पर आकर क्रोधित होते हैं। हम उनकी पीड़ा, मर्म, दर्द नहीं समझ रहे।

(लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं)

सेना को लेकर न हो राजनीति

'विभाजनकारी बयान' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय का संदर्भ बिहार चुनाव प्रचार में राहुल गांधी का वह बयान है, जिसमें वे देश की सेना में कुछ जातियों के वर्चस्व पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ऐसा कहना राष्ट्रीय पार्टी के नेता के तौर पर बहुत ही अप्रत्याशित बयान है। अपने बयान से पूर्व उन्हें यह बताना चाहिए था कि बिहार विधानसभा चुनाव टिकट वितरण में उनकी पार्टी ने किस सीमा तक समावेशी भागीदारी सुनिश्चित की है? उन्हें यह भी बताना चाहिए कि बिहार के अलावा जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी से उनकी पार्टी का सीधा मुकाबला रहता है, वहां कांग्रेस पर किस वर्ग या समूह का प्रभुत्व रहता है? तभी सही मायने में वे सामाजिक न्याय के पक्षधर कहलाएंगे। ऐसी बयानबाजी से तो केवल सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने वाली राजनीति को ही बल मिलेगा। सेना जैसी संस्था को तो राजनीति से परे ही रखना चाहिए। ऐसे बयान की निंदा ही की जा सकती है।

mananmk8155@gmail.com

भारतीय लोकंतत्र की मजबूती

बुधवार को राजीव सचान द्वारा लिखित आलेख लापता हुई आम सहमति की राजनीति पढ़ा। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बहुलता, विविधता और विचारों की व्यापकता रही है। इसी विविधता को संतुलित रखने का माध्यम रही आम सहमति की राजनीति, जिसने दशकों तक नीति-निर्माण, सामाजिक मुद्दों और राष्ट्रीय हितों पर राजनीतिक दलों को एक साझा धरातल पर खड़ा रखा। किंतु आज यह

मेलबाक्स

सहमति तेजी से क्षीण होती दिख रही है। बीते वर्षों में राजनीतिक विमर्श में मतभेद स्वाभाविक प्रक्रिया से आगे बढ़कर विरोध और दुश्मनी का रूप ले चुका है। संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप ने ले ली है। लोकसभा और राज्यसभा में महत्वपूर्ण विधेयकों पर बिना व्यापक चर्चा के निर्णय होने लगे हैं। राजनीतिक दल एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी समझने लगे। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है। समय-समय पर मतदाता सूची में पुनरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव आयोग द्वारा नौ राज्यों एवं तीन केंद्र शासित राज्यों में मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसका बंगाल और तमिलनाडु सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है। आयुष्मान योजना को पूर्व की दिल्ली की आप सरकार ने लागू नहीं किया था। यह राजनीति में गिरती नैतिकता का परिचायक है। आज राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता की प्राप्ति है, इसीलिए आम सहमति की राजनीति समाप्त होती जा रही है। क्षेत्रीय और जातीय पहचान की राजनीति ने साझा राष्ट्रीय दृष्टि को कमजोर किया है। संवाद की संस्कृति समाप्त होती जा रही है। सरकारों को चाहिए कि व्यापक विमर्श की परंपरा को पुनर्जीवित करें, महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर विपक्ष को सहभागी बनाएं। वहीं विपक्ष को भी विरोध की राजनीति से ऊपर उठकर रचनात्मक सहयोग देना चाहिए। ऐसा होने से भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होगा।

हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी, बिहार

भारत में महिला क्रिकेट का नया युग

आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर गर्व व्यक्त करना चाहती हूं। इस जीत ने हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा, समर्पण और जुझारूपन को दर्शाया है, जिसने दुनिया को दिखाया है कि भारतीय महिलाएं भी किसी भी खेल में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक ताकत के रूप में खड़ी हो सकती हैं। हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा जैसी हमारी खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने लाखों युवा लड़कियों को क्रिकेट को अपना करियर बनाने के लिए आत्मविश्वास से प्रेरित किया है। इस जीत ने न केवल अन्य देशों के प्रभुत्व को तोड़ा है, बल्कि भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत भी की है। अब यह सरकार और खेल अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं, वित्तीय सहायता और समान अवसर सुनिश्चित करें, ताकि भारत एथलेटिक्स के हर क्षेत्र में और अधिक चमक सके।

मीनल, दोआबा कालेज, जालंधर, पंजाब

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, डी- 210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

****